सत्यमेव जयते

भारत सरकार

निर्गम परिणाम अनुवीक्षण रूपरेखा

2026-2027

वित्त मंत्रालय

फरवरी, 2026

निर्गम परिणाम अनुवीक्षण रूपरेखा 2026-27

(प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं)

प्रस्तावना

पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा व्यय संबंधी प्रमुख सुधार किए गए हैं। इसमें न केवल मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रियाओं का सरलीकरण शामिल है, बल्कि बजट की प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन भी शामिल हैं, जैसे,- आयोजना और आयोजना-भिन्न भेद को दूर करना। नतीजतन, लागत-केंद्रों को केवल सांविधिक राजस्व पूंजी ढांचे के भीतर एक एकीकृत रुप में देखा जा रहा है। यह एक और प्रमुख संरचनात्मक सुधार को सक्षम करता है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक योजनाओं और परियोजनाओं को एक अनुवीक्षणीय निर्गम- परिणाम ढांचे के तहत लाना है।

2017-18 के बाद से, बजट दस्तावेज़ में इंगित की जा रही मंत्रालयों की योजनाओं की वित्तीय रूपरेखा के अलावा, योजनाओं के अपेक्षित आउटपुट और परिणाम भी बजट सहित समेकित परिणामी बजट दस्तावेज में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के निष्पादन में शामिल एजेंसियों को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए इन परिव्ययों, निर्गमों और परिणामों को संसद में माप्य रुप में प्रस्तुत किया जा रहा है। परिव्यय वह राशि है जो बजट में किसी योजना या परियोजना के लिए प्रदान की जाती है; जबकि निर्गम (आउटपुट) कार्यक्रम संबंधी कार्यों के प्रत्यक्ष और माप्य उत्पाद को संदर्भित करता है, जिसे अक्सर भौतिक शब्दों या इकाइयों में व्यक्त किया गया है। परिणाम का आशय इन सेवाओं के वितरण में सामूहिक परिणाम या गुणात्मक सुधार से है।

वित्त वर्ष 2026-27 के आरंभ से परिणामी बजट को निर्गम परिणाम अनुवीक्षण रुपरेखा (ओओएमएफ) के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ओओएमएफ में (क) वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय परिव्यय (ख) के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित निर्गम और परिणाम (ग) माप्य निर्गम और परिणाम संकेतक और (घ) विशिष्ट निर्गम और परिणाम लक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इससे सरकार की विकास कार्यसूची की पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता और समझने में आसानी बढ़ जाएगी।

सरकार का लक्ष्य इस अभ्यास के माध्यम से शासन की एक खुली, जवाबदेह, सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण शैली को बढ़ावा देने के लिए महज नतीजों पर ध्यान न देकर परिणामोन्मुख निर्गम और परिणामों पर अधिक ध्यान दिया जाना है। इस प्रयास से मंत्रालयों को योजना के उद्देश्यों पर नज़र रखने और उनके द्वारा निर्धारित विकास लक्ष्यों की दिशा में काम करने में सुविधा होगी। यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा दस्तावेज़ परिणाम बजट 2025-26 का एक उद्धरण है और इसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 500 करोड़ रूपए से अधिक परिव्यय वाली मुख्य सीएस और सीएसएस योजनाओं के लिए निर्गम-परिणाम रुपरेखा शामिल है। अतः यह दस्तावेज़ 172 सीएस/सीएसएस योजनाओं को कवर करता है।

अभिस्वीकृतियाँ

निर्गम-परिणाम अनुवीक्षण रूपरेखा, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न हितधारकों की सहकारिता, टीमवर्क और सहयोग का परिणाम है।

सभी मंत्रालयो और विभागों के सचिवों के नेतृत्व में उनके नोडल अधिकारियों तथा विभिन्न सीएस और सीएसएस योजनाओं के प्रभारी प्रभागाध्यक्षों की अथक मदद और समर्थन के बिना इस संपूर्ण रूपरेखा को उपलब्ध कराना संभव नहीं होता।

श्री सुमन बेरी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग के नेतृत्व में विषय-वस्तु वर्टिकल श्रीमती निधि छिब्बर, महानिदेशक, डॉ. राधा आर. आश्रित, उप महानिदेशक, डॉ. देवी प्रसाद भुक्या, निदेशक तथा विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) की टीम द्वारा प्रदान की गई सहायता से इस रूपरेखा को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है।

इसके अलावा, मैं आर्थिक कार्य विभाग में बजट प्रभाग के सभी अधिकारियों को इस रूपरेखा को तैयार करने के संबंध में उनके दृढ़ समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं व्यय विभाग में अपनी टीम के सभी सदस्यों और विशेष रूप से मंत्रालयों और विभागों में वित्तीय सलाहकारों द्वारा इस दस्तावेज के संबंध में दर्शाए गए दृढ़ विश्वास के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं।

और अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन और माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और का विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने पारदर्शी और जवाबदेह व्यय प्रबंधन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हमें यह महत्वपूर्ण कदम उठाने में सक्षम बनाने के लिए अपना मार्गदर्शन प्रदान किया।

श्री वी. वुअलनाम

(सचिव, व्यय विभाग)

वित्त मंत्रालय

भारत सरकार

अनुदान मांगों की सूची

क्र.सं.	मंत्रालय	विभाग	मांग सं.	पृष्ठ सं.
1.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	1	5
2.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2	23
3.	आयुष मंत्रालय	लागू नहीं	4	26
4.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	उर्वरक विभाग	6	28
5.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	औषधि विभाग	7	29
6.	नागर विमानन मंत्रालय	लागू नहीं	8	33
7.	कोयला मंत्रालय	लागू नहीं	9	34
8.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	वाणिज्य विभाग	10	36
9.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	11	37
10.	संचार मंत्रालय	डाक विभाग	12	40ज
11.	संचार मंत्रालय	दूरसंचार विभाग	13	42
12.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	उपभोक्ता मामरेविभाग	14	45
13.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15	47
14.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	लागू नहीं	17	51
15.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	लागू नहीं	23	52
16.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	लागू नहीं	24	58

क्र.सं.	मंत्रालय	विभाग	मांग सं.	पृष्ठ सं.
17.	शिक्षा मंत्रालय	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	25	66
18.	शिक्षा मंत्रालय	उच्चतर शिक्षा	26	73
19.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	लागू नहीं	27	82
20.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	लागू नहीं	28	91
21.	वित्त मंत्रालय	आर्थिक कार्य विभाग	30	92
22.	वित्त मंत्रालय	वित्तीय सेवाएं विभाग	32	95
23.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	मत्स्यपालन विभाग	43	97
24.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	पशुपालन और डेयरी विभाग	44	100
25.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	लागू नहीं	45	103
26.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46	108
27.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	भारी उद्योग विभाग	48	132
28.	गृह मंत्रालय : गृह मामले	लागू नहीं	49	135
29.	गृह मंत्रालय : पुलिस	लागू नहीं	51	136
30.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	लागू नहीं	60	143
31.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	लागू नहीं	61	155
32.	जल शक्ति मंत्रालय	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	62	157
33.	जल शक्ति मंत्रालय	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	63	162
34.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	लागू नहीं	64	164

क्र.सं.	मंत्रालय	विभाग	मांग सं.	पृष्ठ सं.
35.	विधि और न्याय मंत्रालय	न्याय विभाग	65	166
36.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	लागू नहीं	68	169
37.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	लागू नहीं	70	177
38.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	लागू नहीं	71	180
39.	पंचायती राज मंत्रालय	लागू नहीं	72	188
40.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	लागू नहीं	76	193
41.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	लागू नहीं	78	197
42.	विद्युत मंत्रालय	लागू नहीं	79	199
43.	रेल मंत्रालय	लागू नहीं	85	203
44.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	लागू नहीं	86	209
45.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	ग्रामीण विकास विभाग	87	211
46.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	भूमि संसाधन विभाग	88	220
47.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	89	221
48.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	बायोटेक्नोलॉजी विभाग	90	231
49.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	लागू नहीं	92	234
50.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	93	236
51.	अंतरिक्ष विभाग	लागू नहीं	95	241
52.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	लागू नहीं	96	246

क्र.सं.	मंत्रालय	विभाग	मांग सं.	पृष्ठ सं.
53.	वस्त्र मंत्रालय	लागू नहीं	98	250
54.	पर्यटन मंत्रालय	लागू नहीं	99	252
55.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	लागू नहीं	100	254
56.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	लागू नहीं	101	262
57.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	खेल विभाग	102	271

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
63,500	1. योजना का कवरेज	1.1. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत नामांकित पात्र लाभार्थियों की संख्या (करोड़ में)	9.5	1. कृषि योग्य भूमि धारक सभी किसानों को सुनिश्चित आय सहायता	1.1. कृषि एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता का उपयोग करने वाले किसानों का %	100
		1.2. लाभार्थियों को जारी कुल धनराशि (करोड़ रुपए में)	63,500			
	2. सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)	2.1 वित्तीय वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों का %	95		1.2. कृषि इनपुट के लिए इस राशि का उपयोग करने वाले किसानों का %	75

2. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
22,600	1. वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए अल्पकालिक ऋण और वित्तीय वर्ष के दौरान एमआईएसएस के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले केसीसी[1] के खाताधारक	1.1 वर्ष के दौरान केसीसी के माध्यम से अल्पकालिक ऋण (एसटीसी) प्राप्त करने वाले खातों की संख्या में निवल वृद्धि (खातों की संख्या लाख में)[2]	5	1. किसानों को दिए गए कृषि ऋण का विस्तार	1.1 वर्ष के दौरान किसानों को दिए गए अल्पकालिक ऋण की कुल राशि। (करोड़ रुपए में)	16.30

[1] *किसान क्रेडिट कार्ड*

[2] *लक्ष्य किसान ऋण पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों आधार पर निर्धारित किया जाएगा।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		1.2 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए केसीसी के माध्यम से दिए गए ऋण से लाभान्वित होने वाले खातों की कुल संख्या (खातों की संख्या करोड़ में)[3]	7.77			
		1.3 ऋण से लाभान्वित होने वाले एसएमएफ के खातों की कुल संख्या (खातों की संख्या करोड़ में)	6.10		1.2 वर्ष के दौरान प्रदत्त कृषि ऋण की कुल राशि (करोड़ रुपए में)	30
		1.4 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर अल्पकालिक ऋण के बदले दिए गए आईएस और पीआरआई की राशि (करोड़ रुपये में)	22,600			

3. फसल बीमा योजना: (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
12,200	1. कवरेज में वृद्धि	1.1. फसल बीमा के अंतर्गत किसान आवेदनों की संख्या (खरीफ के लिए 15 अगस्त तक और रबी सीजन के	14.5[4]	1. कृषक परिवारों के लिए जोखिम	1.1 जीवीए (फसलों) पर बीमा कवरेज (%)	10.5

[3] अन्य के लिए लक्ष्य नाबार्ड और आरबीआई से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तय किया जाएगा।

[4] खरीफ- 9.5 और रबी- 5

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		लिए आगामी वर्ष 15 जनवरी तक) (करोड़ में)		न्यूनीकरण में वृद्धि		
		1.2. फसल बीमा पीएमएफबीवाई[5] कार्यान्वयनकर्ता राज्य के अंतर्गत बीमित क्षेत्र, (खरीफ के लिए 15 अगस्त तक और रबी सीजन के लिए आगामी वर्ष 15 जनवरी तक) (करोड़ हेक्टेयर)	6.25[6]			
		1.3. कुल बीमा राशि (लाख करोड़ रुपए में)	3			
	2. प्रौद्योगिकी और दावा निपटान तंत्र के माध्यम से कुशल दावा मूल्यांकन	2.1. येस-टेक लागू करने वाले जिलों की संख्या (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली) येस-टेक मैन्युअल के अनुसार	250	2. बड़ी संख्या में किसानों को जोखिम संरक्षण	2.1. कुल किसानों के मुकाबले बीमित किसानों का %	35
		2.2. विंड्स[7] मैनुअल के अनुसार स्थापित एडब्ल्यूएस और एआरजी की संख्या	7,500			
		2.3. चालू सीजनों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को डिजि-क्लेमस के माध्यम से भुगतान किए गए स्वीकृत दावों का % (प्रगति की रिपोर्ट सीजन के समापन के बाद अगली तिमाही में दी जाएगी, अर्थात खरीफ के लिए दिसंबर और रबी के लिए अगले वर्ष जून को सीजन समापन माह माना जाएगा)	90			
		2.4. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा फसल क्षति एवं उपज के आंकड़े उपलब्ध कराने के एक माह के भीतर निपटान दावों का %	80			

[5] *पीएमएफबीवाई: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना*

[6] *खरीफ- 3.25 और रबी- 3*

[7] *विंड्स: मौसम सूचना नेटवर्क डेटा प्रणाली*

4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
8,550	1. कृषि और संबद्ध योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना।	1.1. कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की कुल संख्या	500	1. किसानों के प्रयासों को मजबूत करने, जोखिम कम करने और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से खेती को लाभकारी आर्थिक कार्यकलाप बनाना।	1.1. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में क्रियान्वित परियोजनाओं की संख्या	500
					1.2. आरकेवीवाई की डीपीआर आधारित योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं की कुल संख्या(1000-1100)	1100
	2. संभावित राज्यों में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना	2.1 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में उद्यमियों को प्रदान किए गए प्रशिक्षणों की संख्या	800		1.3. वित्तीय सहायता प्राप्त उद्यमियों/स्टार्टअप्स की संख्या	400
	क. प्रति बूंद अधिक फसल					
	1. पानी को अच्छे से पहुंचाने और पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले डिवाइस - स्प्रिंकलर, ड्रिप आदि।	1.1. सूक्ष्म सिंचाई (एमआई) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	12	1. जल उपयोग दक्षता में वृद्धि	1.1. सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों की संख्या (लाख में)	11.5
	ख. फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि यंत्रीकरण (सीआरएम सहित एसएमएएम) पर उप मिशन					
	1. फसल उत्पादन और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए छोटे और सीमांत किसानों तक फार्म मशीनीकरण की पहुंच में वृद्धि	1.1. वित्तीय वर्ष के दौरान फसल अवशेष मशीनरी सहित कृषि मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले	1,50,000	1. फसल अवशेष प्रबंधन के लिए लक्षित लाभार्थियों के बीच फार्म मशीनीकरण की पहुंच में वृद्धि।	1.1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इन-सीटू और एक्स-सीटू विकल्पों के अंतर्गत मशीनरी द्वारा प्रबंध की गई फसल अवशेषों की	25

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		किसानों/लाभार्थियों की संख्या			मात्रा। (एम टी)	
		1.2. वित्तीय वर्षके दौरान फसल अवशेष प्रबंधन सहित स्थापित सीएचसी, हाई-टेक हब की संख्या।	5,000			
		1.3. प्रशिक्षित किसानों और अन्य हितधारकों की संख्या।	10,000	2. किसानों के बीच फसल अवशेषों के प्रबंधन को अधिक से अधिक अपनाया जाना।	2.1 वर्ष 2018 की तुलना में आग लगने की घटनाओं में आई कमी का %	25-50
		1.4. उन गांवों की संख्या जहां वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि-यांत्रिकी को समर्थन दिया गया।	1,500			
	ग. जलवायु अनुकूल एकीकृत कृषि प्रणाली (सीएसएस)/वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)					
	1. मॉडल कृषि क्षेत्र का विकास	1.1. विकसित किए गए मॉडल कृषि क्षेत्रों की संख्या	6,000	1. जलवायु-अनुकूल एकीकृत कृषि प्रणालियों का प्रोत्साहन	1.1. जलवायु-अनुकूल एकीकृत कृषि प्रणाली के अंतर्गत कुल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	0.3
				2. एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने में वृद्धि।	2.1 वित्तीय वर्ष के दौरान एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाने वाले किसानों की संख्या (लाख में)	0.3
	घ. हरित क्रांति: परंपरागत कृषि विकास योजना (सीएसएस)					
	1. जैविक खेती के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि	1.1. जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया कुल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[8]	1. जैविक खेती के बारे में जागरूकता में वृद्धि।	1.1. सक्रिय जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में % की वृद्धि।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए

[8] *मांग के आधार पर*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
						जा सकते
		1.2. जैविक खेती को अपनाने वाले किसानों की संख्या (लाख में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[9]		1.2. जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत आने वाले किसानों की संख्या में % की वृद्धि।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
	ङ. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना (एसएच एंड एफ)					
	1. जारी/निर्मित सॉइल स्वास्थ्य कार्ड की संख्या में वृद्धि और किसानों के बीच जागरूकता में वृद्धि।	1.1. वित्तीय वर्ष के दौरान जारी/जनरेट किए गए सॉइल स्वास्थ्य कार्ड की संख्या (लाख)	50	1. किसानों/छात्रों की संख्या में वृद्धि	1.1. प्रशिक्षित किसानों की संख्या (लाख)	50
		1.2. स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत भाग लेने वाले विद्यालयों की संख्या	1,020		1.2. प्रशिक्षित छात्रों की संख्या	1,00,000
	च. कृषि वानिकी[10]					
	1. बेहतर गुणवत्ता वाली पौध सामग्री का उत्पादन	1.1. वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित की गई नई नर्सरियों की संख्या	232	1. कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता।	1.1. गुणवत्ता रोपण सामग्री (पौध) का उत्पादन (लाख में)	280

[9] *मांग के आधार पर*

[10] *ईएफसी मेमो में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार*

5. कृषोन्नति योजना (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
11,200	**क. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन और ऑयल पाम (एनएमईओ-ओएस और ओपी)**					
	I. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस)					
	1. प्राथमिक तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि	1.1. 600 मूल्य श्रृंखला समूहों के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज (लाख हेक्टेयर में)	10	1. देश में खाद्य तेल उत्पादन में वृद्धि	1.1. घरेलू खाद्य तेल उत्पादन (लाख टन में)	143.40
		1.2. किसानों को मुफ्त बीज वितरण (लाख क्विंटल में)	5.48		1.2. तिलहन का उत्पादन (लाख टन में)	459
		1.3. प्राथमिक तिलहनों के अंतर्गत वार्षिक क्षेत्र कवरेज (लाख हेक्टेयर में)	304			
	II. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी)					
	1. ऑयल पाम के बागानों का उत्पादन बढ़ाना	1.1. एनएमईओ-ओपी के अंतर्गत वार्षिक क्षेत्र विस्तार (लाख हेक्टेयर में)	1	1. देश में क्रूड ऑयल पाम के उत्पादन में वृद्धि	1.1. क्रूड पाम ऑयल का उत्पादन (लाख टन में)	23.30
	ख. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन					
	1. उपज /उत्पादकता में वृद्धि	1.1. खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता। (चावल, गेहूं, मोटा अनाज और पोषक अनाज) (एमटी) (किग्रा/हेक्टेयर)	3,123	1. खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता	1.1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन (चावल, गेहूं, मोटा अनाज और पोषक अनाज) (एमटी)	3.40
		1.2. पोषक अनाजों की उत्पादकता (किग्रा/हेक्टेयर)	1,494			
		1.3. मोटे अनाजों की उत्पादकता (किग्रा/हेक्टेयर)	3,797			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	ग. समेकित बागवानी विकास मिशन					
	1. नर्सरी की बढ़ी हुई क्षमता	1.1. तैयार की गई नई नर्सरियों की संख्या	50	1. बागवानी फसलों की अत्यधिक उत्पादन	1.1. बागवानी उत्पादों का कुल उत्पादन (मिलियन टन में)	365
		1.2. नई नर्सरियों के माध्यम से लगाए गए पौधों की संख्या (लाख में)	20			
	2. कृषि क्षेत्र का विस्तार।	2.1 नए बागानों के माध्यम से खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र में वृद्धि। (हेक्टेयर में)	80,000			
	3. पुनर्जीवित जीर्ण बागान के अंतर्गत क्षेत्र	3.1 कुल कृषि क्षेत्र जहां जीर्ण पौधों को पुनर्जीवित किया गया है (हेक्टेयर में)	8,000			
	4. संरक्षित खेती	4.1 कुल कृषि क्षेत्र जहां संरक्षित खेती की जा रही है (हेक्टेयर में)	15,000	2. बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र	2.1 बागवानी फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर में)	29.5
	5. फसलोपरान्त प्रबंधन को वृद्धि	5.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज यूनिट की क्षमता (लाख मीट्रिक टन में)	1.7			
	6. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण / विस्तार / जागरूकता	6.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण के लिए शामिल किए किसानों की संख्या	70,000			
	घ. कृषि विस्तार					
	1. एमएएनएजीई[11] और विस्तारित शिक्षा संस्थान (ईईआई) के माध्यम से	1.1. वित्तीय वर्ष के दौरान एमएएनएजीई द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणों की	38,000	1. राज्य के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र विभाग में कार्यरत वरिष्ठ	1.1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान एमएएनएजीई द्वारा प्रशिक्षित विस्तार कार्यकर्ताओं की संख्या।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[12]

[11] *राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	विस्तार कार्यकर्ताओं के ज्ञान और कौशल का उन्नयन, कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। (केंद्रीय क्षेत्र योजना)	संख्या		और मध्यम स्तर के विस्तार कर्मियों की क्षमता निर्माण .		
		1.2. वित्तीय वर्ष के दौरान ईईआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या।	4,600		1.2. वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान प्रशिक्षित विस्तार कार्यकर्ताओं की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[13]
	2. एटीएमए[14] (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत राज्यों को किसानों के प्रशिक्षण और विस्तार संबंधी सहायता प्रदान करना।	2.1 वित्तीय वर्ष के दौरान एटीएमए कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या	15,91,088	2. कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में किसानों एवं ग्रामीण युवाओं की क्षमता निर्माण	2.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान नई कृषि प्रौद्योगिकी अपनाने वाले लाभार्थियों की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[15]
		2.2 प्रदर्शन प्राप्त लाभार्थी किसानों की संख्या (लाख)	2,57,527			
		2.3 किसान मेला/गोष्ठी/किसान-वैज्ञानिक संवाद में आगंतुकों की संख्या	14,36,693			
		2.4 कृषि विद्यालयों के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या	3,26,708			
	3. कृषि उद्यमियों और इनपुट डीलरों का प्रशिक्षण। (केंद्रीय क्षेत्र	3.1 एसी और एबीसी[16] योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कृषि उद्यमियों की संख्या	2,870	3. एसी और एबीसी द्वारा स्थापित नए उद्यम	3.1 एसी एंड एबीसी द्वारा स्थापित किए जाने वाले कृषि उद्यमों की कुल संख्या	1,005

[12] *इस तकनीक को अपनाने की दर तुरंत पता नहीं चल पाती है।*

[13] *इस तकनीक को अपनाने की दर तुरंत पता नहीं चल पाती है।*

[14] *कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी*

[15] *इस तकनीक को अपनाने की दर तुरंत पता नहीं चल पाती है।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	योजना)	3.2 इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा (डीएईएसआई) के लिए बैचों की संख्या (डीएईएसआई)	375		3.2 प्रशिक्षित इनपुट डीलरों की संख्या।	15,000
	4. किसानों के लिए आउटरीच कार्यक्रम (केंद्रीय क्षेत्र योजना)	4.1 इस वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित किसान कॉल सेंटरों की संख्या	22	4. किसानों के लिए आउटरीच कार्यक्रमों की वृद्धि।	4.1 इस वित्तीय वर्ष के दौरान किसानों को जारी परामर्शिकाओं की कुल संख्या (लाख)	50
		4.2 दूरदर्शन (डीडी) और आकाशवाणी(एआईआर) के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों की कुल संख्या	18,876[17]		4.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि पर आधारित दूरदर्शन कार्यकर्मों के दर्शकों की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[18]
	ङ. डिजिटल कृषि मिशन					
	1. किसान आईडी सृजित करना जो संचयी रूप से लिंक किए गए कृषि भूमि और बोई गई मूल फसल से लिंक किए गए हो।	1.1. वित्तीय वर्ष के दौरान सृजित किए गए किसान आईडी की संख्या। (करोड़ में)	11	1. किसानों को पारदर्शी तरीके से बाधा रहित सेवाएं और योजनाओं का लाभ प्रदान करना।	1.1. वित्तीय वर्ष के दौरान रजिस्ट्री से लिंक की गई सेवाओं/योजनाओं, जैसे कि ऋण, बीमा, खरीद आदि की संख्या। (करोड़)	1
	2. जिओ-रेफेरेंस्ड विलेज मैप।	2.1 इस वित्तीय वर्ष के दौरान जिओ-रेफेरेंस्ड गांवों की संख्या।	लक्ष्य निर्धारित	2. राज्य के डीसीएस में शामिल होने के बाद,	2.1 गांवों की संख्या जहां इस वित्तीय वर्ष के दौरान डीसीएस	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा

[16] *एग्रीक्लीनीक्स और एग्री बिजनेस केंद्र*

[17] *डीडी=3,276 और एआईआर=15,600*

[18] *कृषि आधारित दूरदर्शन कार्यक्रमों की दर्शक संख्या का वित्तीय वर्ष के दौरान सटीक पूर्वानुमान या मात्रा निर्धारण पूर्व-निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दर्शक संख्या अनेक गतिशील कारकों पर निर्भर करती है, इसलिए इसे अनुमानित रूप से या मापनीय रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
			नहीं किए जा सकते[19]	भूखंड स्तर के ग्राम मैप के डिजिटलीकरण के तुरंत बाद सर्वेक्षण शुरू किया जा सकता है।	चलाया गया है।	सकते[20]
	3. डिजिटल फसल सर्वेक्षण	3.1 वित्तीय वर्ष के दौरान डिजिटल फसल सर्वेक्षण पूरा करने वाले जिलों की संख्या।	25[21]	3. केंद्र/राज्य मैनुअल ग्रिडवारी प्रणाली के बजाय डीसीएस आधारित फसल क्षेत्र का उपयोग करेंगे।	3.1 राज्यों की संख्या जहां वित्तीय वर्ष के दौरान त्वरित फसल क्षेत्र आकलन किया गया।	12
	4. सपोर्ट रजिस्ट्री तैयार करना	4.1 वित्तीय वर्ष के दौरान बनाए गए लाइव सपोर्ट रजिस्टरों की संख्या।	20	4. सपोर्ट रजिस्ट्रियों के माध्यम से कृषि सेवाओं की बेहतर उपलब्धता।	4.1 वित्तीय वर्ष के दौरान डिजिटल समाधान और सेवाओं के लिए सपोर्ट रजिस्ट्रियों का उपयोग करने वाली योजनाओं/प्रणालियों की संख्या।	40
	5. कोर रजिस्ट्री का उपयोग करने के लाभ (यूस केसेस)।	5.1 वित्तीय वर्ष के दौरान एग्रीस्टैक के साथ डेटा और नीतियों को साझा करने के लिए अधिसूचित राज्यों की संख्या।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[22]	5. किसानों के लिए बेहतर सेवाएं	5.1 किसान केंद्रित समाधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए कोर रजिस्ट्रियों के डेटा का उपयोग करने वाले यूस केसेस की संख्या।	40

[19] *सभी जिलों में भौगोलिक संदर्भ वाले ग्राम मानचित्र होंगे*

[20] *सभी गांवों, जहां मैप जिओ-रेफेरेंस किया गया है, मेंडीसीएस लागू किया गया है।*

[21] *25 राज्यों में डीसीएस*

[22] *अधिसूचित किया जाना है और सभी राज्यों को शामिल किया जाना है।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	च. कृषि विपणन					
	i. **कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)**					
	1. कृषि विपणन अवसंरचना का विकास/सुदृढ़ीकरण	1.1. अनुमोदित भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं की क्षमता (लाख मीट्रिक टन में)	12.25	1. कृषि विपणन अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना	1.1. कृषि विपणन अवसंरचना में निजी निवेश (करोड़ में)	2,000
		1.2. अनुमोदित भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	600	2. महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण	2.1 महिला उद्यमियों द्वारा प्रोत्साहित परियोजनाओं की संख्या	200
	ii. **राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम)**					
	1. ई-एनएएम के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग के संबंध में अधिक जागरूकता	1.1. ई-नाम के माध्यम से जोड़े गए बाजारों की संख्या	150	1. नए ई-नाम बाजारों में ई-नाम के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार को अपनाया जाना	1.1 ई-नाम के माध्यम से व्यापार किए गए उत्पाद की मात्रा (एमटी)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[23]
		1.2. आयोजित जागरूकता कैंपों में भाग लेने वाले किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों की संभावित संख्या।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[24]			
		1.3. ई-नाम के अतंर्गत प्रशिक्षित किसानों की संख्या	लक्ष्य निर्धारित			

[23] 31.12.2025 तक, ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर कुल 13.01 करोड़ मीट्रिक टन का व्यापार दर्ज किया गया है।अंतिम आंकड़ा इस समय उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ई-एनएएम के माध्यम से व्यापार लक्ष्य की गणना 31.03.2026 तक के वास्तविक व्यापार आंकड़ों के आधार पर की जा सकती है।

24 *वर्तमान रणनीतिक साझेदार के साथ अनुबंध की अवधि मार्च 2026 में समाप्त हो रही है, इसलिए ई-एनएएम के तहत हितधारकों के प्रशिक्षण के लक्ष्यों पर विचार नहीं किया जा रहा है।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
			नहीं किए जा सकते[25]			

6. 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन और संवर्धन (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
500	1. उत्पादक संगठन की पहुंच में वृद्धि	1.1 मौजूदा एफपीओ से जोड़े गए अतिरिक्त किसानों की संख्या	10,00,000	1. एफपीओ के लिए ऋण की उपलब्धता और वित्तीय पात्रता में वृद्धि	1.1 एफपीओ द्वारा प्राप्त इक्विटी ग्रांट फंड (ईजीएफ) का कुल मूल्य (करोड़)	150
		1.2 विभिन्न लाइसेंस (बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि) प्राप्त करने वाले एफपीओ की संख्या	2,500		1.2 वित्तीय वर्ष के दौरान एफपीओ के औसत टर्नओवर में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि	40
	2. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	2.1 आयोजित एफपीओ के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	160		1.3 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) द्वारा प्राप्त क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफ) का कुल मूल्य (करोड़)	60
		2.2 प्रशिक्षित होने वाले मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) की संख्या	1,000		1.4 ई-नाम प्लेटफॉर्म/ओएनडीसी[26] एवं अन्य	3,000

[25] *वर्तमान रणनीतिक साझेदार के साथ अनुबंध की अवधि मार्च 2026 में समाप्त हो रही है, इसलिए ई-एनएएम के तहत हितधारकों के प्रशिक्षण के लक्ष्यों पर विचार नहीं किया जा रहा है।*

[26] *ओपन नेटवर्क हेतु डिजिटल कॉमर्स*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
		2.3 प्रशिक्षित होने वाले निदेशक मंडल (बीओडी)/सदस्यों की संख्या	4,000		ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाले एफपीओ की संख्या	
					1.5 बीज उत्पादन करने वाले एफपीओ की संख्या	400

7. कृषि अवसंरचना कोष (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
910	1. कृषि अवसंरचना के निर्माण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना	1.1 पूर्ण परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई निधि का %	55	1. कृषि अवसंरचना के लिए संसाधन प्रावधान में सुधार	1.1 कृषि अवसंरचना कोष हस्तक्षेप के कारण प्राप्त अतिरिक्त निवेश (करोड़ रु.)	30,000
		1.2 वित्त पोषित अवसंरचना कार्यकलापों के कारण कृषि क्षेत्र में कुल भंडारण क्षमता में वृद्धि (एलएमटी में)	1,000[27]			
	2. उपलब्ध कराए गए अनुदान और क्रेडिटगारंटी सहायता की धनराशि में वृद्धि	2.1 क्रेडिट गारंटी कवरेज पर व्यय धनराशि (रु. करोड़ में)	290	2. रोजगार के अवसरों का सृजन।	2.1 अवसंरचना निर्माण के माध्यम से सृजित कुल ग्रामीण रोजगार (लाख)	18
		2.2 योजना के अंतर्गत कुल ऋण विस्तार के क्रेडिट गारंटी कवरेज का औसत (%)	35			

[27] *वित्तीय वर्ष के अंत तक संचयी*

8. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम योजना (पीएम-आशा) (सीएस)[28]

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
7,200	1. संकट की स्थिति में आवश्यकता आधारित खरीद हस्तक्षेप (पीएसएस)	1.1 तिलहन की खरीद (लाख मीट्रिक टन में)	24.49	1. किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना	1.1 एमएसपी/खरीद मूल्य और बाजार मूल्य (5-10) के बीच औसत मूल्य अंतर	10
		1.2 दालहन की खरीद (लाख मीट्रिक टन में)	33.58			
		1.3 पीएसएस के अंतर्गत किसानों की उपज प्राप्त होने के बाद भुगतान में लगने वाला औसत विलंब (दिनों में)	3			
	2. किसानों के कवरेज में वृद्धि (पीडीपीएस)	2.1 भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) के अंतर्गत किसानों का पंजीकरण (%)	100	2. किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना	2.1 पीडीपीएस के अंतर्गत कवर की गई मंजूरी का %	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
		2.2 पीडीपीएस के अंतर्गत किसानों को उनकी उपज की प्राप्ति के बाद किए गए भुगतान में औसत विलंब (दिनों में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[29]			
	3. किसानों की कवरेज में वृद्धि	3.1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	7-10	3. किसानों को उनकी उपज के लिए बाजार	3.1. खरीदे गए सामान का 3 दिनों के भीतर समय पर भुगतान	100

[28] *पीएसएस के तहत, सरकार ने दलहन, तिलहन और खोपरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों अर्थात नेफेड और एनसीसीएफ को नकद क्रेडिट सुविधा प्रदान करने हेतु 50,000 करोड़ रुपये की सरकार की गारंटी दी है। केंद्रीय नोडल एजेंसियां किसानों को एमएसपी मूल्य का भुगतान करने और पीएसएस प्रचालनों में शामिल अन्य आकस्मिक व्ययों के लिए सरकार की गारंटी के तहत आवश्यक धनराशि वापस लेती हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास किसी विशेष तिलहन फसल के लिए संपूर्ण राज्य में किसी खरीद सत्र में पीएसएस या पीडीपीएस में से किसी एक को चयनित करने का विकल्प होता है। एमआईएस के तहत, संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश राज्य द्वारा नामित एजेंसियों को किसानों को भुगतान करने और प्रचालन में शामिल अन्य आकस्मिक व्ययों के लिए पूंजीगत निधि उपलब्ध कराती है। बजट निधि का प्रावधान ऐसे कार्यों में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए होता है। सांकेतिक बजट अनुमान योजनाओं की विगत वर्षों की मांग पर आधारित हैं और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार संशोधित किए जाते हैं।नोट: उपरोक्त योजना के तहत खरीद पूरी तरह से बाजार परिदृश्य और राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों के निर्णय पर निर्भर करती है। अतः, खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा का अनुमान लगाना बहुत कठिन है।*

[29] *कोई विलंब नहीं/यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	(एमआईएस)	3.2. वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान खरीदे गए उत्पाद की कुल मात्रा (लाख मीट्रिक टन)	25[30]	मूल्य और समय पर भुगतान होने पर बाजार हस्तक्षेप का प्रभाव।	किए जाने का %	

9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27.[31]	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
750	1. रसायन मुक्त, प्राकृतिक खेती के अंतर्गत शामिल क्षेत्र।	1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान रसायन मुक्त, प्राकृतिक कृषि क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि। (लाख हेक्टेयर में)[32]	6.5	1. देश में 1 करोड़ किसानों के मध्य प्राकृतिक कृषि	1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि। (लाख)	16.25

[30] *राज्य उत्पादन का 25% तक*

[31] *2026-27 का लक्ष्य अनंतिम आंकड़ा है जो वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए एनएमएनएफ योजना के अनुमोदन के अधीन है।*

[32] *वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ) के मसौदा ईएफसी का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 65,000 क्लस्टर (प्रत्येक 50 हेक्टेयर) बनाकर 32.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ) के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के मसौदा ईएफसी को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27[31]	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	2. 1 करोड़ किसानों को सक्षम बनाने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को प्रशिक्षित किया गया है।	2.1 वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षित (सीआरपी) सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की संख्या	26,000	जागरुकता में वृद्धि	1.2 पीजीएस[33]-इंडिया नेचुरल प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि% (लाख हेक्टेयर)	5
	3. प्राकृतिक कृषि इनपुट की सुगम उपलब्धता के लिए बायो-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी)।	3.1 वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित बायो-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) की संख्या	5,000			
	4. प्रदर्शन फार्म का सृजन।	4.1 वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित प्रदर्शन फार्मों की संख्या	2,858			

10. नमो ड्रोन दीदी (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
676.85	1. महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को सतत व्यवसाय और आजीविका सहायता प्रदान करना।	1.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान महिला एसएचजी को आपूर्ति किए गए ड्रोनों की संख्या।	3,000	1. ड्रोन के उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना।	1.1 इस योजना के अंतर्गत एक निश्चित समयावधि के भीतर ड्रोन उड़ाने के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षित और प्रमाणित महिलाओं की संख्या (2000-2500)।	2,500
		1.2 वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या।	3,000			

[33] *भागीदारी गारंटी प्रणाली*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		1.3 वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान ड्रोन सहायक के रूप में प्रशिक्षित एसएचजी सदस्यों/पारिवारिक सदस्यों की संख्या।	3,000		1.2 प्रशिक्षण के बाद ड्रोन का उपयोग करके आय अर्जित करने वाली महिला की संख्या(2000-2500)।	2,500
	2. नैनो उर्वरकों का प्रयोग	2.1 वित्तीय वर्ष के दौरान नैनो उर्वरकों के अंतर्गत शामिल कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)।	45,000		1.3 वित्तीय वर्ष के दौरान ड्रोन एप्लीकेशनों के अंतर्गत फसल क्षेत्र में वृद्धि -(हेक्टेयर में)	45,000

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

1. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
969.50	1. नॉलेज/विकसित प्रौद्योगिकी उत्पाद	1.1 केंद्रीय किस्म रिलीज समिति द्वारा जारी की जाने वाली किस्मों की संख्या	160	1. बाधाओं का निराकरण	1.1 5 वर्षों में औसत की तुलना में मुख्य फील्ड फसलों के उत्पादकता में वृद्धि (%)	0.65
		1.2 विकसित प्रलेखित बेहतर कृषि प्रणालियों / (जीएवी) की संख्या	110			
		1.3 पंजीकृत गुण विशिष्ट जननद्रव्य की संख्या	75	2. व्यवसाय मानदंडों का रूपांतरण	2.1 वर्ष के दौरान प्रजनक बीज श्रृंखला में प्रविष्ट की गई नई किस्मों की संख्या	150
		1.4 (तीव्र नैदानिक टूल्स/कार्यप्रणाली/कार्यविधियां/कीट-परोपजीवों और रोगों के लिए डिचिटल पूर्व चेतावनी प्रणाली/मानक/प्रोटोकॉल/संरचना/सॉफ्टवेयर की संख्या	10		2.2 प्रौद्योगिकी/टूल्स/प्रक्रियाएं/संरचनाएं/व्यवसायीकृत/लाइसेंस्ड/किसानों, कॉपरेटिव को को सफलतापूर्वक हस्तांतरण/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की संख्या	30
					2.3 उत्पादित प्रजनक बीज (क्वि. में)	85,000
	2. ज्ञान प्रसार और क्षमता निर्माण	2.1 प्रशिक्षित किसानों की संख्या	11,000	3. आउटकम गुणवत्ता	3.1 प्रदान किए गए/ पंजीकृत पेटेंट, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)/ भौगोलिक संकेत (जीआई)/ कॉपीराइट/ लाईसेंस की संख्या	60
		2.2 मूल्यवर्धन विकास और विस्तार कार्यकरण सहित अन्य हितधारकों की संख्या	1,000			
		2.3 उत्तीर्ण यूजी[34], पीजी[35] और पीएचडी[36] छात्रों की संख्या	600			

[34] *स्नातकीय*

[35] *पोस्ट ग्रेजुएशन*

[36] *डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		2.4 प्रभावकारक वाले अनुसंधान प्रकाशनों की संख्या	1,200		3.2 नियुक्त छात्र/ एग्री-उद्यमी/उच्च शिक्षा चुनने वाले छात्रों का %	95
		2.5 मैनुअल, पुस्तक/पुस्तक अध्याय और अन्य प्रकाशन जैसे नीतिगत कागजता/नीतिगत	800	4. नीति सहायता	4.1 नॉलेज उत्पाद /निविष्टियाँ / सरकारी नीतियों में शामिल मॉडल/सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों की कार्यप्रणालियां	50

2. सुदृढ़ीकरण, कृषि शिक्षा, प्रबंधन एवं सामाजिक विज्ञान (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
514.87	1. शिक्षण, लर्निंग सुदृढ़ीकरण/ विकसित	1.1 विकसित नीतिगत कागजात/ट्रेनिंग मॉड्यूल्स/सॉफ्टवेयर/मेथडोलॉजी की संख्या	8	1. कृषि शिक्षा के माहौल को बढ़ावा देना	1.1. प्रति वर्ष आईसीएआर फेलोशिप (एसआरएफ[37]/जेआरएफ[38]/आईसीएआर पीजी[39]/एनटीएस[40] इत्यादि) के लिए योग्य स्टूडेंट्स	7,000

[37] *वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता*

[38] *कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता*

[39] *भारतीय कृषि अनुसंधान स्नातकोत्तर परिषद*

[40] *राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	ज्ञान उत्पाद	1.2 डिजिटल रिसोर्स (ई-कोर्स/ एमओओसी[41] /बनाए गए या अपडेट किए गए वीडियो) की संख्या	6		1.2. एयू[42] में कैंपस के ज़रिए नौकरी पाने वाले/उच्च शिक्षा के लिए चुने गए/प्लेस हुए छात्रों की संख्या	20,000
		1.3 कृषि विश्वविद्यालयों में कौशल विकास हेतु यूजी छात्रों की संख्या	22,000	2. बिज़नेस के नियमों/प्रोफेशनल एक्सीलेंस में बदलाव	2.1 छात्रों और इनक्यूबेटर्स द्वारा स्टार्ट-अप्स की संख्या	65
		1.4 कृषि विश्वविद्यालयों में कौशल विकास हेतु यूजी छात्राओं की संख्या	11,100		2.2 एमओओसी / वोकेशनल कोर्स में प्रतिभागियों की संख्या	4,000
		1.5 स्कॉलरशिप/फेलोशिप (जेआरएफ/पीजीएस/एनटीएस) प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	23,000		2.3 कृषि विश्वविद्यालय/इंडस्ट्री के साथ सहयोग/ समझौता-ज्ञापन (एमओयू) की संख्या	8
	2. ज्ञान प्रसार एवं क्षमता निर्माण बुनियादी सुविधा सृजन	2.1 आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	200	3. आउटकम गुणवत्ता	3.1 प्रदान किए गए अथवा पंजीकृत किए गए पेटेंट, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर))/ भौगोलिक संकेतक (जीआई)/ कॉपीराइट लाइसेंस की संख्या	2
		2.2 एडवांस्ड टेक्नीक/मैनेजमेंट पर इन-हाउस प्रशिक्षिण हितधारकों (फैकल्टी, किसान, इंडस्ट्री, छात्रों) की संख्या	9,000	4. नीति समर्थन	4.1 सरकारी नीतियों/सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र की रणनीतियों में शामिल ज्ञान उत्पाद/इनपुट/मॉडल	4
		2.3 स्टूडेंट/फैकल्टी के लिए सुविधाएं तैयार करना (स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, एग्जामिनेशन हॉल, इत्यादि) (संख्या में)	150			
		2.4 शोध पत्र मैनुअल, पुस्तक/ पुस्तक अध्याय और दूसरे प्रकाशनों की संख्या।	90			

[41] *बड़े पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम*

[42] कृषि विश्वविद्यालयों

1. राष्ट्रीय आयुष मिशन[43] (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
1,300	1. आयुष सेवाओं का प्रावधान	1.1 आयुष बुनियादी ढांचे के उन्नयन/नए बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त आयुष सुविधाओं की संख्या[44]	5,100	1. आयुष स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत हुई	1.1 पिछले वर्ष की तुलना में आयुष सुविधाओं में आयुष सेवाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की वृद्धि का %	3
		1.2 आयुष दवाओं/औषधियों की आपूर्ति के लिए सहायता प्राप्त आयुष इकाइयों की संख्या	27,600			
		1.3 ऑस्टियोआर्थराइटिस और अन्य मस्कुलोस्केलेटल विकारों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत नामांकित लाभार्थियों की संख्या	5,50,000		1.2 पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत आयुष उपचार से दर्द, चलने-फिरने की दूरी आदि के संबंध में जीवन की गुणवत्ता में सुधार पाने वाले रोगियों की संख्या।	3,00,000

[43] नोट: क. एनएएम योजना का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है और तदनुसार, आउटपुट और आउटकम के अनुमानित लक्ष्य राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के पिछले वर्षों के रुझानों के साथ-साथ विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रदर्शन पर आधारित हैं। ख. चूंकि योजना का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए लाभार्थियों की प्रतिशतता के आंकड़ों में वृद्धि एसएएपी के विभिन्न अनुमोदित कार्यकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन की उनकी प्रगति पर निर्भर करती

[44] नोट: आयुष सुविधाओं में आयुष अस्पताल, आयुष औषधालय, आयुष्मान आरोग्य मंदिर-आयुष, एकीकृत आयुष अस्पताल, आयुष शैक्षणिक संस्थान (यूजी एंड पीजी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) की सह-स्थापित इकाइयां शामिल हैं

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		1.4 राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय-वाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के साथ आयुष के एकीकरण के अंतर्गत एनसीडी के लिए जांच/नामांकित लाभाथयों की संख्या	8,00,000		1.3 राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय-वाहिका रोग और आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के साथ आयुष के एकीकरण के अंतर्गत आयुष जीवन शैली संबंधी सलाह, योग, ध्यान और आयुष दवाओं के माध्यम से लाभान्वित एनसीडी रोगियों की संख्या	2,50,000
		1.5 आयुर्वेद (स्कूली बच्चों के लिए आयुष के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली) के तहत कवर किए गए स्कूलों की संख्या	1,000		1.4 उन छात्रों की संख्या जिन्हें आयुष पद्धतियों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली के लिए संवेदनशील बनाया गया और आयुर्विद्या (स्कूली बच्चों के लिए आयुष के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली) के तहत सामान्य औषधीय पौधों के बारे में जागरूक बनाया गया	3,00,000
		1.6 सुप्रजा, वयोमित्र, आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट, कारुण्य और लिम्फेटिक फाइलेरिया (लिम्फोएडेमा) के रुग्णता प्रबंधन तथा विकलांगता निवारण हेतु आयुष संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमएमडीपी) के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की संख्या	14,00,000		1.5 सुप्रजा, वयोमित्र, आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट, कारुण्य और लिम्फेटिक फाइलेरिया (लिम्फोएडेमा) के रुग्णता प्रबंधन तथा विकलांगता निवारण हेतु आयुष संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमएमडीपी) के अंतर्गत लाभान्वित लोगों की संख्या	4,00,000

उर्वरक विभाग

1. यूरिया राजसहायता (सीएस)

वित्तीय परिव्यय। (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
1,16,805	1. यूरिया का संवर्धित घरेलू उत्पादन	1.1. यूरिया का कुल घरेलू उत्पादन (एलएमटी[45] में)	296	1. यूरिया की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता	1.1. यूरिया की कुल बिक्री (एलएमटी में)	392
		1.2. यूरिया के आयात में कमी ('एलएमटी')	2		1.2. यूरिया की उपलब्धता (एलएमटी में)	422
					1.3. नैनो यूरिया की कुल बिक्री (प्रत्येक 500 मिलीलीटर की लाख बोतलों में)	248

2. पोषकतत्व आधारित राजसहायता (सीएस)

वित्तीय परिव्यय। (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
54,000	1. पीएण्डके उर्वरकों[46] का संवर्धित घरेलू उत्पादन	1.1. पीएण्डके उर्वरकों का कुल घरेलू उत्पादन (एलएमटी में)	236	2. पीएण्डके उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता	1.1. पीएण्डके उर्वरकों की कुल बिक्री (एलएमटी में)	330
		1.2. पीएण्डके उर्वरकों के आयात में कमी ('एलएमटी' में)	10		1.2. पीएण्डके उर्वरकों की उपलब्धता (एलएमटी में)	412
					1.3. नैनो डीएपी[47] की कुल बिक्री (प्रत्येक 500 मिलीलीटर की लाख बोतलों में)	164

[45] *लाख मीट्रिक टन*

[46] *फॉस्फेटिक और पोटासिक*

[47] *डी अमोनियम फॉस्फेट*

औषध विभाग

1. उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाएँ (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
2,499.84	**क. बल्क औषधि के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना**					
	1. बल्क औषधि के विनिर्माण के लिए क्षमता वृद्धि	1.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए क्षमता वृद्धि लक्ष्य (एमटी/वर्ष में)	500	1. अनुमोदित महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआईएस) और सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) के उत्पादन / बिक्री में वृद्धि	1.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआईएस) और सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) का उत्पादन (करोड़ ₹ में)	1,250
	ख. चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना					
	1. नई चिकित्सा उपकरण परियोजनाओं की शुरूआत	1.1 चिकित्सा उपकरण विनिर्माण के लिए पीएलआई के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या	3	1. पीएलआई योजना के तहत चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण में वार्षिक वृद्धि।	1.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के तहत की गई स्वीकृत उत्पादों की कुल बिक्री (करोड़ ₹ में)	4,000
	ग. औषध के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना					
	1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रतिबद्ध निवेश	1.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रुपये में)	3,455	1. वित्तीय वर्ष 2026-27 में औषध का उत्पादन	1.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 में औषध का उत्पादन (करोड़ ₹ में)	1,08,224

2. औषध उद्योग के विकास के लिए योजना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
967.84	**क. औषध एवं चिकित्सा उपकरण संवर्धन विकास योजना (पीएमपीडीएस)**					
	1. औषध उद्योग के विकास से संबंधित सम्मेलनों/सेमिनारों/ कार्यशालाओं का आयोजन	1.1 आयोजित सम्मेलनों/सेमिनारों और कार्यशालाओं की संख्या	20	1. औषध उद्योग की जागरूकता और संवेदनशीलता में वृद्धि करना	1.1 आयोजित सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाओं में प्रतिभागियों की संख्या	2,000
	2. पीएमपीडीएस योजना के अंतर्गत औषध उद्योग पर अध्ययन आयोजित करना	2.1 किए गए अध्ययनों की संख्या	5	2. औषध उद्योगों पर पूरी हुई अध्ययन रिपोर्टें	2.1 पूर्ण किए गए अध्ययनों और अंतिम रूप दी गई रिपोर्टों की संख्या	5
	ख. पुनर्निर्मित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (आरपीटीयूएएस)					
	1. प्रौद्योगिकी का उन्नयन	1.1 संशोधित अनुसूची एम / डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानकों के अनुपालन के लिए समर्थित एमएसएमई इकाइयों की संख्या	40	1. औषध उद्योग की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना	1.1 योजना के तहत रुचि व्यक्त करने वाली और पंजीकृत कुल इकाइयों में संशोधित अनुसूची एम/डब्ल्यूएचओ-जीएमपी अनुपालन करने वाली एमएसएमई इकाइयों का %	60
					1.2 पिछले वर्ष की तुलना में संशोधित अनुसूची एम/डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानक का अनुपालन करने वाली दवा निर्माण इकाइयों में % वृद्धि	125
	ग. सामान्य सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)					
	1. औषध क्लस्टरों में साझे सुविधा केंद्र (सीएफसी) का निर्माण	1.1 वित्त वर्ष 2026-27 में स्वीकृत सीएफसी की संख्या	2	1. मौजूदा औषध क्लस्टरों की क्षमता का सुदृढ़ीकरण	1.1 सीएफसी सेवाओं का लाभ उठाने वाली क्लस्टर में इकाइयों का %	90
		1.2 वर्ष 2025-26 में स्वीकृत	100		1.2 सीएफसी से लाभान्वित एमएसएमई	1,700

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		परियोजनाओं के लिए सीएफसी स्थापना में प्रगति (पूर्ण हुए कार्य का %)			इकाइयों की संख्या	
	घ. बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन की योजना					
	1. बल्क औषधि पार्कों में सीआईएफ के विकास के लिए जारी केंद्रीय अनुदान सहायता की राशि	1.1 बल्क औषधि पार्कों में सीआईएफ के विकास के लिए उपयोग की गई निधि (संचयी % में)	100	1. बल्क औषधि पार्कों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण	1.1 बल्क औषधि पार्क में सीआईएफ के विकास के लिए पूर्ण किये गये कार्य का संचयी %	100

3. फार्मा-मेड टेक में अनुसंधान और नवाचार का संवर्धन (पीआरआईपी) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
750	1. नाईपर[48] में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना	1.1 सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	60	1. घटक-क - संबंधित क्षेत्रों में सीओई के माध्यम से अनुसंधान अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और नवाचार का विकास करना	1.1 उत्कृष्टता केंद्र के संबंधित क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों/साझेदारी/समझौतों की संख्या	35
		1.2 सीओई की स्थापना के लिए नाईपर को निधि जारी करना (करोड़ रुपये में)	150		1.2 सीओई द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के संबंधित क्षेत्रों में दायर पेटेंटों की संख्या	15

[48] *राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	2. घटक-ख के अंतर्गत कंपनियों/स्टार्ट-अप्स का चयन	2.1 वित्तीय सहायता से प्राप्त आरएण्डडी[49] परियोजनाओं की संख्या	100	2. घटक-ख - फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन	2.1 उच्चतर टीआरएल[50] तक पहुँचने वाली पीआरआईपी समर्थित प्रौद्योगिकियों की संख्या	40
		2.2 वित्तीय सहायता से समर्थित स्टार्टअप/एमएसएमई[51] परियोजनाओं की संख्या	60		2.2 रणनीतिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों/उत्पादों की संख्या	20
		2.3 रणनीतिक प्राथमिकता वाले नवाचार क्षेत्रों (जैसे, दुर्लभ रोग, एएमआर[52], टीके) में वित्तीय सहायता प्राप्त अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या	15			

[49] *अनुसंधान और विकास*

[50] *प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल)*

[51] *सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम*

[52] *रोगाणुरोधी प्रतिरोध*

नागर विमानन मंत्रालय

1. क्षेत्रीय सम्पर्क स्कीम-संशोधित उड़ान (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
550	1. हवाईअड्डा अवसंरचना: योजना के तहत अवॉर्ड किए गए प्रस्तावों के आधार पर एएआई[53] और राज्यों द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित अवसंरचना का उन्नयन/ पुनरुद्धार	1.1 उन्नयन/ पुनरुद्धार किए जाने वाले आरसीएस हवाईअड्डे/ हेलीपैड/ वॉटर ड्रोन (संख्या में)	17	1. बेहतर क्षेत्रीय हवाई संपर्क	1.1 आरसीएस उड़ानों में यात्रा करने वाले यात्री (संख्या में)	20,00,000
		1.2 आरंभ किए जाने वाले आरसीएस मार्ग (संख्या में)	100			
	2. मार्गों के माध्यम से एयरोड्रोमों को जोड़कर आरसीएस हवाई संपर्क	2.1 प्रचालनरत किए गए आरसीएस हवाई अड्डे(संख्या में)	12	2. बेहतर क्षेत्रीय हवाई संपर्क	2.1 आरसीएस उड़ानों में यात्रा करने वाले यात्री (संख्या)	40,000
	3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए आरसीएस हवाई संपर्क	3.1 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचालनरत लिए जाने वाले मार्ग (संख्या)	16	3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बेहतर हवाई संपर्क	3.1 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यात्रा करने वाले यात्री (संख्या)	1,00,000
		3.2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जुड़े हुए हवाई अड्डे/ हेलीपोर्ट (संख्या)	4		3.2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जुड़े हुए गंतव्य (संख्या)	4

[53] *भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण*

1. कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
755	1. कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों में संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण	1.1 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के साथ ड्रिलिंग की लंबाई (लाख मीटर में) (24 फोल्ड सीडीपी के साथ लाइन किमी में)	1.75	1. नए संसाधन जोड़े जाने हैं	1.1 पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में नए संसाधनों को जोड़ना (बिलियन टन में)	1.50
		1.2 वर्ष के दौरान अन्वेषण किया गया क्षेत्र (वर्ग किमी में)	115			
		1.3 कोयले के क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए उपलब्ध 10,760 वर्ग किमी क्षेत्र में से अन्वेषित क्षेत्र (संचयी) (वर्ग किमी में)	741			
	2. गैर-सीआईएल[54] ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण	2.1 ड्रिल किए गए क्षेत्र की लंबाई (लाख मीटर में)	5.00	2. प्रमाणित श्रेणी में जोड़ा जाने वाला संसाधन	2.1 पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जोड़े गए प्रमाणित संसाधन (बिलियन टन में)	2.00
		2.2 वर्ष के दौरान अन्वेषण किया गया क्षेत्र (वर्ग किमी में)	125			
		2.3 कोयले के विस्तृत अन्वेषण के लिए उपलब्ध 5670 वर्ग किमी क्षेत्र में से अन्वेषित क्षेत्र (संचयी) (वर्ग किमी में)	856			

[54] *कोल इंडिया लिमिटेड*

2. कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण के संवर्धन हेतु योजना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
3,525	1. भारत में कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देना	1.1 चिन्हित गैसीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास (संख्या में)	2	1. कोयला गैसीकरण परियोजनाओं की स्थापना	1.1 वित्तीय प्रोत्साहन की पहली किस्त का वितरण (परियोजनाओं की संख्या)	3
		1.2 वित्तीय समापन की उपलब्धि	3			

वाणिज्य विभाग

1. निर्यात संवर्धन मिशन (सीएस)[55]

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
2,300	1. निर्यात प्रोत्साहन	1.1 प्रत्येक निर्यात संबंधित मिशन सहायता हस्तक्षेप के तहत प्राप्त व्यापार वित्त का मूल्य (करोड़ रूपये में)	1,440	1. निर्यात प्रोत्साहन	1.1 निर्यात प्रोत्साहन के तहत समर्थित निर्यातकों की संख्या	1,440
	2. निर्यात दिशा	2.1 समर्थित गैर- टैरिफ उपायों को दूर करने के लिए संख्या	2,270[56]	2. निर्यात दिशा	2.1 निर्यात दिशा के तहत समर्थित निर्यातकों की संख्या	2,270
		2.2 समर्थित भंडारण अवसंरचना की संख्या।				
		2.3 समर्थित ब्रांडिंग अभियानों की संख्या				
		2.4 समर्थित व्यापार आसूचना पहलों की संख्या				
		2.5 समर्थित बाज़ार पहुँच पहलों की संख्या				

[55] *बाजार पहुँच पहल और ब्याज समतुलयकरण योजना को इस नई योजना "निर्यात संवर्धन मिशन" में मिला दिया गया है।*

[56]

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

1. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
3,000	1. औद्योगिक कॉरिडोर नोड्स में मुख्य अवसंरचना पैकेजों को पूरा करना और 11 औद्योगिक कॉरिडोरों के तहत नई परियोजनाओं के लिए मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य शुरू करना तथा उसे स्वीकृति प्रदान करना।	1.1 आंकलित परियोजनाओं की संख्या (एनआईसीडीआईटी)	1[57]	1. क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं के विकास से ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे और इससे क्षेत्र के भावी विकास को और प्रोत्साहन मिलेगा।	1.1 सृजित रोजगारों की संख्या (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)	10,000
		1.2 औद्योगिक इकाइयों को भूखंडों के रूप में आबंटित भूमि की संख्या, एकड़ में	400[58]		1.2 भूमि के आबंटन द्वारा प्राप्त कुल निवेश क्षमता (करोड़ रुपए में)	2,000

2. स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,200	1. स्टार्टअप में निवेश के लिए वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ)	1.1 वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) द्वारा प्रतिवर्ष आहरण (करोड़ रुपए में)	1,200	1. एआईएफ के माध्यम से	1.1 एआईएफ के माध्यम से वित्तपोषित	160

[57] *केबीएनआईआर, राजस्थान*

[58] *एसबीआईए: 100 एकड़, डीएसआईआर: 200 एकड़, आईआईटीजीएनएल: 50 एकड़, कृष्णापट्टनम: 50 एकड़*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	को प्रदान की गई निधि।	1.2 स्टार्टअप को वित्तीय पहुंच का लाभ उठाने में मदद के लिए एआईएफ ईकोसिस्टम में स्थापित उद्यम निधियों की संख्या।	8[59]	स्टार्टअप को सहायता।	स्टार्टअप की संख्या।	

3. व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी लाइट्स) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,003.54	1. इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी	1.1 इस स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित इकाइयों की संख्या।	80[60]	1. निवेश से होने वाली बिक्री।	1.1 पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में वृद्धिशील बिक्री का %[61]	32
	2. संवितरित की गई प्रोत्साहन राशि	2.1 इस स्कीम के तहत संवितरित की गई प्रोत्साहन राशि (करोड़ रुपए में)।	1,000	2. रोजगार सृजन	2.1 इस स्कीम के माध्यम से सृजित रोजगारों की संख्या।	52,308
	3. संयंत्र एवं मशीनरी में किया गया निवेश	3.1 वर्ष 2026-27 में किए गए निवेश की राशि (करोड़ रुपए में)।	1,257			
	4. व्हाइट गुड्स का उत्पादन	4.1 पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी लाइट) के उत्पादन मे % वृद्धि[62]	32[63]			

[59] *स्कीम के अंतर्गत कॉर्पस की उपलब्धता के अध्यधीन।*

[60] *राउंड 4 में 10 नवंबर, 2025 तक आवेदन विंडो खुली होने से कुल आवेदकों की संख्या बढ़ने की संभावना है।*

[61] *(Rs. 25,467 करोड़)*

[62] *(Rs. 25,467 करोड़)*

[63] *अर्थात (33,743 करोड़ रुपए)*

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाईयों को केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी लौटाना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
724.21	1. सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित इकाइयों को बजटीय सहायता प्रदान करके उनकी सहायता करना।	1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत पात्र पाई गई नई इकाइयों की संख्या	4[64]	1. एक सद्भावना उपाय के रूप में इकाइयों के लिए बजटीय सहायता का प्रावधान करना, जो इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा और इन क्षेत्रों के निवेश विकास को बढ़ावा देगा।	1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत शामिल की गई तरलता राशि	724.20

[64] *वित्त वर्ष के दौरान नई इकाइयों के पंजीकरण के अध्यधीन*

डाक विभाग

1. आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
759	1. प्रत्येक कार्यालय को कम से कम दो भिन्न नेटवर्क प्रदाताओं से जोड़ने के लिए नेटवर्क की निरंतर उपलब्धता	1.1. ऐसे विभागीय डाकघरों की संख्या, जिनमें वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान नेटवर्क की निरंतरता बनाए रखने के लिए नेटवर्क हार्डवेयर को अपग्रेड किया गया।	20,000	1. डाकघरों में आम नागरिकों को निर्बाध काउंटर सेवाएं प्राप्त करने में सहूलियत	1.1. विभागीय डाकघरों में नेटवर्क की निरंतर उपलब्धता की माहवार प्रतिशतता (% में)	98
	2. नवीनतम प्रौद्योगिकियों के माध्यम से डाक सेवाओं का उन्नयन	2.1 ऐसे डाकघरों की संख्या, जिनमें वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवीनतम प्रौद्योगिकियों जैसे डाक-वस्तुओं की रियल-टाइम ट्रैकिंग, सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग की मदद से सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है।	1,00,000	2. ग्राहकों की सुविधा के लिए डाक संबंधी लेन-देन के डिजिटलीकरण में वृद्धि	2.1 डाक विभाग में विगत वित्त वर्ष में संदर्भित सीबीएस.[65] आईएसएस और आर्टिकल की बुकिंग सहित डाक विभाग में किए गए डिजिटल लेन-देन की संख्या में वृद्धि % आईएमएस (एन्श्योरेंस) (% में)	20
				3. काउंटर पर खुदरा ग्राहकों द्वारा डिजिटल भुगतान में वृद्धि	3.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 में काउंटरों पर खुदरा ग्राहकों द्वारा डिजिटल लेन-देन बनाम नकद भुगतान की प्रतिशतता (% में)	20

[65] *सीबीएस : कोर बैंकिंग सॉल्यूशन; आईएमएस: बीमा प्रबंधन निवारण; डीओपी: डाक विभाग*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	3. सभी डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) स्कीमों के लिए ई-केवाईसी समाधान लागू करना	3.1. ऐसे डाकघरों की संख्या जिनमें वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान ई-केवाईसी समाधान लागू किया गया।	65,000	4. इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रणाली के फलस्वरूप सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं तथा बेहतर ग्राहक संतुष्टि	4.1 वित्त वर्ष 2026-27 में किए गए ई-केवाईसी आधारित लेन-देन की प्रतिशतता (% में)	85
		3.2. वित्त वर्ष 2026-27 में ई-केवाईसी के माध्यम से खोले गए पीओएसबी खातों की संख्या (करोड़ में)	1	5. आम नागरिकों को ई-केवाईसी के माध्यम से पीओएसबी खाते खोलने में सहूलियत	5.1 विगत वर्ष की तुलना में पीओएसबी खाता खोलने में लगने वाले औसत समय में कमी (% में)	50

दूरसंचार विभाग

1. घरेलू उद्योग प्रोत्साहन योजना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
वित्तीय वर्ष 2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
1,989.72	**क. डीआईआईएस- दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना**					
	1. घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लक्षित खंडों में निवेश को आकर्षित करना।	1.1 कुल अनुमोदित कंपनियों (संख्या) में से वार्षिक (पीएलआई) प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली कंपनियां (संख्या)	20[66]	1. घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना	1.1 पिछले वर्ष के संदर्भ में पात्र दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों की बिक्री में परिवर्तन (% में)	14[67]
		1.2 निवेश (करोड़ में)	0[68]	2. भारत में निर्मित दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए भारत को विनिर्माण केंद्र बनाना	2.1 पिछले वर्ष के संदर्भ में निर्यात के मूल्य में परिवर्तन (% में)	10[69]
					2.2 निर्यात का मूल्य (करोड़ में)	18,551
		1.3 बिक्री का मूल्य (करोड़ में)	59,777	3. रोजगार सृजित करना	3.1 अतिरिक्त रोजगार सृजन (संख्या में)	4,172
	ख. डीआईआईएस- प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन (टीडीआईपी) निधि					
	1. वैश्विक मानक सेटिंग	1.1 भारत में आयोजित	16	1. भारतीय आवश्यकताओं	1.1 प्रासंगिक तकनीकी दस्तावेजों	4,700

[66] योजना के तहत कुल अनुमोदित लाभार्थी कंपनियां 42 थीं, जिनमें से 5 कंपनियों की योजना अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक थी। शेष 37 कंपनियों के लिए, योजना अवधि वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 है। हालांकि, पिछले 3 वर्षों में, कुल 42 में से केवल 23 अलग-अलग कंपनियां दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन का दावा करने में सक्षम रही हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के प्रदर्शन के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में प्रोत्साहन संवितरण का लक्ष्य लिया गया है।

[67] वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिक्री और निर्यात लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में कम है; इसलिए नकारात्मक वृद्धि हुई।

[68] योजना के तहत निवेश की अवधि 31.03.2026 तक है; इसलिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निवेश लक्ष्य शून्य है।

[69] वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिक्री और निर्यात लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में कम है; इसलिए नकारात्मक वृद्धि हुई।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
वित्तीय वर्ष 2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	निकायों में भारतीय दूरसंचार मानक विकास सोसायटी (टीएसडीएसआई) का योगदान	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानक बैठकें (संख्या)		के साथ दूरसंचार मानकों का विकास	(कार्य मद प्रस्ताव, अध्ययन मद प्रस्ताव, परिवर्तन अनुरोध आदि) द्वारा प्रमाणित वैश्विक मानकों में संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया भारत का योगदान	
		1.2 वैश्विक मानक-सेटिंग निकायों में भारतीय प्रतिभागी (संख्या)।	1,900			

2. टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और विस्तार के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
वित्तीय वर्ष 2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
24,000	**क. भारतनेट परियोजना**					
	1. हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जुड़ीं ग्राम पंचायतें	1.1 हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जुड़ी ग्राम पंचायतें[70] (संख्या)	42,000	1. भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग की स्थिति	1.1 डार्क फाइबर का उपयोग (कुल किलोमीटर)	1,40,000
		1.2 ग्राम पंचायतें (जीपी) जो 'रिंग टोपोलॉजी'[71] में जुड़ी/अपग्रेड की गई हैं (संख्या)	28,000		1.2 तिमाही के दौरान डेटा खपत (टीबी में)	21,35,000
		1.3 बिछाई गई ओएफसी[72] (कुल मिलाकर किलोमीटर में)	1,60,000		1.3 एफटीटीएच कनेक्शन (कुल संख्या में)	20,50,000
	ख. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी)					

[70] 2025-26 के दौरान उपलब्धि का अनुमान यह है कि 10000 सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों को भारतनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

[71] 2025-26 के दौरान उपलब्धि का अनुमान यह है कि 10000 सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों को रिंग के ज़रिए भारतनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

[72] 2025-26 के दौरान उपलब्धि का अनुमान यह है कि 80000 किलोमीटर ओएफसी बिछाई गई है।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
वित्तीय वर्ष 2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	1. अरुणाचल प्रदेश में 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं का प्रावधान	1.1 वित्तीय वर्ष 26-27 में इस स्कीम के तहत मोबाइल टावर संस्थापित करने का प्लान है	54	1. अरुणाचल प्रदेश के सेवा से वंचित गांव में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी की उपलब्धता	1.1 वित्तीय वर्ष 26-27 में सेवा से वंचित उन गांवों की संख्या जिन्हें सेवा प्रदान की जानी है	101
	ग. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवाओं के लिए स्कीम (चरण-II)					
	1. वामपंथी प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान (चरण-II)	1.1 वित्तीय वर्ष 26-27 में इस स्कीम के तहत मोबाइल टावर संस्थापित करने का प्लान है	235	1. इन इलाकों में विशेष रूप से गृह मंत्रालय आदि की सिक्योरिटी एजेंसियों तक उन्नत तकनीक के साथ मोबाइल की पहुंच बढ़ाना।	1.1 वित्तीय वर्ष 26-27 में उन गांवों की संख्या जिन्हें सेवा प्रदान की जानी है	244
	घ. आकांक्षी जिला परियोजना (7287 आकांक्षी जिले परियोजना और 502 आकांक्षी जिले परियोजना)					
	1. आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवा का प्रावधान (7287 आकांक्षी जिले परियोजना और 502 आकांक्षी जिले परियोजना)	1.1 वित्तीय वर्ष 26-27 में इस स्कीम के तहत मोबाइल टावर संस्थापित करने का प्लान है	948	1. आकांक्षी जिलों में उन्नत तकनीक के साथ मोबाइल की पहुंच बढ़ाना	1.1 वित्तीय वर्ष 26-27 में उन गांवों की संख्या जिन्हें सेवा प्रदान की जानी है	1,232
	ड. 4जी सेचुरेशन परियोजना					
	1. 4जी सेचुरेशन योजना	1.1 वित्तीय वर्ष 26-27 में इस स्कीम के तहत मोबाइल टावर संस्थापित करने का प्लान है	2,578	1. सेवा से वंचित गांवों को मोबाइल सेवा प्रदान करना	1.1 वित्तीय वर्ष 26-27 में उन गांवों की संख्या जिन्हें सेवा प्रदान की जानी है	4,056

उपभोक्ता मामले विभाग

1. मूल्य स्थिरीकरण कोष (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
4,100.00	1. दालें: दालों की भारित औसत खुदरा कीमतों को स्थिर बनाए रखना।[73]	1.1. दालों के संयुक्त भारित औसत खुदरा मूल्यों में वर्ष-दर-वर्ष उतार-चढ़ाव[74] को मासिक वर्ष-दर-वर्ष भिन्नता के आधार पर एक निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखा जाएगा (%)	5.42-8.39	1. सीपीआई[75] में दालों और उत्पादों की महंगाई दर बनाए रखना	1.1. दालों और उत्पादों में सीपीआई मुद्रास्फीति को बरकरार रखा जाएगा (%)	4-6
	2. दालें: राज्यों में दालों की भारित औसत कीमतों के स्थानिक फैलाव को बनाए रखना।	2.1 राज्यों में दालों के राज्यवार संयुक्त भारित औसत खुदरा मूल्य में भिन्नता[76] का गुणांक विगत सीवी[77] के आधार पर निर्धारित लक्ष्य पर बनाए रखा जाएगा	0.222			
	3. दालें: दालों की मंडी कीमतों पर खुदरा बिक्री का औसत मूल्य मार्क-अप बनाए रखना।	3.1 संयुक्त भारित मॉडल मंडी मूल्यों[78] पर दालों के संयुक्त भारित औसत खुदरा मूल्यों का % मार्क-अप, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विगत स्तर के आधार पर निर्धारित लक्ष्य पर बनाए रखा जा रहा है (%)	37.15			

[73] *चना दाल, तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल और मसूर दाल के लिए संयुक्त भारित औसत खुदरा मूल्य की गणना सीपीआई भार का उपयोग करके की जाती है*

[74] *वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2025-26 तक*

[75] *सीपीआई: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक*

[76] *वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2025-26*

[77] *माध्य से विचलन*

[78] *(अर्थात खुदरा मूल्यों के प्रतिशत के रूप में खुदरा मूल्यों और मंडी मूल्यों के बीच अंतर)*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	4. प्याज: प्याज की औसत खुदरा कीमतों को स्थिर बनाए रखना।	4.1 प्याज की औसत खुदरा कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष उतार-चढ़ाव[79] को मासिक वर्ष-दर-वर्ष भिन्नता के आधार पर एक निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखा जाएगा। (%)[80]	7.21-46.81	2. सीपीआई में प्याज की महंगाई दर बनाए रखना	2.1 प्याज में सीपीआई मुद्रास्फीति बरकरार रखी जाएगी (%)	<16
	5. प्याज: राज्यों में प्याज की कीमतों का स्थानिक फैलाव बनाए रखना।	5.1 राज्यों में प्याज के राज्यवार औसत खुदरा मूल्य (वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2025-26 में भिन्नता के गुणांक को विगत सीवी[81] के आधार पर एक निर्धारित लक्ष्य पर बनाए रखा जाएगा	0.479			
	6. प्याज: प्याज की मंडी कीमतों पर खुदरा बिक्री का औसत मूल्य मार्क-अप बनाए रखना।	6.1 मंडी मॉडल कीमतों[82] पर प्याज के औसत खुदरा कीमतों का प्रतिशत मार्क-अप, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विगत स्तर के आधार पर निर्धारित लक्ष्य पर बनाए रखा जा रहा है (%)	48.18			
	7. मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्रों द्वारा दैनिक मूल्य रिपोर्टिंग में नियमितता बनाए रखना	7.1 दैनिक मूल्य डेटा रिपोर्ट करने वाले केंद्रों का %	95			

[79] *वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2025-26 तक*

[80] *तिमाही वार लक्ष्य के लिए, डेटा सेट की संगत तिमाहियों के अधिकतम और न्यूनतम वर्ष-दर-वर्ष मासिक प्रतिशत भिन्नताएं ली जाती हैं; और वार्षिक लक्ष्य सीमा के लिए त्रैमासिक भिन्नताओं के अधिकतम और न्यूनतम को लिया जाता है*

[81] *औसत से विचलन*

[82] *अर्थात खुदरा कीमतों के प्रतिशत के रूप में खुदरा कीमतों और मंडी कीमतों के बीच अंतर*

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
2,27,429	1. खाद्यान्नों की खरीद (एनएफएसए[83] के तहत वितरण और बफर स्टॉक के लिए)[84]	1.1 खरीद किए जाने वाले धान की मात्रा (एलएमटी[85])	775	1. किसानों को लाभ	1.1. धान की खरीद में लाभान्वित किसानों की संख्या (लाख में)	110
		1.2 खरीदे गए गेहूं की मात्रा (एलएमटी)	265		1.2. गेहूं की खरीद में लाभान्वित किसान (लाख में)	22
		1.3 खरीदे गए मोटे अनाज की मात्रा (एलएमटी)	10.54		1.3. मोटे अनाज की खरीद से लाभान्वित किसान (लाख में)	3.96
					1.4. धान की खरीद के लिए किसानों को भुगतान किया गया अनुमानित एमएसपी[86] मूल्य (लाख करोड़ रुपए में)	1.76
					1.5. गेहूं की खरीद के लिए किसानों को भुगतान किया गया अनुमानित एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ रुपए में)	0.59
					1.6. मोटे अनाज की खरीद के लिए किसानों को भुगतान किया गया अनुमानित एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ रुपए में)	39.41
	2. भंडारण सुविधा में	2.1 पीपीपी[87] मोड के तहत वैज्ञानिक ढंग से निर्मित स्टील	09	2. पात्र लाभार्थियों को निर्धारित	2.1 कुल लेन-देन में से अंतरा-राज्यीय पोर्टेबिलिटी लेन-देन (% में)	20

[83] *नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट*

[84] *लक्ष्य वार्षिक होंगे।*

[85] *लाख टन में*

[86] *मिनिमम सपोर्ट प्राइस*

[87] *पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	बृद्धि	साइलो भंडारण सुविधा (क्षमता लाख टन में)		मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति करना।	2.2 कुल लेन-देन में से अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी लेन-देन (% में)	0.4
					2.3 राशन कार्डों की अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी में वृद्धि % में)	0.1
	3. लक्षित लाभार्थियों को खाद्यान्न की कुशल और प्रभावी आपूर्ति।	3.1 राशन कार्डों के साथ आधार को जोड़ना (सीडिंग) (% में)	100	3. चावल और गेहूं की प्रति क्विंटल संचालन लागत का युक्तिकरण।	3.1 ओवरहेड लागत/ संचालन की मात्रा (रुपये प्रति क्विंटल)	151.56
		3.2 सभी एफपीएस[88] पर ई-पीओएस[89] की उपलब्धता (% में)	100		3.2 कुल सब्सिडी के **%** के रूप में ओवरहेड लागत **(%** में)	18.04
		3.3 लाभार्थी का जैव- प्रमाणीकरण (% में)	99.5			
		3.4 पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों का ई-केवाईसी (% में)	90			
	4. खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए एफसीआई[90] को एक कुशल, सक्षम और प्रभावी संगठन	4.1 सभी प्रमुख खरीद केंद्रों में स्वचालित अनाज विश्लेषक (एजीए) की स्थापना (संख्या में)	400	4. स्टॉक के खरीद, वितरण और रखरखाव हेतु	4.1 लाभान्वित होने वाले किसान और पीएमजीकेएवाई लाभार्थी (% में)	100
		4.2 वाहन स्थान ट्रैकिंग प्रणाली (वीएलटीएस) के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले वाहनों की संख्या (% में)	100			
		4.3 भांडागार इन्वेंट्री नेटवर्क और शासी प्रणाली से जुड़ी मिलें	100			

[88] *फेयर प्राइस शॉप*

[89] *इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल*

[90] *फ़ूड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	बनाना।	(विंग्स) (% में)				
	5. एफसीआई को खाद्य सब्सिडी	5.1 भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को जारी की जाने वाली, वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित संपूर्ण खाद्य सब्सिडी (करोड़ रुपये में)	1,35,000	5. पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को वितरण हेतु	5.1 लाभान्वित होने वाले किसान और पीएमजीकेएवाई लाभार्थी (% में)	100
	6. डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी	6.1 डीसीपी राज्यों को जारी की जाने वाली, वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित संपूर्ण खाद्य सब्सिडी (करोड़ रुपये में)	75,000			

2. एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता ((सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गत 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गत	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	परिणाम	लक्ष्य 2026-27
6,500	1. एफपीएस के द्वार तक अनाज की सुपुर्दगी	1.1 एफपीएस के द्वार तक पहुंचाए गए खाद्यान्न की मात्रा (लाख टन में)	550	1. उचित दर दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों का सुचारू वितरण सुनिश्चित करना	1.1 आवंटन की तुलना में उचित दर दुकानों के द्वार पर सुपुर्द की गई खाद्यान्न की मात्रा (% में)	100
	2. लाभार्थियों की बेहतर कवरेज सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्नों की प्रामाणिक सुपुर्दगी	2.1 आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से वितरित खाद्यान्न की मात्रा (% में)	100	2. लीकेज को कम करना और यह सुनिश्चित करना कि खाद्यान्न लक्षित आबादी तक पहुंचे	2.1 आधार-प्रमाणित लेनदेन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का %	100

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गत 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गत	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	परिणाम	लक्ष्य 2026-27
	3. ई-पीओएस उपकरण का इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू के साथ एकीकरण	3.1 इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू के साथ एकीकृत ई-पीओएस उपकरण वाले राज्यों की संख्या	23	3. लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता	3.1 पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न की पात्र मात्रा का वितरण सुनिश्चित करना (% में)	100
	4. लाभार्थियों की बेहतर कवरेज सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्नों की प्रामाणिक सुपुर्दगी।	4.1 इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू से युक्त ई-पीओएस उपकरण की संख्या	100	4. यह सुनिश्चित करना कि अनाज लक्षित आबादी तक उनकी पात्रता के अनुसार पहुंचे और लीकेज को कम किया जा सके।	4.1 इलेक्ट्रॉनिक तौल ब्रिज के साथ एकीकृत ई-पीओएस उपकरण का %	100

3. इथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्कीम (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गत 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गत	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
600	1. वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित की गई धनराशि	1.1 उपयोग की गई धनराशि का %	100	1. देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना	1.1. शीरा और अनाज आधारित डिस्टिलरियों से अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन क्षमता (करोड़ लीटर में)	200
		1.2 जारी की गई सहायता राशि (करोड़ रुपये में)	1,000			
	2. इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि	2.1 आपूर्ति किया गया इथेनॉल (करोड़ लीटर में)	1,100	2. पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्यों को प्राप्त करना	2.1 पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण का प्राप्त %	20[91]

[91] *20% का मिश्रण लक्ष्य पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संचयी लक्ष्य है।*

1. न्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
4,788.45	1. इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए उद्योग को शामिल करना	1.1. पोर्टल पर पंजीकृत पात्र कंपनियों की संख्या	750	1. उद्योग की भागीदारी में वृद्धि	1.1 इंटर्नशिप पोस्ट करने वाली कंपनियों की प्रतिशतता में वृद्धि	50
	2. पात्र युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर की सुविधा प्रदान करना	2.1 पोर्टल पर पोस्ट किए गए इंटर्नशिप अवसरों की संख्या	73,333	2. पीएमआईएस पोर्टल पर पोस्ट किए गए इंटर्नशिप के अवसरों में वृद्धि	2.1. पीएमआईएस पोर्टल पर इंटर्नशिप के अवसरों की संख्या की प्रतिशतता में वृद्धि	50
		2.2 संवितरित मासिक डीबीटी[92] सहायता की संख्या	73,333		2.2. सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरी करने वाले इंटर्न का प्रतिशत	100

[92] *प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण*

1. प्रधान मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डिवाइन) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
2,306	1. सामाजिक विकास, आजीविका और अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से अवसंरचना का निर्माण	1.1 स्वीकृत सामाजिक विकास परियोजनाओं की संख्या	4	1. पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीव्र और समग्र विकास	1.1 सामाजिक विकास परियोजनाओं की संख्याजो चालू हो गई हैं	4
		1.2 12 महीनों के भीतर पूरी हुई सामाजिक विकास परियोजनाओं की संख्या	4		1.2 सामाजिक विकास स्कीम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	3,000
		1.3 स्वीकृत आजीविका परियोजनाओं की संख्या	2		1.3 आजीविका परियोजनाओं की संख्याजो चालू हो गई हैं	1
		1.4 12 महीनों के भीतर पूरी हुई आजीविका परियोजनाओं की संख्या	1		1.4 आजीविका स्कीम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	500
		1.5 स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	4		1.5 अवसंरचना स्कीम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	2,500
		1.6 12 महीनों के भीतर पूरी हुई अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	3		1.6 अवसंरचना परियोजनाओं की संख्याजो चालू हो गई हैं	3

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपयेमें)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
2,500	**क. सड़कें**					
	1. जुड़े हुए गाँव/बस्तियाँ,	1.1 निर्मित सड़कों की लंबाई	266.66	1. सड़क नेटवर्क में	1.1 निर्मित सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या	225

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपयेमें)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	जैसा कि आउटपुट में बताया गया है	(किमी)		सुधार	1.2 सड़कों के निर्माण से लाभान्वित लोगों की संख्या	8,52,114
	I. सड़क अवसंरचना के अलावा अन्य					
	1. विद्युत अवसंरचना	1.1 निर्मित/अपग्रेड किए गए सब-स्टेशनों की संख्या	2	1. बिजली की उपलब्धता में सुधार	1.1 ऐसे घरों की संख्या जहां 24x7 बिजली रहती है	8,97,665
	2. प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य क्षेत्र अवसंरचना	2.1 अस्पताल भवनों/स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण/उन्नयन की पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	5	2. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार	2.1 चालू की गई स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	5
					2.2 प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	13,61,094
					2.3 ऐसे जिला अस्पतालों की संख्या जिनमें प्रति एक लाख आबादी पर कम से कम 22 बेड हैं	5
	3. माध्यमिक शिक्षा अवसंरचना	3.1 निर्मित/अपग्रेड किए गए स्कूलों की संख्या	1,430	3. शिक्षा तक पहुंच में सुधार	3. 1 निर्मित/अपग्रेड की गई प्रत्येक अवसंरचना परियोजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या	2,92,466
	4. जलापूर्तिअवसंरचना	4.1 पूरी होने वाली जलापूर्ति परियोजनाओं की संख्या	8	4. पेयजल की आपूर्ति में सुधार	4.1 सुरक्षित पेयजल के लिए घरों को दिए जाने वाले कनेक्शनों की संख्या	50,957
					4.2 सड़क निर्माण द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	8,52,114

3. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीम (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपयेमें)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
825	1. पर्यटन अवसंरचना में सुधार	1.1 स्वीकृत की जाने वाली पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	1	1. पर्यटकों के आगमन में वृद्धि	1.1 चालू की जाने वाली अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	2
		1.2 12 महीनों के भीतर पूरी की जाने वाली अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	8		1.2 अपग्रेड की गई प्रत्येक अवसंरचना सुविधा के कारण पर्यटकों की संख्या में वृद्धि%	72
	2. खेल एवं शिक्षा अवसंरचना में सुधार	2.1 स्वीकृत की जाने वाली शिक्षा अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	2	2. शैक्षिक सुविधाओं का विकास	2.1 चालू की जाने वाली अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	15
		2.2 महीनों के भीतर पूरी की जाने वाली शिक्षा अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	21		2.2 स्कूल/परियोजना में नामांकित छात्रों/युवाओं की संख्या में वृद्धि	9,434
					2.3 स्कूल जाने वाले नामांकित छात्रों का %	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
	3. खेल एवं शिक्षा अवसंरचना में सुधार	3.1 स्वीकृत की जाने वाली खेल अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	0	3. खेलों के प्रदर्शन में सुधार	3.1 चालू की जाने वाली खेल अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	6
		3.2 12 महीनों के भीतर पूरी की जाने वाली खेल अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	7		3.2 खेल परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले छात्रों और युवाओं की संख्या	5,500
	4. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कोसहायता	4.1 स्वीकृत की जाने वाली कृषि परियोजनाओं की संख्या	2	4. पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि और संबद्ध गतिविधियों को	4.1 चालू की जाने वाली कृषि परियोजनाओं की संख्या	9

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपयेमें)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
		4.2 12 महीनों के भीतर पूरी की जाने वाली कृषि परियोजनाओं की संख्या	9	बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र/यूनिट/लाभार्थियों की कवरेज में वृद्धि	4.2 बागवानी/खेतों की फसलों के तहत स्थापित नया क्षेत्र (हेक्टेयर/यूनिट में)	795
					4.3 लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि	6,155
	5. औद्योगिक इको-सिस्टम में सुधार	5.1 स्वीकृत की जाने वाली औद्योगिक अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	1	5. उत्पादक आर्थिक गतिविधियों का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या	5.1 चालू की जाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं की संख्या	1
		5.2 12 महीनों के भीतर पूरी की जाने वाली औद्योगिक अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	6		5.2 लाभार्थियों की संख्या	1,20,548
	6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में सुधार	6.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं की संख्या जो स्वीकृत होने वाली हैं	1	6. उत्पादों और प्रक्रियाओं में सुधार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से कौशल में सुधार	6.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं की संख्या जो चालू की जानी हैं	10
		6.2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं की संख्या जो 12 महीनों के भीतर पूरी की जानी हैं	10		6.2 निर्मित किए गए नए उत्पादों/बेहतर की गई प्रक्रियाओं की संख्या	159
					6.3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या	71,200
	7. पूर्वोत्तर क्षेत्र सेसंबंधित हस्तक्षेपों (आईपीआर) को बढ़ावा देना	7.1 स्वीकृत की जाने वाली औद्योगिक अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	1	7. बेहतर जागरूकता और प्रचार अभियान	7.1 चालू की जाने वाली अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	3

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपयेमें)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		7.2 12 महीनों के भीतर पूरी की जाने वाली अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या	18		7.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित पहलों वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देने से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या	1,78,263
	8. आईएफसी और डब्ल्यूएसएम सेक्टर को समर्थन	8.1 जल संचयन और जलापूर्ति से संबंधित परियोजनाओं की संख्या जो स्वीकृत होने वाली हैं	3	8. चिन्हित किएगए पिछड़े ब्लॉक से संबंधित परियोजनाओं की संख्या, जिन्हें सीडीब्लॉक में प्रमुख चिन्हित सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरा किया जाना है और चिन्हित किए गए पिछड़े ब्लॉकों में प्रमुख सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना और समग्र विकास को बढ़ावा देना	8.1 बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोधी कार्य से संबंधित परियोजनाओं की संख्या	3
		8.2 चिन्हित किए गए पिछड़े ब्लॉक से संबंधित परियोजनाओं की संख्या, जिन्हें सीडी ब्लॉक में प्रमुख चिन्हित सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरा किया जाना है	6		8.2 जल संचयन और जलापूर्ति परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या	26,812
		8.3 बाढ़ नियंत्रण और मिट्टी के कटाव को रोकने से संबंधित परियोजनाओं की संख्या जो पूरी की जानी हैं	0		8.3 चिन्हित किए गए पिछड़े ब्लॉक से प्रमुख चिन्हित सेवा परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या	2,13,900
		8.4 बाढ़ नियंत्रण और मिट्टी के कटाव को रोकने से संबंधित परियोजनाओं की संख्या जो चालू की जानी हैं	0			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपयेमें)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	9. बेहतर तृतीयक स्वास्थ्य सेवा	9.1 स्वीकृत की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं की संख्या	1	9. स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच	9.1 लाभान्वित रोगियों की संख्या	28,022
		9.2 12 महीनों के भीतर पूरी की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं की संख्या	5			

1. डीप ओशन मिशन (डीओएम) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
625	1. 6000 मीटर गहराई के लिए रेटेड मानव सबमर्सिबल का डिज़ाइन और विकास	1.1 उथले पानी में सभी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के साथ तीन मानवों के साथ 500 मीटर की गहराई तक इंटीग्रेटेड सबमर्सिबल डेवलपमेंट (%)	100	1. महासागरीय संसाधनों की खोज के लिए 6,000 मीटर की गहराई तक मानवयुक्त सबमर्सिबल के इंजीनियरिंग परीक्षण	1.1 तीन मानवों को लेकर मानव सबमर्सिबल का प्रदर्शन पूरा हुआ, जिसमें 500 मीटर गहराई तक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली भी शामिल है (%)	100
		1.2 एमएटीएसवाईए[93]-6,000 के लिए 6,000 मीटर गहराई वाले घटकों का विकास और सबसिस्टम असेंबली, जिसमें टी आई स्फियर शामिल है (%)	75		1.2 6000 मीटर दर के लिए टी आई स्फियर का परीक्षण (%)	75
	2. महासागरीय जलवायु परामर्शिकाओं का सृजन।	2.1 क्षेत्रीय जलवायु डाउनस्केलिंग के लिए ग्लोबल महासागर मॉडल का विकास (%)	100	2. भारतीय तटीय क्षेत्रों पर महासागर-जलवायु प्रभावों की बेहतर समझ।	2.1 वर्ष 2100 के लिए 1:25,000 स्केल के मल्टी-हज़ार्ड वल्नरेबिलिटी मैप बनाना, जिसमें समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी और चक्रवात के अनुमान शामिल हैं (%)	75
		2.2 डीप ओशन ऑब्ज़र्विंग सिस्टम लगाना	100		2.2 जलवायु अनुमानों के लिए महासागर मॉडल को समझना और उनका सत्यापन (हाँ/नहीं)	हाँ

[93] *समुद्री अन्वेषण के लिए मानवयुक्त स्वायत्त/उन्नत परिवहन पनडुब्बी*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		(4 ग्लाइडर मिशन, 30 डी डब्ल्यू एस बी डी[94] और 50 ए आर जी ओ[95]) (%)				
	3. भारतीय ईईजेड[96] में भारतीय सीमाउंट के जैव विविधता हॉटस्पॉट का सर्वेक्षण और अन्वेषण	3.1. समुद्री पहाड़ों के पास गहरे समुद्र की जैव विविधता सर्वेक्षणों की संख्या	5	3. गहरे समुद्र की जैव विविधता के लिए संरक्षण योजना। भारतीय सीमाउंट के गहरे समुद्र के जीवों का रिपॉजिटरी और डीएनए बैंक, और गहरे समुद्र के माइक्रोब्स के कल्चर के लिए टेक्नोलॉजी	3.1 चिह्नित किए गए, इकट्ठा किए गए और वाउचर किए गए नए गहरे समुद्र जीवों की संख्या	50
	4. हाइड्रोथर्मल सर्वेक्षण	4.1 हाइड्रोथर्मल वेंट फील्ड में दूर से चलने वाले वाहन (आरओवी) को लगाना (हां/नहीं)	हाँ	4. हाइड्रोथर्मल खनिज संसाधनों की बेहतर समझ और संभावित खोज।	4.1 निष्क्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज	2
					4.2 आरओवी का उपयोग करके हाइड्रोथर्मल वेंट डिपॉजिट का संभावित सैंपलिंग (हां/नहीं)	हाँ
	5. महासागर अनुसंधान पोत का अधिग्रहण	5.1 स्टील स्ट्रक्चर इरेक्शन (स्तरवार) और श्रेणी अनुमोदन	100	5. महासागर अनुसंधान पोत का निर्माण	5.1 महासागरीय संसाधनों, सजीव और निर्जीव दोनों का गहरे समुद्र में अन्वेषण सर्वेक्षण (हाँ/नहीं) (%)	30

[94] *गहरे पानी की सतह पर बोया डेटा*

[95] *वास्तविक समय भूस्थैतिक समुद्र विज्ञान के लिए सरणी*

[96] *विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	6. ऑफशोर ओटीईसी-[97]संचालित विलवणीकरण संयंत्र के लिए डिज़ाइन दस्तावेज़ तैयार करना।	6.1 एक ओटीईसी ऑफशोर प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करना और संबंधित घटकों /मॉडल अध्ययन करना (%)	100	6. ऑफशोर अक्षय ऊर्जा और पेय जल के लिए टेक्नोलॉजी।	6.1 लक्षद्वीप के द्वीपों में ऊर्जा और पेय जल की मांग को पूरा करना। (हाँ/नहीं)	हाँ

2. मिशन मौसम (एमएम) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,342.29	1. भारत में वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क का विस्तार/सुदृढ़ीकरण	1.1 डीडब्ल्यूआर[98], एमआर[99], एडब्ल्यूओएस[100], एग्रो[101] एडब्ल्यूएस, आरवीआर[102], आदि	250	1. सार्वजनिक सुरक्षा और खराब मौसम की घटनाओं से बचाव के लिए बेहतर मौसम सेवाएं।	1.1 2025 के पूर्वानुमान की तुलना में बेहतर समझ और मौसम का पूर्वानुमान।	हाँ
					1.2 नाउकास्ट सेवाओं में सुधार (हां/नहीं)	हाँ

[97] *महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण*

[98] *डॉप्लर मौसम रडार*

99 मौसम संबंधी राडार

[100] *स्वचालित मौसम अवलोकन प्रणाली*

[101] *कृषि मौसम विज्ञान स्वचालित मौसम स्टेशन*

[102] *रनवे विज़ुअल रेंज*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		सहित वायुमंडलीय प्रेक्षण प्रणाली की संस्थापना और आरंभ किया जाना			1.3 डीडब्ल्यूआर के तहत कवरेज क्षेत्र में वृद्धि (हाँ/नहीं)	हाँ
					1.4 गरज युक्त तूफान के पूर्वानुमान की सटीकता में वृद्धि (हां/नहीं)	हाँ
					1.5 एरोसोल गुणों और वायुमंडलीय ओजोन की निगरानी (हाँ/नहीं)	हाँ
	2. मौसम और जलवायु पूर्वानुमान के लिए डेटा-संचालित और ए ई-आधारित मॉडल का विकास	2.1 मौसम पूर्वानुमान के लिए ए ई मॉडल का विकास	75	2. बेहतर लघु- और मध्यम -अवधि मौसम पूर्वानुमान प्रणाली	2.1 मौसम पूर्वानुमान की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार	हाँ
	3. क्लाउड फिजिक्स और मौसम संशोधन में अनुसंधान और विकास	3.1 क्लाउड फिजिक्स और मौसम में बदलाव के अध्ययन के लिए मापन अध्ययनों के साथ एक कन्वेक्शन क्लाउड चैंबर और उससे जुड़ा अवसंरचना स्थापित करना। (%)	30	3. उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में बाउंड्री लेयर डायनामिक्स, क्लाउड पैरामीटराइजेशन, संवहन और वर्षा प्रक्रियाओं की मूलभूत समझ, मौसम संशोधन के पहलू।	3.1 एससीआई पत्रिकाओं में प्रकाशनों की संख्या	5
	4. विज़ुअलाइज़ेशन और निर्णय समर्थन प्रणाली का प्रारम्भ होना	4.1 विभिन्न मौसम प्रणालियों को शामिल करते हुए निर्णय समर्थन प्रणाली का स्वदेशी विकास। (%)	100	4. पूर्वानुमान तैयार करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना	4.1 उपयोगानुकूल, स्वचालित पूर्वानुमान उत्पादन प्रणाली जिसे मौसम विज्ञान केंद्र संचालित करते हैं (हां/नहीं)	हाँ

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	5. डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क (डीबीनेट)स्टेशनों का कार्यान्वयन	5.1 दिल्ली/एनसीआर और चेन्नई में डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क (डीबीनेट) स्टेशनों की स्थापना। (%)	100	5. एनडब्ल्यूपी मॉडल में डेटा एसिमिलेशन के लिए विदेशी सैटेलाइट प्रेक्षण का तेज़ी से अधिग्रहण।	5.1 पूर्वानुमान की बेहतर क्षमताओं के लिए सैटेलाइट प्रेक्षण का बेहतर समावेशन। (%)	10
	6. युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली का विकास	6.1 लघु और मध्यम अवधि के पूर्वानुमान के लिए महासागर-वायुमंडल युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली का परीक्षण (%)	100	6. मौसम पूर्वानुमान के लिए बेहतर संभावित/ निर्धारणात्मक पूर्वानुमान जिसमें गंभीर मौसम की घटनाएं भी शामिल हैं।	6.1 अधिक असर वाली और घातक मौसमी घटनाओं की सटीक लघु और मध्यम दूरी के पूर्वानुमान के लिए बेहतर क्षमता (हाँ/नहीं)	हाँ

3. पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
800	**I उप-योजना: महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओएसएमएआरटी)**					
	1. महासागर सूचना और पूर्व चेतावनी सेवाओं का सृजन और प्रसार।	1.1 महासागर प्रेक्षण प्लेटफार्मों का नियोजन (संख्या में)	60	1. हिंद महासागर की प्रभावी निगरानी और समझ।	1.1 2025 की तुलना में महासागर स्थिति का बेहतर पूर्वानुमान (% में)	15
					1.2 वैज्ञानिक / तकनीकी प्रकाशनों की संख्या।	8
		1.2 मछली पकड़ने के वाले संभावित क्षेत्रों संबंधी एडवाइजरी और	100	2. तटीय और समुद्री समुदायों की आजीविका	2.1 मछली के झुंडों को खोजने में मछुआरों द्वारा लगने	हाँ

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		हानिकारक शैवाल ब्लूम संबंधी एडवाइजरी का प्रसार (%)		और सुरक्षा में सुधार। कोई झूठी चेतावनी नहीं और सटीक चेतावनी (तूफ़ानी लहरें और सुनामी)	वाले समय और मेहनत में कमी।	
		1.3 समुद्री बहु-खतरों की पूर्व चेतावनियों का सृजन और प्रसार (%)	100			
	2. विलवणीकरण संयंत्र शुरू करने का कार्यान्वयन.	2.1 एंड्रोथ में एक विलवणीकरण संयंत्र चालू करना (% में)	100	3. द्वीपों के लिए स्वच्छ जल हेतु प्रौद्योगिकी विकास	3.1 एंड्रोथ, लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लोगों के लाभ के लिए प्रतिदिन उत्पादित किया जाने वाला ताज़ा पानी (किलो लीटर में)।	150
	3. समुद्री निर्जीव संसाधनों की खोज	3.1 भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में बैथिमेट्रिक डेटा अधिग्रहण के तहत कवर किया गया क्षेत्र (% में)	95	4. भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के समुद्र तल की आकृति विज्ञान के बारे में ज्ञान और नई जानकारी में वृद्धि।	4.1 सुनामी, तूफ़ान, समुद्री स्थिति के पूर्वानुमान जैसी बेहतर सेवाओं के लिए (हाँ/नहीं)	हाँ
	4. तटीय निगरानी और सेवाएँ	4.1 तटीय प्रदूषण की निगरानी के लिए स्थानों की संख्या	50	5. महासागर स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी करना	5.1 एसडीजी-14 के भाग के तौर पर समुद्री प्रदूषण निगरानी संबंधी स्थिति रिपोर्ट / प्रकाशन (संख्याओं में)	4
		4.2 उन राज्यों की संख्या जहां तटीय कटाव की निगरानी की जा रही है	4		5.2 तटरेखा परिवर्तन मानचित्र / प्रकाशन जिसमें राज्यों में कटाव वाले हॉटस्पॉट का वर्णन हो, उन्हें कम करने के उपाय बताए गए हों।	4
	II उप-योजना ध्रुवीय विज्ञान हिमांकमण्डल (पीएसीईआर)					

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	1. अंटार्कटिक, आर्कटिक और हिमालय के अभियान	1.1 ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुमंडलीय और महासागरीय वेधशालाओं की संख्या	8	1. ध्रुवीय और समुद्री क्षेत्रों और उनके वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव की बेहतर समझ।	1.1 अंटार्कटिका, आर्कटिक, दक्षिणी महासागर और हिमालय की बेहतर समझ पर प्रकाशनों की संख्या जिसमें ट्रॉपिक और ध्रुवों के बीच टेलीकनेक्शन शामिल हैं।	45
		1.2 हिमालय में लगातार निगरानी के लिए ग्लेशियरों की संख्या	6		1.2 क्रायोस्फेरिक क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान प्रसार, वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी और ज्ञान साझा गतिविधियाँ	20
		1.3 अंटार्कटिका में प्रत्येक दो स्टेशनों पर अभियान के दिन	365			
		1.4 आर्कटिक में अभियान के दिन	300		1.3 अंटार्कटिक, आर्कटिक और हिमालय में नए भूवैज्ञानिक / क्रायोस्फेरिक / वायुमंडलीय / जैविक / पर्यावरणीय / जलवायु / समुद्री डेटा रिकॉर्ड का सृजन (संख्या में)	30
		1.5 आर्कटिक में अभियान के दिन	200			
	III उपयोजना: भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान (एसएजीई)					
	1. राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क (एनएसएन)	1.1 नए भूकंपीय प्रणालियों की स्थापना (संख्या में)	10	1. भूकंप के पैरामीटर में ज़्यादा सटीकता के साथ भूकंप का पता लगाने की क्षमताओं में सुधार।	1.1 मौजूदा नेटवर्क के ज़रिए देश के ज़्यादातर हिस्सों में 3.0 की न्यूनतम तीव्रता वाले भूकंपों का (3 मिनट के अंदर) पता लगाया जा सकना (हाँ/नहीं)	हाँ
		1.2 हिमाचल प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभिक भूकंप चेतावनी प्रणाली स्थापित करना (% में)	75			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	IV उपयोजना: अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच (रीचआउट)					
	1. एक्स्ट्रामूरल फंडिंग	1.1 देश के विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में (आर एण्ड डी.[103]) गतिविधियों को करने के लिए समर्थित परियोजनाओं की संख्या।	80	1. विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।	1.1 एक्स्ट्रामूरल फंडिंग के माध्यम से किए गए शोध पर आधारित प्रकाशनों की संख्या	40
	2. आउटरीच और जागरूकता	2.1 स्कूलों / कॉलेजों / विश्वविद्यालयों की संख्या जहाँ आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।	50	2. छात्रों में पृथ्वी विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाना और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, जिसमें अर्थ साइंस ओलंपियाड में प्रतिभागिता करना भी शामिल है।	2.1 आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रमों में विद्यार्थी की सहभागिता।	हाँ

[103] *अनुसंधान एवं विकास*

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल)

1. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय। (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
12,750.00	1. सभी स्कूल दिनों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पात्र कक्षाओं (I-VIII) और बालवाटिकाओं में बच्चों को भोजन का प्रावधान।	1.1 वर्तमान वित्त वर्ष में देश में पीएम पोषण योजना के तहत भोजन परोसने वाले स्कूलों की संख्या (लाखों में)	10	1. बच्चों को अधिक नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना।	1.1 छात्रों की औसत उपस्थिति में परिवर्तन (%)	1
		1.2 योजना के तहत भोजन परोसने वाले स्कूलों का %	100	2. बच्चों के पोषण स्तर में सुधार और विशेष परिस्थितियों के दौरान पोषण सहायता का प्रावधान।	2.1 गर्मी की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पोषण संबंधी सहायता प्राप्त करने वाले पात्र बच्चों का (%)	100
		1.3 औसत आधार पर भोजन का लाभ उठाने वाले छात्रों का %	90			
		1.4 स्कूल दिवस जब भोजन परोसा गया का %	95			
		1.5 भोजन वितरण में व्यवधान की सूचना देने वाले स्कूलों का %	0			
		1.6 पीएम पोषण के तहत भोजन परोसने वाले बलवाटिकाओं का %	100		2.2 आपदा के समय पोषण समर्थन प्रदान किए गए पात्र बच्चों (%)	100
	2. पीएम पोषण के तहत स्वास्थ्य घटक	2.1 छात्रों के लिए स्वास्थ्य जांच आयोजित करने वाले स्कूलों का %	70		2.3 विशेष परिस्थितियों में भोजन प्रदान करने वाले राज्यों की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[104]

[104] *यह लक्ष्य इस संकेतक के अनुरूप नहीं है, क्योंकि विशेष परिस्थितियों का सामना करने वाले राज्यों की अनुमानित संख्या के आधार पर इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।*

वित्तीय परिव्यय। (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		2.2 छात्रों को द्विवार्षिक रूप से डी-वर्मिंग दवाएं वितरित करने वाले स्कूलों (%)	70	3. छात्रों और अभिभावकों की भागीदारी में सुधार	3.1 स्कूल पोषण उद्यानों में शामिल बच्चों का %	50
		2.3 छात्रों को आयरन एंड फोलिक एसिड (आईएफए) टैबलेट वितरित करने वाले स्कूलों का %	70		3.2 वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिन स्कूलों में सामाजिक लेखापरीक्षा की गई, उनका %	90
		2.4 एनएफएसए के तहत निर्धारित पोषण मानकों को बनाए रखने वाले स्कूलों (%)	100		3.3 तिथि भोजन आयोजित करने वाले स्कूलों का %	40
	3. रसोइया सह सहायक	3.1 वर्तमान वित्त वर्ष में प्राथमिक विद्यालयों में प्रति स्कूलों कार्यरत रसोइया सह सहायक की औसत संख्या।	2		3.4 छात्रों की संख्या जिन्हें तिथि भोजन प्रदान किया गया (करोड़ में)	4
		3.2 वर्तमान वित्त वर्ष में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति स्कूल कार्यरत रसोइया सह सहायकों की औसत संख्या	2			
		3.3 वर्तमान वित्त वर्ष में प्रशिक्षित रसोइया -सह-सहायकों का %	50			
	4. भोजन की तैयारी और स्कूल पोषण उद्यान के लिए बुनियादी ढांचा	4.1 पृथक रसोई-सह-भंडार वाले स्कूलों का %	90			
		4.2 भोजन तैयार करने के लिए स्वच्छ ईंधन/एलपीजी का उपयोग करने वाले स्कूलों का %	80			
		4.3 सुरक्षित पेयजल तक पहुंच वाले स्कूलों का %	95			

वित्तीय परिव्यय। (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		4.4 स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यानों (एस.एन.जी.) की स्थापना (लाख में)	2			
		4.5 स्कूलों में एसएनजी उगाई गई सब्जियों का उपयोग करने वाले स्कूलों का %	90			
		4.6 वर्तमान वित्त वर्ष में रसोई सह भंडार की मरम्मत की संख्या	10,000			

2. समग्र शिक्षा (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
42,100.02	1. सार्वभौमिक पहुंच, प्रतिधारण और अवसंरचनात्मक गतिविधियां	1.1 खोले गए नए स्कूल / मौजूदा स्कूलों का उन्नयन	200	1. बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना	1.1 माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन दर (जीईआर) (%)	83
		1.2 सुदृढ़ीकरण के तहत शामिल स्कूल (प्री-प्राइमरी कक्षाएं)	20,000		1.2 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) (%)	62
		1.3 सुदृढ़ीकरण के तहत शामिल स्कूल (अतिरिक्त कक्षाओं और प्रयोगशालाओं सहित)	9,000		1.3 ट्रांजिशन दर (कक्षा VIII से IX तक) (%)	92
		1.4 स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या जिन्हें एनआईओएस के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण (प्रारंभिक स्तर)/सहायता प्रदान की गई (लाख में)	4		1.4 ट्रांजिशन दर (कक्षा X से XI) (%)	81
		1.5 परिवहन और अनुरक्षण सुविधा प्रदान किए गए	5	2. छात्रों के अधिगम	2.1 प्रारंभिक स्तर पर प्रतिधारण	84

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		बच्चों को संख्या (लाख में)		परिणामों में वृद्धि करना और सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल प्राप्त करना।	दर	
		1.6 धारा 12 (1) (ग) के तहत कवर किए गए बच्चों की संख्या[105] (लाख में)	30	3. शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना	3.1 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित कक्षा XI और XII के छात्र जो एनएसक्यूएफ स्तर 3/4 प्रमाणन % प्राप्त कर रहे हैं	60
	2. आरटीई पात्रता, गुणवत्ता और नवाचार मध्यवर्तन	2.1 छात्र %, जिनको मुफ्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान की गई (प्रारंभिक स्तर) (करोड़ में)	9	4. स्कूल शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतर को समाप्त करना	4.1 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जीपीआई	1
		2.2 बच्चों की संख्या जिन्हें मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के तहत शिक्षण-अधिगम सामग्री प्रदान की गई (करोड़ में)	2		4.2 कुल नामांकन के % के रूप में सीडब्ल्यूएसएन का नामांकन (%)	1
		2.3 छात्रों की संख्या जिन्हें अधिगम वृद्धि/संपोषण कार्यक्रम (कक्षा 6 से 12) प्रदान किया गया (करोड़ में)	1			
		2.4 विद्यालयों की संख्या जिनमें पुस्तकालय सुविधा प्रदान की गई (लाख में)	5			
		2.5 विद्यालयों की संख्या जिनमें खेल उपकरण सुविधा प्रदान की गई (लाख में)	5			
		2.6 आईसीटी और डिजिटल पहलों (स्मार्ट क्लासरूम सहित) के तहत आने वाले विद्यालयों की संख्या	10,000			

[105] आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत प्रवेश शुल्क के 25% के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	3. शिक्षक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण।	3.1 वर्ष के दौरान डाइट की संख्या जिनका अवसंरचना सुदृढ़ीकरण किया गया	100			
		3.2 वर्ष के दौरान पूर्व-सेवा और सेवाकालीन प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या (लाख में)	20			
	4. भोजन तैयार करने और स्कूल पोषण बागानों के लिए अवसंरचना	4.1 समग्र शिक्षा (कक्षा 9-12) के तहत माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले नए विद्यालयों की संख्या	2,000			
		4.2 वर्तमान में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों (कक्षा 9-12 में) की संख्या (लाख में)	35			
		4.3 मध्य चरण (कक्षा 6 से 8) में व्यावसायिक शिक्षा (10 बैगलेस दिनों सहित) के लिए किसी भी रूप में अनुभव प्रदान करने वाले स्कूलों की संख्या	50,000			
	5. शिक्षा में जेडंर समानता, समता और समावेश।	5.1 लड़कियों के लिए स्व-रक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूलों की संख्या (लाख में)	2			
		5.2 प्रशस्त ऐप के माध्यम से जांच किए गए छात्रों की संख्या (लाख में)	10			
		5.3 सीडब्ल्यूएसएन की जाँच, मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए ब्लॉक पहचान शिविरों की संख्या	10,000			

3. प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक[106]	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
7,500.00	1. पीएम श्री स्कूल में गुणवत्तापूर्ण और कार्यात्मक अवसंरचना	1.1 स्मार्ट कक्षा वाले माध्यमिक/ वरिष्ठ माध्यमिक पीएम श्री स्कूल (%)	100	1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच और अधिगम परिणामों में सुधार	1.1 पीएम श्री स्कूल हेतु कक्षा 8 से कक्षा 9 में परिवर्तन की दर (%)	100
		1.2 आईसीटी लैब वाले माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक पीएम श्री स्कूल (%)	100			
		1.3 एकीकृत विज्ञान और विषय विशिष्ट प्रयोगशालाएं (भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) वाले माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक पीएम श्री स्कूल (%)	100		1.2 वर्ष 2023-24 के संदर्भ में माध्यमिक स्तर पर छात्रों की ड्रॉपआउट दर में गिरावट (%)	5
	2. प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई)	2.1 कक्षा 1 से शुरू होने वाले और 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों हेतु कम से कम एक बाल वाटिका वाले पीएम श्री स्कूल (%)	100	2. माध्यमिक स्तर पर छात्र अधिगम परिणाम में सुधार	2.1 वर्ष 2023-24 के संदर्भ में कक्षा - 10 में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि (%)	2
	3. व्यावसायिक और कौशल शिक्षा	3.1 न्यूनतम एक व्यावसायिक विषय को कार्यान्वित करने वाले माध्यमिक /वरिष्ठ माध्यमिक वाले पीएम श्री स्कूल (%)	100	3. बढ़ी हुई रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता	3.1 एनएसक्यूएफ स्तर ¾ प्रमाणन अर्जित करने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कक्षा XI और XII में नामांकित छात्र (%)	80
		3.2 कैरियर संबंधी मेले /औद्योगिक अनुभव प्रदान करने वाले दौरे का आयोजन करने वाले माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक वाले पीएम श्री स्कूल (%)	100			

[106] *सातवें चरण तक चयनित वाले पीएम श्री स्कूल हेतु*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक[106]	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	4. शिक्षा में लैंगिक समानता, समता और समावेशन	4.1 बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करने वाले वाले पीएम श्री स्कूल (%)	100			
	5. शिक्षक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण	5.1 पीएमश्री स्कूल के शिक्षक जिन्होंने वित्त वर्ष में कम से कम 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) अवसरों में भाग लिया है(%)	100			
	6. ग्रीन और सस्टेनेबल स्कूल (मिशन लाइफ एलाइनमेंट)	6.1 विद्यार्थियों के नेतृत्व वाले इको क्लब के साथ मिशन लाइफ गतिविधियों का संचालन करने वाले पीएम-श्री स्कूल (%)	100			
	7. सामुदायिक भागीदारी और अभिशासन	7.1 माता-पिता और स्थानीय प्रतिनिधि की भागीदारी के साथ एसएमसी/एसडीसी की बैठकें आयोजित करने वाले पीएम श्री स्कूल (%)	100			

4. राज्यों के लिए शिक्षक-अधिगम और परिणामों का सुदृढ़ीकरण (स्टार्स) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
500	1. स्कूल से कार्यस्थल तक अंतरण को सुदृढ़ करना	1.1 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे (%)	12	1. माध्यमिक स्तर पर जीईआर में सुधार।	1.1 जीईआर में सांकेतिक वृद्धि (%)	3
	2. डिजिटल और प्रौद्योगिकी एकीकृत अधिगम अवसंरचना में सुधार	2.1 डिजिटल और प्रौद्योगिकी एकीकृत अधिगम अवसंरचना के साथ स्तरोन्नत माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	22,137			

उच्चतर शिक्षा विभाग

1. राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,250	1. छात्र जिन्हें वित्त वर्ष में प्रशिक्षुता प्रदान की जाएगी	1.1 प्रशिक्षुता प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या (लाखों में)	6	1. छात्र व्यावहारिक, उद्योग-विशिष्ट कौशल प्राप्त करते हैं	1.1 उद्योग द्वारा 'अच्छा' और उससे ऊपर के रूप में घोषित प्रशिक्षुओं का %	40

2. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,850	1. बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू)	1.1 एमईआरयू में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या	35	1. बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू)	1.1 प्रदान किए गए पेटेंट की संख्या	900
		1.2 स्वयम्[107] और अन्य एमओओसी[108] के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री की पेशकश	700		1.2 प्रकाशित पत्रों की संख्या	15,000

[107] *स्वयम्-युवा आकांक्षी व्यक्तियों के लिए सक्रिय अधिगम का स्टडी वेब*

[108] *एमओओसी-मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम*

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		1.3 समर्थ ईआरपी[109] का उपयोग करने वाले एचईआई की संख्या	432		1.3 एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) पर पंजीकृत एचईआई की संख्या और शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु प्रवेश और विकास की पेशकश	400
	2. उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान	2.1 वित्त वर्ष में वित्तीय रूप से समर्थित प्रत्यायन प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या (एमईआरयू को छोड़कर)	42	2. मान्यता	2.1 गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या	10
		2.2 वित्त वर्ष में वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या (एमईआरयूएस को छोड़कर)	31		2.2 गैर-मान्यता प्राप्त कॉलेजों की संख्या	30
		2.3 वित्त वर्ष में वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त प्रत्यायित कॉलेजों की संख्या	212		2.3 एनएएसी[110] प्रत्यायन ग्रेड में सुधार करने वाले एचईआई की संख्या	50
		2.4 वित्त वर्ष में वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त प्रत्यायित कॉलेजों की संख्या	187			
	3. फोकस जिले	3.1 फोकस जिलों में वित्तीय सहायता प्राप्त कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की संख्या	460	3. समता, पहुंच और समावेशन	3.1 समानता, पहुंच और समावेशन में सुधार के लिए आयोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों/प्रशिक्षणों/कार्यक्रमों में नामांकित छात्राओं की संख्या	50,000
		3.2 समानता, पहुंच और समावेशन में सुधार के लिए आयोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों/प्रशिक्षणों/कार्यक्रमों की	400		3.2 समानता, पहुंच और समावेशन में सुधार के लिए आयोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों/प्रशिक्षणों/कार्यक्रमों	50,000

[109] *ईआरपी-उद्यम संसाधन आयोजना*

[110] एनएएसी-*राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद*

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		संख्या			में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग[111]/ट्रांसजेंडर, आदि छात्रों की संख्या	

3. पीएम रिसर्च फैलोशिप (पीएमआरएफ) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
600	1. गहन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सबसे मेधावी छात्रों को छात्रवृति के माध्यम से पहले दो वर्षों के लिए @ 70,000 रुपये, तीसरे वर्ष के लिए 75,000 रुपये और चौथे और पांचवें वर्ष के लिए 80,000 रुपये सहायता दी जाती है।	1.1 वित्त वर्ष में पहले स्वीकार किए गए फेलो को निरंतर फेलोशिप की संख्या	1,445	1. आईआईएससी/आईआईटी/आईआईएसईआर/सीयू में पीएचडी करने के लिए प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित करना। पीएमआरएफ पीएचडी स्नातक सीएफटीआई और अन्य प्रमुख संस्थानों के लिए गुणवत्तापूर्ण संकाय प्रदान करेंगे।	1.1 रूपांतरात्मक अनुसंधान की संख्या	105
					1.2 प्रकाशित प्रकाशनों की संख्या	4,524
					1.3 दायर किए गए पेटेंट की संख्या	214
				2. आईटीआई/पॉलिटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्यापन द्वारा रिसर्च फेलो की भागीदारी के माध्यम से ज्ञान का अंतरण	2.1 आईटीआई/पॉलिटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाने वाले रिसर्च फेलो की संख्या (सप्ताह में एक बार)	1,444

[111] *एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग*

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
				करना, जिससे तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।		
				3. आस-पास के संस्थानों में सभी विद्वानों को तकनीकी ज्ञान का प्रसार करना	3.1 कौशल विकास शिक्षण में प्रत्येक पीएमआरएफ द्वारा दी गई औसत कार्य अवधि (प्रति माह 4 घंटे)	50

4. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,560	**क. ब्याज सब्सिडी और गारंटी फंड के लिए योगदान (सीएस)**					
	1. योजना के तहत ब्याज अनुदान दावों को जारी करना	1.1 वित्त वर्ष में जारी ब्याज अनुदान के दावों की संख्या (नया)	1,00,000	1. व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों तक अधिक पहुंच	1.1 लाभार्थी छात्रों की संख्या जिन्होंने उच्चतर शिक्षा के दिए गए स्तर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है.[112]	80,000
		1.2 छात्रों के दावों की संख्या जिनके लिए वित्त वर्ष (नवीनीकरण) में जारी ब्याज अनुदान दावे जारी किए गए	2,00,000			
	2. शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड	2.1 छात्रों के खातों की कुल संख्या जिनकी गारंटी दी जाएगी	1,90,000	2. ऋण देने वाले बैंकों पर एनपीए[113] के बोझ को	2.1 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋणों की संख्या जो	80

[112] *(ब्याज सब्सिडी धारकों की संख्या (नवीनीकरण) जिन्होंने पिछले वर्ष अपनी शिक्षा के स्तर को पूरा कर लिया है) (व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम)*

[113] एनपीए-*अनर्जक आस्तियां*

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
				कम करना जिसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में पात्र छात्रों को कवर करने के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा	सीएसआईएस और सीजीएफएसईएल (शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना) दोनों के तहत कवर किए गए हैं[114]	
	ख. कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (सीएस)					
	1. पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति जारी करना।	1.1 योजना के तहत वर्ष के दौरान जारी छात्रवृत्तियों की संख्या (नई)	60,000[115]	1. तीव्र प्रक्रिया प्रवाह	1.1 उसी वित्तीय वर्ष में सत्यापित और वितरित की गई नवीनीकरण छात्रवृत्ति का %	90
		1.2 योजना के तहत वर्ष के दौरान जारी छात्रवृत्तियों की संख्या (नवीनीकरण)	1,40,000			
		1.3 छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों में महिला छात्रों का %	50			
	ग. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति					
	1. जम्मू-कश्मीर के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति जारी की गई।	1.1 वर्ष के दौरान योजना के तहत जारी छात्रवृत्तियों की संख्या (नई)	4,000	1. विश्वविद्यालय शिक्षा तक अधिक पहुंच	1.1 लाभार्थी छात्रों का % जिन्होंने दिए गए वर्ष को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जिसके लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है	90
		1.2 वर्ष के दौरान योजना के तहत जारी छात्रवृत्तियों की संख्या (नवीनीकरण)	12,000			

*[114] सीएसआईएस-(केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी) और सीजीएफएसईएल (शिक्षा ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम)/ 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण की संख्या जो सीएसआईएस*100 के तहत कवर किए गए हैं। (% में)*

[115] स्कॉलरशिप पोर्टल को बंद करने में देरी के कारण, मेरिट तैयार करना, डिडुप्लीकेशन प्रक्रिया, नई के लिए संवितरण आमतौर पर मार्च के महीने में शुरू होता है। इसलिए मेरिट योग्यता सूची में चयनित सभी लाभार्थियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप 31 मार्च से पहले नहीं दी जा सकी।

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		1.3 छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों में महिला छात्रों का %	36		(नए और नवीकरण दोनों छात्रों को ध्यान में रखते हुए) (% में)	

5. विश्व स्तरीय संस्थान (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
900	1. प्रतिष्ठित संस्थानों के रूप में निजी संस्थानों का चयन जो विश्व स्तरीय संस्थानों के रूप में उभरेंगे	1.1 विश्व स्तरीय संस्थान के रूप में अधिसूचित निजी संस्थानों की संख्या।	4	1. डब्ल्यूसीआई की विश्व रैंकिंग में सुधार	1.1 विश्व रैंकिंग में शीर्ष 500 में डब्ल्यूसीआईएस की संख्या.[116]	6
	2. स्वदेशी छात्रों को वहनीय दर पर देश के भीतर विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना	2.1 औसत संकाय - विश्व स्तरीय संस्थानों में छात्र अनुपात	01:15			
		2.2 भारतीय विश्व स्तरीय संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या।	8,762			
		2.3 भारतीय विश्व स्तरीय संस्थानों में विदेशी संकाय की संख्या.[117]	2,438			

[116] टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग या क्यूएस या शंघाई का जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी

[117] आईओई दिशानिर्देश 2017 के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक जिसने किसी विदेशी देश में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त की है, एक प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग में शीर्ष 500 संस्थानों से अपनी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव प्राप्त किया है, को विदेशी संकाय माना जाएगा।

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		2.4 समकक्ष समीक्षित विदेशी पत्रिकाओं में प्रति संकाय सदस्य प्रकाशित शोध पत्रों की औसत संख्या	1.35			
		2.5 दायर किए गए पेटेंट की संख्या	1,651			

6. आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (सीएस)[118]

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
650	1. नवाचार: ऑटोमेशन, ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर बिल्डिंग और सिमुलेटेड प्रयोगों के लिए व्यावहारिक शिक्षा	1.1 कवर किए गए संस्थानों की संख्या (ई-यंत्र)	100	1. परियोजना आधारित समस्या-समाधान, ओपन-सोर्स सहयोग, और प्रयोग के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना।	1.1 ई-यंत्र प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित छात्रों की संख्या	1,000
		1.2 इंटर्नशिप/ हैकथॉन/ कार्यशालाओं की संख्या (एफओएसएसईई[119])	4,000		1.2 ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षित छात्रों और संकाय की संख्या	1,20,000
		1.3 सिमुलेशन-आधारित	20		1.3 नए प्रयोगों की संख्या।	150

[118] एनएमईआईसीटी योजना के अगले चरण का प्रस्ताव व्यय विभाग में विचाराधीन है और बाद में कैबिनेट के अनुमोदन के अध्यधीन है। यहां विस्तृत आउटपुट और आउटकम अस्थायी हैं और वित्तीय अनुमोदन के अध्यधीन हैं।

[119] फ्री लाईबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजूकेशन

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		प्रयोगशाला की संख्या (आभासी प्रयोगशालाएं)			1.4 आभासी प्रयोगशालाओं लैब्स से लाभान्वित छात्रों की संख्या।	40,000
	2. अनुसंधान: अकादमिक अखंडता, बेहतर संगठन और अनुसंधान प्रोफाइलों, प्रकाशनों और शैक्षणिक संसाधनों की दृश्यता।	2.1 लाख में सत्यापित दस्तावेजों की संख्या (ई-शोधशुद्धि-पीडीएस[120])	8	2. डिजिटल नेटवर्क, टूल्स और रिपॉजिटरी के माध्यम से अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार।	2.1 लाभान्वित छात्रों/ विद्वानों/शोधकर्ताओं की संख्या (लाख में)	1.8
		2.2 संस्थानों की संख्या (आईआरआईएनएस[121])	300		2.2 आईआरआईएनएस पर बनाए गए संकाय प्रोफाइल की संख्या।	20,000
		2.3 एकीकृत एचईआई की संख्या (ओएनओके[122])	40		2.3 डिजिटल सामग्री (मिलियन में)	10
	3. शासन: उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रक्रियाओं का डिजिटल रूपांतरण।	3.1 लाख में नए छात्रों और कर्मचारियों की संख्या (लाख में) (समर्थ ईआरपी)	30	3. एचईआई की संस्थागत प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना।	3.1 डिजिटल भुगतान की राशि (करोड़ रुपये में)	1,500
	4. अधिगम संसाधन: ऑनलाइन अधिगम, कौशल विकास और प्रतिस्पर्धी परीक्षा तैयारी तक पहुंच।	4.1 स्वयम एमओओसी विकास (पाठ्यक्रमों की संख्या)	390	4. उच्च गुणवत्ता वाली अधिगम सामग्री तक न्यायसंगत पहुंच बढ़ाना।	4.1 ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या	80,00,000
		4.2 स्वयम एमओओसी वितरण (पाठ्यक्रमों की संख्या)	2,840		4.2 परीक्षा के लिए पंजीकरण की संख्या	16,00,000
		4.3 स्वयम प्लस पाठ्यक्रमों का विकास	40		4.3 जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	12,00,000
		4.4 स्वयम प्लस डिलीवरी	40		4.4 स्वयं + में ऑनलाइन	1,50,000

[120] *पीडीएस-साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टेयर*

[121] *आरआईएनएस-भारतीय अनुसंधान सूचना नेटवर्क प्रणाली*

[122] *ओएनओके-एक राष्ट्र एक ज्ञान*

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		(पाठ्यक्रमों की संख्या)			पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या	
		4.5 एसएटीएचईई[123] पाठ्यक्रम मॉड्यूल तैयार करना।	105		4.5 परीक्षा के लिए पंजीकरण की संख्या	30,000
					4.6 जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या।	15,000
					4.7 ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या	3,00,000

[123] *एसएटीएचईई-प्रवेश परीक्षा के लिए स्व-मूल्यांकन जांच और सहायता*

1. इलेक्ट्रॉनिकी संघटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
500	क. इलेक्ट्रॉनिकी संघटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस)					
	1. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकोसिस्टम के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	1.1. वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान वितरित प्रोत्साहन की राशि (करोड़ रुपये में)	500	1. इलेक्ट्रॉनिक्स संघटक विनिर्माण क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और सृजित रोजगार	1.1. वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक योजना के तहत निवेश (करोड़ रुपये में)	11,156
					1.2. वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक योजना के तहत उत्पादन (करोड़ रुपये में)	29,024
					1.3. वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक रोजगार	19,240
				2. इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में आत्मनिर्भरता हासिल करना और आयात निर्भरता को कम करना	2.1. इलेक्ट्रॉनिक्स संघटकों के आयात में कमी	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते।[124]

2. भारत में सेमीकंडक्टर और डिसप्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
8,000	क. भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना					

[124] कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन वास्तविक परिणाम प्रदान किया जाएगा

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	1. सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए परियोजना लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करना	1.1. समर्थित किए जाने वाले सेमीकंडक्टर फैब की संख्या	1	1. सेमीकंडक्टर में निवेश और रोजगार सृजन	1.1. योजना के तहत वर्ष के दौरान इकाइयों द्वारा निवेश (करोड़ रुपये में)	4,000
		1.2. वितरित की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि (करोड़ रुपये में)	2,000		1.2. योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान समर्थित इकाइयों द्वारा सृजित रोजगार (संख्या में)	1,500
	ख. भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीएमपी) और ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना					
	1. कंपाउंड सेमीकंडक्टर/एसआईपीएच/सेंसर/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब/एटीएमपी इकाइयों की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना।	1.1. समर्थित किए जाने वाले कंपाउंड/एसआईपीएच/सेंसर/ डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब/एटीएमपी इकाइयों की संख्या	9	1. कंपाउंड सेमीकंडक्टर/एसआईपीएच/सेंसर/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर/एटीएमपी में निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन	1.1. योजना के तहत वर्ष के दौरान इकाइयों द्वारा निवेश (करोड़ ₹ में)	11,000
		1.2. वितरित की जाने वाली वित्तीय समर्थन की राशि (करोड़ रुपये में)	5,000		1.2. योजना के तहत वर्ष के दौरान समर्थित इकाइयों द्वारा सृजित रोजगार (संख्या में)	3,000
	ग. डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना					
	1. सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन करने के लिए परियोजना लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करना	1.1. समर्थित सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों की संख्या	30	1. योजना के तहत आईपी कोर का डिजाइन और विकास और रोजगार सृजन	1.1. समर्थित कंपनियों द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए सेमीकंडक्टर आईपी कोर की संख्या	10
		1.2. वितरित की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि (करोड़ रुपये में)	100		1.2. समर्थित कंपनियों द्वारा नियोजित सेमीकंडक्टर डिजाइन जनशक्ति की संख्या	200

3. इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) को बढ़ावा देना (केंद्रीय क्षेत्र की योजना) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
720	**क. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआईपीएस)**					
	1. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआईपीएस) आवेदक को वित्तीय सहायता प्रदान करना	1.1. संवितरित प्रोत्साहन की राशि (करोड़ रुपये में)	319	1. सृजन ईएसडीएम[125] क्षेत्र में निवेश और रोजगार सृजन	1.1. एमएसआईपीएस के तहत वर्ष के दौरान इकाइयों द्वारा निवेश (करोड़ ₹ में)	300
		1.2. सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	5		1.2. एमएसआईपीएस के तहत वर्ष के दौरान इकाइयों द्वारा सृजित रोजगार (संख्या में)	1,000
	ख. इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना					
	1. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को वित्तीय सहायता प्रदान करना	1.1. जारी सहायता अनुदान राशि (करोड़ रुपये में)	40	1. ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे का आधार बनाना और उसे मजबूत करना	1.1. इकाइयों की संख्या जिनके लिए भूमि आवंटित की गई	30
					1.2. इकाइयों द्वारा प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रुपये में)	600
	ग. संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना					
	1. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को वित्तीय सहायता प्रदान करना	1.1. जारी सहायता अनुदान की राशि (करोड़ रुपये में)	80	1. ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे का आधार बनाना और उसे मजबूत करना	1.1. इकाइयों की संख्या जिनके लिए भूमि आवंटित की गई	20
					1.2. ईएमसी में इकाइयों द्वारा प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ ₹ में)	2,200
	घ. इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि (ईडीएफ़)					

[125] *इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का रूप और उत्पादन*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	1. वेंचर फंड में ईडीएफ द्वारा विनिवेश	1.1. डॉटर फंड की संख्या जिसमें विनिवेश (पूर्ण/आंशिक) ईडीएफ (संचयी) के माध्यम से किया जाएगा	8	1. इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो-इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में काम करने वाली कंपनियों के लिए जोखिम पूंजी की वापसी	1.1. उन स्टार्टअप्स की संख्या जिनसे विनिवेश (पूर्ण/आंशिक) अपेक्षित है	24
		1.2. डॉटर फंड में ईडीएफ के विनिवेश की राशि (करोड़ ₹ में)	246.18		1.2. स्टार्ट-अप में डॉटर फंड के विनिवेश की राशि (करोड़ रुपये में)	1,867
	ङ. इलेक्ट्रॉनिक संघटक और सेमीकंडक्टर विनिर्माण संवर्धन योजना (एसपीईसीएस)					
	1. इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और सेमिकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना	1.1. वित्त वर्ष 2026-27 में इकाइयों को किए गए संवितरण की राशि (करोड़ रुपये)	239	1. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बढ़ा हुआ निवेश	1.1. योजना के तहत शामिल की गई इकाइयों द्वारा निवेश (करोड़ रुपये में)	2,500
		1.2. समर्थित इकाइयों की संख्या	3	2. इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और सेमिकंडक्टरों के उत्पादन में वृद्धि	2.1. योजना के अंतर्गत शामिल की गई इकाइयों द्वारा आउटपुट (करोड़ रुपये में)	2,600
				3. इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि	3.1 योजना के तहत शामिल की गई इकाइयों द्वारा रोजगार	1,000

4. आईटी / इलेक्ट्रॉनिकी / सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,248.33	**क. अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) इलेक्ट्रॉनिकी और राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम)**					
	1. इलेक्ट्रॉनिकी और एनएसएम में अनुसंधान	1.1. इस समूह के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	13	1. उल्लिखित क्षेत्रों में इनक्यूबेशन/स्टार्ट-	1.1. की गई प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संख्या	15

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	एवं विकास	1.2. चल रही परियोजनाओं की संख्या	47	अप शुरू करने के लिए प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप, उत्पादों और प्रयासों को पूरा करके नई प्रौद्योगिकियों का विकास	1.2. इस समूह के तहत सफलतापूर्वक पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	17
		1.3. दायर किए गए पेटेंट की संख्या	60			
		1.4. परियोजना में पीएचडी सहित प्रशिक्षित विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनशक्ति की संख्या	800			
	ख. अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)					
	1. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में अनुसंधान और विकास	1.1. इस समूह के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	11	1. उल्लिखित क्षेत्रों में इनक्यूबेशन/स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप, उत्पादों और प्रयासों को पूरा करके नई प्रौद्योगिकियों का विकास	1.1. किए गए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संख्या	2
		1.2. चल रही परियोजनाओं की संख्या	26		1.2. इस समूह के तहत सफलतापूर्वक पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	7
		1.3. दायर किए गए पेटेंट की संख्या	5			
		1.4. परियोजना में पीएचडी सहित प्रशिक्षित विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनशक्ति की संख्या	500			
	ग. अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सीसी एंड बीटी					
	1. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), इलेक्ट्रॉनिकी और संचार अभिसरण और ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी (सीसी एंड बीटी) में अनुसंधान और विकास	1.1. इस समूह के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	2	1. उल्लिखित क्षेत्रों में इनक्यूबेशन/स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप, उत्पादों	1.1. किए गए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संख्या	3
		1.2. चल रही परियोजनाओं की संख्या	12		1.2. इस समूह के तहत सफलतापूर्वक पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	3
		1.3. दायर किए गए पेटेंट की संख्या	50			
		1.4. परियोजना में पीएचडी सहित प्रशिक्षित विज्ञान और प्रौद्योगिकी	200			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		जनशक्ति की संख्या		और प्रयासों को पूरा करके नई प्रौद्योगिकियों का विकास		
	घ. अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) इनोवेटिव स्टार्टअप के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट (जेनेसिस)					
	1. स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों में इनक्यूबेटरों को सक्षम करना	1.1. समर्थित इन्क्यूबेटरों की संख्या	64	1. टियर 2 और टियर 3 शहरों में उद्यमिता और नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देना	1.1. समर्थित स्टार्टअप की संख्या	330
		1.2. स्टार्टअप्स और इन्क्यूबेटरों का समर्थन करने के लिए आयोजित कार्यक्रमों/गतिविधियों/कार्यक्रमों की संख्या	115		1.2. विकसित उत्पादों/प्रोटोटाइप/पीओसी की संख्या	198
					1.3. दायर किए गए आईपीआर की संख्या	83

5. इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
628.18	1. डिजिटल लॉकर की स्थापना	1.1. नये उपयोगकर्ता पंजीकरण (करोड़ में)	10	1. डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटल दस्तावेजों का बढ़ा हुआ उपयोग	1.1. डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर खपत किए गए दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि (करोड़ में)	150

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	2. उमंग के माध्यम से सभी भारतीय नागरिकों के लिए अखिल भारतीय ई-गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग करने के लिए एक एकल मंच	2.1. उमंग पर उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त सेवाएं (सेवाओं की संख्या)	220	2. उमंग सेवाओं का बढ़ता उपयोग	2.1. उमंग प्लेटफॉर्म पर लेनदेन की संख्या में वृद्धि (करोड़ में)	150
	3. मेघराज एप्लीकेशन को क्लाउड पर स्थापित करना	3.1. एनआईसी क्लाउड पर चल रहे अनुप्रयोगों की कुल संख्या	100	3. मेघराज क्लाउड पर एप्लिकेशन/उपयोगकर्ताओं की होस्टिंग	3.1 एनआईसी (मेघराज) क्लाउड पर होस्ट किए गए एप्लिकेशन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं/ग्राहकों की संख्या में वृद्धि	100
		3.2. एनआईसी क्लाउड पर चलने वाले वर्चुअल सर्वरों की कुल संख्या	8,000			

6. क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
600	1. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी)	1.1. प्रशिक्षित' उम्मीदवारों की कुल संख्या - [पूर्वोत्तर सहित] (संख्या में)	1,100,000	1. सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी और संचार प्रौद्योगिकी (आईईसीटी) क्षेत्र में प्रशिक्षण/शिक्षा क्षमता	1.1. उम्मीदवारों की कुल संख्या 'प्रमाणित' - [पूर्वोत्तर सहित] (संख्या में)	5,09,000

7. साइबर सुरक्षा परियोजना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
790	1. भारतीय साइबरस्पेस को सुरक्षित करने के लिए वास्तविक समय के खतरे का आकलन और स्थितिजन्य जागरूकता	1.1. मेटा-डेटा एकत्रित करने वाली साइटों की कुल संख्या	400	1. खतरे के आकलन के लिए औसत समय	1.1. खतरों की पहचान करने का औसत समय (मिनटों में)	30
		1.2. 3 महीने की अवधि के दौरान लक्षित संगठनों के साथ साझा किए गए कार्रवाई योग्य साइबर-खतरे अलर्ट की संख्या।	3,600		1.2. संगठनों को खतरे के आकलन और अधिसूचना के लिए औसत समय (घंटों में)	12
	2. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास	2.1. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में शुरू की गई नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं	5	2. साइबरस्पेस की सुरक्षा के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास	2.1. साइबरस्पेस की सुरक्षा के लिए विकसित की गई नई प्रौद्योगिकियां (संख्या में)	2
	3. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के अनुसार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा शासन।	3.1 डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के तहत विनियमों की अधिसूचना (अधिसूचित किए जाने वाले नियमों की कुल संख्या)	25	3. डेटा संरक्षण बोर्ड (डीपीबी) की स्थापना	3.1 जनशक्ति भर्ती, प्लेटफॉर्म विकास आदि के संदर्भ में बोर्ड के लिए डिजिटल कार्यालय की स्थापना में प्रगति का %	100

8. इंडिया एआई मिशन (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,000	1. भारत की तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित	1.1. केंद्रीय मंत्रालयों में कई एआई क्यूरेशन इकाइयाँ की संख्या स्थापित की जाएंगी	20	1. समावेशन, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए	1.1. सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या विवरणों	5

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना और घरेलू सुविधाओं और क्षमताओं का निर्माण करना	1.2. पूरे भारत में स्थापित की जाने वाली इंडियाएआई प्रयोगशालाओं की संख्या	80	घरेलू एआई इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक और एकीकृत मिशन की स्थापना।	को संबोधित करने के लिए लागू एआई परियोजनाओं की संख्या।	
		1.3. मिशन के तहत वित्तपोषित किए जाने वाले डीप स्टार्टअप्स की संख्या	25			
		1.4. मिशन के तहत वित्तपोषित की जाने वाली उद्योग आधारित परियोजनाओं की संख्या	3			

9. राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
665	1. एनकेएन के लिए राजकोषीय सहायता	1.1. संवितरित की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि	665	1. 10-100 जीबीपीएस पर कोर बैकबोन लिंक का निर्माण/उन्नयन	1.1. अपग्रेड किए गए मौजूदा कोर लिंक कीई संख्या	50
				2. 100 एमबीपीएस -1 जीबीपीएस पर जिलों के लिंक का निर्माण/उन्नयन	2.1. एनकेएन के साथ नए एनआईसी जिला केंद्र कनेक्टिविटी की संख्या	20

1. प्रदूषण नियंत्रण (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,091	1. वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्यान्वयन गतिविधियों की निगरानी	1.1 मौजूदा निगरानी स्टेशनों की संख्या	2,011	1. वायु गुणवत्ता में सुधार	1.1 वार्षिक लक्ष्य के अनुसार पीएम10 के स्तर में कमी वाले शहरों का %[126]	100
		1.2 स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित निगरानी स्टेशनों की संख्या	1,046		1.2 शहर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) प्राप्त करने वाले शहरों का %[127]	25
	2. जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्यान्वयन गतिविधियों की निगरानी	2.1 मौजूदा निगरानी स्टेशनों की संख्या	5,000	2. प्रदूषित नदी क्षेत्रों में कमी	2.1 प्रदूषित नदी क्षेत्रों में कमी का %	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते।[128]
		2.2 स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित निगरानी स्टेशनों की संख्या	89		2.2 जल की गुणवत्ता निगरानी के तहत शामिल की गई नदियों की कुल संख्या	622
	3. ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्यान्वयन गतिविधियों की निगरानी	3.1 ध्वनि निगरानी स्टेशनों की संख्या	226	3. ध्वनि के स्तर को कम करना	3.1 बढ़े हुए ध्वनि प्रदूषण के स्तर में कमी का %	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते।[129]
		3.2 स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित निगरानी स्टेशनों की संख्या	144		3.2 ध्वनि निगरानी कवरेज वाले नए मिलियन प्लस शहरों की संख्या	36

[126] *130 शहर*

[127] *33 शहर*

[128] *वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए बाद में प्रस्तुत किया जाएगा।*

[129] *वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए बाद में प्रस्तुत किया जाएगा।*

आर्थिक कार्य विभाग

1. भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता के तहत लाइन ऑफ क्रेडिट योजना (आई.डी.ई.ए.एस.) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य[130] 2026-27
1,675.18	1. एग्जिम बैंक को ब्याज समतुल्यीकरण सहायता (आईईएस) प्रदान की जाती है ताकि वह विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर ऋण दे	1.1 वित्त वर्ष के दौरान एक्ज़िम बैंक को दी गई ब्याज समतुल्यीकरण सहायता राशि (करोड़ रुपये में)	4,577.21[131]	1. भारत के रणनीतिक और राजनीतिक हितों में सुधार	1.1 आईईएस के माध्यम से एक्जिम बैंक को सहायता प्राप्त करने वाले देशों की कुल संख्या (संचयी)	49
		1.2 कुल प्रदत्त क्रेडिट लाइनों (एलओसी) की संख्या[132]	13		1.2 वर्ष के दौरान एक्जिम बैंक को आईईएस का समर्थन करने के लिए देशों के साथ हस्ताक्षरित नए अनुबंधों की संख्या	17
		1.3 वित्त वर्ष के दौरान प्रदत्त लाइन ऑफ क्रेडिट का मूल्य ((करोड़ रुपये में)	20,986.45[133]			
		1.4 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित कुल संख्या की तुलना	65			

[130] *वास्तविक परिणाम वित्त वर्ष 2026-27 के अंत में घोषित किए जाएंगे।*

[131] *वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आईईएस दावा अनुमान*

[132] *विदेश मंत्रालय द्वारा पत्र सं. डीपीए 1/230/19/2025 के तहत प्रदत्त डेटा के आधार पर (मॉरीशस (**440** मिलियन अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपये समतुल्य), अंगोला (**1,685** करोड़ रुपये), भूटान (**4,000** करोड़ रुपये), केन्या (**250** मिलियन अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपये समतुल्य), वियतनाम (**150** मिलियन अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपये समतुल्य), गुयाना (**50** मिलियन अमेरिकी डॉलर), लाओ पीडीआर (**15** मिलियन अमेरिकी डॉलर), सेशेल्स (**100** मिलियन अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपये समतुल्य), म्यांमार (**200** मिलियन अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपये समतुल्य), नाइजीरिया (**50** मिलियन अमेरिकी डॉलर), नामीबिया (**100** मिलियन अमेरिकी डॉलर), युगांडा (**110** मिलियन अमेरिकी डॉलर), ईरान (**250** मिलियन अमेरिकी डॉलर)*

[133] *1 अमेरिकी डॉलर = 89.2213 भारतीय रुपये की अनुमानित विनिमय दर पर आरबीआई संदर्भ दर के अनुसार दिनांक 26.11.2025 को परिवर्तित किया गया। (नई एलओसी की घोषणा 03 बिलियन यूएसडी प्रतिवर्ष की समग्र-सीमा के अंदर की जाएगी)*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य[130] 2026-27
	सके।	में लाइन ऑफ क्रेडिट वाले देशों की कुल संख्या (64)[134]				
		1.5 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित कुल संख्या (99) की तुलना में विभिन्न देशों को दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत समर्थित परियोजनाओं की कुल संख्या[135]	91	2. भारत के माल और सेवा निर्यात में सुधार हुआ।	2.1. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित मूल्य (₹ 7218.48 करोड़) की तुलना में वर्ष के दौरान के माध्यम से भारत के निर्यात उत्पादों का मूल्य (करोड़ रुपये में)	6,069.81[136]
		1.6 प्रदत्त लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत परियोजनाओं का कुल मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	8,256.96		2.2. भारतीय निर्यातकों को प्राप्त कारोबार का मूल्य (करोड़ रुपये में) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित मूल्य (₹9624.64 करोड़) की तुलना में	8,093.09
		1.7 वित्त वर्ष के दौरान नई परियोजनाओं की संख्या[137]	8		2.3. वित्त वर्ष के दौरान भारतीय निर्यातकों को दिए गए नए अनुबंधों का मूल्य (भारतीय रुपये/अमेरिकी डॉलर में)	959.40[138]
		1.8 वित्त वर्ष के दौरान संविदा के माध्यम से लाभान्वित होने वाले नए निर्यातकों की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[139]	3. साझेदार देश की बेहतर सामाजिक-	3.1 पिछले वर्ष की तुलना में लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार	3.63

[134] *64 देशों के वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित गणना और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 65 की लाइन ऑफ क्रेडिट गणना में भूटान और नामीबिया की सरकारों के लिए स्थान शामिल हैं क्योंकि हस्ताक्षर करने के लिए सटीक समय-सीमा का आकलन नहीं किया जा सकता है।*

[135] *99 परियोजनाओं के लिए अनुमानित गणना में वियतनाम सरकार के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 2 नई परियोजनाएं और तंजानिया सरकार के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 1 परियोजना शामिल थी।*

[136] *1 अमेरिकी डॉलर = 89.2213 भारतीय रुपये की अनुमानित विनिमय दर पर आरबीआई संदर्भ दर के अनुसार दिनांक 26.11.2025 को परिवर्तित किया गया।*

[137] *नई परियोजनाएं और आगे की वृद्धि ऋण लेने वाले देशों की मांग पर निर्भर करेगी*

[138] *वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान भारत सरकार समर्थित एलओसी के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अपेक्षित संविदा।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य[130] 2026-27
				आर्थिक स्थिति	के % में वृद्धि (वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 18,383 लोगों के लिए रोजगार सृजन)।	

[139] *यह डेटा उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदारों का चयन अभी बाकी है।*

वित्तीय सेवाएं विभाग

1. **रूपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना (व्यक्ति-से-व्यापारी) (सीएस)**

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
2,000	1. डिजिटल भुगतान की बढ़ती पैठ	1.1 यूपीआई स्वीकृति बुनियादी ढांचे में वृद्धि (का %)	10	1. भीम-यूपीआई लेनदेन में वृद्धि	1.1 भीम-यूपीआई लेनदेन की संख्या में % वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2025-26 से वृद्धि %)	25
		1.2 भीम-यूपीआई के माध्यम से व्यापारी डिजिटल भुगतान लेन-देन (पी2एम) की संख्या (करोड़ में)	18,187			

2. **अटल पेंशन योजना में सरकार का सह-अंशदान (सीएस)**

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27[140]

[140] *वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नामांकित ग्राहकों की संख्या के संबंध में परिणाम संकेतकों के लक्ष्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही तक अंतिम रूप दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तिमाही आधार पर अन्य लक्ष्यों का वितरण साध्य नहीं है, क्योंकि* पिछले वित्तीय वर्ष के कार्यनिष्पादन के आधार पर पीएफआरडीए बैंकों और डाक विभाग को सकल वार्षिक लक्ष्य सौंपे गए हैं। बैंक और डाक विभाग को नामांकन के लिए लक्ष्य दिए गए हैं।

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27[140]
547.75	1. अटल पेंशन (एपीवाई) सेवा प्रदाताओं (एसपी) को प्रोत्साहन राशि	1.1 एपीवाई सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन के लिए स्वीकृत राशि (करोड़ में)	542.75	1. नामांकन और सततता में वृद्धि करता है	1.1 नामांकित अभिदाताओं की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
					1.2 बनाए रखे गए अभिदाताओं की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
	2. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत प्रचार अभियान	2.1 प्रचार अभियानों के लिए स्वीकृत राशि (करोड़ में)	5.00	2. बेहतर जागरूकता से अभिदाताओं को अधिक कवरेज और वृद्धावस्था सुरक्षा मिलेगी	2.1 नामांकित ग्राहकों की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
					2.2 बनाए रखे गए ग्राहकों की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते

मत्स्यपालन विभाग

1. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
2,500	1. मात्स्यिकी में नई प्रौद्योगिकी को अपनाना एवं क्षमता निर्माण करना	1.1 उन्नत जल कृषि प्रणालियों के अंतर्गत सहायता प्रदत्त कुल अतिरिक्त क्षेत्र (केज, आरएएस, बायो फ्लोक इत्यादि (हेक्टेयर में)	180	1. मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप आय और जीवन स्तर में सुधार हुआ	1.1. विगत वर्ष की तुलना में मत्स्य उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन[141]	9
				2. कम लागत और बेहतर कीमतों के कारण निर्यात में वृद्धि, मात्स्यिकी क्षेत्र का विकास और रोजगार सृजन	2.1. विगत वर्ष की तुलना में मत्स्य निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा आय में % की वृद्धि	10
		1.2 कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	80,000		2.2. मात्स्यिकी क्षेत्र में सृजित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की संख्या (संख्या में)	11,00,000
					2.3. वर्ष के दौरान मत्स्य पालन क्षेत्र में महिलाओं और सीमांत समुदायों के लिए बनाए गए नए रोज़गारों की संख्या।	2,50,000

[141] *वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कुल मत्स्य उत्पादन (लाख टन में)*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	2. जल कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि	2.1. जल कृषि के अंतर्गत लाया गया कुल अतिरिक्त क्षेत्र (हेक्टेयर में)	10,000	3. बेहतर मत्स्य प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट	3.1. स्वच्छ और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित की गई कुल मात्रा (टन में)	3,25,400
	3. सुदृढ़ पोस्ट-हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण	3.1. वर्ष के दौरान निर्मित फिश हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स की संख्या	10	4. गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ मत्स्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना	4.1. गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ मत्स्य की वार्षिक बिक्री (संख्या में)/(टन में)	14,471
		3.2. निर्मित / सहायता प्रदत्त पोस्ट-हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर की कुल क्षमता (आइस प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज, इंसुलेटिड/रेफ्रिजरेट कंटेनरों/ट्रकों के माध्यम से) मीट्रिक टन में)	1,800			
	4. मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और आधुनिकीकरण तथा मार्केट लिंकेज को सुगम बनाना	4.1 अतिरिक्त आधुनिक विपणन क्षमता (टन में)	17,025	5. उन्नत समुद्री शैवाल उत्पादन	5.1. विगत वर्ष की तुलना में समुद्री शैवाल के उत्पादन में परिवर्तन का प्रतिशत	20
		4.2 सहायता प्राप्त मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) और सहकारी समितियों/संघों की संख्या	50			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	क. प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई)					
	1. जलीय कृषि बीमा कवरेज में वृद्धि	1.1 जलकृषि बीमा के अंतर्गत बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	10,000	1. दावों पर समय पर कार्रवाई और निपटान	1.1 दावों के भुगतान के लिए औसतन समय, दिनों की संख्या।	90
		1.2 कुल दिया गया प्रोत्साहन (करोड़ रुपये में)	25	2. बीमित जलकृषि किसानों के लिए जोखिम कवरेज में वृद्धि	2.1. बीमा कंपनियों द्वारा जल कृषि किसानों को भुगतान किए गए स्वीकृत दावों का प्रतिशत	70

1. **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सीएस)**

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
2,010	1. एमयूवी का प्रयोग करके किसानों के घर पर पशु चिकित्सा सेवाएं	1.1. प्राप्त कॉलों की संख्या (लाखों में)	60	**1.** एमयूवी का प्रयोग करके किसानों के घर पर पशु चिकित्सा सेवाएं	1.1. एमयूवी से लाभ पाने वाले किसानों की संख्या (लाखों में)	55
	2. एफएमडी का नियंत्रण और उन्मूलन	2.1 एफएमडी के सापेक्ष टीका लगाए गए जानवरों की संख्या (करोड़ में)	50		1.2. इलाज किए गए जानवरों की संख्या (लाखों में)	120
	3. पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे का उन्नयन	4. राज्य प्रयोगशालाओं की संख्या (30)	1	**2.** एफएमडी का नियंत्रण और उन्मूलन	2.1. सीरोसर्विलांस (% एनएसपी रिएक्टर)	<10
		5. जिला प्रयोगशालाओं की संख्या (750)	25			
				3. अच्छी क्वालिटी की डायग्नोस्टिक सर्विस की उपलब्धता और पहुँच	3.1. प्रति वर्ष परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते.[142]

[142] *दूसरे साल से अपेक्षित परिणाम*

2. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (सीएस)**

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम **2026-27**			**परिणाम 2026-27**		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्यों को 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
800	1. कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार	1.1 कृत्रिम गर्भाधान किया गया (%)	45	1. दूध की उत्पादकता में वृद्धि	1.1. दूध उत्पादकता में वृद्धि (%)	1
	2. गैर-गोजातीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार	2.1 वीर्य की उपलब्धता (संख्या मिलियन में)	1			
	3. सॉर्टेड सेक्स सीमेन द्वारा नस्ल सुधार	3.1 लिंग के अनुरूप सीमेन की डोज़ प्रयोग की गई (लाख में)	40	2. गैर-गोजातीय पशुओं के विकास में वृद्धि	2.1. मांस उत्पादन में वृद्धि (%)	5
	4. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) द्वारा नस्ल सुधार	4.1 स्थानांतरित भ्रूणों की संख्या	10,000			
	5. देशी नस्लों का विकास और संरक्षण	5.1 सीमेन स्टेशनों पर शामिल किए गए एचजीएम बैल (संख्या)	1,700			

3. **डेयरी विकास (सीएस)**

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	**निर्गम 2026-27**			**परिणाम 2026-27**		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्यों को 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
1,055	1. दूध मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए बुनियादी ढांचा	1.1. वर्ष के दौरान एक्स्ट्रा मिल्क चिलिंग कैपेसिटी बनाना (टीएलपीडी में)	1,045	1. छोटे पशुपालकों की भागीदारी बढ़ाकर और दूध की खरीद बढ़ाकर संगठित डेयरी सेक्टर का कवरेज बढ़ाना ।	1.1. दूध खरीद की मात्रा में वृद्धि का %	2
		1.2. संचालित डेयरी सहकारी समिति (डीसीएस/दूध पूलिंग प्वाइंट (एमपीपी)) की संख्या	7,600		1.2. लाभान्वित छोटे पशुपालकों की संख्या में वृद्धि का %	2
		1.3. मौजूदा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी/मिल्क पूलिंग पॉइंट पर लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट की संख्या	3,800			
		1.4. प्रमाणीकरण के साथ आधुनिकीकृत/सुदृढ़ की गई राज्य/ज़िला लेवल की लैब की संख्या	12			
		1.5. स्थापना के लिए स्वीकृत सीबीजी/बायो गैस प्लांट की संख्या	2			
	2. दूध मूल्य श्रृंखला में महिला किसानों को सुदृढ़ करना	2.1. कोऑपरेटिव के तहत लाई गई अतिरिक्त महिला किसानों की संख्या (हज़ार में)	200			

1. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
915	**क. खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना**					
	1. बढ़ायी गयी खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन	1.1 वर्ष के दौरान चालू होने वाली खाद्य प्रसंस्करण/ परिरक्षण इकाइयों की संख्या	105	1. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सृजित नए रोजगार अवसरों की संख्या	1.1 खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार से सृजित कुल रोज़गार (व्यक्तियों की संख्या)	8,505
		1.2 वर्ष के दौरान अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण इकाइयों की संख्या	243	2. खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता में वृद्धि हुई	2.1 वर्ष के दौरान कुल बढ़ी कृषि उत्पाद प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता (लाख मीट्रिक टन)	23.52
		1.3 वर्ष के दौरान दुर्गम क्षेत्रों में अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण इकाइयों की संख्या	50			
	ख. एकीकृत शीत शृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना (विकिरण परियोजनाओं के अलावा)					
	1. एकीकृत शीत शृंखला और परिरक्षण	1.1 स्थापित की जाने वाली शीत शृंखला इकाइयों की संख्या	22	1. सृजित नए रोज़गार के अवसरों की संख्या	1.1 सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	43,010

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	अवसंरचना सुविधाओं का सृजन	1.2 वर्ष के दौरान चालू शीत श्रृंखला इकाईयों की संख्या	22	2. प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता में वृद्धि हुई	2.1 सृजित की जाने वाली कुल प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता (लाख मीट्रिक टन)	13.42
		1.3 पूर्ण हो चुकी परियोजना की कोल्ड स्टोरेज/ नियंत्रित वातावरण /एमए[143]/फ्रोजन स्टोर (एमटी) की कुल क्षमता	57,618			
	ग. एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना (विकिरण परियोजनाएँ)					
	1. खाद्य विकिरण इकाइयों का सृजन	1.1 स्थापित की जाने वाली खाद्य विकिरण इकाइयों की संख्या	3	1. सृजित नए रोज़गार के अवसरों की संख्या	1.1 सृजित रोजगार (संख्या)	324
		1.2 चालू की गई खाद्य विकिरण इकाइयों की संख्या	3	2. बढ़ी विकिरण उत्पादन क्षमता	1.2 सृजित विकिरण क्षमता (केसीआई[144])	11,000
	घ. मानव संसाधन और संस्थान योजना					
	1. खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधि	1.1 वर्ष के दौरान पूरी हो चुकी परियोजनाओं की संख्या	8	1. विकसित नई प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण बढ़ा	1.1 वर्ष के दौरान व्यावसायीकृत/अंतरित नई प्रौद्योगिकी की संख्या	8

[143] *संशोधित वातावरण*

[144] *किलोक्यूरी*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		1.2 वर्ष के दौरान विकसित नई प्रौद्योगिकी की संख्या	8		1.2 प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या	10
					1.3 वर्ष के दौरान पेटेंट की गई प्रौद्योगिकी की संख्या	4
	ङ. खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना					
	1 खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण अवसंरचना की स्थापना	1.1 एनएबीएल[145] मान्यता प्राप्त चालू एफटीएल की संख्या	20	1. सृजित परीक्षण क्षमता	1.1 मासिक परीक्षण क्षमता (औसत 1,500 नमूने)	30,000
					1.2 क्षमता उपयोग 70% की दर से	21,000
		1.2 एनएबीएल मान्यता प्राप्त अनुमोदित एफटीएल[146] की संख्या	3			

[145] *परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड*

[146] *खाद्य ट्रैसेबिलिटी सूची*

2. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई योजना) का औपचारिकीकरण (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,700	1. व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को सहायता	1.1 चालू वर्ष में सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	10,000	1. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश का लाभ लेना	1.1 महिलाओं सहित अतिरिक्त रोज़गार के अवसर सृजित हुए (व्यक्तियों की संख्या)	980
		1.2 योजना के तहत सहायता प्राप्त एसएचजी सदस्यों की संख्या	20,000	2. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों में सुधार	2.1 कुल निवेश की राशि(करोड़ रुपये में) जिसका लाभ लिया	50,000
		1.3 योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त महिला सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	3,000			
		1.4 औपचारिकीकरण की गई इकाइयों का प्रतिशत	40			

3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,200	1. प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों (तैयार-पकाने योग्य/खाने योग्य खाद्य पदार्थ और सब्जियां/समुद्री उत्पाद/मोज़ेरेला पनीर/नवीन/जैविक/मिलेट उत्पाद) के निर्माण को प्रोत्साहन देना।	1.1 सहायता प्राप्त आवेदकों की संख्या (संख्या)	85	1. तैयार - पकाने/खाने-योग्य पदार्थ एवं सब्जी/समुद्री उत्पाद/मोज़ेरेला चीज़/नवीन /जैविक/मिलेट उत्पाद के विनिर्माण में वृद्धि	1.1 सहायता प्राप्त आवेदकों द्वारा बिक्री (निर्यात सहित) (₹ करोड़ में)	1,17,826
	2. भारतीय ब्रांडों को विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन के लिए प्रोत्साहित करना	2.1 सहायता प्राप्त आवेदकों की संख्या (संख्या)	40	2. विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन के लिए सहायता प्राप्त भारतीय ब्रांडों के निर्यात में वृद्धि करना	2.1 पिछले वर्ष के मुकाबले विदेशों में सहायता प्राप्त भारतीय ब्राण्डों के निर्यात में % की बढ़ोतरी हुई	4

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

1. आरसीएच एवं स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
31,820	**क. एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाना**					
	1. आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राथमिक परिचर्या सेवाओं का विस्तारित दायरा।	1.1. आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष एएएम को छोड़कर) का % जिनमें सेवाओं के सभी 12 विस्तारित पैकेजों को लागू किया गया है।	92	1. सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का बेहतर उपयोग	1.1. आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि (पिछले वर्ष की तुलना में)	10
	2. सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्र (एसएचसी तक) में डीवीडीएमएस[147] का कार्यान्वयन	2.1 स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों का प्रतिशत जो डीवीडीएमएस (एसएचसी तक) लागू कर रही हैं	60	2. सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों (एसएचसी तक) में औषधियों की उपलब्धता में वृद्धि।	2.1 सीपीएचसी[148] दिशानिर्देशों के अनुसार 80% या उससे अधिक आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने वाली सुविधा केंद्रों का %	70

[147] *डीवीडीएमएस - औषधि एवं टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली*

[148] *सीपीएचसी - व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	3. आईपीएचएस[149]-अनुपालक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र	3.1 आईपीएचएस के अनुरूप कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र (प्रतिशत में)	40	3. आईपीएचएस के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का बेहतर उपयोग	3.1 सीएचसी और उससे उच्च स्तर के सुविधा केंद्रों में बिस्तर अधियोग दर में सुधार।	10
					3.2 पिछले वर्ष की तुलना में एएएम में ओपीडी सेवाओं में प्रतिशत वृद्धि	10
	4. एनक्यूएएस[150] प्रमाणित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र	4.1 एनक्यूएएस प्रमाणित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की कुल संख्या (प्रतिशत में)	50	4. गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को सुदृढ़ बनाना	4.1 एनक्यूएएस प्रमाणित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में कुल ओपीडी रोगियों में % की वृद्धि (पिछले वर्ष की तुलना में)।	10
	5. सिकल सेल रोग के लिए जांच किए गए लाभार्थी (नया संकेतक)	5.1 सिकल सेल रोग के लिए जांच किए गए व्यक्तियों की संख्या (31.03.2027 तक)[151]	1,00,00,000	5. सिकल सेल रोग से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार किया जाता है	5.1 सिकल सेल रोग से प्रभावित व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत को हाइड्रोक्सीयूरिया दवा दी गई	90
	ख. गैर-संक्रामक रोग कार्यक्रम: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम					

[149] *आईपीएचएस - भारतीय जन स्वास्थ्य मानक*

[150] *एनक्यूएएस - राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक*

[151] *(1,00,00,000 (31.03.2027 तक))*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	1. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर कवरेज	1.1. डीएमएचपी[152] इकाइयों में उपलब्ध मनोचिकित्सकों/प्रशिक्षित एमओ की संख्या।	686	1. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर कवरेज	1.1. पिछले वर्ष की तुलना में जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाइयों में मानसिक विकारों से पीड़ित लोगों के पंजीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? (आधार मान 654)[153]	10
	ग. गैर-संक्रामक रोग कार्यक्रम: राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता नियंत्रण कार्यक्रम					
	1. एनपीसीबी एवं वीआई[154] के अंतर्गत नेत्र परिचर्या सेवाएं जिला स्तर पर प्राथमिक और मध्यम तथा उससे निचले स्तर पर प्रदान की जाती हैं।	1.1. दृष्टि संबंधी समस्याओं के लिए जांच किए गए व्यक्तियों की संख्या (करोड़ों में)	5	1. मोतियाबिंद, अपवर्तक दोष और कॉर्निया संबंधी रोगों के कारण होने वाले अंधेपन और दृष्टिहीनता की समुचित पहल करके प्रबंधन करना।	1.1 की जाने वाली मोतियाबिंद सर्जरी की संख्या	1,05,00,000
					1.2 कॉर्नियल प्रत्यारोपण के लिए एकत्रित की जाने वाली दान-प्राप्त नेत्रों की संख्या	85,000
					1.3 स्कूली बच्चों और दूर दृष्टि से ग्रस्त व्यक्तियों (45 वर्ष और उससे अधिक आयु) को निःशुल्क चश्मों का वितरण।	50,00,000
	घ. रोग नियंत्रण कार्यक्रम: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम					
	1. तंबाकू मुक्ति सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि	1.1. तंबाकू मुक्ति केंद्रों की अतिरिक्त संख्या	50	1. तंबाकू मुक्ति सेवाओं तक पहुंच	1.1. पिछले वर्ष की तुलना में 2026-27 में तंबाकू मुक्ति	10

[152] डीएमएचपी-जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

[153] 2026-27 के लिए वार्षिक लक्ष्य 654 से 5% की वृद्धि हो सकता है।

[154] एनपीसीबी एंड वीआई - राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टिबाधितता नियंत्रण कार्यक्रम

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
					सेवा का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई	
	ङ. रोग नियंत्रण कार्यक्रम: राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम					
	1. बढ़ते सर्वेक्षणों के माध्यम से जी2डी से पीड़ित मामलों की संख्या में वृद्धि और उपचार के लिए भर्ती किए गए ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या।	1.1. राष्ट्रीय स्तर पर नए मामलों में से ग्रेड II विकलांगता (जी2डी) के नए मामलों का पता लगाने के प्रतिशत में कमी	1.3	1. कुष्ठ रोग के कारण होने वाली ग्रेड II की विकलांगता (जी2डी) में कमी	1.1. राष्ट्रीय स्तर पर प्रति मिलियन जनसंख्या पर ग्रेड II विकलांगता (जी2डी)	0.70
	च. गैर-संक्रामक रोग कार्यक्रम: गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) (सीएसएस)					
	1. प्रत्येक जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) की स्थापना।	1.1. स्थापित किए गए डे केयर कैंसर केंद्रों की कुल संख्या	450	1. डीसीसीसी की सेवाओं का उपयोग	1.1. डीसीसीसी में सेवाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या	2,000
	2. उच्च रक्तचाप और उच्च रक्त शर्करा हेतु वार्षिक जांच	2.1 उच्च रक्तचाप हेतु प्रतिवर्ष जांच किए गए व्यक्तियों की संख्या (करोड़ में) [155]	30	2. शीघ्र निदान और उपचार शुरू करना	2.1 निदान प्राप्त उच्च रक्तचाप के रोगियों में से उपचार शुरू करने वाले रोगियों का प्रतिशत	90

[155] *(राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल)*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		2.2 उच्च रक्त शर्करा के लिए प्रतिवर्ष जांच किए गए व्यक्तियों की संख्या (करोड़ में) [156]	30		2.2 निदान प्राप्त मधुमेह रोगियों का उपचार शुरू करने का प्रतिशत	90
	3. कैंसर के लिए संचयी स्क्रीनिंग (मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा का) (प्रत्येक 5 वर्ष में)	3.1 मुख कैंसर के लिए जांच किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या (करोड़ में)	30	3. कैंसर रोगियों का शीघ्र निदान और उपचार शुरू करना	3.1 एक वर्ष में मुख कैंसर से पीड़ित रोगियों में से उपचार शुरू करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत।	90
		3.2 स्तन कैंसर की जांच के लिए भर्ती किए गए रोगियों की कुल संख्या (करोड़ में)	16		3.2 एक वर्ष में स्तन कैंसर से पीड़ित रोगियों में से उपचार शुरू करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत।	90
		3.3 गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच के लिए भर्ती किए गए रोगियों की संचयी संख्या (करोड़ में)	10		3.3 एक वर्ष में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से पीड़ित रोगियों में से उपचार शुरू करने वाले रोगियों का प्रतिशत।	90
	छ. गैर-संक्रामक रोग कार्यक्रम: राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी)					
	1. राज्यों को जिला अस्पताल (डीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर	1.1. जिला अस्पताल स्तर और उससे नीचे के दंत चिकित्सा [157] इकाइयों की संख्या में पिछले वर्ष की	100	1. जिला अस्पताल और उससे निचले स्तर के अस्पतालों में रोगियों के लिए	1.1. पिछले वित्त वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और बाल विकास केंद्र (डीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	5

[156] राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल)

[157] वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संचयी लक्ष्य 2016 जिले, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संचयी लक्ष्य 316 जिले

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	पर दंत चिकित्सा इकाई स्थापित करने में सहायता प्रदान करना।	तुलना में वृद्धि (9234 दंत चिकित्सा इकाइयाँ) [158]		किफायती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण मुख स्वास्थ्य संबंधी परिचर्या की उपलब्धता।	(सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में लाभार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि(2.4 करोड़ लाभार्थी) [159]	
	ज. गैर-संक्रामक रोग कार्यक्रम: राष्ट्रीय बधिरता निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीपीसीडी)					
	1. समुदाय में सक्रिय स्क्रीनिंग (2026-27)	1.1. जांच किए गए व्यक्तियों की संख्या	30,00,000	1. सर्जरी, श्रवण यंत्र लगाने और पुनर्वास उपायों द्वारा श्रवण संबंधी समस्या वाले रोगी का प्रबंधन करना।	1.1 पुनर्वासित श्रवण समस्या वाले व्यक्तियों की संख्या	1,00,000
					1.2 की गई सर्जरी की संख्या	50,000
					1.3 श्रवण यंत्र लगवाने वाले व्यक्तियों की संख्या	10,000
	झ. गैर-संक्रामक रोग कार्यक्रम: फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीसीएफ)					
	1. सभी प्रभावित जिलों में कार्यक्रम कार्यकलापों का प्रभावी कार्यान्वयन	1.1. एनपीपीसीएफ कार्यकलापों को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले जिलों की संख्या	163	1. फ्लोराइड प्रभावित जिलों में नमूनों (यूरिन और जल) की जांच में सुधार	1.1. फ्लोराइड प्रभावित जिलों में जांचे जा रहे जल संबंधी नमूनों की संख्या (वित्त वर्ष 24-25 में	1,68,000

[158] आधारभूत स्तर: (वित्त वर्ष 2024-25) - 9183 दंत चिकित्सा इकाइयाँ; वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संचयी लक्ष्य = 9243 दंत चिकित्सा इकाइयाँ (आधारभूत आंकड़ों से 60 इकाइयों की वृद्धि)

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संचयी लक्ष्य = 9343

[159] वित्त वर्ष 2024-25 = 2.3 करोड़ लाभार्थी; वित्त वर्ष 2025-26 का लक्ष्य = पिछले वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि (2.4 करोड़ लाभार्थी); वित्त वर्ष 2026-27 का लक्ष्य = पिछले वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि (2.52 करोड़ लाभार्थी)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
					उपलब्धि: 1,60,513 नमूने)	
					1.2. फ्लोराइड प्रभावित जिलों में जांचे किए जा रहे यूरिन नमूनों की संख्या। (वित्त वर्ष 24-25 में उपलब्धि: 1,11,235 नमूने)	1,16,000
					1.3. परीक्षण किए गए पेयजल नमूनों में से फ्लोराइड-सुरक्षित पाए जाने वाले नमूनों का अनुपात (बीआईएस मानकों के अनुसार $\leq$1 मिलीग्राम/लीटर), पिछले वर्ष की तुलना में (%)	85
	ञ. आरएमएनसीएएच+एन (प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण)[160]					
	1. गर्भवती महिलाओं को 180 आयरन फोलिक एसिड (आईएफए) टैबलेट प्रदान की	1.1. प्रसवपूर्व निगरानी के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से % को 180 आयरन	95	1. मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी	1.1. प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) (आधार वर्ष	84

[160] *संचयी संख्या को मापने वाले सभी संकेतकों के लिए आधार वर्ष और आधार मान (पिछले वर्ष के लिए निरपेक्ष आंकड़े)*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	गई।	फोलिक एसिड (आईएफए) टैबलेट प्रदान की गई [161]			2021-23, आधार मान 88/लाख जीवित जन्म)[162]	
	2. प्रसव के दौरान कुशल प्रसव सहायिका प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत (संस्थागत + घर)	2.1 कुल दर्ज प्रसवों में कुशल प्रसव सहायकों (एसबीए) द्वारा कराए गए प्रसवों का प्रतिशत [163]	95			
	3. विशेष नवजात शिशु परिचर्या इकाई (एसएनसीयू) की सफल डिस्चार्ज दर	3.1 एसएनसीयू की सफल डिस्चार्ज दर (प्रतिशत में)[164]	82	2. एसएनसीयू में अधिक संख्या में बीमार नवजात शिशुओं के उपचार प्रबंधन से नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आएगी।	2.1 एसएनसीयू में अधिक संख्या में बीमार नवजात शिशुओं के उपचार प्रबंधन से नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आएगी। प्रति 1,000 जीवित जन्म (एनएमआर) आधार वर्ष 2023	18
	4. पूर्ण टीकाकरण कवरेज	4.1 पूर्ण टीकाकरण कवरेज (एफआईसी) का प्रतिशत	90	3. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु	3.1 प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 5 वर्ष से कम आयु के	27

[161] अंश: 180 आयरन फोलिक एसिड (आईएफए) टैबलेट प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या (स्रोत: एचएमआईएस), हर: एएनसी के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या (स्रोत: एचएमआईएस)

[162] (एसआरएस एमएमआर बुलेटिन 2021-23 वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी किया गया)

[163] अंश - कुशल प्रसव कर्मियों द्वारा संपन्न कराए गए कुल प्रसवों की संख्या (संस्थागत प्रसव + कुशल प्रसव कर्मियों द्वारा संपन्न कराए गए घरेलू प्रसव)। हर - दर्ज किए गए कुल प्रसवों की संख्या (संस्थागत प्रसव + घरेलू प्रसव)। (स्रोत: एचएमआईएस)

[164] अंश - किसी दिए गए वर्ष में विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू)/नवजात गहन देखभाल इकाइयों (एनआईसीयू) से जीवित छुट्टी पाने वाले नवजात शिशुओं की संख्या, हर - किसी दिए गए वर्ष में विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू)/नवजात गहन देखभाल इकाइयों (एनआईसीयू) में भर्ती होने वाले नवजात शिशुओं की संख्या

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
		(प्रतिशत में)[165]		दर (यू5एमआर) में कमी	बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) में कमी[166]	
	5. यू-विन	5.1 यूडब्ल्यूआईएन[167] में आयोजित कुल टीकाकरण सत्रों की संख्या बनाम नियोजित कुल टीकाकरण सत्रों की संख्या (%)[168]	90			
	ट. रोग नियंत्रण कार्यक्रम: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम					
	1. मलेरिया: मामलों की संख्या में कमी	1.1. पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मामलों की संख्या में प्रतिशत कमी (कैलेंडर वर्ष के लिए कमी)	12	1. मलेरिया: एपीआई[169] में कमी	1.1. राष्ट्रीय स्तर पर कैलेंडर वर्ष के लिए एपीआई में % की कमी (एपीआई की गणना कैलेंडर वर्ष के अनुसार की गई है)	12
	2. काला अजार: वीएल और पीकेडीएल मामलों का उपचार।	2.1 केए और पीकेडीएल[170] मामलों का पूर्ण उपचार प्रतिशत	100	2. काला अज़ार: काला अज़ार (केए) के उन्मूलन सीमा स्तर को बनाए	2.1 ब्लॉक स्तर पर प्रति 10000 जनसंख्या पर 1 से कम काला अजार (केए) मामले की रिपोर्ट करने	100

[165] अंश - एक वर्ष से कम आयु के पूर्णतः प्रतिरक्षित शिशुओं की कुल संख्या, हर - वार्षिक रूप से एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की कुल संख्या। (स्रोत: एचएमआईएस) (>90% और इसे बनाए रखना)।

[166] (एसआरएस 2023 वित्त वर्ष 2025-26 में जारी किया गया)

[167] सार्वभौमिक टीकाकरण विन (कार्यबल एवं सूचना नेटवर्क)

[168] अंश: आयोजित टीकाकरण सत्रों की कुल संख्या, हर: यूडब्ल्यूआईएन पर नियोजित टीकाकरण सत्रों की कुल संख्या

[169] वार्षिक परजीवी घटना

[170] पीकेडीएल - पोस्ट काला-अजार डर्मल लीशमैनियासिस

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
				रखना	वाले स्थानिक ब्लॉकों का प्रतिशत।	
	3. जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) / राष्ट्रीय स्तर पर नियमित टीकाकरण में जेई का कवरेज	3.1 जेई के लिए नियमित टीकाकरण के अंतर्गत पात्र आबादी का प्रतिशत (कैलेंडर वर्ष के लिए)	90	3. जेई: जेई मामलों में कमी	3.1 प्रति 1 लाख जनसंख्या पर मामलों की संख्या	0.5
	4. लसीका फाइलेरियासिस: लसीका फाइलेरियासिस प्रभावित जिलों में सामूहिक औषधि वितरण (एमडीए) द्वारा जनसंख्या की सुरक्षा करना	4.1 एमडीए के लिए पात्र जिलों की तुलना में एमडीए का अनुपालन करने वाले एलएफ स्थानिक जिलों की संख्या (प्रतिशत में)	100	4. लिम्फैटिक फाइलेरियासिस: टीएएस (ट्रांसमिशन असेसमेंट: सर्वे) सत्यापन के माध्यम से स्थानिक जिलों में एमडीए - रोकना	4.1 टीएएस द्वारा सत्यापित एलएफ स्थानिक जिलों की संख्या जहां एमएफ दर <1% है (लक्ष्य 2030 एसडीजी के अनुरूप है)	195
	ठ. रोग नियंत्रण कार्यक्रम: राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम					
	1. हेपेटाइटिस सी - कार्यक्रम के अंतर्गत रिपोर्टिंग करने वाले कार्यशील उपचार केंद्र	1.1. हेपेटाइटिस सी के उपचार के लिए शुरू किए गए नए रोगियों की संख्या	1,25,000	1. सी श्रेणी के रोगियों का उपचार पूरा करना।	1.1. एचसीवी[171] का उपचार पूरा करने वाले नए रोगियों की संख्या (यह मानते हुए कि 10% रोगी मृत्यु आदि के कारण फॉलो-अप से बाहर हो जाएंगे)	1,12,500

[171] *हेपेटाइटिस सी वायरस*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	2. हेपेटाइटिस बी के कार्यशील उपचार के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत रिपोर्टिंग करने वाले केंद्र	2.1 हेपेटाइटिस बी के उपचार प्रक्रिया प्राप्त नए रोगियों की संख्या	48,000	2. हेपेटाइटिस बी का प्रबंधन उपलब्ध है	2.1 हेपेटाइटिस बी के जिन रोगियों का उपचार शुरू किया गया और जिनका उपचार जारी है, उनकी संख्या। (यह मानते हुए कि 10% मरीज फॉलो-अप से बाहर हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, आदि)	1,60,200
	ड. रोग नियंत्रण कार्यक्रम: राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)					
	1. टीबी मामले की अधिसूचना	1.1. टीबी मामलों की अधिसूचना (सार्वजनिक एवं निजी)	26,00,000	1. टीबी की कुल घटनाएँ	1.1. किसी दिए गए वर्ष में प्रति लाख जनसंख्या पर टीबी के कुल नए मामले	180
	2. टीबी के मामलों में रिफैम्पिसिन प्रतिरोध का शीघ्र पता लगाने की कवरेज में वृद्धि।	2.1 वर्ष 2025-26 से कम से कम रिफैम्पिसिन के लिए उपलब्ध वैध दवा संवेदनशीलता परीक्षण परिणामों में प्रतिशत वृद्धि	2	2. उपचार कवरेज	2.1 किसी दिए गए वर्ष में टीबी के कितने प्रतिशत मामलों का पता चला और उनका उपचार किया गया	90
	ढ. गैर-संक्रामक रोग कार्यक्रम: वृद्धों की स्वास्थ्य परिचर्या के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई)					
	1. जिला अस्पताल और उससे निचले स्तर पर प्राथमिक और मध्यम वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान	1.1. व्यापक जराचिकित्सा आकलन (सीजीए) किट का उपयोग करके जांचे गए बुजुर्ग (=/> 60 वर्ष की आयु) आबादी की	7	1. जिला अस्पताल और उससे निचले स्तर के प्राथमिक और मध्यम वृद्धावस्था	1.1. स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में एनपीएचसीई सेवाओं का उपयोग करने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि (करोड़ में)	14

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		संख्या (करोड़ में)[172]		स्वास्थ्य सेवाओं में एनपीएचसीई की कवरेज बढ़ाना और इसके उपयोग में सुधार करना।	1.2. घर पर वृद्धावस्था परिचर्या प्राप्त करने वाले विकलांग बुजुर्ग (=/> 60 वर्ष की आयु) की संख्या (करोड़ में)[173]	3
	ण. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन					
	1. शहरी भारत में स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच में सुधार	1.1 यूपीएचसी-एएएम और यूएचएससी का % एएएम ने सेवाओं की विस्तारित रेंज के 12 पैकेज शुरू किए[174]	80	1. शहरी भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ता उपयोग	1.1 यूपीएचसी-एएएम और यूएसएचसी-एएएम में सेवाओं का लाभ उठाने वाले कुल लोगों की संख्या में वृद्धि का %[175]	10
	त. राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी)					
	1. संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनआईडीडीसीपी का कार्यान्वयन	1.1 एनआईडीडीसीपी को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या	35	I. संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सॉल्ट और यूरिन सैंपल की जांच में सुधार	1.1 संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परीक्षण किए जा रहे साल्ट के सैंपल की संख्या में वृद्धि (%)	3
					1.2 संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परीक्षण किए जा	3

[172] *अनुमानित बुजुर्ग आबादी के 50% की जांच की जाएगी*

[173] *20% बुजुर्ग आबादी किसी न किसी तरह की विकलांगता से पीड़ित है।*

[174] *आधार वर्ष - 2025-26 आधार मूल्य : 31 मार्च 2026 तक उपलब्धि*

[175] *आधार वर्ष: 2025-26 आधार मूल्यः 31 मार्च, 26 तक उपलब्धि*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
					रहे यूरिन सैंपल की संख्या में वृद्धि (%)	

2. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएजेएवाई) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
9,500	1. अस्पताल में भर्ती	1.1 अस्पताल में भर्ती (लाख में)	300	1. अस्पताल में भर्ती होने की दर	1.1 प्रति लाख लाभार्थियों में कुल अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या (पिछले वर्ष की तुलना में % बढ़ोतरी)	5
	2. लाभार्थी की पहचान	2.1 लाभार्थियों को जारी किए गए आयुष्मान कार्डों की अनुमानित संख्या (लाख में)	300	2. लाभार्थी परिवारों को इस योजना के तहत अपने अधिकारों के बारे में पता है	2.1 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के इलाज कराने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में % बदलाव	5

	3. दावा भुगतान	3.1 जमा किए गए दावों की रकम (करोड़)	36,000	3. स्कीम की उपयोगिता में वृद्धि।	3.1 इलाज कराने वाले खास लाभार्थियों की संख्या में % बदलाव (पिछले साल के मुकाबले % वृद्धि)	5
	4. अस्पताल पैनलीकरण	4.1 वर्ष के दौरान पैनल में शामिल किए गए कुल सरकारी अस्पतालों की संख्या	800	4. योजना के तहत स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदाताओं तक पहुंच में वृद्धि	4.1. पैनल में शामिल किए गए अस्पतालों की संख्या में कुल % बदलाव (पिछले साल के मुकाबले % वृद्धि)	8
		4.1 साल के दौरान पैनल में शामिल किए गए प्राइवेट अस्पतालों की कुल संख्या	1,000			
	5. पुष्ट धोखाधड़ी के दावों का पता लगाना	5.1 कुल प्रस्तुत किए गए दावों के मुकाबले पुष्ट धोखाधड़ी दावों की प्रतिशत	1	5. उपचार की गुणवत्ता	5.1 अस्पताल में भर्ती होने वालों की तुलना में दोबारा भर्ती होने वालों की संख्या (डिस्चार्ज के तीस दिनों के भीतर अस्पताल में भर्ती होना).[176]	7

3. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	**निर्गम 2026-27**			**परिणाम 2026-27**		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
1,725	**क. सरकारी मेडिकल कॉलेजों (यूजी सीटों) और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना**					
	1. सरकारी मेडिकल कॉलेजों (यूजी सीटों)	1.1. एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए मंज़ूर मेडिकल	10	1. डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना	1.1. बढ़ाई गई एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या।	500

[176] *कुल अस्पताल में भर्ती होने वालों में से 7% से कम (कुल मिलाकर)*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	और केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना	कॉलेजों की संख्या				
	ख. नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन)					
	1. नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन)	1.1. स्थापित मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या	5	1. मेडिकल सीटों की उपलब्धता बढ़ाना	1.1. योजना के तहत जोड़ी गई यूजी सीटों की संख्या	500
		1.2. आकांक्षी जिलों डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए गए मेडिकल कॉलेजों की संख्या।	2		1.2. आकांक्षी जिलों में योजना के तहत जोड़ी गई यूजी सीटों की संख्या	200
	ग. नए पीजी विषय शुरू करने और पीजी सीटें बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों को मज़बूत और उनका उन्नयन करना					
	1. नए पीजी विषय शुरू करने और पीजी सीटें बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन (फेज़-III)	1.1. पीजी सीटें बढ़ाने के लिए मंज़ूर मेडिकल कॉलेजों की संख्या	30	1. विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना	1.1. अनुमोदित पीजी सीटों की संख्या	1,000
	घ. नर्सिंग शिक्षा में वृद्धि करने की केंद्र प्रयोजित योजना - मेडिकल कॉलेजों के साथ नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना।					
	1. मेडिकल कॉलेजों के साथ नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना	1.1. स्थापित नर्सिंग कॉलेजों की कुल संख्या	5	1. नर्सिंग सीटों की उपलब्धता बढ़ाना	1.1. योजना के अंतर्गत जोड़ी गयी यूजी सीटों की संख्या	400

4. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम) (सीएस+सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
4,770[177]	**क. एबीएचआईएम-एनएचएम**					
	1. 10 उच्च फोकस वाले राज्यों, अर्थात् बिहार, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और मेघालय के ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए बुनियादी सहायता	1.1 ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना सहायता के तहत बनाए गए उपस्वास्थ्य केंद्रों की संख्या	2,500	1. महामारी की तैयारी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना	1.1 11 उच्च फोकस के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत बीपीएचयू[178] की संख्या	225
					1.2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील आईपीएचएल.[179] की संख्या	150
					1.3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील सीसीबी.[180] की संख्या	50
	2. शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राथमिक देखभाल सेवाओं का विस्तारित दायरा	2.1 शहरी क्षेत्रों में - आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (शहरी-एएएम) की संख्या	3,200			

[177] *सीएसः570, सीएसएसः4200*

[178] *ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई*

[179] *एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला*

[180] *क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	3. जिला और ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना	3.1 11 उच्च फोकस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्मित ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिटों की संख्या	750			
		3.2 योजना के तहत निर्मित एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की संख्या	300			
		3.3 योजना के तहत बनाए गए क्रिटिकल केयर ब्लॉक (यूजी) की संख्या	90			
	ख. एबीएचआईएम-एनसीडीसी					
	1. बीएसएल-3 प्रयोगशालाओं की स्थापना	1.1 बीएसएल-3[181] लैब के लिए सभी जगहों की पहचान	7	1. प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण	1.1 उन लैब्स की संख्या जिनके लिए सेटअप करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है	7
		1.2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	7			
		1.3 कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान	7	2. पूर्व परियोजना गतिविधियों को पूरा करना	2.1 प्रशिक्षण स्थलों की संख्या के संदर्भ में बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी में हितधारकों की क्षमता निर्माण संख्या	10
		1.4 आयोजित बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी ट्रेनिंग	1			
	2. एनसीडीसी को मजबूत और अपग्रेड करना	2.1 उन प्रभागों की संख्या जिन्होंने उपकरण खरीदे हैं	2	3. नए संक्रमण के फैलने और उनकी निगरानी	3.1 एनसीडीसी द्वारा जांचे गए/समर्थित प्रकोपों की संख्या	10

[181] *बीएसएल-जैव सुरक्षा स्तर*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		और कौशल-सुधार आधारित प्रशिक्षण संचालित किए हैं।		के लिए बेहतर स्किल सेट		
		2.2 एपिडेमियोलॉजी सर्विलांस में एनसीडीसी[182] स्टाफ के लिए आयोजित प्रशिक्षण की संख्या	2		3.2 एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ इवेंट की निगरानी में उन्नत स्किल सेट वाले एचआर की संख्या	250
					3.3 बीमारियों/संक्रमण/स्वास्थ्य से जुड़ी घटनाओं की संख्या जिनके लिए जांच बढ़ाई गई	1
	3. क्षेत्रीय एनसीडीसी की स्थापना	3.1 उन राज्य शाखाओं की संख्या जिनके लिए स्थल को अंतिम रूप दिया गया है।	1	4. परियोजना - पूर्व गतिविधियों को पूरा करना	4.1 क्षेत्रीय एनसीडीसी की संख्या जहां वित्त वर्ष में निर्माण गतिविधियां शुरू की गई हैं	2
		3.2 रीजनल एनसीडीसी की साइटों पर एचआर और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों का मूल्यांकन पूरा करना	2		4.2 प्रकाशित रिपोर्टों की संख्या	6
	4. मेट्रोपॉलिटन पीएच निगरानी इकाई	4.1 स्थापित निष्पादन परफॉर्मेंस बेंचमार्क को पूरा करने वाली मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिटों (एमएसयू) की संख्या	20	5. कार्यात्मक महानगरीय पीएच निगरानी इकाई	5.1 मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट्स से आईडीएसपी[183]-आईएचआईपी[184] पर रिपोर्टिंग प्रतिशत	100

[182] *एनसीडीसी - राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र*

[183] *आईडीएसपी - एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम*

[184] *आईएचआईपी - एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	5. राज्यों में एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना	5.1 मानव संसाधन भर्ती (भर्ती/स्थानांतरण)	10	6. एनसीडीसी शाखाओं का संचालन।	6.1 महामारी विज्ञान और प्रयोगशाला में प्रशिक्षण आयोजित करने वाली शाखाओं की संख्या।	8
		5.2 उपकरणों की खरीद और स्थापन।	10			
		5.3 जनशक्ति का प्रशिक्षण - महामारी विज्ञान, निगरानी, प्रकोप जांच और प्रयोगशाला	14			
	6. आईएचआईपी का विस्तार	6.1 सार्वजनिक क्षेत्र के आरयू और निजी क्षेत्र के अस्पतालों से उन्नत रिपोर्टिंग (क) सार्वजनिक क्षेत्र के रिपोर्टिंग रियल टाइम डाटा से आईएचआईपी के माध्यम से आईडीएसपी निगरानी यूनिट (प्रतिशत में)।	75	7. आईएचआईपी का विस्तार	7.1 2026-27 के लिए आईएचआईपी लक्ष्य के अनुसार (क) पी फॉर्म की रिपोर्टिंग प्रतिशतता	84
		6.2 सार्वजनिक क्षेत्र के आरयू एवं निजी क्षेत्र के अस्पतालों से उन्नत रिपोर्टिंग (ख) आईएचआईपी के माध्यम से रियल टाइम डाटा की रिपोर्टिंग करने वाले चिह्नित निजी क्षेत्र के अस्पताल (प्रतिशत में)।	40		7.2 2026-27 के लिए आईएचआईपी लक्ष्य के अनुसार (ख) एल फॉर्म की रिपोर्टिंग प्रतिशतता	85
	ग. एबीएचआईएम- आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ					

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	1. सहयोग, हित और मैत्री (भीष्म) क्यूब के लिए भारत स्वास्थ्य पहल के माध्यम से आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता को बढ़ाना	1.1 उन चिह्नित एम्स/आईएनआई की संख्या जहां भीष्म क्यूब्स डिलीवर किए गए, जिन्होंने भीष्म क्यूब के डिप्लॉयमेंट के लिए संस्थान विशिष्ट एसओपी तैयार किए हैं।	15	1. आपदाओं और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सपोर्ट को मज़बूत करना	1.1 तैयार एसओपी (नंबर) के आधार पर, आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया के अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी मॉक-ड्रिल करना।	5

5. राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
3,477	1. एचआईवी के लिए परीक्षण	1.1 कुल आबादी में एचआईवी जांच (लाख में)	650	1. एआरटी और वायरल रूप से दबा हुआ	1.1. पीएलएचआईवी का प्रतिशत, जो एआरटी पर हैं और	95

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	2. एआरटी[185] पर एचआईवी से पीड़ित लोग (पीएलएचआईवी)	2.1 एआरटी पर पीएलएचआईवी की संख्या (संचयी)[186] (लाख में)	20.50	पीएलएचआईवी	वायरल रूप से दबा हुआ है	
	3. एआरटी पर पीएलएचआईवी के बीच वायरल भार की जांच	3.1 पीएलएचआईवी में एआरटी पर किए गए वायरल भार परीक्षण की संख्या (लाख में)	18.50			

6. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
2,005	1. एम्स और एम्स जैसे संस्थानों तक पहुंच में	1.1. कुल बिस्तरों की संख्या (20 एम्स में)	15,700	1. बेहतर विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा और	1.1. नए एम्स में आईपीडी मरीज़ (हर साल)	7,00,000

[185] *एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी)*

[186] *निजी क्षेत्र सहित*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	वृद्धि	1.2. स्पेशलिटी विभागों की कुल संख्या	625	चिकित्सा शिक्षा	1.2. नए एम्स में ओपीडी केस (हर साल)	1,40,00,000
		1.3. स्नातक (एमबीबीएस) सीटों की संख्या (20 एम्स में)	2,300		1.3. मेडिकल स्नातक की संख्या (एक साल में एम्स से ग्रेजुएट होने वाले)	2,250
		1.4. पीजी सीटों की संख्या-एमडी/एमएस/आदि (18 एम्स में)[187]	1,700			
		1.5. पीजी सीटों की संख्या-सुपर-स्पेशियलिटी (डीएम/एमसीएच/आदि) (18 एम्स में)	550			
		1.6. नर्सिंग (बी.एससी.) सीटों की संख्या	1,200			
		1.7. नर्सिंग (एम.एससी.) की संख्या	230			
		1.8. रिक्त पदों को भरना (संकाय) (31.12.2025 तक खाली पदों का 10%)	200			
		1.9. रिक्त पदों को भरना (गैर-संकाय) [188] (31.12.2025 तक खाली पदों का 10%)	1,500			

[187] क्रमांक 1.4 और 1.5 पर आउटपुट में दिए गए संकेतक, अर्थात् 'प्रशिक्षित स्नातकोत्तर सीटों की संख्या' को 13.11.2025 को आयोजित ओओएमएफ समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन में अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	2. सस्ती/भरोसेमंद विशिष्ट परिचर्या और चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता	2.1 जीएससी.[189] में बनाए गए सुपर स्पेशियलिटी विभाग की संख्या: 75 सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी	500			
		2.2 सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी बेड की कुल संख्या (लगभग 75 सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में अस्पताल बेड)	17,500			
	3. चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान में वृद्धि	3.1 प्रकाशित हुए शोधपत्रों की संख्या	3,500			

[188] उत्पादन में क्रमांक 1.7, 1.8 और 1.9 पर नए संकेतक 13.11.2025 को आयोजित ओओएमएफ समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन में जोड़े गए हैं।

[189] जीएमसी - सरकारी मेडिकल कॉलेज/संस्थान

7. परिवार कल्याण योजना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
643.46	**क. मुक्त आपूर्ति और सामाजिक विपणन योजना के अंतर्गत एफपी वस्तुओं की आपूर्ति**[190]					
	1. परिवार नियोजन की अधूरी आवश्यकता	1.1. परिवार नियोजन की अधूरी आवश्यकता का प्रतिशत (15-49 वर्ष की महिलाएं)	10	1. 15-49 वर्ष की विवाहित महिलाओं (एमडब्ल्यूआरए प्रजनन आयु की विवाहित महिलाएं) के बीच आधुनिक परिवार नियोजन विधियों का उपयोग[191]	1.1. आधुनिक गर्भनिरोधक विधियों से मांगपूर्ति का प्रतिशत[192]	75
	ख. स्वस्थ नागरिक अभियान (एसएनए)					
	1. आईईसी अभियानों/आयोजनों /आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	1.1. चलाए गए वास्तविक अभियानों की संख्या	160[193]	1. आईईसी के परिणाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों/कार्यक्रमों के परिणामों में परिलक्षित होते हैं।	1.1. जागरूकता स्तर और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में वृद्धि	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[194]
	ग. जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पीआरसी)					
	1. पीआरसी द्वारा पूर्ण किए गए शोध अध्ययनों की संख्या	1.1. पीआरसी द्वारा पूर्ण किए गए शोध अध्ययनों की संख्या	55	1. शोध अध्ययनों का प्रसार एवं चयनित अध्ययनों का प्रकाशन	1.1. प्रसार कार्यशाला का संचालन	1

[190] *पीपीआईयूसीडी स्वीकृति दर और मुक्त आपूर्ति एवं सामाजिक विपणन योजना के अंतर्गत एफपी की आपूर्ति को मुक्त आपूर्ति एवं सामाजिक विपणन योजना के अंतर्गत एफपी की आपूर्ति में समाहित कर लिया गया है।*

[191] *स्रोत:- एनएफएचएस, एमडब्लयूआरए- प्रजनन आयु वाली विवाहित महिलाएं*

[192] *आधुनिक पद्धति से पूर्ण होने वाली 75% विवाहित महिलाएं (15-49 वर्ष की आयु) का प्रतिशत*

[193] *वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान में एसएनए के लिए कम किए गए बजट और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ पीडी अपने स्वयं के बजट से आईईसी क्रियाकलापों के लिए व्यय कर रहे हैं, एसएनए डिवीजन द्वारा की जाने वाली क्रियाकलापों की संख्या को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 160 की तुलना में 100 रखा गया है।*

[194] *जागरूकता स्तर और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में वृद्धि*

1. ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग (सीएस) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026- 27			परिणाम 2026- 27		
2026- 27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
5,939.87	1. उन्नत ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) उत्पादों के क्षेत्रों में मज़बूत आपूर्ति शृंखला का निर्माण करना ।	1.1 चैंपियन मूल उपकरण निर्माता (ओईएम)[195] सेगमेंट के तहत अनुमोदित आवेदकों द्वारा प्राप्त डीवीए[196] प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या	40	1. ऑटोमोटिव क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियों का उभरना।	1.1 स्कीम के अंतर्गत शामिल अनुमोदित आवेदकों द्वारा की गई बिक्री में वृद्धि (करोड़ रुपये में)।	64,252
		1.2 कंपोनेंट चैंपियन सेगमेंट के तहत अनुमोदित आवेदकों द्वारा प्राप्त डीवीए प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या	15			
	2. ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग में घरेलू उत्पादन के लिए प्रोत्साहनों के माध्यम से उद्योगों को प्रोत्साहित करना	2.1 चैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता सेगमेंट के तहत अनुमोदित आवेदकों द्वारा किया जाने वाला संचयी निवेश (करोड़ रुपये में)।	3,744			
		2.2 कंपोनेंट चैंपियन सेगमेंट के अंतर्गत अनुमोदित आवेदकों द्वारा किया जाने वाला संचयी निवेश (करोड़ रुपये में)।	2,392			
		2.3 वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक स्कीम के तहत संवितरित किया जाने वाला कुल प्रोत्साहन (करोड़ रुपये में)।	5,922			

[195] *मूल उपकरण निर्माता*

[196] *घरेलू मूल्यवर्धन*

2. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (ड्राइव-पीएम ई)स्कीम (सीएस)

वित्तीय व्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
1,500	1. मांग प्रोत्साहन के माध्यम से एक्सईवी[197] को आसानी से अपनाने को बढ़ावा दें।	1.1 वर्ष में तैनात की गई इलेक्ट्रिक बसों की संख्या।	1,635	1. इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में वृद्धि	1.1 वर्ष में बेचे गए कुल नए वाहनों में एक्सईवी का %	8.5
		1.2 मांग प्रोत्साहन के माध्यम से वर्ष में समर्थित इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसों की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[198]			
		1.3 मांग प्रोत्साहन के माध्यम से वर्ष में समर्थित इलेक्ट्रिक ट्रकों और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या।	1,799			
	2. दस लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों, राज्य की राजधानियों, नामित स्मार्ट शहरों और राजमार्गों में चार्जिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित करना।	2.1 चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने पर खर्च की गई राशि।(करोड़ रुपये में)	655	2. उत्सर्जन कम करना और ईंधन की बचत करना	2.1 वाहनों की प्रयोग अवधि तक कुल बचाए गए ईंधन की मात्रा (बिलियन लीटर में)	592.16
					2.2 वाहन की प्रयोग अवधि तक उत्सर्जन में कुल कमी	0.47

[197] *इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) (हाइब्रिड सहित)*

[198] *दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद सुनिश्चित की जानी है।*

वित्तीय व्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	3. परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन	3.1 आईसीएटी, एनएटीआरएएक्स, जीएआरसी और एआरएआई[199] के उन्नयन पर खर्च की गई राशि (करोड़ रुपये में)	573.64		(मिलियन टन CO_2 में)।	

[199] आईसीएटी अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र है, एनएटीआरएएक्स राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण ट्रैक है, जीएआरसी वैश्विक ऑटोमोटिव अनुसंधान केंद्र है और एआरएआई भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ है।

1. स्वतंत्रता सेनानी (पेंशन और अन्य लाभ) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
589.97	1. स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के लिए धन का समय पर वितरण।	1.1. मुख्य स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद पेंशन स्वीकृत करने के लिए औसत दिनों की संख्या।	0[200]	1. स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए बढ़ी हुई आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा।	1.1. स्वतंत्रता सेनानी लाभार्थियों की संख्या	1,937
					1.2. विधवा लाभार्थियों की संख्या	9,685
					1.3. अविवाहित पुत्री लाभार्थियों की संख्या।	1,447
	2. सभी सत्यापित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को गैर-मौद्रिक कल्याणकारी लाभों का प्रावधान	2.1 वार्षिक आधार पर जारी/नवीनीकृत किए गए रेलवे पास) एसी -II/III) की संख्या।	662		1.4. पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु सफलतापूर्वक हस्तांतरित पात्र अविवाहित/बेरोजगार पुत्रियों का %	1,447

[200] *संवितरण में कोई देरी नहीं क्योंकि बैंकों द्वारा पेंशन वितरित की जाती है*

पुलिस विभाग

1. पुलिस अवसरंचना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
5,393.37	**क. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निर्माण परियोजनाएं (सीएपीएफ)**					
	1. सीएपीएफ के लिए सुरक्षा, प्रशासनिक बुनियादी ढांचे और अस्पतालों का प्रावधान प्रदान करना	1.1. निर्मित बैरकों की संख्या	213	1. निर्मित अवसंरचना का प्रचालन	1.1. बैरकों में ठहराए गए सीएपीएफ कर्मियों की औसत संख्या	13,861
		1.2. निर्मित कार्यालय भवनों की संख्या	345		1.2. परिचालित किए गए कार्यालय भवनों की संख्या	257
		1.3. योजना के तहत परिचालित अस्पतालों की संख्या	31		1.3. अस्पताल की अधिभोग दर (%)[201]	620
					1.4. आईपीडी (अंतःरोगी विभाग) में रोगियों की संख्या)	2,207
					1.5. असम राइफल्स (एआर) के संबंध में वर्तमान वित्त वर्ष में अस्पतालों में डॉक्टर-रोगी अनुपात	1:150
					1.6. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ) को संबंध में वर्तमान वित्त वर्ष	1:999

[201] *कुल रोगियों की संख्या/कुल बिस्तरों की संख्या*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
					में अस्पतालों में डॉक्टर-रोगी अनुपात	
					1.7. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के संबंध में (सी.आर.पी.एफ) वर्तमान वित्त वर्ष में अस्पतालों में डॉक्टर-रोगी अनुपात	3:117
					1.8. सशस्त्र सुरक्षा बल के संबंध में (एस. एस. बी.) वर्तमान वित्त वर्ष में अस्पतालों में डॉक्टर-रोगी अनुपात	1:560
					1.9. सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) के संबंध में वर्तमान वित्त वर्ष में अस्पतालों में डॉक्टर-रोगी अनुपात	2:760
					1.10. भारत तिब्बत सीमा पुलिस के संबंध में (आई.टी.बी.पी.) वर्तमान वित्त वर्ष में अस्पतालों में डॉक्टर-रोगी अनुपात	1:840
					1.11. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी.) वर्तमान वित्त वर्ष में अस्पतालों में	1:320

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
					डॉक्टर-रोगी अनुपात	
	2. सीएपीएफ के लिए आवासीय भवनों का प्रावधान प्रदान करना	2.1 निर्मित मकानों की संख्या	6,239	2. आवासीय भवनों का परिचालन	2.1 आवासों और क्वार्टरों में रहने वाले सीएपीएफ कर्मियों की संख्या	6,239
	ख. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो					
	1. प्रशिक्षण के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे का प्रावधान प्रदान करना	1.1. केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई), चंडीगढ़ का पुनर्वास एवं अवसंरचना विकास की पूर्णता प्रतिशत	100	1. पुलिसकर्मियों की क्षमता में वृद्धि करना	1.1. उन पुलिस कर्मियों की संख्या जिनके कौशल का उन्नयन किया गया है	2,000
	2. पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण	2.1 पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	70			
	ग.नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो					
	1. कार्यालय परिसर का प्रावधान प्रदान करना। (i) दिल्ली, (ii) रायपुर, (iii) भोपाल, (iv) देहरादून, (v) बेंगलुरु.	1.1. निर्मित नए कार्यालय भवनों की संख्या.[202]	5	1. कार्यालय-सह-आवासीय परिसरों और कार्यालय परिसरों का संचालन	1.1. कार्यालय-सह आवासीय परिसर की अधिभोग दर (%) (संचयी)	100

[202] *2014 को रिपोर्ट के लिए आधार वर्ष माना जाता है। (i) जम्मू में कार्यालय परिसर सहित वर्ष 2025 तक पूर्ण किए गए चार कार्यालय परिसरों का निर्माण कार्य। (वर्ष 2025 में रेडीमेड भवन खरीदा गया)। (ii) दिल्ली में कार्यालय परिसर का निर्माण चल रहा है और रायपुर, भोपाल, देहरादून और बैंगलोर में कार्यालय परिसरों के निर्माण की शुरुआत वर्ष 2026-27 में होने की संभावना है।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	2. कार्यालय सह आवासीय परिसर का प्रावधान प्रदान करना (i) लखनऊ (ii) इंफाल (iii) गोरखपुर (iv) पटना	2.1 निर्माण किए गए भवन (कार्यालय सह-आवासीय परिसर) की संख्या[203]	5		1.2. निर्मित कार्यालय भवनों की अधिभोग दर (%) (संचयी)	100
					1.3. अंचल कार्यालयों की कुल संख्या के मुकाबले परिचालन वाले अंचल कार्यालयों का %	33
	घ.पुलिस अवसरंचना : दिल्ली पुलिस[204]					
	1. स्वयं के कार्यालय भवनों और रखरखाव का प्रावधान सुनिश्चित करना।	1.1. निर्माणाधीन कार्यालय भवनों की संख्या।	29	1. पुलिस स्टेशन का अपना भवन है	1.1. परिचालित किए गए कार्यालय भवनों की संख्या।	29
	2. आवासीय अवसंरचना का प्रावधान सुनिश्चित करना	2.1 निर्माणाधीन[205] स्टाफ क्वार्टरों की संख्या	372	2. आवास संतुष्टि स्तर में सुधार किया गया है।	2.1 अधिग्रहित स्टाफ क्वार्टरों की संख्या	372

*[203] 2015 को रिपोर्ट के लिए आधार वर्ष माना जाता है। (i) 2025 तक 05 कार्यालय परिसर पूरे किए गए। (ii) लखनऊ, इम्फाल, गोरखपुर और पटना में कार्यालय सह आवासीय परिसर का निर्माण वर्ष 2026-27 से शुरू होने की संभावना है। (i) कार्यालय-सह-आवासीय परिसर की संख्या/कार्यालय-सह आवासीय परिसर की संख्या का निर्माण -5/5=100% (ii) कब्जे वाले कार्यालय परिसरों की संख्या/कार्यालय परिसर की संख्या का निर्माण -5/5(01 तैयार कार्यालय भवन खरीदा) =100% (iii) अंचल कार्यालयों की कुल संख्या के मुकाबले स्वयं के भवनों से परिचालन करने वाले अंचल कार्यालयों का प्रतिशत 33% है जो 2026-27 तक ओसी के निर्माण (और खरीदे गए रेडीमेड भवन) पर आधारित है (iv) उदाहरण- 30 क्षेत्र 10 कार्यालय परिचालन = (10/30*100)=33%*

[204] 3 पुलिस स्टेशन, पिछले वर्ष 2025-26 से 1 पुलिस पोस्ट को 2026-27 के लिए आगे बढ़ाया गया है। पीपी और पीएस के लिए नए प्रतिबंध जारी किए गए हैं और इन्हें वर्ष 2026-27 में शामिल किया गया है।

[205] पिछले वर्ष 2025-26 से 155 192 स्टाफ क्वार्टरों को 2026-27 के लिए आगे बढ़ाया गया है। नए 180 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए प्रतिबंध जारी किए गए हैं और 2026-27 में शामिल किए गए हैं। निर्माण के लिए 01 महिला छात्रावास जारी किया गया है और 2026-27 में शामिल किया गया है।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		2.2 निर्माणाधीन महिला छात्रावासों की संख्या।	1[206]		2.2 छात्रावास में रहने वाली महिलाओं का %	0
	ङ. मादक द्रव्य नियंत्रण के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता[207]					
	1. राज्य के मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) को मजबूत करना	1.1. खरीदे गए ड्रोन सहित निगरानी उपकरणों की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते	1. बेहतर निगरानी हेतु राज्यों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना।	1.1. दर्ज मामलों के सापेक्ष उन मामलों का % जिनमें आरोप पत्र दाखिल किया गया है।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
		1.2. मौके पर परीक्षण हेतु खरीदे गए रासायनिक-आधारित ड्रग टेस्टिंग किट की संख्या।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते	2. मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) की परिचालन दक्षता में सुधार	2.1 चालू वित्त वर्ष में अच्छी और गुणवत्तापूर्ण जब्ती के मामले।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
		1.3. प्रवर्तन के लिए खरीदे गए उपकरणों की संख्या जैसे आईटी उपकरण, कैमरा, सीसीटीवी, के9 आदि।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते	3. अवैध फसल के खेती को संवर्धित विनाश के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना	3.1. अवैध फसल खेती क्षेत्र के विनाश में वृद्धि	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
		1.4. खतरनाक सामग्री और जब्त दवाओं के विनाश के लिए खरीदे गए अन्य उपकरणों	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते	4. जप्त मादक पदार्थों की चोरी रोकने तथा उनके उचित भंडारण	4.1. ऐसे मामलों की संख्या जहां जब्त की गई दवाओं का निस्तारण किया गया है	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते

[206] *132 महिलाएं*

[207] *वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लक्ष्यों का मात्रात्मक विवरण पिछले वर्ष के मादक द्रव्य नियंत्रण हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता योजना के तहत राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध पर आधारित है। इस मैट्रिक्स के तहत वास्तविक उपलब्धियां वर्तमान वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त वास्तविक प्रस्तावों के अधीन हैं।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		की संख्या		एवं निस्तारण को सुनिश्चित करना		
		1.5. प्रत्येक जिले या प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अत्याधुनिक मालखाना / ई-मालखानों की स्थापना।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते	5. जिलों में मालखानों की स्थापना के परिणामों का आकलन करना।	5.1. मालखाने में जब्त दवाओं की मात्रा	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
	2. राज्यों को सहायता प्रदान करके गैर प्रवर्तन गतिविधियों के लिए राज्य क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण।	2.1 अवैध फसल की खेती के विनाश के लिए उपकरण/मशीनरी की खरीद।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते	6. वैकल्पिक आजीविका प्रदान करके किसानों को अवैध फसल की खेती से दूर करना	6.1 अवैध फसल की खेती का नष्ट किया गया क्षेत्र	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
					6.2 मौजूदा वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अवैध फसल की खेती वाले क्षेत्रों में कमी की सीमा।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते

2. अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
550	1. आईसीजेएस 2.0 का रोलआउट	1.1 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां आईसीएसजेएस 2.0 शुरू किया गया है।	10	1. मामलों के समय पर निपटान के लिए जांच में सहायता करना	1.1 राष्ट्रीय डेटाबेस पर की गई खोजों की संख्या (करोड़ में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
	2. आईसीजेएस दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन।	2.1 उन राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां हार्डवेयर खरीदा गया है।	15			

3. महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
889.05	**क. फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए योजना**					
	1. सभी जिलों में मोबाइल फोरेंसिक वैन (एमएफवी) की तैनाती	1.1 तैनात एमएफवी की संख्या	370	1. अपराध स्थल का समय पर दौरा	1.1 निरीक्षण किए गए अपराध स्थल की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
	2. फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार।	2.1 राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित ऑफ-कैंपस की संख्या	1	2. फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति का निर्माण।	2.1 राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) से स्नातक होने वाले छात्रों की संख्या	1,405
					2.2 एनएफएसयू में शिक्षक-छात्र अनुपात	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[208]
	ख. आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसए)					
	1. सभी जिलों में एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली का कवरेज	1.1 ईआरएसएस पहुँच वाले जिलों की संख्या।[209]	17	1. कुशल सेवा वितरण[210]	1.1 कार्रवाई योग्य कॉल[211] का %	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
					1.2 औसत प्रतिक्रिया समय	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते

[208] यह संकेतक प्रकृति में परिवर्तनशील है जो कुल स्वीकृत पदों और किसी विशेष समय पर पद पर शिक्षकों की संख्या पर निर्भर करता है। इसलिए लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। दिए गए समय पर वास्तविक अनुपात प्रदान किया जा सकता है।

[209] छत्तीसगढ़ के 33 में से 17 जिलों को छोड़कर भारत के सभी जिलों में 157 ईआरएसएस उपलब्ध है।

[210] प्राप्त कॉलों की संख्या की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, इसलिए वार्षिक लक्ष्य भी नहीं दिया जा सकता है, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का अपना प्रतिक्रिया समय होता है, इस प्रकार केवल अखिल भारतीय के लिए औसत दिया जाता है।

*[211] कार्रवाई योग्य कॉल का 159% = कुल कार्रवाई योग्य कॉल की संख्या * 100/कुल प्राप्त कॉल की संख्या*

1. एमआरटीएस (मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) और मेट्रो परियोजनाएं (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
30,940	1. नई मेट्रो लाइनों का निर्माण	1.1 वित्त वर्ष 2026-27 में चालू की गई नई मेट्रो लाइनों की लंबाई (किमी में)।	112	1. सिटी के शहरी इलाकों में बेहतर गतिशीलता	1.1 नई मेट्रो लाइनों के चालू होने से दैनिक यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी (लाख)	12
	2. रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) लाइन का निर्माण।	2.1 वित्त वर्ष 2026-27 में चालू की गई नई आरआरटीएस लाइनों की संख्या (किमी में)।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते	2. इससे दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीड़भाड़ और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी	2.1 चालू की गई नई आरआरटीएस लाइनों पर औसत दैनिक यात्री संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[212]
	3. मेट्रो और नॉन-मेट्रो परियोजनाओं के लिए शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता विकास	3.1 परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के लिए परिवहन योजना हेतु आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण सत्रों की संख्या	15	3. उन्नत प्रशिक्षित क्षमता (मानव)	3.1 प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	500

[212] दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर का बचा हुआ हिस्सा वित्त वर्ष 2025-26 में ही चालू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, प्रस्तावित नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर, अर्थात दिल्ली-गुरुग्राम-बावल और दिल्ली-पानीपत-करनाल, अभी मूल्यांकन चरण में हैं। इन्हें अनुमोदन मिलने के बाद, ये कॉरिडोर 5-6 वर्षों में चालू हो जाएंगे।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-यू) 2.0 (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)		निर्गम 2026-27		परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
21,625.05	**क. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-यू -2.0) (अन्य घटक) - लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) और किराए पर किफायती आवास (एआरएच) (सीएसएस)**					
	1. लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)/ संवर्द्धन - शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस आवास की बेहतर आपूर्ति	1.1. वित्त वर्ष (बीएलसी) में बने ईडब्ल्यूएस आवासों की संख्या (लाख में)	5.00	1. पुनर्वास और रहने की सम्मानजनक स्थिति के कारण शहरी आबादी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जीवन स्तर में सुधार	1.1 आवास के साथ-साथ बुनियादी नागरिक सुविधाओं से सम्मानित जीवन जीने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या (लाख में)	29.25
	2. साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) - शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस आवास की बेहतर आपूर्ति	2.1 वित्त वर्ष में बने ईडब्ल्यूएस आवासों की संख्या (एएचपी) (लाख में)	1.50		1.2 सौंपी गई आवासीय इकाइयों की संख्या (एआरएच) (लाख में)	1.50
	3. विकसित किए गए किफायती किराया आवास (एआरएच)	3.1. वित्त वर्ष (एआरएच) में विकसित किराया आवास इकाइयों की संख्या लाख में	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए		1.3 सौंपी गई आवासीय इकाइयों की संख्या (एएचपी) (लाख में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)		निर्गम 2026-27		परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
			जा सकते.[213]			सकते.[214]
		3.2. मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली आवासों का उपयोग करते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित एआरएच की संख्या (लाख में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते.[215]		1.4 स्लमवासियों के लिए मंज़ूर आवासों की संख्या (लाख में)	1.00
		3.3. सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा विकसित एआरएच की संख्या (लाख में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए	2. शहरी गरीबों/प्रवासियों के लिए किराए के आवासों बेहतर की उपलब्धता	2.1 विकसित किराया आवासीय इकाइयों (एआरएचसी) के लिए कुल लाभार्थी (लाख में)	0.10

[213] एआरएच के मामले में कोई लक्ष्य नहीं दिखाया गया है, क्योंकि एआरएच के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा होने में लगभग 36 महीने लगते हैं। तदनुसार, एआरएच का लक्ष्य 2026-27 के बाद दिखाया जाएगा।

[214] एआरएच के मामले में कोई लक्ष्य नहीं दिखाया गया है, क्योंकि एआरएच के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा होने में लगभग 36 महीने लगते हैं। तदनुसार, एआरएच का लक्ष्य 2026-27 के बाद दिखाया जाएगा।

[215] एआरएच के मामले में कोई लक्ष्य नहीं दिखाया गया है, क्योंकि एआरएच के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा होने में लगभग 36 महीने लगते हैं। तदनुसार, एआरएच का लक्ष्य 2026-27 के बाद दिखाया जाएगा।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)		निर्गम 2026-27		परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
			जा सकते.[216]			
	ख. प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 ब्याज अनुवृत्ति योजना (आईएसएस) (सीएस)					
	1. गृह ऋण पाने के इच्छुक ईडब्ल्यूएस, निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और एमआईजी लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करना	1.1. ईडब्ल्यूएस, एलआईजी लाभार्थियों की संख्या (लाखों में)	3.6	1. शहरी लाभार्थियों (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी) को पर्याप्त भौतिक और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पानी, रसोई, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सेवाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य उनकी अपनी वाली आवास इकाइयां प्रदान करके सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करना है।	1.1. सौंपे गए आवासों की दर (%)	90
		1.2. मध्यम वर्ग (एमआईजी) लाभार्थियों की संख्या (लाखों में)	1.4			
		1.3. ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए वित्तीय वर्ष में कुल सब्सिडी की राशि (करोड़ रुपये में)	1,500		1.2. सौंपे गए आवास से लाभान्वित होने वाले लोगो की संख्या (लाख में संख्या)	22.50
		1.4. एमआईजी के लिए वित्तीय वर्ष में कुल सब्सिडी की राशि (करोड़ रुपये में)	600			

[216] *एआरएच के मामले में कोई लक्ष्य नहीं दिखाया गया है, क्योंकि एआरएच के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा होने में लगभग 36 महीने लगते हैं। तदनुसार, एआरएच का लक्ष्य 2026-27 के बाद दिखाया जाएगा।*

3. अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
8,000	1. शहरी परिवारों के लिए पानी के चालू नल कनेक्शन का प्रावधान	1.1. वित्त वर्ष में पानी के नए नल कनेक्शन/सर्विस[217] किए गए मौजूदा कनेक्शन वाले आवासों की संख्या (लाखों में)	30	1. सभी मिशन शहरों के घरेलू आवासों में पानी की आपूर्ति के लिए सार्वभौमिक कवरेज	1.1. शहरी क्षेत्रों में कितने % परिवारों को नल से पानी का कनेक्शन मिला है?	80[218]
	2. सीवेज शोधन क्षमता में सुधार, और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग क्षमता	2.1. वित्त वर्ष में अतिरिक्त सीवेज शोधन क्षमता स्थापित और प्रचालित (एमएलडी में)	400	2. मिशन शहरों में आवासों के लिए सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन तक बेहतर पहुंच।	2.1. सीवर कनेक्शन या सेप्टेज प्रबंधन प्रदान पाने वाले परिवारों का %[219]	60[220]
		2.2. वित्त वर्ष में अतिरिक्त अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण क्षमता स्थापित और प्रचालित (एमएलडी में)	150		2.2. वित्त वर्ष में रिसायकल पानी का उपयोग (एमएलडी में विकसित) किया गया	150
		2.3. वित्त वर्ष में आवासों को प्रदान किए गए नए घरेलू सीवरेज कनेक्शनों (लाख में)/ सर्विस किए गए मौजूदा कनेक्शनों की संख्या[221]	12			

[217] *मिशन का फोकस पानी की सुरक्षा, और मिशन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने/ठीक करने पर है, ताकि उन कनेक्शन को फिर से चालू किया जा सके जो वैसे इस्तेमाल में नहीं थे/बंद हो गए थे।*

[218] *सीडब्ल्यूबीपी में शहरों/राज्यों द्वारा प्रदान की गई आधार जनसंख्या के अनुसार*

[219] *इसमें एफएसटीपी/सह-उपचार आदि के अभाव में उचित निपटान सुविधाओं से नहीं जुड़े सेप्टिक टैंक सहित सेप्टिक टैंक वाले परिवार शामिल हैं*

[220] *अमृत शहरों में 2021 तक आधार जनसंख्या के अनुसार जो केवल शहरों द्वारा प्रदान की जाती है*

[221] *मिशन का फोकस पानी की सुरक्षा, और मिशन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने/ठीक करने पर है, ताकि उन कनेक्शन को फिर से चालू किया जा सके जो वैसे इस्तेमाल में नहीं थे/बंद हो गए थे।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	3. हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास	3.1. विकसित किए गए नए या बेहतर हरित क्षेत्रों/ पार्कों की संख्या	180[222]	3. मिशन शहरों में गुणवत्तापूर्ण हरित स्थानों तक पहुंच में वृद्धि	3.1. बेहतर हरित आवरण और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्थानों पार्कों का विकास (एकड़ में)	2,000
	4. जलाशयों का पुनरुद्धार	4.1 पुनरुद्धार किए गए जलाशयों की संख्या	250[223]	4. शहरों में बेहतर जल प्रबंधन और संरक्षण	4.1 वित्त वर्ष में पुनरुद्धार किए गए जलाशयों का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	4,000

4. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
2,500	1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण	1.1 वित्त वर्ष में बने कुल घरेलू शौचालयों की संख्या	50,000	1. सभी वैधानिक शहर खुले में शौच	1.1. वित्त वर्ष में ओडीएफ+ प्रमाणन वाले वैधानिक शहरों की संख्या (नए प्रमाणित	95[224,225]

[222] *पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या*

[223] *पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या*

[224] *ग्रामीण निकायों के शहरी नगर पालिकाओं में बदलने की वजह से, समय-समय पर पूरे देश में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए, ऐसी नगर पालिकाओं की संख्या का संकेत एसबीएम के तहत सही प्रगति को नहीं दिखाएगा, इसलिए, ऐसे शहरों का प्रतिशत पैरा नंबर 1.1, 5.1 और 5.2 में दिखाया गया था।*

[225] *ओडीएफ+, ओडीएफ++, वाटर+ और जीएफसी का प्रमाणन वर्ष में एक बार किया जाता है।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	2. सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण	2.1. वित्त वर्ष में निर्मित सामुदायिक शौचालय सीटों की कुल संख्या	5,000	से मुक्त (ओडीएफ) हो गए हैं	और साथ ही पुराने प्रमाणन की स्थिति बनाए रखने वाले) (%)	
		2.2. वित्त वर्ष में निर्मित सार्वजनिक शौचालय सीटों की कुल संख्या	10,000			
	3. घर-घर जाकर सूखा कचरा संग्रहण में सुधार	3.1. वित्त वर्ष में 100% डोर टू डोर कलेक्शन वाले वार्डों का % (%)	99	2. बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और प्रसंस्करण क्षमता	2.1. उत्पन्न कुल कचरे में से संसाधित कचरे का %	82
	4. कम्पोस्टिंग के माध्यम से गीले कचरे का प्रसंस्करण	4.1 खाद संयंत्रों की स्थापित क्षमता (टीपीडी)	3,000[226]		2.2. 3 स्टार जीएफसी (कचरा मुक्त शहर) प्रमाण पत्र वाले शहरों की संख्या (%)	10[227]
	5. बायो-मीथेनेशन के ज़रिए गीले कचरे का प्रसंस्करण	5.1 सीबीजी (संपीड़ित बायोगैस) संयंत्रों की स्थापित क्षमता (टीपीडी)	1,000[228]			
	6. सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ) के माध्यम से सूखे कचरे का प्रसंस्करण।	6.1 एमआरएफ की स्थापित क्षमता (टीपीडी)	4,500[229]			

[226] *राज्यों/यूएलबी द्वारा परियोजनाओं को पूरा किए जाने पर निर्भर।*

[227] *ओडीएफ+, ओडीएफ++, वाटर+ और जीएफसी का प्रमाणन वर्ष में एक बार किया जाता है।*

[228] *राज्यों/यूएलबी द्वारा परियोजनाओं को पूरा किए जाने पर निर्भर।*

[229] *राज्यों/यूएलबी द्वारा परियोजनाओं को पूरा किए जाने पर निर्भर।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	7. निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट प्रसंस्करण	7.1 154 शहरों में सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण की स्थापित क्षमता। (टीपीडी)	1,000[230]	3. भूमि की पुन: प्राप्ति	3.1 पुनः प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	2,000
	8. पुराने अपशिष्ट का उपचार	8.1 पुराने अपशिष्ट की मात्रा जिसका उपचार किया गया (एलएमटी)	500[231]	4. प्रयुक्त जल प्रबंधन में सुधार	4.1 वित्त वर्ष में जल+ प्रमाणन वाले सांविधिक शहरों की संख्या (नए प्रमाणित और साथ ही पुराने प्रमाणन को बनाए रखने वाले) (%)	15[232,233]
	9. सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी)/एसटीपी सह मल कीचड़ शोधन संयंत्रों (एफएसपी) का निर्माण	9.1 सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) सह मल कीचड़ शोधन संयंत्रों (एफएसटीपी) की निर्मित क्षमता (एमएलडी में)	500[234]		4.2 वित्त वर्ष में ओडीएफ++ प्रमाणन वाले वैधानिक शहरों की संख्या (नए प्रमाणित और साथ ही पुरानी प्रमाणन स्थिति को बनाए रखने वाले) (%)	55[235,236]

[230] राज्यों/यूएलबी द्वारा परियोजनाओं को पूरा किए जाने पर निर्भर।

[231] राज्यों/यूएलबी द्वारा परियोजनाओं को पूरा किए जाने पर निर्भर।

[232] ग्रामीण निकायों के शहरी नगर पालिकाओं में बदलने की वजह से, समय-समय पर पूरे देश में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए, ऐसी नगर पालिकाओं की संख्या का संकेत एसबीएम के तहत सही प्रगति को नहीं दिखाएगा, इसलिए, ऐसे शहरों का प्रतिशत पैरा नंबर 1.1, 5.1 और 5.2 में दिखाया गया था।

[233] ओडीएफ+, ओडीएफ++, वाटर+ और जीएफसी का प्रमाणन वर्ष में एक बार किया जाता है।

[234] राज्यों/यूएलबी द्वारा परियोजनाओं को पूरा किए जाने पर निर्भर।

[235] ग्रामीण निकायों के शहरी नगर पालिकाओं में बदलने की वजह से, समय-समय पर पूरे देश में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए, ऐसी नगर पालिकाओं की संख्या का संकेत एसबीएम के तहत सही प्रगति को नहीं दिखाएगा, इसलिए, ऐसे शहरों का प्रतिशत पैरा नंबर 1.1, 5.1 और 5.2 में दिखाया गया था।

[236] ओडीएफ+, ओडीएफ++, वाटर+ और जीएफसी का प्रमाणन वर्ष में एक बार किया जाता है।

5. आवासीय (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	**निर्गम 2026-27**			**परिणाम 2026-27**		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
1,150	1. सामान्य पूल आवास का निर्माण	1.1. वित्त वर्ष में स्वीकृत आवासीय इकाईयों की संख्या	1,514[237]	1. सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की बेहतर उपलब्धता	1.1 वित्त वर्ष में आवंटित और अधिकृत इकाईयों का %	100[238]
		1.2. वित्त वर्ष में पूरी हुई आवासीय परियोजनाओं की संख्या	2[239]		1.2 आवास की मांग में कमी पूरी होने का %	7.49[240]
		1.3. वित्त वर्ष में सौंपी गई आवासीय इकाईयों की संख्या	1,531[241]			

[237] *सीसीएस, अमरावती में जीपीआरए*

[238] *यह देखते हुए कि आवंटित सभी इकाईयां अधिकृत होंगी*

[239] *{1. जीआरपीए नया-रायपुर में 729 क्वार्टर (टाइप II - 180, टाइप III - 364, टाइप IV - 112, टाइप V - 68, टाइप VI - 5), दुकानें, घर, क्रेच/नर्सरी और डिस्पेंसरी का निर्माण। (ईपीसी आधार पर सभी विकास कार्य और वर्कस एवं बल्क सर्विसेज़ (सिविल और इलेक्ट्रिकल) शामिल हैं। 2. कस्तूरबा नगर फेज़-I, नई दिल्ली में पुनर्विकास परियोजना}*

[240] *गणना (1531/20436)* 100 = 7.49% (पिछले साल के दौरान आवासीय मांग = 21677 आवास, 25-26 के दौरान पूरी की गई मांग की कमी = 1241 आवास, 26-27 में मांग कमी = 20436 आवास*

[241] *(656+875) {1. जीआरपीए नया-रायपुर में 729 क्वार्टर (टाइप II - 180, टाइप III - 364, टाइप IV - 112, टाइप V - 68, टाइप VI - 5), दुकानें, घर, क्रेच/नर्सरी और डिस्पेंसरी का निर्माण। (ईपीसी आधार पर सभी विकास कार्य और वर्कस एवं बल्क सर्विसेज़ (सिविल और इलेक्ट्रिकल) शामिल हैं। 2. कस्तूरबा नगर फेज़-I, नई दिल्ली में पुनर्विकास परियोजना}*

6. गैर-आवासीय (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
4,000	1. सामान्य पूल आवास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण	1.1 वित्त वर्ष में स्वीकृत कार्यालय स्थान का क्षेत्र (स्कवायर मीटर में)	5,20,784[242]	1. केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों के लिए कार्यालय स्थल की बेहतर उपलब्धता	1.1 वित्त वर्ष में निर्मित कुल कार्यालय/गैर-आवासीय स्थानों में से स्थानांतरित कार्यालय/गैर-आवासीय क्षेत्र का %	100
		1.2 वित्त वर्ष में गैर आवासीय परियोजनाओं की संख्या	3[243]		1.2 कार्यालय परिसर की मांगी की कमी को पूरा किया गया (कुल मांग के % में)	80.21[244]
		1.3 वित्त वर्ष में केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों को दिए गए कार्यालय स्थल का क्षेत्र (स्कवायर मीटर में)	2,57,181[245]			

[242] *304752 सीसीएस 4 और 5, 216032 सीसीएस अमरावती*

[243] *(1. सीसीएस 6 और 7 नई दिल्ली, 2. सीसीएस -10- नई दिल्ली, 3. जीपीओए बिलासपुर)*

[244] *257181/320650)*100 = 80.21% (पिछले वर्ष मांग की कमी = 829650 वर्ग मीटर, 25-26 के दौरान पूरी की गई मांग = 509000 वर्ग मीटर, 26-27 के लिए कुल मांग की कमी = 320650 वर्ग मीटर*

[245] *(1. सीसीएस 6 और 7 - 2,01,585 वर्ग मीटर, 2. सीसीएस 10 - 53,200 वर्ग मीटर, 3. जीपीओए बिलासपुर - 2396 वर्ग मीटर)*

7. पीएम-ई-बस सेवा (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
500	1. सिटी बस सेवाओं में बढ़ोतरी	1.1 वित्त वर्ष में स्वीकृत् बसों की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[246]	1. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बसों की संख्या में बढ़ोतरी	1.1 वित्त वर्ष में चलाई गई बसों की कुल संख्या	1,500
	2. बिहाईंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास	2.1 बिहाइंड-द-मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की संख्या	40	2. इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए बिहाइंड-द-मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण	2.1 पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चालू किए गए डिपो की संख्या	27
	3. डिपो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास	3.1 सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की संख्या	40	3. इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण	3.1 सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चालू किए गए डिपो की संख्या	27

[246] *सभी 10,000 ई-बसों को वित्त वर्ष 2025-26 के क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में स्वीकृत किया जाएगा।*

8. पीएम-स्वनिधि- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
900	1. पथ विक्रेताओं (एसवी) के लिए कार्यशील पूंजी/वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना	1.1 संवितरित किए गए ऋणों की संख्या (लाख में)	20	1. पथ विक्रेताओं को शहरी अर्थव्यवस्था में स्थान देना	1.1 संवितरित ऋण की कुल राशि (करोड़ रुपए में)	4,300
		1.2 जारी किए गए क्रेडिट कार्ड की संख्या (लाख में)	3		1.2 पथ विक्रेताओं को दी गई क्रेडिट कार्ड लिमिट की राशि (करोड़ रुपये में)	300
	2. पथ विक्रेताओं के बीच डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना	2.1 डिजिटल रूप से सक्रिय विक्रेता की संख्या (लाख में)	8.4	2. पथ विक्रेताओं के बीच डिजिटल लेन-देन में बढ़ोतरी	2.1 डिजिटल रूप से सक्रिय पथ विक्रेताओं की प्रति माह डिजिटल लेन-देन की औसत संख्या	50
	3. स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत पथ विक्रेताओं के परिवार को कवरेज	3.1 सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग के तहत सर्वेक्षण किए गए पथ विक्रेताओं की संख्या (लाख में)	8.4	3. पथ विक्रेताओं के परिवारों दी गई सामाजिक सुरक्षा	3.1 स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत पात्र योजना आवेदन के संबंध में 3.1% योजना स्वीकृत की गई (%)	70

1. प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
509.24	1. प्रसारण अवसंरचना का डिजिटलीकरण आधुनिकीकरण और विस्तार	1.1 अपग्रेड किए जाने वाले/जोड़े जाने वाले मौजूदा प्रोडक्शन सेट-अप की संख्या (स्टूडियो, समाचार यूनिट और आउटस्टैंडिग ब्रॉडकास्टिंग (ओबी) वैन सहित)	73	1. उत्पादन और प्लेआउट सुविधाओं का सुदृढ़ीकरने/संवर्धन	1.1 सुदृढ़/नवीनीकृत की जाने वाली उत्पादन एवं प्लेआउट सुविधाओं का %	54.88
		1.2 अपग्रेड किए जाने वाले/जोड़े जाने वाले सैटेलाइट अपलिंक स्टेशनों की संख्या, अर्थ स्टेशन, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग (डीएसएनजी) यूनिटों और डीटीएच अर्थ स्टेशनों सहित)	15	2. डारेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्लेटफॉर्म की टीवी चैनल क्षमता में वृद्धि।	2.1 डारेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्लेटफॉर्म के टीवी चैनलों की संख्या में % वृद्धि।	89.83
		1.3 एचडी में अपग्रेड/स्थानांतरित किए जाने वाले मौजूदा उत्पादन/ट्रांसमिशन केंद्रों की संख्या	12	3. दर्शकों को वास्तविकता के साथ बेहतर दृश्य अनुभव प्रदान करना	3.1 एचडी कंटेंट (उत्पादन एवं प्रसारण) में अपग्रेड/स्थानांतरित किए जाने वाले केंद्रों की % वृद्धि	28.57
	2. रणनीतिक/राष्ट्रीय हित के क्षेत्रों सहित सार्वजनिक सेवा प्रसारण की पहुंच के विस्तार के लिए नए एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना	2.1 स्थापित किये जाने वाले एफएम ट्रांसमीटर की कुल संख्या (1 किलोवाट, 5 किलोवाट और 10 किलोवाट	30	4. पूरे भारत में कवरेज, सीमावर्ती क्षेत्रों और ग्रामीण आबादी पर विशेष जोर	4.1. जम्मू-कश्मीर और एलओसी सीमा सहित देश में एफएम स्थलीय प्रसारण के कवरेज क्षेत्र में % वृद्धि	3.80
		2.2 जम्मू कश्मीर और एलओसी सीमा पर लगाए जाने वाले 5 किलोवाट मोबाइल एफएम ट्रांसमीटर की कुल संख्या	5			
		2.3 पुणे, अहमदाबाद और राजकोट में 3 अतिरिक्त 10 किलोवाट एफएम ट्रासंमीटर और सलूम्बर (राजस्थान) में 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर की	4			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
		स्थापना				
	3. अतिरिक्त स्टूडियो सुविधा	3.1 कार्यक्रम वाले स्टूडियो की संख्या । उज्जैन स्टूडियों में स्टूडियों सुविधा । शिवमोग्गा में बहुउद्देशीय स्टूडियों की स्थापना।	2			
		3.2 68 स्थानों पर मल्टीपर्पस (एमपी) स्टूडियों के एनालॉग कंसोल को बदलना।	68			

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

1. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (सीएसएस)[247]

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
6,587.00[248]	क. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं (एआईबीपी)					
	1. वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विकास।	1.1 मौजूदा वित्तीय वर्ष में पूर्ण की जाने वाली एआईबीपी परियोजनाओं की संख्या	5	1. सिंचित क्षेत्र में वृद्धि।	1.1 अप्रैल 2016 से संचयी सिंचाई क्षमता सृजन (लाख हेक्टेयर में)	74.18
		1.2 अप्रैल 2016 से अब तक पूर्ण पूर्ण की जाने वाली एआईबीपी परियोजनाओं की संचयी संख्या	83			
		1.3 मौजूदा वित्तीय वर्ष में सिंचाई क्षमता का सृजन	1	2. अनुपालन द्वारा व्यवहार्यात्मक परिवर्तन	1.2 अप्रैल 2016 से अब तक सृजित सिंचाई क्षमता के मुकाबले उपयोग की गई संचयी सिंचाई क्षमता [249] (लाख हेक्टेयर में)	50

[247] यह एक व्यापक योजना है, जिसके अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी जैसी योजनाएं शामिल हैं।

[248] वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु में): एआईबीपी)- 2,250; हर खेत को पानी- 700

[249] परियोजनाओं के पूरा होने के बाद सिंचाई क्षमता उपयोग (आईपीयू) में वृद्धि होती है।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	ख. हर खेत को पानी[250]					
	1.1. सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं का विकास	1.1. मौजूदा वित्तीय वर्ष में पूर्ण की जाने वाली सतही लघु सिंचाई मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार परियोजनाओं की संख्या	100	1. कृषि उत्पादकता में वृद्धि।	1.1. अप्रैल 2016 से संचयी सिंचाई क्षमता सृजन (लाख हेक्टेयर में)	6.65
		1.2. अप्रैल 2016 से पूर्ण की जाने वाली सतही लघु सिंचाई मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार परियोजनाओं की संचयी संख्या	7,176			
		1.3. मौजूदा वित्तीय वर्ष में सिंचाई क्षमता सृजन (लाख हेक्टेयर में)	0.70		1.2. अप्रैल 2016 से अब तक सृजित सिंचाई क्षमता के मुकाबले उपयोग की गई संचयी सिंचाई क्षमता (लाख हेक्टेयर में)	6.65

[250] *सतही लघु सिंचाई-मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार*

2. राष्ट्रीय गंगा योजना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	**निर्गम 2026-27**			**परिणाम 2026-27**		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
3,100	1. गंगा नदी में सीधे सीवेज के निर्वहन को रोकना और सीवेज का उपचार करना।	1.1. स्थापित सीवेज उपचार क्षमता। (एमएलडी में)[251])	600	1. वर्ष 2027 तक निर्धारित स्नान मानकों को प्राप्त करने के लिए जल की गुणवत्ता में सुधार करना।	1.1. वार्षिक आधार पर जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) > 3 मिलीग्राम/लीटर दर्शाने वाले निगरानी केंद्रों का %[252]	<20
	2. गंगा नदी में औद्योगिक अपशिष्ट के सीधे निर्वहन को विनियमित करके प्रदूषण को कम करना।	2.1 निगरानी की गई अत्यधिक प्रदूषणकारी इकाइयों की संख्या।	4,000		1.2. वार्षिक आधार पर घुलित ऑक्सीजन (डीओ) < 5 मिलीग्राम/लीटर (% के संदर्भ में) दर्शाने वाले निगरानी केंद्रों का %[253]	<10
					1.3. अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का प्रतिशत अनुपालन (% में)	80

[251]प्रति दिन 10 लाख लीटर।

[252] यदि लगातार तीन महीनों तक बीओडी >3 मिलीग्राम/लीटर हो तो निगरानी स्टेशन को गैर-अनुरूप माना जाएगा और उसकी गणना की जाएगी

[253] निगरानी स्टेशन को गैर-अनुरूप माना जाएगा और लगातार तीन महीनों तक डीओ <5 मिलीग्राम/लीटर गिना जाएगा

3. नदियों को आपस में जोड़ना (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**नतीजा**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
1,906.07	1. केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन।	1.1. दौधन बांध के संबंध में भूमि अधिग्रहण का पूर्ण होने वाला संचयी[254] प्रतिशत।	100	1. कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) में वृद्धि करना, बिजली उत्पादन बढ़ाना और विभिन्न उपयोगों के लिए पानी उपलब्ध कराना।[255]	1.1. सिंचाई क्षमता का सृजन और उपयोग।[256] (लाख हेक्टेयर में)	0.20
		1.2. केबी लिंक नहर के लिए भूमि अधिग्रहण का संचयी प्रतिशत जो पूरा किया जाना है।	90		1.2. रोजगार सृजन (श्रम दिन)	7,00,000
		1.3. दाउधन बांध के सिविल कार्यों (बुनियादी अवसंरचना कार्यों सहित) की संचयी प्रगति (%)	30			
		1.4. लोअर ओर्र बांध, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स (एमपी) की संचयी प्रगति (%)	85			
		1.5. पैलानी बैराज, केन मुख्य नहर और तालाबों, बरियारपुर, पारीछा और बरुआ सागर (यूपी) के नवीकरण की संचयी प्रगति (%)	15			

[254] संचयी का तात्पर्य भूमि पर भौतिक कब्जे से है। भूमि अधिग्रहण (पीटीआर-6017 और 3239 हेक्टेयर भूमि के जलमग्न होने) के लिए अधिसूचना जारी की गई।

[255] परिणाम: परियोजना मार्च 2030 तक पूरी हो जाएगी। अत: परियोजना के कार्यान्वयन के बाद परिणाम प्राप्त होगा।

[256] परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद सिंचाई क्षमता सृजन और उपयोग में वृद्धि होगी। 2026-27 के दौरान: मध्य प्रदेश की द्वितीय चरण की परियोजनाओं से आईपीसी और आईपीयू की उम्मीद है।

4. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-गंगा बेसिन के अलावा (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	नतीजा	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
550	1. नदियों में प्रदूषण भार के प्रवेश को रोकने लिए सीवरेज अवसंरचना का निर्माण।	1.1. निर्मित सीवेज उपचार क्षमता। (एमएलडी में)[257])	158	1. नदी जल की गुणवत्ता में सुधार।	1.1. प्रदूषण के स्तर में कमी दर्शाने वाले चिन्हित प्रदूषित नदी खण्डो की संख्या।	4
		1.2. सीवर नेटवर्क बिछाया गया। (किलोमीटर में)	125		1.2. एसटीपी की क्षमता उपयोग में प्रतिशत वृद्धि (% में)[258]	5

5. बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	नतीजा	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
797	1. संकटग्रस्त क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, कटाव-रोधी, बाढ़ नियंत्रण और समुद्री कटाव-रोधी कार्यों का निष्पादन।	1.1. कुल संरक्षित क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)	0.12	1.1. संरक्षित क्षेत्र में कम नुकसान	1.1 इस कार्यकलाप से लाभान्वित कुल जनसंख्या (लाखों में)	3.07
		1.2. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले बाढ़ प्रबंधन कार्यों/परियोजनाओं की संख्या।	2			

[257] *मिलियन लीटर प्रति दिन*

[258] *सीवेज उपचार संयंत्रों का वर्तमान क्षमता उपयोगिता दर 66.22% है।*

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
7,192	1. प्रभावी एसएलडब्ल्यूएम[259]	1.1 वित्त वर्ष 2026-27 में एसडब्ल्यूएम[260] व्यवस्थाओं से कवर गांवों की संख्या	48,096	1. संपूर्ण स्वच्छता एवं दृश्य साफ-सफाई	1.1 खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल[261] के रूप में घोषित गांवों का %	15
		1.2 वित्त वर्ष 2026-27 में जीडब्ल्यूएम[262] व्यवस्थाओं से कवर गांवों की संख्या	36,119			
		1.3 पीडब्लूएमयू[263] से कवर ब्लॉकों की संख्या	1,352			
		1.4 एफएसएम[264] व्यवस्थाओं से कवर गांवों की संख्या	1,50,000			
	2. कचरे से धन सृजन पहल	2.1 कम से कम एक सामुदायिक आधारित गोबरधन परियोजना वाले जिलों की संख्या	50			

[259] *ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन*

[260] *ठोस कचरा प्रबंधन*

[261] *अंश - वित्त वर्ष 2026-27 में ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किए गए गाँवों की संख्या – _ संख्या हर - कुल गाँवों की संख्या – _ संख्या*

[262] *ग्रे-वाटर प्रबंधन*

[263] *प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ईकाईयों*

[264] *मलीय कचरा प्रबंधन*

2. जल जीवन मिशन (जेजेएम) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपएमें)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
67,670	1. परिसर के भीतर ग्रामीण परिवारों के लिए पेयजल सहायता हेतु सृजित स्थायी अवसंरचना	1.1 एचजीजे[265] संसूचित ग्राम पंचायतों की संख्या	1,70,000	1. जल आपूर्ति की बेहतर नियमितता और गुणवत्ता	1.1 संबंधित ग्राम पंचायत ग्रा. पं.[266] द्वारा जारी जल आपूर्ति अनुसूची के अनुसार नियमित जल की आपूर्ति करने वाले संसूचित और प्रमाणित हर घर जल ग्राम पंचायतों में गांवों का %	> 80
					1.2 संसूचित और प्रमाणित हर घर जल ग्राम पंचायतों में ऐसे गांवों का % जो कुल परिवारों के 90 % से अधिक परिवारों को पर्याप्त जल आपूर्ति की सूचना देते हैं ।	> 80
		1.2 एचजीजे प्रमाणित ग्राम पंचायतों की संख्या	1,30,000		1.3 प्रोटोकॉल के अनुसार परिवार स्तर पर परीक्षण के साथ संसूचित और प्रमाणित हर घर जल ग्राम पंचायतों में गांवों का % 2 एचएच नमूना/माह - एफआरसी[267] और टर्बिडिटी आं.वा. के.[268] और स्कूल - 1 नमूना/माह एफआरसी और टर्बिडिटी	> 90
					1.4 प्रोटोकॉल के अनुसार की गई उपचारात्मक कार्रवाई के साथ संसूचित और प्रमाणित हर घर जल ग्राम पंचायतों में गांवों का %	> 90

[265] *हर घर जल*

[266] *ग्राम पंचायत*

[267] *मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन*

[268] *मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन*

1. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (नई रोजगार सृजन योजना) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
20,082.70	1. वित्तीय सहायता के माध्यम से रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करना	1.1. ईपीएफओ में पहली बार आने वालों की संख्या	84,00,000	1. रोजगार सृजन में वृद्धि	1.1 भाग ए के लाभार्थियों की संख्या	63,00,000
		1.2. ईपीएफओ में दोबारा शामिल होने वालों की संख्या	1,44,00,000		1.2 भाग बी के लाभार्थियों की संख्या	1,50,00,000
		1.3. ईपीएफओ में शामिल नए प्रतिष्ठान	60,000			

2. कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
11,144	1. वित्तीय सहायता के माध्यम से रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करना	1.1. फेस ऑथंटिकेशन प्रौद्योगिकी (एफएटी) [269] के ज़रिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) प्रस्तुतीकरण का %	45	1. पेंशन वितरण की गति	1.1. हर महीने [270] की 3 तारीख तक मासिक पेंशन पाने वाले सक्रिय पेंशनभोगियों की संख्या का %	100
		1.2. वित्त वर्ष 2026-27 [271] में ईपीएस, 95 पेंशनर्स की संख्या में जोड़े गए नए पेंशनर्स की संख्या	3,15,000			

[269] वित्त वर्ष 2024-25 में 27% की उपलब्धि और एफएटी को बढ़ाने की कोशिशों को देखते हुए एफएटी के ज़रिए डीएलसी प्रस्तुतीकरण का 45% का लक्ष्य तय किया गया है। [अंश: एफएटी के ज़रिए डीएलसी के प्रस्तुतीकरण; हर: कुल डीएलसी प्रस्तुतीकरण]

[270] लक्ष्य पहले की समयसीमा में सुधार करना है जो महीने की 7 तारीख तक थी [अंश: 3 दिनों के भीतर पेंशन पाने वाले पेंशनरों की संख्या; हर: कुल सक्रिय पेंशनर]

[271] वित्त वर्ष 2024-25 के असल आंकड़ों के आधार पर, जो 2.99 लाख था, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3.15 लाख नए पेंशनर्स का लक्ष्य तय किया गया है। यह लक्ष्य सक्रिय दावा निपटान के ज़रिए पूरा किया जाएगा।

न्याय विभाग

1. ई-कोर्ट परियोजना चरण-III (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक[272]**	**लक्ष्य 2026-27**
1,200	1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपलब्ध ढांचे को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने का प्रावधान।	1.1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर वाले संस्थानों की संख्या	2,550	1. न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और पहुंच में सुधार करना।	1.1. पिछले वर्ष की तुलना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के ज़रिए होने वाली सुनवाई की संख्या में बदलाव[273] का %	51
	2. ई-सेवा केंद्रों की स्थापना	2.1. न्यायालय परिसरों में कार्यरत ई-सेवा केंद्रों की संख्या	1,467	2. डिजिटल विभाजन को पाटना, ई-फाइलिंग को सुविधाजनक बनाना	2.1 पिछले वर्ष की तुलना में कोर्ट केस की ई-फाइलिंग की संख्या में प्रतिशत बदलाव[274] का	4
	3. क्षमता निर्माण/परिवर्तन प्रबंधन	3.1 आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	91	3. डिजिटल कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं के प्रभावी उपयोग के लिए हितधारकों के बीच क्षमता और जागरूकता बढ़ाना।	3.1 पिछले वर्ष की तुलना में ई-कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप के डाउनलोड की संख्या में प्रतिशत बदलाव [275] का %	20

[272] सभी आउटकम इंडिकेटर्स के लिए डेटा डिवीजन में उपलब्ध नवीनतम डेटा के आधार पर 01 अप्रैल, 2026 तक कैलकुलेट किया जाएगा।

*[273] कैलकुलेशन: (चालू वर्ष में वीसी सुनवाई की संख्या - पिछले वर्ष में वीसी सुनवाई की संख्या) * 100 / पिछले वर्ष में वीसी सुनवाई की संख्या*

*[274]. कैलकुलेशन: (चालू वर्ष में ई-फाइलिंग की संख्या - पिछले वर्ष में ई-फाइलिंग की संख्या) * 100 / पिछले वर्ष में ई-फाइलिंग की संख्या*

*[275] कैलकुलेशन: (चालू वर्ष में ई-कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप डाउनलोड की संख्या - पिछले वर्ष में ई-कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप डाउनलोड की संख्या) * 100 / पिछले वर्ष में ई-कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप डाउनलोड की संख्या*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक[272]	लक्ष्य 2026-27
	4. अदालती रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण	4.1 डिजिटाइज़ किए गए पृष्ठों की संख्या (करोड़ में)	1,864.8	4. डेटा डिजिटल रूप में, कागज़ की बचत, कार्बन फुटप्रिंट में कमी।	4.1 पिछले साल की तुलना में जजमेंट और ऑर्डर सर्च पोर्टल पर अपलोड किए गए फैसलों की संख्या में बदलाव का %	2

2. न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाएं (सीएसएस)[276]

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27[277]	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
812	1. कोर्ट की इमारतों, आवासीय इकाइयों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों, डिजिटल कंप्यूटर	1.1 वित्तीय वर्ष में पूर्ण हुई आवासीय इकाइयों की संख्या	700	1. न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या (25,869) और उपलब्ध न्यायिक अवसंरचना के बीच के अंतर को कम करना।	1.1 स्वीकृत संख्या-25,869 और उपलब्ध कोर्ट हॉलों के बीच के अंतर में कमी [278] का %	20.12
		1.2 वित्तीय वर्ष में पूरे किए गए चालू कोर्ट हॉलों की संख्या	668		1.2 स्वीकृत संख्या-	11.19

[276] वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 5 ड्राफ्ट इंडिकेटर पिछले साल के लिए तय किए गए लक्ष्यों के अनुसार बनाए गए हैं।

[277] निर्भरता कारक: योजना के तहत फंड का वास्तविक आवंटन और राज्य सरकार/उच्च न्यायालयों द्वारा योजना का कार्यान्वयन।

*[278] वर्तमान में स्वीकृत संख्या (25,869) और उपलब्ध कोर्ट हॉल (22,550) के बीच लगभग 3319 का अंतर है। 668 कोर्ट हॉल से स्वीकृत संख्या और उपलब्ध कोर्ट हॉल के बीच के अंतर में लगभग 20.12% की कमी आएगी। गणना: - अंतर = स्वीकृत संख्या - कुल पूर्ण; अंतर में % कमी = (पिछले साल का अंतर - मौजूदा साल का अंतर) *100/ पिछले साल का अंतर*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27[277]	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	कमरों का निर्माण।	1.3 वित्तीय वर्ष में पूरे किए गए वकीलों के हॉल की संख्या	242		25,869 और उपलब्ध आवासीय इकाइयों के बीच के अंतर में में कमी[279] का %	
		1.4 उपलब्ध न्यायालय कक्षों की कुल संख्या (संचयी)	23,218			
		1.5 उपलब्ध आवासीय इकाइयों की कुल संख्या (संचयी)	20,697			

*[279] स्वीकृत संख्या (25,869) और उपलब्ध आवासीय इकाइयों (19,997) के बीच लगभग 5872 का अंतर है। 700 आवासीय इकाइयों से स्वीकृत संख्या और उपलब्ध आवासीय इकाइयों के बीच के अंतर में लगभग 11.19% की कमी आएगी। गणना: - अंतर = स्वीकृत संख्या - कुल पूर्ण; अंतर में % कमी = (पिछले साल का अंतर - मौजूदा साल का अंतर) *100/ पिछले साल का अंतर।*

1. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
4,500	1. रोजगार के अवसर सृजन करने हेतु उद्यमों की स्थापना/उन्नयन करना।	1.1 स्थापित/उन्नयन किये गये नये सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	1,06,715	1. रोजगार सृजन	1.1 नये/उन्नयन किए गए उद्यमों में कार्यरत लोगों की कुल संख्या (व्यक्ति लाख में)	8.54
	2. जारी की गई कुल मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपये में)	2.1 जारी की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपये में)।	4,257.01			

2. पीएम विश्वकर्मा योजना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
3,860.89	1. विश्वकर्मा के रूप में कारीगरों एवं शिल्पकारों	1.1 डिजिटल आईडी और प्रमाणपत्र के माध्यम से मान्यता प्रदत्त विश्वकर्माओं की संख्या और प्राथमिकता क्षेत्र वाले	0[280]	1. स्व- रोजगार	1.1 स्व-रोजगार प्रदत्त पंजीकृत कारीगरों/शिल्पकारों की संख्या।	6,00,000

[280] *यह सूचित किया गया है कि वर्तमान स्कीम ईएफसी नोट के अनुसार, पंजीकरण के लिए 30 लाख का लक्ष्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। मौजूद स्थिति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए उक्त संकेतक की तुलना में लक्ष्य शून्य हो सकता है। तथापि, एक बार नए ईएफसी अधिदेश को मंजूरी मिलने के बाद लक्ष्य की तदनुसार समीक्षा एवं संशोधन किया जा सकता है।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	की पहचान को सुनिश्चित करना।	ऋण के अंतर्गत ऋण सुविधा के लिए उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पारितंत्र (यूएपी) से जोड़कर उनका औपचारीकरण ।				
	2. कौशल उन्नयन प्रदान करना	2.1 बेसिक प्रशिक्षण प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या	6,00,000		1.2 स्व-रोज़गार प्रदत्त महिला कारीगरों/शिल्पकारों की संख्या।	1,80,000
		2.2 उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या	1,50,000			
	3. कार्य-क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना।	3.1 आधुनिक उपकरण लाभप्रदत्त् कारीगरों/शिल्पकारों की संख्या।	10,00,000		1.3 स्व-रोज़गार उपलब्ध कराये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कारीगरों/शिल्पकारों की संख्या।	1,50,000
					1.4 स्वरोजगार प्रदत्त अन्य पिछड़ा वर्ग कारीगरों/शिल्पकारों की संख्या।	3,00,000
					1.5 स्व-रोजगार प्रदत्त दिव्यांग कारीगरों/शिल्पकारों की संख्या।	5,000
	4. लाभार्थियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना और ब्याज छूट	4.1 संपार्श्विक मुक्त उद्यम विकास ऋण द्वारा सहायता प्राप्त पारंपरिक कारीगरों/शिल्पकारों की संख्या।	10,00,000			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	प्रदान करके ऋण की लागत को कम करना।					
	5. विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेनदेन हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।	5.1 डिजिटल लेनदेन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदत्त कारीगरों/शिल्पकारों की संख्या।	10,00,000			

3. एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,500.00	1. संवर्धित संस्थागत कार्य-निष्पादन और डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म	1.1 एमएसएमई मंत्रालय के एकीकृत पोर्टलों की संख्या।	4	1. एमएसएमई मंत्रालय के पोर्टलों और स्कीमों का डिजिटलीकरण।	1.1 एमएसएमई स्कीम ऑनबोर्डिंग के लिए एकीकृत पोर्टल पर	2,500

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	उपयोग ।	1.2 एकीकृत राज्य पोर्टलों की संख्या।	8		पंजीकरण।	
		1.3 ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्लेटफॉर्म के माध्यम से हल किए गए मामलों की संख्या।	1,000	2. विवाद समाधान तंत्र का डिजिटलीकरण।	2.1 एमएसएमई देरी से भुगतान किए जाने से संबंधित मामलों को ओडीआर प्लेटफॉर्म पर दर्ज करना।	10,000
	2. एमएसएमई केंद्र राज्य सहयोग का गतिवर्धन	2.1 कार्यनीतिक निवेश प्लेटफॉर्म (एसआईपी) कार्यान्वयन के माध्यम से एमएसएमई को सहायता देने वाले राज्यों की संख्या।	2			
	3. प्रतिष्ठान क्षमतावर्धन स्कीमों की प्रभावशीलता को बढ़ाना।	3.1 जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) रजत सम्मान से प्रमाणित एमएसएमई की संख्या।	6,000			
		3.2 लीन या जेड स्वर्ण सम्मान से प्रमाणित एमएसएमई की संख्या।				
		3.3 हरित निवेश और परिवर्तन हेतु वित्तपोषण	1,500	3. ट्रेड्स पर छूट वाले इन्वायस की संख्या में	3.1 व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) पर छूट प्राप्त	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते [281]

[281] *लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		स्कीम (गिफ्ट) और चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश के लिए स्कीम (स्पाइस) के माध्यम से हरित वित्तपोषण प्रदत्त वाले एमएसई की संख्या)।		वृद्धि	इन्वायस की संख्या (करोड़ रुपये में)।	
	4. डिजिटल कॉमर्स तक पहुंच	4.1 व्यापार सक्षमता और विपणन (टीम) पहल के माध्यम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल एमएसई की संख्या।	1,00,000	4. ई-कॉमर्स तक पहुंच में वृद्धि	4.1 टीम पहल के अंतर्गत पंजीकृत विक्रेता नेटवर्क प्रतिभागियों (एसएनपी) की संख्या।	15

4. खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,094.51	1. खादी और पॉलीवस्त्र के उत्पादन पर आधारित आशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) के माध्यम से खादी का	1.1 एमएमडीए प्रदान किए जाने वाले खादी संस्थानों की संख्या।	1,050	1. खादी में सुधार	1.1 वर्ष के दौरान खादी और खादी से संबंधित उत्पादों का उत्पादन (करोड़ रुपये में)।	4,100
		1.2 खादी संस्थानों और कारीगरों को संवितरित एमएमडीए (करोड़ रुपये में)।	250			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	संवर्धन और विकास।	1.3 एमएमडीए के माध्यम से लाभान्वित कारीगरों की संख्या।	1,50,000		1.2 वर्ष के दौरान खादी और खादी से संबंधित उत्पादों की बिक्री (करोड़ रुपये में)।	8,300
	2. कमजोर खादी संस्थानों और विपणन अवसंरचना को सहायता प्रदान करना	2.1 सहायता प्राप्त कमजोर खादी संस्थानों (केआई) की संख्या।	25		1.3 देय वर्ष के दौरान खादी और खादी से संबंधित उत्पादों का निर्यात मूल्य (करोड़ रुपये में)	0.68
		2.2 केआई द्वारा लिया गया ऋण (करोड़ रुपये में)	700	2. ग्रामोद्योगों में रोजगार को बढ़ावा देना।	2.1 ग्रामोद्योग के अंतर्गत सृजित स्व-रोजगार की संख्या।	35,000
		2.3 पुनर्निर्मित बिक्री केंद्रों की संख्या	80			
	3. तकनीकी आधुनिकीकरण प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ग्रामोद्योग का संवर्धन एवं विकास।	3.1 नए प्रशिक्षित ग्रामोद्योग कारीगरों की संख्या।	20,000			
		3.2 कारीगरों को वितरित टूल कीटों की संख्या।	30,000			

5. निधियों का कोष (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
900.00	1. एमएसएमई को इक्विटी/ इक्विटी जैसा	1.1 स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदत्त एमएसएमई की	115	1. एमएसएमई व्यवसायों के तेज	1.1 निवेशित (इनवेस्टी) एमएसएमई द्वारा बिक्री	21,850

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	वित्तपोषण बढ़ाना और स्टॉक एक्सचेंजों पर एमएसएमई को सूचीबद्ध करना।	कुल संख्या।		विकास को सहायता प्रदान करना और रोजगार के अवसर सृजन करना।	(करोड़ रुपये में)	
					1.2 निवेशित एमएसएमई द्वारा सृजित कुल रोजगार।	5,620

6. नई तकनीकी केंद्रों की स्थापना (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
531.20	1. नये प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना	1.1 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) की स्थापना के लिए परियोजना कार्यान्वयन शुरू किया गया	20[282]	1. उन्नत प्रशिक्षण और कौशल तक बेहतर पहुंच	1.1 टीसी/ईसी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं/लाभार्थियों की कुल संख्या।	35,000

[282] *नोट: भवन निर्माण, मशीनरी की खरीद और स्थापना के कारण प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना में लगभग दो वर्ष लगेंगे।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	2. विस्तार केन्द्रों की स्थापना	2.1 स्थापित नये विस्तार केन्द्रों (ईसी) की कुल संख्या।	20	2. उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी तक एमएसएमई की बेहतर पहुंच	2.1 उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच प्रदान करके एमएसएमई की कुल संख्या	100
	3. उद्यमों को सहायता प्रदान करना	3.1 विकसित टूल्स/मोल्ड्स /जिगस/उत्पाद आदि की कुल संख्या	100			

1. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक[283]	लक्ष्य 2026-27	परिणाम[284]	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
2,000	1. विकास में असंतुलन और अंतराल को कम करने के उद्देश्य से विकासात्मक कमी के साथ अभिज्ञात क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा का	1.1. वर्ष 2026-27 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	75	1. विकासात्मक कमी के साथ अभिज्ञात क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार।	1.1. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों का %	25
		1.2. महिला सशक्तिकरण के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	25		1.2. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण किए गए स्कूलों और	20

[283] i. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं का अर्थ अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित एक स्वीकृत बुनियादी ढाँचा पैकेज से है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीजीओ द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में सामुदायिक परिसंपत्तियों का यह सुनिश्चित करते हुए निर्माण करना है कि कैचमेंट क्षेत्र (15 कि.मी. क्षेत्र) में अल्पसंख्यक आबादी 25% से अधिक है। इस परियोजना में परिभाषित कार्यक्षेत्र, स्थान, समय-सीमा, कुल लागत, लागू होने वाली वित्तपोषण पद्धति और निगरानी आवश्यकताओं (निर्धारित जियो-टैगिंग/गुणवत्ता जांच सहित), जैसा कि डीपीआर में दिया गया है, के साथ एक या अधिक 'इकाइयां' शामिल हो सकती हैं।

ii. किसी परियोजना को परिभाषित करने के लिए कोई निश्चित न्यूनतम परिव्यय निर्धारित नहीं है; यह लागत डीपीआर में उल्लिखित परियोजना क्षेत्र, स्थान और अनुमोदित तकनीकी मापदंडों के आधार पर भिन्न हो सकती है।

iii. "इकाई" का अर्थ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित किसी अभिज्ञात बुनियादी ढांचा कार्य से है (उदाहरण के लिए-स्कूल भवन/अतिरिक्त कक्षाएँ, छात्रावास, पीएचसी ब्लॉक, आईटीआई भवन, पेयजल सुविधा, आंगनवाड़ी केंद्र, खेल परिसर सुविधा आदि), डीपीआर प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पोर्टल पर जिसकी वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां दर्ज की गई हैं।

iv. "परियोजना लागत" का अर्थ किसी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम परियोजना की कुल स्वीकृत लागत अर्थात उस अनुमोदित पैकेज में शामिल सभी इकाइयों की कुल लागत से है।

[284] पिछले वित्तीय वर्ष तक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना इकाइयों की संचय संख्या में से।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक[283]	लक्ष्य 2026-27	परिणाम[284]	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	विकास परियोजनाओं का विकास				आवासीय स्कूलों की संख्या का %	
		1.3. उन जिलों की संख्या जिनमें प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं स्वीकृत की गईं	50		1.3. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत पूरे किए गए आईटीआई/पॉलिटेक्निक/कौशल केंद्रों की संख्या का %	20
		1.4. उन आकांक्षी जिलों की संख्या जिनमें प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं स्वीकृत की गईं	25		1.4. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत पूरी की गई खेल सुविधाओं की संख्या का %	20
		1.5. शिक्षा और कौशल क्षेत्र के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	35			
		1.6. स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	12			
		1.7. खेल क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	8			
		1.8. अन्य सामुदायिक अवसंरचना क्षेत्रों में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	20			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक[283]	लक्ष्य 2026-27	परिणाम[284]	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	2. योजना की निगरानी बढ़ाना और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम परिसंपत्तियों की पहचान करना	2.1. वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जियो-टैग की गई प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम परिसंपत्तियों का %	80	2. जियो-टैग की गई परिसंपत्तियों की संख्या में वृद्धि	2.1. वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित जियो टैग की गई परिसंपत्तियों की संख्या में % वृद्धि	50

1. सौर विद्युत (ग्रिड) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,775	1. देश में ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत (ग्राउंड माउंटेड/रूफटॉप) को चालू करना। (पीएम-कुसुम और पीएम-एसजी: एमबीवाई को छोड़कर)[285]	1.1. सौर पार्कों में चालू की गई क्षमता (मेगावाट)	7,000	1. योजनाओं के तहत सौर विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन	1.1 योजनाओं के तहत उत्पादित सौर ऊर्जा (बीयू)	15.51[286]
		1.2. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना (मेगावाट) के तहत परियोजनाओं में चालू की गई क्षमता (मेगावाट)	1,100			
	2. सौर पैनलों और सौर सेलों के स्वदेशी विनिर्माण में वृद्धि	2.1 एमएनआरई की डीसीआर [287]योजनाओं: सीपीएसयू योजना चरण-II के कारण स्वदेशी तौर पर विनिर्मित सौर पैनलों और सेलों की क्षमता (मेगावाट)	1,430	2. योजना के कारण आयात पर निर्भरता में कमी	2.1 सीपीएसयू योजना चरण-II योजना के कारण सौर पैनलों और सेलों के स्वदेशी विनिर्माण से आयातों के मूल्य में कमी (करोड़ में)	2,860
		2.2 एमएनआरई की डीसीआर योजनाओं: पीएम-कुसुम घटक-ख के कारण स्वदेशी तौर पर विनिर्मित सौर मॉड्यूलों और सेलों की क्षमता (मेगावाट)	480		2.2 पीएम-कुसुम घटक-ख योजना के कारण सौर मॉड्यूलों और सेलों के स्वदेशी विनिर्माण के कारण आयातों के मूल्य में कमी (करोड़ में)	960

285 पीएम- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) ,पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई)

[286] सीपीएसयू योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए 21 प्रतिशत सीयूएफ तथा सौर पार्क योजना के अंतर्गत 22 प्रतिशत सीयूएफ के साथ अनुमानित

[287] घरेलू सामग्री की आवश्यकता(डीसीआर)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		2.3 एमएनआरई की डीसीआर योजनाएं: पीएम-कुसुम घटक-ग के कारण स्वदेशी तौर पर विनिर्मित सौर मॉड्यूलों की क्षमता (मेगावाट)	4,500[288]		2.3 पीएम-कुसुम घटक-ग योजना के कारण सौर मॉड्यूलों और सेलों के स्वदेशी विनिर्माण के कारण आयातों के मूल्य में कमी (करोड़ में)	9,000
		2.4 एमएनआरई की डीसीआर योजनाएं: पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के कारण स्वदेशी तौर पर विनिर्मित सौर मॉड्यूलों और सेलों की क्षमता (मेगावाट)	11,700		2.4 पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के कारण सौर मॉड्यूलों और सेलों के स्वदेशी विनिर्माण के कारण आयातों के मूल्य में कमी (करोड़ में)	23,400

2. पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) - (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
22,000	1. घरों पर रूफटॉप सौर प्रणालियों (आरटीएस) की स्थापना	1.1 योजना के अंतर्गत आरटीएस स्थापनाओं की संख्या (लाख में)	39	1. घरों पर रूफटॉप सौर प्रणालियों	1.1 रुफटॉप सौर प्रणालियों से विद्युत का	17.42[289]

[288] *5 किलोवाट पंप सौरीकरण का अनुमान लगाते हुए, कुल मेगावाट 5*9 लाख = 4500 मेगावाट होगा*

[289] *सौर रूपटॉप परियोजनाओं के लिए 17 प्रतिशत सीयूएफ के साथ अनुमानित। (रूफटॉप सौर प्रणालियों से विद्युत का अनुमानित उत्पादन (बीयू) 17.42= 11.7*10^6*.17*24*365/10^9)*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		1.2 आरटीएस की स्थापित क्षमता (गीगावाट)	11.7	(आरटीएस) से विद्युत उत्पादन	अनुमानित उत्पादन (बीयू)	

3. पीएम- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) - (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
5,000	**क. ऑफ-ग्रिड/वितरित और विकेन्द्रित नवीकरणीय विद्युत**					
	1. पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत स्टैण्डअलोन सौर चालित कृषि पंपों की स्थापना	1.1 वित्त वर्ष में स्थापित स्टैण्डअलोन सौर चालित कृषि पंप (सं.)	1,00,000	1. डीजल बचत	1.1 सौर पंपों का उपयोग करते हुए डीजल की मात्रा में बचत (मिलियन लीटर)[290]	69
		1.2 सौर पंपों से लाभान्वित किसान (सं.)	1,00,000			
	ख. ख. ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत					
	1. पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण	1.1 पीएम-कुसुम योजना के घटक-ग के अंतर्गत सौरीकृत ग्रिड कनेक्टड कृषि पंप (सं.)	9,00,000	1. राज्य सब्सिडी बचत	1.1 फीडर सौरीकरण द्वारा राज्य सब्सिडी में बचत[291] (करोड़ में)	2,664

[290] प्रतिदिन 4.6 लीटर डीजल के औसत उपयोग की धारणा पर आधारित; 150 दिन प्रतिवर्ष की दर से उपयोग; 1.6 मिलियन यूनिट प्रति मेगावाट प्रति वर्ष के 18.3 प्रतिशत पीएलएफ की दर से उत्पादन

*[291] 3.3 रुपए प्रति यूनिट के टैरिफ और 5 किलोवाट पंप के लिए 7 रुपए प्रति यूनिट की पारंपरिक विद्युत दर पर अनुमानित (1.6 *10^6 (U) * 3.7 (Rs/U)* 100000/200*9= 2664 करोड़)*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	2. पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत विकेन्द्रित ग्राउंड माउंटेड ग्रिड-कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना	2.1 पीएम-कुसुम योजना घटक-क के अंतर्गत स्थापित विकेन्द्रित ग्राउंड माउंटेड ग्रिड-कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट)	2,000	2. पीएम कुसुम से विद्युत का उत्पादन	2.1 योजनाओं के अंतर्गत उत्पादित सौर विद्युत (बीयू)	3.2

4. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
599.99	1. क्रियान्वयन कर रहे 10 राज्यों में ट्रांसमिशन प्रणाली का निर्माण	1.1 निर्मित संचयी इंट्रा-स्टेट ट्रांशमिशन लाइनें (सीकेएम)	12,760[292]	1. क्रियान्वयन कर रहे 10 राज्यों में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता का ग्रिड-एकीकरण	1.1 क्रियान्वयन कर रहे 10 राज्यों में जोड़ी गई संचयी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (मेगावाट)	32,000[293]
		1.2 चालू की गई संचयी सब-स्टेशन क्षमता (एमवीए)[294]	30,690[295]			

[292] *(जीईसी-I 9760+जीईसी-II 3000) = 12,760*

[293] *(जीईसी-I 24000+जीईसी-II 8000) = 32,000*

294 *मेगावोल्ट एम्पीयर*

[295] *(जीईसी-I 22690+जीईसी-II 8000) = 30,690*

5. राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
600	1. ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता की स्थापना करना	1.1 ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता सहायता का आवंटन (एमटीपीए)	1,00,000[296]	1. भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता को स्थापित करना	1.1 भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा की स्थापना (एमएमटीपीए)	4,12,000[297]
		1.2 इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता का आवंटन (एमडब्ल्यूपीए)(संचयी)	3,000[298]		1.2 भारत में इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता की स्थापना (एमडब्ल्यूपीए)	3,000[299]
	2. सहायता प्राप्त पायलट परियोजनाएं	2.1 परिवहन क्षेत्र में सहायता प्राप्त पायलट परियोजनाएं (संचयी सं.)	11[300]	2. भारत में हार्ड-टू-एबेट क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाना	2.1 भारत में हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन और संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[301]
		2.2 इस्पात क्षेत्र में सहायता प्राप्त पायलट	12[302]		2.2 भारत में रेट्रो-फिटिंग,	2[303]

[296] ग्रीन मेथनॉल (जिसकी मात्रा 1,00,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन के बराबर होने की उम्मीद है) के उत्पादन और आपूर्ति के लिए क्षमताएं आवंटित करने की योजना है।

[297] संभावित कमीशनिंग, मौजूदा कमीशनिंग समय-सीमा के अधीन। यह ट्रांच I में आवंटित क्षमता है।

[298] स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए 3,000 मेगावाट प्रति वर्ष प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। पूरी क्षमता प्रदान की जा चुकी है।

[299] संभावित कमीशनिंग, मौजूदा कमीशनिंग समय-सीमा के अधीन।

[300] परिवहन क्षेत्र में 5 पायलट परियोजनाएँ पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। इसके लिए आवंटित धनराशि लगभग 208 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2025-26 में और अधिक परियोजनाएं प्रदान किये जाने की उम्मीद है।

[301] परिवहन क्षेत्र में प्रदान की गई पहली 5 परियोजनाओं के वित्त वर्ष 2026-27 में चालू होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं में 37 हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले वाहन और 9 हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन लगाए जाएँगे।

[302] इस्पात क्षेत्र में 5 पायलट परियोजनाएँ पहले ही चालू की जा चुकी हैं। इसके लिए आवंटित धनराशि लगभग 132 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2025-26 में और अधिक परियोजनाएं चालू किये जाने की उम्मीद है।

[303] डेवलपर्स द्वारा साझा की गई समय-सीमा के अनुसार

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		परियोजनाएं (संचयी सं.)			बंकरिंग और पुनः ईंधन-भरने की सुविधाएं	
		2.3 नौवहन क्षेत्र में सहायता प्राप्त पायलट परियोजनाएं (संचयी सं.)	2[304]		2.3 भारत में हाइड्रोजन या इसके डेरिवेटिव से चलने वाले जहाजों का विकास और बंकरिंग एवं ईंधन भरने की सुविधाओं की स्थापना	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[305]
	3. हाइड्रोजन और उससे संबंधित उपकरणों की सहायता प्राप्त परीक्षण परियोजनाएं	3.1 सहायता प्राप्त परियोजनाएं(संचयी सं.)	8[306]	3. भारत में स्थापित की गई हरित हाइड्रोजन परीक्षण सुविधाएं	3.1 भारत में हरित हाइड्रोजन और संबंधित उपकरण परीक्षण सुविधाओं की स्थापना	5[307]

[304] नौवहन क्षेत्र में पायलट परियोजना के दो घटक हैं। घटक A, ग्रीन हाइड्रोजन या उसके डेरिवेटिव आधारित जहाजों के विकास के लिए है, और घटक B, बंकरिंग और ईंधन भरने की सुविधाओं के विकास के लिए है।

[305] जहाज के लिए, कार्यकारी समूह की सातवीं बैठक में दोहरे ईंधन वाले जहाज प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। यह वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदान किए जाने की उम्मीद है। VOCPA में बंकरिंग और ईंधन भरने की सुविधा का विकास वित्त वर्ष 2025-26 में (मौजूदा कमीशनिंग समय-सीमा के अनुसार) शुरू होने की उम्मीद है। जहाज को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स से चलाने की अनुमति मिल सकती है

[306] मिशन की परीक्षण योजना के तहत 5 परियोजनाएँ पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में और परियोजनाएँ स्वीकृत होने की उम्मीद है।

[307] परीक्षण योजना के तहत स्वीकृत पहली 5 परियोजनाएँ वित्त वर्ष 2026-27 में (मौजूदा कमीशनिंग समय-सीमा के अनुसार) चालू होने की उम्मीद है।

6. पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कार्यक्रम: पवन विद्युत-ग्रिड[308]- (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
500	1. जीबीआई योजना के तहत समर्थित परियोजनाओं के संबंध में विद्युत उत्पादन	1.1. विद्युत की इकाइयों की संख्या (एमयू में)	10,000	1. कार्बन उत्सर्जन को कम करना	1.1. कार्बन उत्सर्जन में कमी (एमएमटी में)	8.34

7. सौर ऊर्जा: ब्याज भुगतान और बॉन्ड पर व्यय जारी करने संबंधी

वित्तीय व्यय (करोड़ रु. में)	आउट्पुट 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**आउट्पुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
1,764.35	**1.** ब्याज का भुगतान और मूलधन की वापसी राशि	**1.1.** ब्याज भुगतान की तीन किश्तें[309]	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[310]	**1.** ब्याज का निपटान और मूलराशि की अदायगी	**1.1.** भुगतान तारीखों की तीन किश्तें[311]	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[312]

---

[308] *1. जीबीआई योजना के तहत समर्थित परियोजना के लिए, पवन ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट के लिए 0.50 रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है।*

2. पवन ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादिरत विद्युत के प्रति यूनिट कार्बन उत्सर्जन को 0.834 किग्रा/यूनिट माना जाता है।

3. यह ध्यान देने योग्य है कि ग्रिड इंटरैक्टिव पवन ऊर्जा के लिए आवंटित बजट पुराने पवन उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (GBI) योजना की देनदारियों को पूरा करने के लिए है, जो 17.12.2009 से 31.03.2017 तक कमीशन किए गए पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध थी। इसलिए, आगामी वर्ष में इस बजट के साथ कोई नई क्षमता/परियोजना आने की संभावना नहीं है और आवंटित बजट और नए पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कमीशनिंग के बीच कोई संबंध नहीं है। इसलिए निगरानी किए जा सकने वाले इंडिकेटर्स को देखते हुए, इन परियोजनाओं से बिजली उत्पादन को जीबाआई के तहत रिलीज से जोड़ना उपयुक्त नहीं है।

[309] *भुगतान करने की तिथियां: 06-08-2026, 23-08-2026 और 06-09-2026*

[310] *ब्याज की किश्तों का निपटान और मूल राशि की वापसी*

[311] *भुगतान की तिथियां: 06-08-2026, 23-08-2026 और 06-09-2026*

[312] *ब्याज की किश्तों का निपटान और मूलराशि का पुनर्भुगतान*

वित्तीय व्यय (करोड़ रु. में)	आउट्पुट 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**आउट्पुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
		1.2. ब्याज का निपटान और मूलराशि की अदायगी.[313]	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते		**1.2.** ब्याज भुगतान की तीन किश्तें और मूल अदायगी.[314]	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते

[313] *पुनर्भुगतान की तीन किश्तों की तिथियां: 06-02-2027,23-02-2027 और 06-03-2027*

[314] *पुनर्भुगतान की तीन किश्तों की तिथियां: 06-02-2027, 23-02-2027 और 06-03-2027*

1. **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आरजीएसए) (सीएसएस)**

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
1,142.31	**क. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आरजीएसए) - क्षमता निर्माण (सीएसएस)**					
	1. पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के बुनियादी अवसंरचना और निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करना	1.1. वर्तमान वर्ष में प्रशिक्षित निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और पंचायत पदाधिकारियों की संख्या।	36,00,000	1. पंचायत शासन, ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना और सेवा प्रदायगी में सुधार के उद्देश्य से बेहतर योजना के लिए पीआरआई का क्षमता निर्माण ।	1.1. ई- ग्रामस्वराज के योजना मॉड्यूल पर तैयार और अपलोड की गई ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की संख्या	2,55,000
		1.2. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पीईएसए) पर प्रशिक्षित निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों की संख्या।	25,000		1.2. ई- ग्रामस्वराज के योजना मॉड्यूल पर तैयार और अपलोड की गई ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) की संख्या	6,400
		1.3. वर्तमान वर्ष में प्रशिक्षित निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या	14,40,000		1.3. ई- ग्रामस्वराज के योजना मॉड्यूल पर तैयार और अपलोड की गई जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) की संख्या	650
		1.4. एक्सपोजर विजिट में भाग लेने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की संख्या	6,120			
		1.5. विकसित पंचायत शिक्षण केंद्रों (पीएलसी) की संख्या	500			
		1.6. नए ग्राम पंचायत भवन में प्रदान की गई ग्राम पंचायतों की संख्या	1,000			
		1.7. पंचायत भवनों में सहस्थापित सार्वजनिक सेवा केंद्रों (सीएससी) की संख्या।	1,000			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		1.8. कंप्यूटर से सुसज्जित ग्राम पंचायतों की संख्या	5,800			
		1.9. निर्मित जिला पंचायत संसाधन केंद्रों (डीपीआरसी) की संख्या	26			
		1.10. राज्य पंचायत संसाधन केंद्रों (एसपीआरसी) में स्थापित कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की संख्या (वर्तमान वर्ष में)	3			
		1.11. जिला पंचायत संसाधन केंद्रों (डीपीआरसी) में स्थापित कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की संख्या (वर्तमान वर्ष में)	35			
	ख. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) -ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजनाएं (सीएसएस)					
	1. इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पंचायतों की सेवाओं में वृद्धि करना	1.1 ई-पंचायत एप्लीकेशन, ई-ग्राम स्वराज (ईजीएस), ऑडिट ऑनलाइन, ग्राम मानचित्र और स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) पर आयोजित प्रशिक्षणों और कार्यशालाओं की संख्या	8	1. पंचायतों की सेवाओं मे सुधार	1.1 प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या।	50
		1.2 ई-ग्राम स्वराज में अपनी विकास योजनाएँ अपलोड करने वाले पीआरआई की संख्या (लाख में)	2.7		1.2 ई-ग्रामस्वराज पर अपनी विकास योजनाएं अपलोड करने वाली पंचायती राज संस्थाओं का (%)	100
		1.3 ऑनलाइन लेनदेन के लिए ई-ग्राम स्वराज- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) इंटरफ़ेस का	2.7		1.3 ऑनलाइन भुगतान लेनदेन के लिए ई-ग्रामस्वराज- (पीएफएमस) इंटरफ़ेस (ईजीएसपीआई) का उपयोग करने	95

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		उपयोग करने वाली पंचायती राज संस्थाओं (ईजीएसपीआई) की संख्या (लाख में)			वाली पीआरआई का (%)	
		1.4 पंचायती राज संस्थाओं की संख्या, जो अपनी मासिक/ वार्षिक पुस्तकों को बंद कर रही हैं (वित्तीय वर्ष 2026-27) (लाख में)	2.5		1.4 अपनी मासिक/वार्षिक किताबें बंद करने वाली पीआरआई का (%) (वित्तीय वर्ष 2026-27)	95
		1.5 ग्राम पंचायतों की संख्या जो प्रति वर्ष ई-ग्राम स्वराज पर अपनी प्रोफ़ाइल अपडेट कर रही हैं (लाख में)	2.5		1.5 प्रति वर्ष ई-ग्रामस्वराज पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने वाली ग्राम पंचायतों का (%)	90
		1.6 ऑडिटऑनलाइन पर शामिल ऑडिटी (पीआरआई) की संख्या (वित्त वर्ष 2025-26) (लाख में)	2.6		1.6 ऑडिट ऑनलाइन का उपयोग करके सांविधिक ऑडिट पूरा करने वाली पीआरआई का (%) (वित्त वर्ष 2025-26)	90
	2. परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग	2.1 उन ग्राम पंचायतों की संख्या जिनकी परिसंपत्ति जियो-टैगिंग के ज़रिए मैप की गई है (लाख में)	2.5	2. परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग में प्रगति	2.1 परिसम्पत्तियों की जियो-टैगिंग की रिपोर्ट करने वाली ग्राम पंचायतों का (%)	100
	ग. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) - पंचायतों का प्रोत्साहन (सीएसएस)					
	1. 'सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण' की दिशा	1.1 राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित की गई पंचायतों/समकक्ष निकायों की संख्या	42	1. सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में	1.1 पंचायतों/समकक्ष निकायों की संख्या जिन्होंने सतत विकास लक्ष्यों के	1,000[315]

[315] *पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) स्कोर के आधार पर 1000 ग्राम पंचायतों को श्रेणी 'बी' से श्रेणी 'ए' में स्थानांतरित किया गया है। पीएआई एक सूचकांक है जो सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की दिशा में ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें श्रेणीबद्ध करता है। श्रेणी ए: अग्रणी (75 से 90 से कम स्कोर); श्रेणी बी: उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली (60 से 75 से कम स्कोर)*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली पंचायतों/समकक्ष निकायों और प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित करना।	1.2 सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए ग्राम पंचायतों/ समकक्ष निकायों को संस्थागत सहायता उपलब्ध कराने के लिए सम्मानित किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या	3	ग्राम पंचायतों/समकक्ष निकायों के प्रदर्शन में वृद्धि	स्थानीयकरण के 9 विषयों पर निम्न श्रेणियों से उच्च श्रेणियों में अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। यह मापन पंचायत विकास सूचकांक (पीएआई) के माध्यम से किया गया है	
	घ. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) - मिडिया और प्रचार (सीएस)					
	1. पंचायती राज मंत्रालय के कार्यक्रमों और पहलों के बारे में जागरूकता लाना	1.1 मंत्रालय द्वारा प्रकाशित डिजिटल/ पेपरबैक समाचार पत्रिकाओं/ पुस्तक/ पुस्तिकाओं/ दस्तावेजों की संख्या	7	1. जागरूकता में सुधार	1.1 जागरूकता लाने हेतु इसका उपयोग करने के लिए राज्यों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) में वितरण के लिए सार्वजनिक डोमेन में अपलोड किए गए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) - ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों की संख्या	20
		1.2 प्रचारित कुल आईईसी ऑडियो-विजुअल कार्यक्रम	11		1.2 पिछले वर्ष की तुलना में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के फ़ॉलोअर्स में (%) वृद्धि	20
		1.3 प्रचार-प्रसार/ जागरूकता लाने वाले सोशल मीडिया पोस्टों की कुल संख्या	3,000			
		1.4 मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं की	5			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		संख्या				
	ङ. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) - कार्य अनुसंधान एवं शोध अध्ययन[316] (सीएस)					
	1. पीआरआई और उनकी कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करना	1.1 पहचान किए गए विषयों की संख्या	6	1. ज्ञान एवं साक्ष्य-आधारित योजना/कार्यक्रम/नीति निर्माण का प्रसार	1.1 वर्तमान वर्ष में पूर्ण किए गए अध्ययनों की संख्या	5
		1.2 वर्तमान वर्ष में स्वीकृत अनुसंधान अध्ययन/अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या	6		1.2 पूर्ण किए गए अध्ययनों की संख्या जिनकी सिफारिशें नीति/कार्यक्रम गठन/संशोधन में शामिल की गई हैं	3

[316] *मीडिया एवं प्रचार और* कार्य अनुसंधान एवं शोध अध्ययन *कार्य अनुसंधान और प्रचार योजना घटक (अम्ब्रेला आरजीएसए योजना के तहत) के उप-घटक हैं।*

कार्य अनुसंधान और प्रचार योजना घटक के लिए वर्ष 2026-27 में समग्र बीई 15.00 करोड़. रुपये है। इन उप-घटकों के लिए फ्रेमवर्क में संकेतकों का अलग से उल्लेख किया गया है।

1. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-एलपीजी (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
1,500	1. अतिरिक्त नगद अतरण कंप्लायंट लाभार्थी	1.1 नगद अंतरण का पालन करने वाले लाभार्थियों की संख्या (करोड़)	लक्ष्य अनुकूल नहीं[317]	1. सभी मौजूदा और नए घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के खातों में सीधे डीबीटी की प्राप्ति	1.1 लाभार्थी परिवारों का एलपीजी आच्छादन (%)	100
	2. लाभ का तेज़ी से अंतरण	2.1 डीबीटी में लगने वाला औसत समय (घंटे में)	48[318]		1.2 प्रति वर्ष औसत रिफिल	6
		2.2 एलपीजी सिलेंडर का ऑर्डर देने के बाद डिलीवरी का समय (घंटे)	36		1.3 एलपीजी (डीबीटी) लाभार्थियों की कुल संख्या (करोड़ में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[319]
		2.3 घर पर डिलीवर किए गए सिलेंडर बनाम एजेंसी पर रिफिल किए गए सिलेंडर (%)	99[320]			

[317] अभी, एलपीजी आच्छादन 100% से ज़्यादा है, इसलिए वर्ष 2026-27 में जोड़े जाने वाले अतिरिक्त नगद अंतरण कंप्लाएंट लाभार्थी और एलपीजी (डीबीटी) लाभार्थी की कुल संख्या ओएमसीज को मिली एप्लीकेशन पर आधारित होगी और इस तरह यह मांग पर आधारित होगी। इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

[318] अब राजसहायता जीओआई के पीएफएमएस प्रणाली के ज़रिए अंतरित होती है, इसलिए यह पैरामीटर ओएमसीज/ एमओपीएंडएनजी के सीधे नियंत्रण से बाहर होगा।

[319] अभी, एलपीजी आच्छादन 100% से ज़्यादा है, इसलिए वर्ष 2026-27 में जोड़े जाने वाले अतिरिक्त नगद अंतरण कंप्लाएंट लाभार्थी और एलपीजी (डीबीटी) लाभार्थी की कुल संख्या ओएमसीज को मिली एप्लीकेशन पर आधारित होगी और इस तरह यह मांग पर आधारित होगी। इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

[320] डीकेवी (दुर्गम क्षेत्रीय वितरक) डिस्ट्रीब्यूटर्स को छोड़कर, सभी ओएमसी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी ज़रूरी है।

2. गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन-पीएमयूवाई (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
9,200	1. बीपीएल परिवारों (एचएचएस) को जमानत मुक्त एलपीजी कनेक्शन	1.1 बीपीएल परिवारों को जारी किए गए अतिरिक्त कनेक्शन (करोड़)	0[321]	1. स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन अर्थात एलपीजी का बढ़ता उपयोग	1.1 जिन परिवारों को योजना के तहत जमानत मुक्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे और वे निर्यातक कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं[322] (%)	90
		1.2 गरीबों की कुल संख्या परिवारों को बिना जमानत के दी गई एलपीजी योजना के तहत कनेक्शन (करोड़)	10.58		1.2 पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष औसत रिफिल	4.7

[321] इस इंडिकेटर का लक्ष्य 0 रखा गया है क्योंकि पीएमयूवाई के तहत और एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव अभी शुरू नहीं हुआ है।

[322] विनियामन का अर्थ है पिछले 12 महीनों में कम से कम एक बार रिफिल।

3. इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
700	1. आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का निर्माण	1.1 पूर्वोत्तर गैस ग्रिड (एनईजीजी) पाइपलाइन की कुल लंबाई (कि.मी. में)	190	1. उपयोग का अधिकार (आरओयू) अधिग्रहण और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अग्रणी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए	1.1 वितरित मुआवजे की राशि या संवितरण के लिए सक्षम अधिकारियों के खातों में अंतरण किया गया (करोड़ रुपये)	41
		1.2 पूरे हुए स्टेशनों की संख्या[323] (संख्या में)	34		1.2 प्रत्यक्ष और परोक्ष रोज़गार की संख्या	3,300
				2. आईजीजीएल पाइपलाइन ग्रिड के चालू होने से इस क्षेत्र में गैस की खपत बढ़ने की उम्मीद है।	2.1 पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक गैस की खपत बढ़ी (एमएमएससीएमडी)[324]	0.35

[323] पूरे हुए स्टेशनों की संख्या:

i.यहां, स्टेशन प्रत्येक पाइपलाइन खंड में मौजूद सेक्शनलाइजिंग वाल्व स्टेशन, रसीद टर्मिनल, इंटरमीडिएट पिगिंग स्टेशनों को इंगित करते हैं।

ii.इसमें शामिल काम हैं - सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल कार्य।

iii.स्टेशन का पूरा होना यह बताएगा कि स्टेशन कमीशन होने के लिए तैयार है।

iv.एनईजीजी परियोजना (चरण- I, II, III) में स्टेशनों की कुल संख्या 101 है।

v. निर्धारित लक्ष्य उन स्टेशनों की संख्या दिखाता है जिन्हें हर तिमाही में कमीशन करने के लिए तैयार करने की योजना है।

[324] मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सब्सिडी सहित अन्य देय सब्सिडी (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,103	1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में एपीएम ग्राहकों को प्राकृतिक गैस राजसहायता (घरेलू गैस मूल्य का 40%) का आच्छादन।	1.1 जिन गैस ग्राहकों को जीएलसी आवंटन मिला है और जिन्हें एनईआर में राजसहायता वाली घरेलू गैस आपूर्ति की जा रही है (संख्या)	33	1. एनईआर में राजसहायता वाली प्राकृतिक गैस की निरंतरता।	1.1 जीएलसी आवंटन वाले ग्राहकों को आपूर्ति की गई गैस की मात्रा (एमएमएससीएमडी)[325]	4

[325] *मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे*

1. सागरमाला (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
616.88	1. पत्तनों पर अवसंरचना निर्माण और पत्तनों का आधुनिकीकरण करना	1.1 चालू वित्त वर्ष में पूरी की गई रो- रो यात्री जेट्टी परियोजनाएं (सं.)	6	1. पर्यटन में संवर्धन	1.1 पत्तनों पर जाने वाले पर्यटक (सं.)	50,000
		1.2 चालू वित्त वर्ष में पूरी की गई क्रूज टर्मिनल परियोजनाएं (सं)	1			
	2. महापत्तनों में ब्राउनफील्ड क्षमता में वृद्धि	2.1 पूरी की गई ब्राउनफील्ड परियोजनाएं (सं)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[326]	2. कार्गो हैंडलिंग क्षमता में संवर्धन	2.1 महापत्तनों पर हैंडल किए गए कार्गो की मात्रा में वृद्धि (एमटीपीए)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
	3. आतंरिक सड़क और रेल संपर्कता में सुधार	3.1 चालू वित्त वर्ष में पूरी की गई आतंरिक पत्तन सड़क / रेल परियोजनाएं (सं)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते	3. कार्गो की समय पर रिक्तीकरण और भीड़-भाड़ कम करना	3.1 माल को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में औसत समय (घंटों में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
	4. मैरीटाइम क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन	4.1 चालू वित्त वर्ष में वित्तीय समर्थन प्रदान किए गए स्टार्टअप (विभिन्न स्तर पर पीओसी, एमवीपी, व्यवसायीकरण चरण) (सं.)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते	4. मैरीटाइम समाधानों का व्यवसायीकरण	4.1 व्यवसायीक रूप से तैयार उत्पाद/ समाधान (सं.)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा

[326] *क्रमाक 2 से 5 पर लक्ष्य और परिणाम सागरमाला 2.0 योजना के अनुमोदन पर समाश्रित है।*

वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
						सकते
	5. क्षेत्र में क्षमता निर्माण	5.1 चालू वित्त वर्ष में क्षमता निर्माण हेतु समर्थित केंद्र (सं.)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते	5. मैरीटाइम कार्यबल की क्षमता में वृद्धि	5.1 प्रमाणित पेशेवर (सं.)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते

2. पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) और राष्ट्रीय पोत निर्माण मिशन (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
515	1. भारतीय शिपयार्डों द्वारा जलयानों के निर्माण और डिलीवरी हेतु वित्त	1.1 चालू वित्त वर्ष में डिलीवर किए गए जलयान (सं.)	42	1. रोजगार और व्यवसाय के अवसर उत्पन्न करने के लिए घरेलू शिपयार्ड में पोत निर्माण को बढ़ावा देना	1.1 पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में उत्पन्न व्यवसाय की मात्रा में परिवर्तन (%)	25
		1.2 चालू वित्त वर्ष में योजना के तहत जारी किए गए वित्तीय प्रोत्साहन (करोड़ में)	500		1.2 पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में सृजित रोजगार में परिवर्तन (%)	30
					1.3 पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में सकल टनभार में परिवर्तन (%)	12.5

1. संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (सीएस)

वित्तीय व्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
18,000	1. हानि न्यूनीकरण कार्यों के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु	1.1. अवार्ड किए गए कार्यों (%) में से हानि न्यूनीकरण कार्यों को पूरा किया गया	62	1. डिस्कॉम[327] की प्रचालन दक्षता में सुधार करना	1.1. डिस्कॉम में एटी एंड सी हानि का स्तर (%)	14
	2. देश में स्मार्ट मीटर संस्थापित करने हेतु	2.1. संस्थापित स्मार्ट मीटर (संचयी संख्या)	10,00,00,000	2. डिस्कॉम की वित्तीय स्थिरता में सुधार करना	2.1. डिस्कॉम (रुपये/केडब्ल्यूएच) में एसीएस-एआरआर अंतर स्तर	0.1
	3. देश में वितरण फीडरों की ऑनलाइन निगरानी बढ़ाने के लिए	3.1 कुल फीडरों में से वितरण फीडरों की निगरानी की जाती है। (%)	95	3. डिस्कॉम में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार करना	3.1. निगरानी किए गए शहरी फीडरों (घंटे/दिन) पर वार्षिक औसत दैनिक विद्युत आपूर्ति घंटे	23.5
	4. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और अन्य सक्षम तथा सहायक गतिविधियाँ	4.1 आरडीएसएस[328](संचयी संख्या) के अंतर्गत प्रशिक्षित डिस्कॉम कार्मिक	9,000		3.2. निगरानी किए गए ग्रामीण फीडरों (घंटे/दिन) पर औसत दैनिक विद्युत आपूर्ति घंटे	22.6

[327] *वितरण कंपनियाँ*

[328] *पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना*

2. विद्युत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (सीएस)

वित्तीय व्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
969.11	**i. अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण**					
	1. पैकेज की परियोजना पूर्णता और उनका कार्यान्वयन	1.1 अवार्ड किए गए पैकेजों पर संचयी प्रगति (11407.8 करोड़ रुपये की प्रस्तावित आरसीई-[329] II लागत के अनुसार) (%)	81	1. क्षेत्र में विद्युत पारेषण क्षमता में सुधार	1.1. क्षेत्र में विद्युत पारेषण में वृद्धि (एमवीए[330]):	105

3. विद्युत प्रणाली विकास निधि (सीएस)

वित्तीय व्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
1,102.62	1. ग्रिड विश्वसनीयता और अनुकूलन में सुधार के लिए पीएसडीएफ-वीजीएफ[331] सहायता के माध्यम	1.1. बीईएसएस परियोजनाओं (जीडब्ल्यूएच) के लिए वित्तीय समापन (एनटीपीसी[333] के	30	1. बीईएसएस संस्थापना के लिए परियोजना	1.1. संस्थापना हेतु सुनिश्चित लक्षित	100

[329] *संशोधित लागत अनुमान*

[330] *मेगा वोल्ट एम्पीयर*

[331] *विद्युत प्रणाली विकास निधि व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण*

वित्तीय व्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	से ग्रिड-स्केल बीईएसएस[332] परियोजनाओं का निष्पादन।	लिए एलओए प्लेसमेंट)		तत्परता में सुधार	बीईएसएस क्षमता (%)	
	2. पारेषण लाइनों पर ऑप्टिकल ग्राउंड वायर और टर्मिनल उपकरण की संस्थापना	2.1. संस्थापित ऑप्टिकल ग्राउंड वायर की लंबाई (सीकेएम)	2,299	2. संचार नेटवर्क की विश्वसनीयता में वृद्धि	2.1. संचार नेटवर्क अपटाइम (%)	99[334]
		2.2. चालू संचार लिंक (संख्या)	99			

4. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (सीएस)

वित्तीय व्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,000	1. वीजीएफ[335] स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित बीईएसएस क्षमता की शुरुआत	1.1 चालू की गई बीईएसएस परियोजनाओं की कुल क्षमता (संचयी) (एमडब्ल्यूएच)	8,000	1. ग्रिड प्रचालन के लिए बीईएसएस क्षमता की उपलब्धता	1.1. ग्रिड प्रचालन के लिए उपलब्ध कमीशन की गई बीईएसएस क्षमता	100[336]

---

[333] *राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम*

[332] *बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली*

[334] *>99*

[335] *व्यवहार्यता अंतर निधि*

[336] *(8000 एमडबल्यूएच का)*

वित्तीय व्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	2. बीईएसएस के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण का वितरण करना	2.1 वित्त वर्ष 2026-27 में संवितरण के लिए अनुमोदित कुल व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (करोड़ में)	1,000		(%)	

1. चल स्टॉक (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
52,108.73	1. प्रत्येक किस्म के चल स्टॉक का अधिग्रहण	1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान परिचालन में लाई गई इंजनों की संख्या	1,700	1. माल ढुलाई और यात्री सेवाओं में बेहतर प्रवाह क्षमता	1.1 पिछले वर्ष की तुलना में यात्री प्रवाह में वृद्धि (%)	4.91
		1.2 वित्तीय वर्ष के दौरान परिचालन में लाए गए सवारी डिब्बों की संख्या	9,000		1.2 पिछले वर्ष की तुलना में माल प्रवाह में वृद्धि (%)	0.89
		1.3 वित्तीय वर्ष के दौरान परिचालन में लाई गई रेलपथ मशीनों की संख्या	133			

2. नई लाइनें (सीएस)

3. आमान परिवर्तन (सीएस)

4. लाइन दोहरीकरण (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
79,071.55	1. नई लाइनों के निर्माण, आमान	1.1. नई लाइनों का निर्माण (किमी)	500	1. बिना संपर्कता वाले मार्गों विशेष रूप से एलडब्ल्यूई जिलों, सामरिक रूप	1.1. नई लाइनों के निर्माण के कारण रेलवे से जुड़ने वाले स्थानों की	15

वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	परिवर्तन और लाइन दोहरीकरण की गति में तेजी	1.2. पूर्ण किए गए गेज परिवर्तन की कुल लंबाई (किमी)	100	से महत्वपूर्ण जिलों, जनजातीय क्षेत्रों, आदि में बेहतर पंहुच	संख्या	
		1.3. पूर्ण किए गए लाइन दोहरीकरण की कुल लंबाई (किमी)	2,400	2. अधिक संरक्षा और प्रवाह क्षमता के साथ-साथ सघन मार्गों पर अधिक माल यातायात सेवाएं।	2.1 पिछले वर्ष की तुलना में यात्री प्रवाह में वृद्धि (%)	4.91
					2.2 पिछले वर्ष की तुलना में माल प्रवाह में वृद्धि (%)	0.89

5. रेलपथ नवीनीकरण (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
22,853	1. नवीनीकृत रेलपथ की अधिक लंबाई	1.1. नवीनीकृत रेलपथ की कुल लंबाई (किमी)	6,400	1. संपत्ति की विश्वसनीयता में वृद्धि	1.1 पिछले वर्ष की तुलना में रेल/वेल्ड विफलताओं की संख्या में कमी (%)	25

6. ग्राहक सुविधाएं (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
11,971.82	1. यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाना	1.1 अपग्रेडेड स्टेशनों की संख्या	151	1. अधिक यात्री संतुष्टि सूचकांक	1.1 यात्री संतुष्टि सूचकांक (प्रतिशत में)	85
		1.2 निर्मित पैदल पार पुलों की संख्या	100			
		1.3 आधुनिकीकरण किए गए माल गोदामों की संख्या	452			

7. यातायात सुविधाएं - यार्ड रीमॉडलिंग और अन्य (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
7897.27	1. कार्यों की अधिक कवरेज	1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कमीशन किए गए कार्यों की संख्या	100	1. जहां यार्ड रिमॉडल किए गए हैं, उन मार्गों पर अधिक यात्री और माल प्रवाह	1.1 पिछले वर्ष की तुलना में यात्री प्रवाह में वृद्धि (%)	4.91
					1.2 पिछले वर्ष की तुलना में माल प्रवाह में वृद्धि (%)	0.89

8. सिगनल एवं दूरसंचार (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
7,500	1. सिग्नलों को बदलने का कार्य	1.1 आधुनिक सिग्नलिंग कार्य पूर्ण किए गए स्टेशनों की संख्या	385	1. सिगनलों को बदलने के कार्य किए गए स्टेशनों पर संरक्षा में वृद्धि	1.1. सिगनल विफलताओं से उत्पन्न असुरक्षित कार्यप्रणाली की घटनाओं की संख्या	0
		1.2 कवच से आच्छादित मार्ग किलोमीटर (आरकेएम)	1,600			
	2. समपार फाटकों की इंटरलॉकिंग	2.1 इंटरलॉकिंग कार्य पूरे किए गए समपार गेटों की संख्या	300	2. इंटलॉकिंग कार्य किए गए समपार गेटों पर संरक्षा में वृद्धि	2.1 गेटों पर होने वाली घटनाओं की संख्या जहां समपार गेट इंटलॉकिंग कार्य किए गए हैं	0

9. सड़क संरक्षा कार्य- समपार (सीएस)

10. सड़क संरक्षा कार्य- ऊपरी/निचले सड़क पुल (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
9,025	1. आरओबी/ आरयूबी का निर्माण	1.1 हटाए गए मानव-संचालित समपारों की संख्या	900	1. सुरक्षा में वृद्धि	1.1 समपारों पर दुर्घटनाओं की संख्या में कमी	0
		1.2 निर्मित किए गए आरओबी/आरयूबी की संख्या	1,100			

11. उत्पादन इकाइयों सहित कारखाने (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
3,888.29	1. परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करना	1.1. वित्तीय वर्ष के दौरान कमीशन की गई परियोजनाओं की संख्या	330	1. रेलवे परिसंपत्तियों का कारखानों और उत्पादन इकाइयों में समयबद्ध एवं दक्ष रखरखाव तथा उत्पादन	1.1 लक्षित उत्पादन के सापेक्ष प्राप्त रोलिंग स्टॉक उत्पादन (%)	100
					1.2 सेवित चल स्टॉक का बकाया अनुरक्षण (%)	0

12. महानगर परिवहन परियोजनाएं (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
2,886	1. उप-नगरीय रेलगाड़ियों की अधिकतम उपलब्धता	1.1. कमीशन किए गए महानगरीय नई लाइन कार्यों की लंबाई (किमी)	48.11	1. इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप यात्रियों के प्रवाह क्षमता में वृद्धि हुई	1.1 कुल उपनगरीय यात्री-किलोमीटर (पीकेएम) की उपलब्धि (मिलियन में)	1,24,682

13. पुल संबंधी, सुरंग संबंधी कार्य एवं पहुंच मार्ग (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
2,557.96	1. पुल कार्यों की गति में वृद्धि	1.1. प्रारंभ किए गए पुल कार्यों की संख्या	2,600	1. नेटवर्क पर गति प्रतिबंधों में कमी	1.1. हटाए गए गति प्रतिबंधों की संख्या	12

14. **मशीनरी एवं संयंत्र (सीएस)**

वित्तीय परिव्यय (रु. करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
649.49	1. नई मशीनरी को बदलना और संयंत्र का संस्थापन	1.1 प्रतिस्थापन खाते पर खर्च की जाने वाली मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य (रु. करोड़ में)	300	1. रेलवे परिसंपत्तियों का कारखानों और उत्पादन इकाइयों में समयबद्ध एवं दक्ष रखरखाव	1.1 लक्षित उत्पादन के सापेक्ष प्राप्त रोलिंग स्टॉक उत्पादन (%)	100
		1.2 अतिरिक्त खाते पर खर्च की जाने वाली मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य (रु. करोड़ में)	900			
		1.3 आरआरएसके[337] खाते पर खर्च की जाने वाली मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य (रु. करोड़ में)	300		1.2 सेवित चल स्टॉक का बकाया अनुरक्षण (%)	0

[337] *राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष*

1. सड़क स्कंध (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
3,09,291.77[338]	1. सभी योजनाओं में देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क नेटवर्क का विकास	1.1. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सभी योजनाओं में निर्मित कुल सड़क की लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग (किमी में)	10,000	1. आवाजाही में सुगमता	1.1. विगत वित्त वर्ष की तुलना में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लेन 4 (में %) राजमार्ग में परिवर्तन	8
					1.2. विगत वित्त वर्ष की तुलना में एकल लेन/इंटरमीडिएट लेन रारा में परिवर्तन (% में)	10
		1.2. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में निर्मित रारा की लंबाई (किमी में)	1,200			
		1.3. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जनजातीय क्षेत्र में निर्मित रारा की लंबाई (किमी में)	400			
		1.4. राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित हाई स्पीड कॉरिडोर की संचयी लंबाई (किमी में)	6,000			
	2. निजी निवेश	2.1 वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी पीपीपी परियोजनाओं के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास में निजी क्षेत्र के रियायतग्राहियों द्वारा निवेश की गई राशि (करोड़ रुपये में)	30,000	2. पीपीपी संविदाओं में वृद्धि	2.1 वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल सौंपी गई लंबाई के % के रूप में सौंपे गए पीपीपी अनुबंध।	30
	3. राष्ट्रीय राजमार्ग का परिसंपत्ति मुद्रीकरण	3.1 वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के मुद्रीकरण से जुटाई गई धनराशि (करोड़ रुपये में)	30,000	3. अतिरिक्त संसाधन जुटाना	3.1 चालू वित्त वर्ष में परिसंपत्ति मुद्रीकरण से जुटाए गए बजटीय संसाधन	9
	4. सड़क सुरक्षा	4.1 वर्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों पर	1,000	4. दुर्घटनाओं में	4.1 विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में	लक्ष्य

[338] *सड़क कार्यः 1,21,998.61 करोड़;एनएचएआईः 1,87,293.16 करोड़*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		ब्लैक स्पॉट हटाए जाने की संख्या		कमी	प्रति 10,000 किमी पर सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में कमी (% में)	निर्धारित नहीं किए जा सकते
		4.2 वर्तमान वित्त वर्ष में विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) डेटा के माध्यम से चिन्हित किए दुर्घटना स्थल पर किये गए अल्पकालिक उपाय (संख्या में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते		4.2 पिछले वित्त वर्ष की तुलना में प्रति 10,000 किमी सड़क दुर्घटना की मौतों में कमी (% में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
	5. मार्गस्थ सुविधाएं और टोल प्रतीक्षा समय	5.1 वर्तमान वित्त वर्ष में सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्गस्थ सुविधा संबंधी अनुबंधों की संख्या	80	5. प्रयोक्ता सुविधा में सुधार	5.1 वर्तमान वित्त वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित मार्गस्थ सुविधाएं (संख्या में)	150
		5.2 मल्टी लेन बाधारहित टोलिंग सिस्टम (किमी में) द्वारा कवर की गई एनएच लंबाई	1,200		5.2 चालू वित्त वर्ष में टोल पर प्रतीक्षा समय (सेकंड में)	40

ग्रामीण विकास विभाग

1. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27[339]
54,916.70	1. पर्याप्त बुनियादी सेवाओं से युक्त पक्के आवासों का निर्माण	1.1. निर्मित आवासों की संख्या (शौचालय सहित) (लाख में)	40	1. अधिक से अधिक परिवार बुनियादी सुविधाओं और आजीविका के अवसरों तक पहुंच के साथ गरिमापूर्ण आवासों में रहते हैं।	1.1. आवासहीनता में कमी (% में)	80
		1.2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए निर्मित आवासों की संख्या (लाख में)	16.46			
		1.3. महिला लाभार्थियों/ संयुक्त रूप से महिला और पुरुष लाभार्थियों के स्वामित्व वाले आवासों का %	100		1.2. घरेलू आय में वृद्धि वाले परिवारों का %	20
				2. प्रवास में कमी	2.1. ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने वाली जनसंख्या के % में गिरावट	5

[339] *मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्टों के आधार पर परिणाम संकेतकों से संबंधित प्रगति वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी।*

2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
19,000	1. बारहमासी सड़कों की गुणवत्ता की उपलब्धता और उनका समय पर रखरखाव	1.1. पीएमजीएसवाई-IV के तहत जोड़ी जाने वाली सड़क लंबाई (किलोमीटर में)	26,000	1. पात्र बस्तियों की बारहमासी सड़क संपर्कता के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और गतिशीलता तक पहुंच के लिए मार्ग।	1.1. पीएम जनमन के तहत जुड़ी पात्र बस्तियों का %	100[340]
		1.2. हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सड़क लंबाई का निर्माण (किलोमीटर में)	12,000[341]			
		1.3. एनक्यूएम द्वारा निरीक्षण किए गए कार्यों की संख्या	4,000			
		1.4. पिछले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एनक्यूएम द्वारा वर्गीकृत पूर्ण परियोजनाओं का औसत असंतोषजनक %, जो अनसुलझी रही	<4		1.2. पीएमजीएसवाई-IV के तहत जुड़ी पात्र बस्तियों का %	100
		1.5. एनक्यूएम द्वारा वर्गीकृत रखरखाव परियोजनाओं का औसत असंतोषजनक %, जो चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अनसुलझी रही।	<15			
		1.6. मेरी सड़क ऐप पर पंजीकृत शिकायतों में से 3 महीने से अधिक पुरानी पीएमजीएसवाई से संबंधित शिकायतों का समाधान %	100			
		1.7. वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम (किलोमीटर में) के तहत सड़क लंबाई का निर्माण	830			
		1.8. पीएम-जनमन के तहत बनी सड़कों की लंबाई (किलोमीटर में)	4,400			

[340] *4200*

[341] *100 प्रतिशत*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		1.9. पात्र बस्तियों की संख्या की तुलना में जुड़ी हुई पात्र बस्तियों का %	100			
		1.10. पात्र बस्तियों की संख्या की तुलना में पीएम-जनमन के तहत जुड़ी हुई पात्र बस्तियों का %	100			
		1.11. पात्र बस्तियों की संख्या की तुलना में पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत जुड़ी हुई पात्र बस्तियों का %	100			

3. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
19,200	1. स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का पूंजीकरण	1.1. प्रदान की गई परिक्रामी निधि (आरएफ) और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) (करोड़ में)	7,500	1. गरीबों के लिए सतत आजीविका सेवाएँ	1.1. किसान उत्पादक संगठन (उत्पादक समूह और उत्पादक उद्यम) में शामिल महिला किसानों की संख्या (लाख में)	6

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	2. गरीबों के लिए सतत आजीविका सेवाएं	2.1. सतत आजीविका पद्धतियों में प्रशिक्षित महिला किसानों की संख्या (लाख में)	75	2. एसएचजी का वित्तीय समावेशन	2.1. बैंक ऋण से लाभान्वित एसएचजी की संख्या (लाख में).[342]	42
	3. छोटे व्यापार चलाने वाले एसएचजी सदस्य	3.1. पिछले वित्त वर्ष में स्टार्टअप विलेज एन्ट्रेप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) द्वारा समर्थित उद्यम % जो वर्तमान वित्त वर्ष में भी संचालित हो रहे हैं	90		2.2. एसएचजी द्वारा लिए गए बैंक ऋण की औसत राशि.[343] (लाख में)	3.50
	4. कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति	4.1. दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	2.8	3. डीडीयू-जीकेवाई के माध्यम से नियुक्ति और आरएसईटीआई योजना के माध्यम से स्वरोजगार	3.1. डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत नियोजित व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	1.96
		4.2. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	6.8		3.2. आर.एस.ई.टी.आई. के अन्तर्गत स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	4.8

4. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27	परिणाम 2026-27

[342] *बैंक ऋण के लिए लक्ष्य हर वर्ष तय किए जाते हैं।*

[343] *उक्त*

2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
9,671	**क. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)**					
	1. लाभार्थियों का कवरेज	1.1. लाभार्थियों के खाते से आधार लिंक (%)	100	1. आवश्यक सामाजिक सहायता पाने वाले लाभार्थी	1.1. वि.व. 26-27 में कितने प्रतिशत लाभार्थियों ने संतुष्टि जताई	80.[344]
	2. लाभार्थियों को समय पर लाभ मिलना	2.1. समय पर भुगतान पाने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत	80.[345]			
	3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान पाने वाले लाभार्थी	3.1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताए गए डीबीटी लेनदेन की संख्या (करोड़ में)	16			
	ख. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)					
	1. लाभार्थियों का कवरेज	1.1. लाभार्थियों के खाते से आधार लिंक (%)	100	1. आवश्यक सामाजिक सहायता पाने वाले लाभार्थी	1.1. वि.व. 26-27 में कितने प्रतिशत लाभार्थियों ने संतुष्टि जताई	80.[346]
	2. लाभार्थियों को समय पर लाभ मिलना	2.1. समय पर भुगतान पाने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत	80.[347]			
	3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान पाने वाले लाभार्थी	3.1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताए गए डीबीटी लेनदेन की संख्या (करोड़ में)	4.38			
	ग. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय द्वियांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)					
	1. लाभार्थियों का कवरेज	1.1. लाभार्थियों के खाते से आधार लिंक (%)	100	1. आवश्यक सामाजिक सहायता पाने वाले लाभार्थी	1.1. वि.व. 26-27 में कितने प्रतिशत लाभार्थियों ने	80.[348]
	2. लाभार्थियों को समय पर लाभ	2.1. समय पर भुगतान पाने वाले	80.[349]			

[344] एनएलएम रिपोर्ट के आधार पर लाभार्थियों का संतुष्टि स्तर प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया जाएगा।

[345] लाभार्थियों को पेंशन का समय पर भुगतान करने का प्रदर्शन एनएलएम रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया जाएगा।

[346] एनएलएम रिपोर्ट के आधार पर लाभार्थियों का संतुष्टि स्तर प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया जाएगा।

[347] लाभार्थियों को पेंशन का समय पर भुगतान करने का प्रदर्शन एनएलएम रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया जाएगा।

[348] एनएलएम रिपोर्ट के आधार पर लाभार्थियों का संतुष्टि स्तर प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया जाएगा।

[349] लाभार्थियों को पेंशन का समय पर भुगतान करने का प्रदर्शन एनएलएम रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया जाएगा।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	मिलना	लाभार्थियों का प्रतिशत			संतुष्टि जताई	
	3. डीबीटी के माध्यम से भुगतान पाने वाले लाभार्थी	3.1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताए गए डीबीटी लेनदेन की संख्या (करोड़ में)	0.62			
	घ. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)					
	1. लाभार्थियों का कवरेज	1.1. लाभार्थियों के खाते से आधार लिंक (%)	100	1. आवश्यक सामाजिक सहायता पाने वाले लाभार्थी	1.1. वि.व 26-27 में कितने प्रतिशत लाभार्थियों ने संतुष्टि जताई	80
	2. लाभार्थियों को समय पर लाभ मिलना	2.1. समय पर भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत	80			

5. विकसित भारत - जी-राम-जी (सी.एस.एस.)

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,25,692.31*	1. रोजगार एवं आजीविका सुरक्षा	1.1. सृजित श्रम दिवसों की संख्या (करोड़ में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता [350]	1. मजदूरी आय सहायता प्रदान करना	1.1. प्रति परिवार द्वारा प्राप्त औसतन श्रम-दिवस	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा

**इसमें मनरेगा-कार्यक्रम घटक के लिए रु.30,000/- तथा वीबी-जी-आरएएम-जी के लिए रु.95,692.31/- शामिल है।*

[350] *विकसित भारत - जी-राम-जी एक मांग आधारित कार्यक्रम है। कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किए जाते हैं तथा इनके निष्पादन के लिए कोई पूर्व-निर्धारित लक्ष्य नहीं होता। अतः वर्ष 2026-27 के लिए आउटकम/लक्ष्य का पूर्वानुमान संभव नहीं है। हालांकि, विभिन्न संकेतकों पर की गई उपलब्धियों की जानकारी वर्ष के दौरान त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।*

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	प्रदान करना	1.2. वर्ष के दौरान सृजित कुल परिसंपत्तियों की संख्या (संख्या में)				सकते[351]
		1.3. अभिसरण के माध्यम से सृजित कुल परिसंपत्तियों की संख्या (संख्या में)				
		1.4. मांगे गए रोज़गार की तुलना में लोगों को मिले रोज़गार का %	100%			
	2. ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजना (विकेंद्रीकृत योजना) एवं स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन	2.1 कुल ग्राम पंचायतों के सापेक्ष भू-सूचना प्रणाली आधारित साधनों एवं पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए तैयार एवं स्वीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं की संख्या (केवल उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जहाँ विकसित भारत - जी-राम-जी अधिसूचित है)[352]	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता [353]	2. विकसित ग्राम पंचायतों के लिए ग्रामीण परिसंपत्तियों का सृजन	2.1. जल सुरक्षा से संबंधित कार्यों की संख्या	

[351] विकसित भारत - जी-राम-जी एक मांग आधारित कार्यक्रम है। कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किए जाते हैं तथा इनके निष्पादन के लिए कोई पूर्व-निर्धारित लक्ष्य नहीं होता। अतः वर्ष 2026-27 के लिए आउटकम/लक्ष्य का पूर्वानुमान संभव नहीं है। हालांकि, विभिन्न संकेतकों पर की गई उपलब्धियों की जानकारी वर्ष के दौरान त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।.

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		2.2 पूर्ण कार्यों की संख्या			2.2. मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित कार्यों की संख्या	
	3. शासन, निगरानी एवं जवाबदेहिता में डिजिटल तकनीक का उपयोग	3.1. संरचनात्मक जियो-टैग एवं जियो-फैंसिंग किए गए कार्यों का प्रतिशत	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता [354]		2.3. आजीविका अवसंरचना से संबंधित कार्यों की संख्या	
		3.2. डिजिटल रूप से (मुख प्रमाणीकरण द्वारा) उपस्थिति दर्ज किए गए कार्मिकों का प्रतिशत			2.4. प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के शमन से संबंधित कार्यों की संख्या	
		3.3. कार्य स्थलों के निरीक्षण का प्रतिशत (क्षेत्र अधिकारी ऐप)		3. सामाजिक अंकेक्षण का प्रभावी संचालन	3.1. पंचायत निर्णय ऐप का उपयोग करते हुए किए गए सामाजिक अंकेक्षण वाली ग्राम सभाओं की संख्या	

[353] विकसित भारत - जी-राम-जी एक मांग आधारित कार्यक्रम है। कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किए जाते हैं तथा इनके निष्पादन के लिए कोई पूर्व-निर्धारित लक्ष्य नहीं होता। अतः वर्ष 2026-27 के लिए आउटकम/लक्ष्य का पूर्वानुमान संभव नहीं है। हालांकि, विभिन्न संकेतकों पर की गई उपलब्धियों की जानकारी वर्ष के दौरान त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।.

[354] विकसित भारत - जी-राम-जी एक मांग आधारित कार्यक्रम है। कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किए जाते हैं तथा इनके निष्पादन के लिए कोई पूर्व-निर्धारित लक्ष्य नहीं होता। अतः वर्ष 2026-27 के लिए आउटकम/लक्ष्य का पूर्वानुमान संभव नहीं है। हालांकि, विभिन्न संकेतकों पर की गई उपलब्धियों की जानकारी वर्ष के दौरान त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।.

वित्तीय परिव्यय (रुपये करोड़ में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		3.4. पूर्ण कार्यों के लिए ग्राम सभाओं द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षणों की संख्या				

भूमि संसाधन विभाग

1. वाटरशेड विकास घटक - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
2,500	1. वाटरशेड परियोजनाओं में वर्षा सिंचित/ अवक्रमित भूमि का विकास	1.1. सृजित / नवीकृत जल संचयन संरचनाओं की संख्या (वित्तीय वर्ष 2026-27 में)	57,959	1. वाटरशेड परियोजनाओं की बेहतर दक्षता	1.1. शून्य से एकल फसल/एकल फसल से अधिक फसलों के तहत लाया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में) (वित्तीय वर्ष 2026-27 में)	1,03,089
		1.2. शामिल अवक्रमित भूमि का क्षेत्र/विकसित वर्षा सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में) (वित्तीय वर्ष 2026-27 में)	5,50,434		1.2. विविधीकृत फसलों/ क्रॉपिंग प्रणालियों में परिवर्तन के तहत लाया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में) (वित्तीय वर्ष 2026-27 में)	90,539
		1.3. मृदा तथा नमी संरक्षण संबंधी कार्यकलापों के तहत शामिल क्षेत्र (हेक्टेयर में) (वित्तीय वर्ष 2026-27 में)	1,37,442		1.3. सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत लाया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में) (वित्तीय वर्ष 2026-27 में)	1,05,154
		1.4. पौधरोपण (वनीकरण/बागवानी इत्यादि) के तहत लाया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में) (वित्तीय वर्ष 2026-27 में)	46,824		1.4. सकल फसली क्षेत्र में वृद्धि (हेक्टेयर में) (वित्तीय वर्ष 2026-27 में)	2,00,000
		1.5. पुनरुद्भूत झरनों की संख्या (वित्तीय वर्ष 2026-27 में)	727		1.5. लाभान्वित किसानों की संख्या (वित्तीय वर्ष 2026-27 में)	3,41,964
					1.6. भूजल स्तर में सुधार (मीटर में) (वित्तीय वर्ष 2026-27 में)	2-3 [355]

[355] *एमबीजीएल = भू-स्तर से नीचे (मीटर में) (परियोजना के 3 वर्ष पूरे होने के बाद)*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

1. विज्ञान धारा (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
1,425	**क. एसटीआई नीतिगत सहायता**					
	1. एसटीआई[356] नीति अनुसंधान पारितंत्र को सुदृढ़ करना	1.1 समर्थित नीति अनुसंधान केंद्रों (नए और जारी) की संख्या	10	1. नीति अनुसंधान में सुधार	1.1 सीपीआर द्वारा जारी नीति ब्रीफ़ की संख्या	10
		1.2 समर्थित नीति अनुसंधान अध्येताओं (नए और जारी) की संख्या	10		1.2 प्रशिक्षित नीतिगत पेशेवरों की संख्या	20
		1.3 समर्थित एनएसटीएमआईएस [357]अध्ययनों (नए और जारी) की संख्या	25			
	ख. एस एंड टी मानव क्षमता वर्धन					
	1. एस एंड टी [358]क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं और विद्यालय स्तर पर मानव संसाधन छात्रों की संख्या	1.1 जागरूकता सृजन हेतु आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	30	1. वैज्ञानिक समुदायों के बीच अनुसंधान, नवाचार और वैज्ञानिक प्रवृति को बढ़ावा देना।	1.1 मानक कार्यक्रम के अंतर्गत नवाचार का विचार प्रस्तुत करने वाले छात्रों की संख्या	10,00,000
		1.2 इंस्पायर मानक पुरस्कारों के अंतर्गत चयनित नवाचारी विचारों की संख्या	50,000		1.2 प्रतिभाग करने वाले विद्यालयों की संख्या	5,00,000

[356] *साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन*

[357] *नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम*

[358] *साइंस एंड टेक्नोलॉजी*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	बढ़ाना	1.3 समर्थित इंस्पायर अध्येतावृत्ति की संख्या	3,200		1.3 मानक के अंतर्गत जागरूकता सृजन हेतु आयोजित कार्यशालाओं की कुल संख्या	60
		1.4 आयोजित इंटर्नशिप विज्ञान शिविरों की संख्या	100		1.4 उन अध्येताओं की संख्या जिन्होंने अध्येतावृत्ति की अवधि पूरी की	130
		1.5 समर्थित इंस्पायर संकाय अध्येतावृत्ति की संख्या	400		1.5 समकक्षों द्वारा समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या	400
		1.6 समर्थित एसएचई छात्रवृत्ति की संख्या	25000		1.6 लाभान्वित छात्रों की संख्या	15,000
		1.7 समर्थित वाइज़-पीएच.डी. (नए और जारी) की संख्या	300		1.7 प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में शामिल होने वाले उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (एसएचई) छात्रों की संख्या	4,000
		1.8 समर्थित वाइज़-पीडीएफ (नए और जारी) की संख्या	436		1.8 प्राकृतिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम में शामिल होने वाले एसएचई छात्रों की संख्या	250
		1.9 आईपीआर में समर्थित वाइज़-इंटर्नशिप (नए और जारी) की संख्या	100		1.9 लाभान्वित महिला वैज्ञानिकों की संख्या	800
		1.10 विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाली छात्राओं (9वीं से 12वीं कक्षा) की संख्या।	30,000		1.10 वाइज़ अध्येताओं द्वारा एससीआई पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या	200
		1.11 विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत	300		1.11 मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करने	30,000

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
		समर्थित विद्यालयों की संख्या			वाली लड़कियों की संख्या	
		1.12 स्टेम में महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व के लिए समर्थित संस्थानों की संख्या	65		1.12 सरकारी क्षेत्र में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की संख्या	620
		1.13 वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	28			
	ग. आर एंड डी अवसंरचना विकास					
	1. आर एंड डी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना	1.1 समर्थित विश्वविद्यालयों/विभागों/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या	125	1. आर एंड डी सुविधाओं में सुधार करना	1.1 सुविधाओं का उपयोग करने वाले अनुसंधानकर्ताओं की संख्या	41,600
		1.2 समर्थित अनुसंधान सुविधाओं की संख्या	810		1.2 विश्लेषित नमूनों की संख्या	91,100
		1.3 एफआईएसटी के अंतर्गत विभिन्न केंद्रों में संवर्धित उपकरणों/सुविधाओं की संख्या	20		1.3 सुविधाओं के उपयोग से होने वाली आय (करोड़ में)	13.5
		1.4 समर्थित साथी केंद्रों की संख्या	04		1.4 साथी कार्यक्रम के अंतर्गत मेजबान संस्थान और बाहरी स्रोतों से उपयोगकर्ताओं की संख्या	550
		1.5 स्तुति के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	10		1.5 उद्योगों, एमएसएमई, स्टार्टअप आदि से उपयोगकर्ताओं की संख्या	180
					1.6 स्तुति के अंतर्गत प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ताओं की संख्या (पीएचडी, एमएससी, संकाय सदस्य, वैज्ञानिक)	2,500

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
					1.7 स्तुति के अंतर्गत वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में जागरूक किए गए छात्रों की संख्या	1,500
	घ. अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग					
	1. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर एंड डी के पारितंत्र को बढ़ावा देना।	1.1 समर्थित गैर-औद्योगिक अंतर्राष्ट्रीय आर एंड डी परियोजनाओं (नई और चालू) की संख्या	370	1. एस एंड टी पारितंत्र की गुणवत्ता में सुधार	1.1 एससीआई पत्रिकाओं में संयुक्त प्रकाशनों की संख्या	500
		1.2 समर्थित अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक आर एंड डी परियोजनाओं (नई और चालू) की संख्या	20		1.2 इस प्रकार के सहयोग से फाइल किए गए पेटेंटों की संख्या	20
		1.3 वर्ष के दौरान दी गई अध्येतावृत्तियों की संख्या (आंतरिक और बाह्य) (वैभव फैलोज़ सहित)	150		1.3 इस प्रकार के सहयोग से स्वीकृत पेटेंटों की संख्या	10
		1.4 आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं / विषयगत बैठकों की संख्या	75		1.4 विकसित प्रौद्योगिकियों की संख्या	15
		1.5 आयोजित एक्सपोजर दौरों की संख्या	750			
	ङ. मौलिक अनुसंधान हेतु मेगा सुविधाएं (एमएफबीआर)					
	1. मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशाल	1.1 समर्थित विशाल परियोजनाओं (नई और जारी) की संख्या	40	1. मूल अनुसंधान में प्रौद्योगिकी/ उत्पादों का विकास	1.1 विकसित किए गए प्रोटोटाइपों की संख्या	4
		1.2 विशाल परियोजनाओं में योगदान देने	20		1.2 उद्योग को अंतरित प्रौद्योगिकियों की	5

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	सुविधाओं को सुदृढ़ करना	वाले भारतीय उद्योगों की संख्या			संख्या	
					1.3 विशाल परियोजनाओं को भारतीय वस्तुगत योगदान के रूप में आपूर्ति किए गए उच्च-तकनीकी घटकों की संख्या	100
					1.4 उत्पन्न पीएचडी की संख्या	15
					1.5 एससीआई पत्रिकाओं में शोध प्रकाशनों की संख्या	50
					1.6 उपयोग के लिए उपलब्ध अनुसंधान सुविधाओं की संख्या	8
	च. प्रोटोटाइपिंग, फैब्रिकेशन और इनक्यूबेशन सुविधाएं (पीएफआईएफ)					
	1. प्रौद्योगिकी विकास को सहायता देने, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और नवाचार के संवर्धन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए।	1.1 समर्थित टीबीआई/सीओई/आईटीबीआई (नए और जारी) की संख्या	40	1. प्रौद्योगिकी विकास, परिनियोजन और स्टार्टअप पारितंत्र को सुदृढ़ करना	1.1 लाभान्वित नवप्रवर्तकों/उद्यमियों की संख्या	800
		1.2 समर्थित प्रयास केंद्रों (पीसी) (नए और जारी) की संख्या	50		1.2 समर्थित प्रौद्योगिकियों की संख्या	80
		1.3 सीड सपोर्ट/एक्सेलेरेटर द्वारा समर्थित इनक्यूबेटरों की संख्या (नए और जारी)	42			
		1.4 समर्थित प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं (नए और जारी) की संख्या	250			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	छ. विज्ञान और समाज के संबंध (एसएससी)					
	1. समाज को परस्पर जोड़ना और संचार के विभिन्न माध्यमों से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को लोकप्रिय बनाना।	1.1 समर्थित परियोजनाओं (नए और जारी) की संख्या	220	1. सामाजिक आवश्यकताओं और संचार को संबोधित करने हेतु उद्यमिता और प्रौद्योगिकी परिनियोजन को बढ़ावा देने हेतु पारितंत्र का निर्माण करना।	1.1 सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिनियोजित प्रौद्योगिकियों की संख्या	100
		1.2 आयोजित प्रदर्शनियों और मेलों की संख्या	7		1.2 सामाजिक परियोजनाओं से लाभान्वित होने वालों की संख्या	10,000
		1.3 छात्र केंद्रित गतिविधियों की संख्या	650		1.3 आगंतुकों की संख्या	1,00,000
		1.4 अनसंधानकर्ता केंद्रित गतिविधियों की संख्या	10		1.4 लाभान्वित स्कूली बच्चों की संख्या	2,54,000
		1.5 जनमानस के लिए स्टेम प्रदर्शित गतिविधियों की संख्या	120		1.5 लोकप्रिय/प्रौद्योगिकीय लेखन में शामिल अनुसंधानकर्ताओं की संख्या	2,000
		1.6 आयोजित प्रदर्शनियों और मेलों की संख्या	20		1.6 प्रतिभागियों की संख्या	10,00,000
					1.7 औद्योगिक दौरों से अवगत कराए गए छात्रों की संख्या	2,000
	ज. राज्य एस एंड टी साझेदारी					
	1. राज्य एस एंड टी साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए	1.1 समर्थित एसएसटीसी की कुल संख्या	28	1. व्यवस्थित बेहतरकारी उपायों के माध्यम से राज्य स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और	1.1 सुगमित आईपी फाइलिंग की संख्या	2000
		1.2 स्थानीय विशिष्ट मुद्दों के समाधान हेतु समर्थित आर एंड डी परियोजनाओं (नए और जारी) की संख्या	30		1.2 प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों की संख्या	40
					1.3 लाभार्थियों की संख्या	10,000

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
				नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना।		
	झ. अनुसंधान एवं विकास सहायता कार्यक्रम					
	1. मूल और अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास नेटवर्क को सुदृढ़ करना	1.1 समर्थित अनुसंधान परियोजनाओं (नए और जारी) की संख्या	662	1. प्रौद्योगिकी विकास, व्यावसायीकरण और अनुसंधान क्षमता वर्धन हेतु	1.1 विकसित प्रौद्योगिकियों की संख्या	27
		1.2 समर्थित राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठों की संख्या	28		1.2 प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों की संख्या	37
					1.3 व्यावसायीकृत प्रौद्योगिकियों/उत्पादों की संख्या	7
					1.4 परिनियोजित अनुसंधान सुविधाओं/परीक्षण केंद्रों की संख्या	14
	ञ. समग्र संकेतक					
	1. सामूहिक जानकारी प्रदान करना	1.1 आयोजित क्षमता वर्धन कार्यक्रमों की संख्या	180	1. अनुसंधान परिणाम प्रदान करना	1.1 उन्नत मानव संसाधन कौशल की संख्या	4260
					1.2 एससीआई पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या	5380
					1.3 फाइल किए गए पेटेंटों की संख्या	14
					1.4 स्वीकृत पेटेंटों की संख्या	7

2. राष्ट्रीय अंतरविषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन (एनएम-आईसीपीएस) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
700	**क. प्रौद्योगिकी विकास**					
	1. प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों (टीआईएच) के माध्यम से साइबर-भौतिक प्रणाली और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।	1.1 अंतरविषयक साइबर भौतिक प्रणालियों (नए और जारी) में समर्थित प्रौद्योगिकी विकास पहलों की संख्या	1200	1. उन्नत प्रौद्योगिकी विकास	1.1 विकसित प्रौद्योगिकियों और प्रौद्योगिकी उत्पादों की संख्या	200
		1.2 अंतरविषयक साइबर भौतिक प्रणाली में अंतराष्ट्रीय सहयोगों की संख्या	20		1.2 एससीआई[359] पत्रिकाओं में शोध पत्रों की संख्या	250
					1.3 साइबर भौतिक प्रणाली (सीपीएस)-टीआईएच में शामिल अनुसंधानकर्ताओं की संख्या	250
					1.4 फाइल प्रस्तुत किए गए पेटेंटों की संख्या	20
					1.5 स्वीकृत पेटेंटों की संख्या	0
	ख. नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र					
	1. प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों (टीआईएच) के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहन देना	1.1 संचयी रूप से समर्थित टीबीआई (नए और जारी) की संख्या	25	1. प्रौद्योगिकी और उद्यमिता को बढ़ावा देना	1.1 लाभान्वित स्टार्टअप्स की संख्या	100
		1.2 सीपीएस के तहत समर्थित उद्यमिता कार्यक्रमों की संख्या	60			

[359] *साइंस साइटेशन इंडेक्स*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
		1.3 आयोजित की गई व्यापक चुनौतियों और प्रतियोगिताओं की संख्या	06			
	ग. मानव संसाधन विकास					
	1. प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों (टीआईएच) के माध्यम से मानव संसाधन विकास	1.1 स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्येतावृत्ति तथा डॉक्टरेट एवं पोस्ट-डॉक्टरेट अध्येतावृत्ति के अंतर्गत समर्थित वैज्ञानिकों की संख्या	600	1. अगली पीढ़ी के मानव संसाधनों का संवर्धन	1.1 कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से लाभार्थियों की संख्या	10,000

3. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
900	1. थिमेटिक हबों (टी-हब) का गठन	1.1 समर्थित टी-हबों की संख्या	4	1. प्रौद्योगिकी विकास	1.1 विकसित प्रौद्योगिकियों की संख्या	87
					1.2 फाइल किए गए पेटेंटों की संख्या	34

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
					1.3 एससीआई पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या	133
				2. मानव संसाधन विकास	2.1 समर्थित अध्येतावृत्ति की संख्या	206
					2.2 स्तरोन्नयित मानव संसाधन कौशल की संख्या	1281
					2.3 आयोजित कार्यशालाओं/सम्मेलनों की संख्या	47
				3. उद्यमिता विकास	3.1 समर्थित स्टार्टअप्स की संख्या	36
				4. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	4.1 कार्यान्वित अंतरराष्ट्रीय सहयोगों की संख्या	39

बायोटेक्नोलॉजी विभाग

1. जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार तथा उद्यमिता विकास (बायो-राइड) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
2,300.00	1. प्रतिस्पर्धी अनुसंधान अनुदान।	1.1. वर्ष की शुरूआत में जारी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या।	882	1. प्रतिस्पर्धी अनुसंधान अनुदान।	1.1. वर्ष के दौरान सूचित अनुसंधान प्रकाशन की संख्या।	516
		1.2. वर्ष के दौरान संस्वीकृत की जाने वाली नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या।	473		1.2. वर्ष के दौरान विकसित (रिपोर्टिड) उत्पादों/प्रौद्योगिकियों प्रक्रियाओं की संख्या।	51
		1.3. जारी परियोजनाओं में सहायता प्राप्त मानव संसाधन (जेआरएफ/ एसआरएफ/ आरए) की संख्या।	2,167		1.3. वर्ष के दौरान दायर/प्रदत्त आईपी (पेटेंट/ ट्रेडमार्क/ डिजाइन/ कॉपी राइट/जीआई) की संख्या।	44
					1.4. वर्ष के दौरान विकसित डाटाबेस/टूल्स की संख्या।	55
		1.4. बीटीआईएस-नेट के तहत सहायता प्राप्त केंद्रों की संख्या।	50			
	2. जैवप्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण: मानव संसाधन विकास और अवसंरचना।	2.1 वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त अध्येतावृत्तियों (डीबीटी-जेआरएफ, डीबीटी-आरए, टाटा इनोवेशन, एचजीके-आईवाईबीएफ, डीबीटी आरआरएफ, एमकेबी-वाईआर, बायोकेयर अध्येतावृत्ति कार्यक्रम) की संख्या।	2,120	2. जैवप्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण: मानव संसाधन विकास और अवसंरचना।	2.1 आरआरएसएफ कार्यक्रम के तहत अनुसंधान सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या।	30,000

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
		2.2 सहायता प्राप्त राष्ट्रीय सुविधाओं/उन्नत प्रयोगशालाओं (आरआरएसएफपी) की संख्या।	30		2.2 स्टार कॉलेजों से स्नातकोतर पाठ्यक्रमों के लिए विकल्प चुनने वाले छात्रों की संख्या।	1,000
		2.3 स्टार कॉलेज कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त कालेजों की संख्या।	130		2.3 आयोजित सम्मेलनों/लोकप्रिय व्याख्यानों/प्रदर्शनियों की संख्या (सीटीईपी)।	600
		2.4 सीटीईपी के तहत सहायता प्राप्त कार्यक्रमों की संख्या।	650			
		2.5 सहायता प्राप्त बायो-टेक पार्कों की संख्या।	5			
	3. सामाजिक विकास के लिए जैवप्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम।	3.1 यूएमएमआईडी पहल के तहत स्थापित/ सहायता प्राप्त निदान केंद्रों की संख्या (महत्वाकांक्षी जिले)।	43	3. सामाजिक विकास के लिए जैवप्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम।	3.1 यूएमएमआईडी के तहत गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की संख्या, जिनकी जांच आनुवांशिक रोगों के लिए की गई।	30,000
		3.2 वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त जैवप्रौद्योगिक आधारित सामाजिक परियोजनाओं की संख्या।	13		3.2 बायोटेक किसान हब से लाभान्वित किसानों की संख्या।	2,000
		3.3 सहायता प्राप्त बायोटेक-किसान हब की संख्या।	8			
	4. अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग।	4.1 अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के तहत शामिल देशों की संख्या।	15	4. अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग।	4.1 बीआरसीपी से प्राप्त प्रौद्योगिकियों की संख्या।	4
		4.2 बीआरसीपी (वेलकम ट्रस्ट - इंडिया अलाएंस) के तहत चलाये जा रहे सहायता प्राप्त अध्येतावृत्तियों की संख्या।	240			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	5. औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास।	5.1 सहायता प्राप्त बायो-इन्क्यूबेटर की संख्या।	120	5. औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास।	5.1 विकसित/ व्यवसायीकृत उत्पादों/ प्रौद्योगिकियों की संख्या।	75
		5.2 सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यक्रमों के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या।	158		5.2 दायर/प्रदत्त आईपी (पेटेंट/ ट्रेडमार्क डिजाइन/ कॉपीराइट/ जीआई) की संख्या।	55
		5.3 सहायता प्राप्त उद्यमियों, स्टार्ट-अप की संख्या।	3,632			
	6. जैव विनिर्माण और बायोफाउंड्री को सहायता।	6.1 मूलांकुर- बायोइनेबलर्स (बायोफाउंड्री, जैवविनिर्माण हब और बायो-एआई हब) सेटअप की संख्या।	65	6. जैव विनिर्माण और बायोफाउंड्री को सहायता।	6.1 मूलांकुर- बायोइनेबलर्स (बायोफाउंड्री, जैवविनिर्माण हब और बायो-एआई हब) के लाभार्थियों/उपयोगकर्ताओं की संख्या।	150
		6.2 जैवविनिर्माण के अभिचिन्हित किए गए विषयगत क्षेत्र/उपक्षेत्रों में कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या।	325		6.2 जैवविनिर्माण के तहत प्रमाणित संकल्पना साक्ष्यों की संख्या।	75
		6.3 स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या।	5			
		6.4 आयोजित वेबिनारों की संख्या।	25			

1. पीएम सेतु योजना (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2025-26		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
6140.50	**क. उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशलीकरण और रोजगार क्षमता परिवर्तन (पीएमएसईटीयू) आईटीआई**					
	1. संस्थागत मानकों में सुधार करना	1.1 उन्नत अवसंरचना मानकों का लक्ष्य प्राप्त करने वाले आईटीआई की संख्या	30	1. छात्रों के अधिगम में सुधार	1.1 उत्तीर्ण छात्रों के प्रारंभिक वेतन स्तर में वेतन वृद्धि औसत (%)	5
		1.2 उद्योग मार्गदर्शन संचालित एसपीवी मॉडल द्वारा प्रबंधित आईटीआई क्लस्टर की संख्या	15[360]		1.2 उन्नत आईटीआई में नामांकन में प्रतिशत वृद्धि का %	5
		1.3 हब एंड स्पोक आईटीआई में प्रशिक्षक पदों की रिक्ति में कमी	5%		1.3 उन्नत आईटीआई.[361] (हब एंड स्पोक) में महिला नामांकन में वृद्धि का %	20
		1.4 एनएसटीआई के लिए हस्ताक्षरित वैश्विक साझेदारी समझौता ज्ञापनों की संख्या	4			
		1.5 जॉब-अनुकूल सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यरत प्लेसमेंट सेल वाले आईटीआई का प्रतिशत	80		1.4 1.4 उन्नत आईटीआई (हब एंड स्पोक) में नियोजन में वृद्धि का %	5

[360] *हब स्पोक उद्योग क्लस्टर*

[361] *औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2025-26		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	2. पाठ्यक्रमों में सुधार तथा नए पाठ्यक्रम तैयार करना	2.1 उद्योग की आवश्यकता के अनुसार उन्नत किए गए मौजूदा पाठ्यक्रमों की संख्या	10	2. नए पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता	2.1 उन्नत आईटीआई (हब और स्पोक) में हाल ही में शुरू किए गए नए पाठ्यक्रमों में नामांकन में प्रतिशत वृद्धि	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
					2.2 हब या स्पोक में हाल ही में शुरू किए गए नए पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले छात्रों में प्रतिशत वृद्धि	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
		2.2 नए दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों को तैयार करना	5		2.3 नए तैयार पाठ्यक्रम से संतुष्टि व्यक्त करने वाले छात्रों का %	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
	3. उद्योग से संपर्क स्थापित करना और कौशल संवर्धन एवं क्षमता निर्माण करने वाले प्रशिक्षक	3.1 प्रशिक्षकों के लिए 50,000 के लक्ष्य की तुलना में सेवाकालीन/पुनश्चर्या प्रशिक्षण का %	15	3. नए सहयोगों की प्रभावशीलता और उद्योग स्तर आउटकम में सुधार	3.1 उद्योग सहयोग के माध्यम से शिक्षुता में नियोजित छात्रों का %	5
		3.2 उन्नत एनएसटीआई में नामांकन का %	70		3.2 आईटीआई के प्रशिक्षकों की गुणवत्ता पर उद्योग का फीडबैक	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

1. अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	**निर्गम 2026-27**			**परिणाम 2026-27**		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
6,360	1. अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्ति	1.1. चालू वर्ष में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या (लाखों में)	55.37	1. छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या में वृद्धि	1.1. छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए नामांकित अनुसूचित जाति के (नए) छात्र (लाख में)	30.45[362]
		1.2. चालू वर्ष में कवर की गई महिला लाभार्थियों की संख्या (लाखों में)	27.68[363]		1.2. छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों का प्रतिशत	100

[362] *कुल प्रस्तावित लक्ष्यों का 55%*

[363] *कुल प्रस्तावित लक्ष्यों का 50%*

2. प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27[364]**
2,140	1. चयनित अनुसूचित जाति बहुल गांवों का एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास	1.1. जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति द्वारा अनुमोदित ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपीएस)	7,700	1. गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना	1.1 50 निगरानी योग्य संकेतकों के आधार पर सुधार दर्शाने वाले चयनित गांवों की संख्या	6,600
		1.2. पूरे किए गए चिन्हित कार्यों की संख्या	7700		1.2 आदर्श ग्राम घोषित किए गए गांवों की संख्या	11,000
	2. अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण	2.1 स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	55	2. छात्रावास सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि	2.1 पिछले वर्षों में चालू किए गए छात्रावासों की निवास क्षमता में वृद्धि	5500
		2.2 चालू किए गए छात्रावासों की कुल संख्या	44			
	3. इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान जाता है	3.1 सहायता अनुदान (जीआईए) घटक के अंतर्गत सभी परियोजनाओं के लिए जारी की गई कुल राशि (रुपये करोड़ में)	550	3. अनुसूचित जाति के लाभार्थी/परियोजनाएं जिनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई	3.1 सहायता अनुदान घटक के तहत लाभान्वित अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की कुल संख्या	1,37,500
		3.2 सहायता अनुदान घटक	192.5		3.2 सहायता अनुदान घटक के	66,000

[364] 2025-26 के लिए प्रदान किए गए लक्ष्यों में 10% की वृद्धि के साथ 2026-27 के लिए लक्ष्य प्रस्तावित हैं। यदि आवश्यक हो, तो अगले वित्तीय चक्र के लिए योजना के मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद लक्ष्यों को संशोधित किया जा सकता है।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27[364]
		के कौशल विकास हस्तक्षेत्र के तहत संवितरित कुल राशि (रुपये करोड़ में)			कौशल विकास हस्तक्षेत्र के तहत लाभान्वित अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की कुल संख्या	
		3.3 सहायता अनुदान घटक के आय सृजन हस्तक्षेप के अंतर्गत संवितरित कुल राशि (रुपये करोड़ में)	302.5		3.3 सहायता अनुदान घटक के आय सृजन हस्तक्षेप के तहत लाभान्वित अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की कुल संख्या	77,000
		3.4 कौशल विकास हस्तक्षेप के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं की संख्या	660		3.4 राष्ट्रीय ढांचे के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या	66,000

3. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी[365] के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (यशस्वी) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
2,320	**क. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति**					
	1. छात्रवृत्ति के माध्यम से पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा पूरी करने के लिए ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	1.1 बजटीय आवंटन की तुलना में पात्र लाभार्थियों को जारी की गई निधियों का प्रतिशत	100	1. पोस्ट-मैट्रिक अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और डीएनटी छात्रों की संख्या में वृद्धि	1.1 छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश पाने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत	100
		1.2 चालू वित्त वर्ष में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	35			
		1.3 चालू वित्त वर्ष में कवर की गई महिला लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	11		1.2 छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश पाने वाली महिला लाभार्थियों का प्रतिशत	100
	ख. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति					
	1. छात्रवृत्ति के माध्यम से प्री-मैट्रिक शिक्षा पूरी करने के लिए ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को वित्तीय सहायता	1.1 बजटीय आवंटन की तुलना में पात्र लाभार्थियों को जारी की गई निधियों का प्रतिशत	100	1. प्री-मैट्रिक अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की संख्या में वृद्धि	1.1 छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश पाने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत	100
		1.2 चालू वित्त वर्ष में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	25			

[365] *ओबीसी-अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी -आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और डीएनटी-विमुक्त जनजातियां*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		1.3 चालू वित्त वर्ष में कवर की गई महिला लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	8		1.2 छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश पाने वाली महिला लाभार्थियों का प्रतिशत	100
	ग. ओबीसी के लिए बालकों और बालिकाओं के छात्रावास (सीएसएस)					
	1. छात्रावासों का निर्माण	1.1 पूरे हो चुके छात्रावासों की संख्या	8	1. छात्रावास सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि	1.1 पिछले वर्षों में चालू किए गए छात्रावासों में निवास क्षमता में वृद्धि।	10
		1.2 चालू किए गए छात्रावासों की संख्या	8			

4. अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
577.96	1. अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्ति	1.1 चालू वर्ष में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	27.42	1. छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि	1.1 छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए नामांकित (नए) छात्र (लाख में)	15.08[366]
		1.2 चालू वर्ष में कवर की गई महिला लाभार्थियों की संख्या (लाखों में)	13.71[367]		1.2 छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश पाने वाले छात्रों का प्रतिशत	100

[366] कुल प्रस्तावित लक्ष्यों का 55%

[367] कुल प्रस्तावित लक्ष्यों का 50%

अंतरिक्ष विभाग

1. अंतिरक्ष प्रौद्योगिकी (सी.एस.)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
10,397.06	1. गगनयान - भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम	1.1 मानव अनुकूलित प्रक्षेपण एवं कर्मीदल बचाव प्रणाली के विकास के लिए उड़ान परीक्षणों की संख्या	8	1. मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का विकास एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को सक्षम करना	1.1 % आयोजित परीक्षणों की संख्या के आधार पर भारतीय समानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए तैयारी का %	94
		1.2 मंदन प्रणाली सहित कक्षीय मॉड्यूल की तैयारी हेतु अर्हता परीक्षणों की संख्या	6			
		1.3 मिशन हेतु कर्मी दल प्रशिक्षण के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम मॉड्यूलों की संख्या	9		1.2 गगनयान मिशन के लिए विज्ञान प्रयोगों की तैयारी का %	82
	2. प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं/उन्नत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की शुरुआत	2.1 वर्ष के दौरान प्रारंभ नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या	310	2. उन्नत क्षमता के साथ ई.ओ. एवं स्थितिपरक सेवाओं की निरंतरता प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष ढाँचे का संवर्धन	2.1 भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के समर्थित कार्यक्रमों/गतिविधियों की संख्या	60
		2.2 वर्ष के दौरान पूरी की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या	298	3. स्वदेशी एवं विदेशी उपग्रहों के लिए प्रचालनात्मक प्रमोचन	3.1 स्वदेशी प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित इसरो के उपग्रहों का %	100

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	3. उपग्रहों का डिजाइन, विकास एवं प्रक्षेपण	3.1. वर्ष के दौरान प्रक्षेपित भू-प्रेक्षण (ई.ओ.) उपग्रहों की संख्या	0	सेवाएं सुनिश्चित करना	3.2 स्वदेशी प्रक्षेपण यानों द्वारा प्रक्षेपित विदेशी उपग्रहों की संख्या	3
		3.2. वर्ष के दौरान प्रक्षेपित नौवहन उपग्रहों की संख्या	2			
		3.3. वर्ष के दौरान प्रक्षेपित वैज्ञानिक / वाणिज्यिक / प्रयोक्ता वित्त पोषित अंतरिक्षयान की संख्या	10			
		3.4. वर्ष के दौरान प्रक्षेपित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन की संख्या	3			
	4. अनुसंधान एवं विकास और प्रमोचनयानों का निर्माण	4.1 वर्ष के दौरान प्रक्षेपित ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण (पी.एस.एल.वी.) की संख्या	4	4. अन्य प्रयोजनों के लिए सेवाओं का उपयोग	4.1 वाणिज्यिक लांच सर्विसेज प्रदान करके उत्पन्न राजस्व (रु. करोड़ में)	350
		4.2 वर्ष के दौरान प्रक्षेपित भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण (जी.एस.एल.वी.) की संख्या	3	5. प्रौद्योगिकी क्षमताएं एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में काम	5.1 सामाजिक/वाणिज्यिक/अन्य उद्देश्यों के लिए हस्तांतरित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों की संख्या	20
		4.3 वर्ष के दौरान प्रक्षेपित एल.वी.एम.-3 यानों की संख्या।	1			
		4.4 वर्ष के दौरान प्रक्षेपित एस.एस.एल.वी. यानों की संख्या।	4	6. देश में अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को	6.1 उद्योग के माध्यम से उत्पादन के लिए हस्तांतरित	1

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	5. देश में अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करना	5.1 अंतरिक्ष गतिविधियां करने के लिए समर्थित गैर-सरकारी संस्थाओं की संख्या	20	सक्षम करना	प्रचालनात्मक प्रणालियों की संख्या	
		5.2 देश में अंतरिक्ष स्टार्ट-अपों की संख्या में वृद्धि	5			

2. अंतरिक्ष अनुप्रयोग (सी.एस.)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,725.06	1. ई.ओ., वायु संचालन, संचार, आपदा प्रबंधन सहायता के लिए नीतभारों/अनुप्रयोगों का डिजाइन एवं विकास	1.1. निर्मित ई.ओ./संचार/ वायु संचालन /विज्ञान नीतभारों की संख्या	5	1. प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक आपदाओं, कृषि योजना, बुनियादी ढांचे की योजना के प्रबंधन हेतु सूचना सहायता एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी	1.1 आई.एम.डी., एन.डी.एम.ए. एवं राज्य सरकारों जैसे संबंधित हितधारकों / एजेंसियों को प्रदान की गई प्रमुख आपदा घटनाओं से संबंधित सहायता का %	100
		1.2. प्रयोक्ताओं द्वारा डाउनलोड के लिए होस्ट किए गए डेटा/मूल्य वर्धित डेटा उत्पादों की संख्या	24,00,000			
		1.3. डेटा/मूल्य-वर्धित डेटा उत्पादों के डाउनलोडों की संख्या	1,40,00,000			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	2. भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण	2.1 भू-स्थानिक डोमेन में आयोजित प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की संख्या	80	सेवाओं तक पहुंच		

3. अंतरिक्ष विज्ञान (सी.एस.)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27	परिणाम	संकेतक	2026-27
569.76	1. अंतरिक्ष विज्ञान एवं अंतरग्रहीय मिशन की शुरुआत	1.1 चंद्रयान-4 के पूरा होने की % स्थिति	60	1. ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के डिजाइन एवं विकास के लिए स्वदेशी क्षमता का विकास	1.1 वैज्ञानिक अवलोकन के लिए उपलब्ध अन्तरिक्ष प्लेटफोर्म की संख्या	4
		1.2 चंद्रयान-5 के पूरा होने की % स्थिति	45			
		1.3 शुक्र कक्षीय मिशन के पूरा होने की % स्थिति	77			
		1.4 देश भर में इसरो कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थित शिक्षाविदों में अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या	650			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27	परिणाम	संकेतक	2026-27
		1.5 वर्ष के दौरान पूरा किए गए शैक्षणिक अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या	85		1.2 सार्वजनिक उपयोग के लिए जारी की गई अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित डेटा की मात्रा (टी.बी.एस.) में	4
	2. अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में समानव संसाधन उत्पन्न करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मेजबानी	2.1 आयोजित अंतरिक्ष विज्ञान पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/उपयोगकर्ता बैठकों की संख्या	9		1.3 अंतरिक्ष विज्ञान मिशनों से प्रकाशनों की संख्या	75

1. क्षमता विकास (सीडी) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
570	1. आईसीटी[368] और उन्नत सर्वेक्षण क्षमताओं का उपयोग	1.1. वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीएपीआई[369]/जीआईएस[370]/ अन्य डिजीटल माध्यम का प्रयोग करके किए गए सर्वेक्षणों की संख्या।[371]	12	1. रिपोर्ट/सर्वेक्षण का सामायिक प्रकाशन और सही रिपोर्ट की गई डाटा की उपलब्धता।	1.1. वर्तमान वित्तीय वर्ष में डेटा संग्रहण पूरा होने के 3 महीने के अंदर प्राथमिक डेटा का प्रयोग करके जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट/फैक्टशीट/तिमाही/मासिक बुलेटिन की संख्या	27
					1.2. एनएसओ[372] के सर्वेक्षणों की संख्या जहां अखिल भारतीय स्तर पर प्रमुख संकेतक का सांख्यिकीय अनुमान (वार्षिक) सापेक्ष मानक त्रुटि (आरएसई) की निर्धारित छूट की सीमाओं के भीतर रहते हैं।	5

[368] सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

[369] कंप्यूटर-सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार

[370] भौगोलिक सूचना प्रणाली

[371] भौगोलिक सूचना प्रणाली। सीएपीआई/जीआईएस/अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग कर आयोजित किए गए सर्वेक्षणों की कुल संख्या में शामिल हैं: (क) वार्षिक आवृत्ति के साथ आयोजित सर्वेक्षणों की संख्या= 5; (ख) आयोजित आवधिक/मांग आधारित सर्वेक्षणों की संख्या = 7

[372] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	2. हितधारक जुड़ाव और प्रतिक्रिया तंत्र	2.1 आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम (डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन, राष्ट्रीय सेमिनार, मंथन सत्र, आदि) की संख्या	6	2. उन्नत हितधारक जुड़ाव और सहयोग	2.1. जनसंपर्क कार्यक्रम में प्रतिभागियों/उपयोगकर्ताओं की संख्या[373]	1,200
					2.2. एनएसओ, सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. के जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों की संख्या[374]	6
	3. सर्वेक्षण में सांख्यिकीय कार्मिकों का प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण	3.1. एनएसएस[375] सर्वेक्षण के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	368	3. सर्वेक्षण में बेहतर तकनीकी क्षमता	3.1. एनएसएस सर्वेक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने वाले प्रतिभागियों की संख्या	16,237
	4. सांख्यिकीय कार्मिकों का प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण (एनएसएसटीए[376])[377]	4.1. वर्तमान वित्त वर्ष में आधिकारिक सांख्यिकी (केंद्र + राज्य) पर सांख्यिकीय अधिकारियों के लिए आयोजित व्यक्तिगत प्रशिक्षण की संख्या[378]	15	4. बेहतर सांख्यिकीय क्षमताएं	4.1. वर्तमान वित्त वर्ष में आधिकारिक सांख्यिकी में व्यक्तिगत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सांख्यिकीय अधिकारियों का %	100

[373] प्रतिभागियों में नीतिनिर्माता एवं योजनाकार, विशेषज्ञ समूहों के सदस्य, नीति आयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लाइन मंत्रालय (श्रम, वित्त, कृषि, शिक्षा आदि), अर्थशास्त्री, अनुसंधानकर्ता, शिक्षाविद, छात्र, अंतरराष्ट्रीय संगठन (जैसे विश्व बैंक, एफएओ, आईएलओ) तथा निजी क्षेत्र के संगठन/संस्थान सम्मिलित हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक माँग-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं तथा भविष्य में माँग प्राप्त होने पर इन्हें आयोजित किया जाएगा।

[374] शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान (आईएसआई, आईआईटी, आजीआईडीआईर आदि)

[375] राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

[376] राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी

[377] चूँकि आईएसएस के परिवीक्षाधीन अधिकारी पूरे वर्ष प्रशिक्षण में रहते हैं, अतः लक्ष्यों के निर्धारण के समय आईएसएस का परिवीक्षा प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं किया गया है।

[378] वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्र एवं राज्य स्तर के सांख्यिकीय अधिकारियों के लिए आधिकारिक सांख्यिकी पर आयोजित प्रत्यक्ष (इन-पर्सन) प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
		4.2. वर्तमान वित्त वर्ष में सांख्यिकीय अधिकारियों के लिए एआई[379]/एमएल[380] जैसी नई प्रौद्योगिकी पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या[381]	4		4.2. वर्तमान वित्त वर्ष में एआई/एमएल जैसी नई तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सांख्यिकीय अधिकारियों का %	100
	5. आधिकारिक सांख्यिकी की बेहतर गुणवत्ता	5.1 राष्ट्रीय एसडीजी[382] संकेतकों का प्रतिशत जिसके लिए डेटा उपलब्ध है	97	5. नीति में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के माध्यम से प्रभावी एसडीजी निगरानी	5.1 वर्तमान वित्त वर्ष में एसडीजी-राष्ट्रीय संकेतक रुपरेखा पर आधारित जारी किए गए रिपोर्ट की संख्या	3
	6. 8वीं आर्थिक गणना (ईसी)[383] के आयोजन के लिए प्रशिक्षण	6.1. आयोजित की जाने वाली मास्टर प्रशिक्षकों की अखिल भारतीय कार्यशाला की संख्या (8वीं आर्थिक गणना से संबंधित)	1	6. 8वीं आर्थिक गणना के संचालन के लिए क्षमता निर्माण	6.1. प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों की संख्या	150

(इसमें केवल आईएसएस/एसएसएस प्रभाग से प्राप्त माँग-आधारित प्रशिक्षण तथा आधिकारिक सांख्यिकी से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं)।

[379] कृत्रिम होशियारी

[380] यंत्र अधिगम

[381] वर्तमान वित्तीय वर्ष में एआई/एमएल जैसी नई तकनीकों पर सांख्यिकीय अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या
(केवल इन-सर्विसआईएसएस/एसएसएस प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो नई तकनीकों जैसे एआई/एमएल आदि से संबंधित हैं, को सम्मिलित किया गया है)।

[382] सतत विकास लक्ष्य

[383] मंत्रालय 16वें वित्त आयोग (एफसी) चक्र के अंतर्गत 8वीं आर्थिक गणना कराने का आशय रखता है। 8वीं आर्थिक गणना से संबंधित प्रारंभिक कार्यकलापों वर्ष 2026-27 में की जानी है, जिनमें मुख्य रूप से 8वीं आर्थिक गणना के संचालन हेतु एंड-टू-एंड डिजिटल समाधान का विकास तथा विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। 8वीं आर्थिक गणना के लिए क्षेत्र कार्य आरंभ करने की संभावित तिथि 1 अप्रैल, 2027 है। ये सभी कार्यकलापों आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की स्वीकृति के अधीन होंगी।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
		6.2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या (8वीं आर्थिक गणना)	36		6.2. प्रशिक्षित जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों की संख्या	2,250
	7. एसएसएस[384] उप-योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का समर्थन	7.1. नई एसएसएस योजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करना (संख्या में)	15	7. राज्यों की बढ़ी हुई क्षमताएँ	7.1. कम से कम 2 सांख्यिकीय उत्पादों के उप-राज्य स्तरीय आंकडें जारी करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिशत[385]	50

[384] *सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण*

[385] *सांख्यिकीय उत्पादों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद/जिला घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य हेतु राज्य संकेतक ढाँचा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जैसे–वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, असंघटित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण आदि सम्मिलित हैं।*

1. केंद्रीय रेशम बोर्ड (सिल्क समग्र-2) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
960	1. प्रौद्योगिकी सृजन, सिल्क वार्म सीड उत्पादन, कच्ची रेशम उत्पाद, आयात विकल्प कच्चे रेशम के उत्पादन में प्रगति	1.1 शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या	55	1. उत्पादकता, गुणवत्ता में सुधार, रेशम उत्पादन में वृद्धि, रोजगार और आयात में कमी।	1.1 कच्ची रेशम का कुल उत्पादन (मी.ट.)	44,500
		1.2 मलबरी बीज उत्पादन (लाख में)	439		1.2 उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर कच्ची रेशम किलोग्राम में)	116
		1.3 वान्या (तसर, एरी, मूगा) बीज उत्पादन (संख्या लाख में)	67.93		1.3 वर्ष के दौरान कुल रोजगार सृजन (संख्या लाख में)	98.4
		1.4 आयात विकल्प कच्ची रेशम का उत्पादन (मी.ट.)	12,220		1.4 वर्ष के दौरान सिल्क मार्क लेबल की बिक्री से प्राप्त राजस्व (मूल्य के संदर्भ में) (करोड़ रुपये में)	2
	2. क्षमता निर्माण कौशल उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	2.1 प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	15,975			
		2.2 बेचे गए गुणवत्ता प्रमाणित सिल्क मार्क लेबल (लाख में)	40			

2. राज्य और केंद्रीय कर और मैनमेड-अप्स के अपैरल/गारमेंट निर्यात पर शुल्क छूट योजना (आरओएससीटीएल) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
5,000	1. इस अवधि में आरओएससीटीएल दावे के साथ दायर शिपिंग बिल की संख्या	1.1 बीमाकृत पशुओं की कुल संख्या (लाख में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[386]	1. आरओएससीटीएल योजना इस सिद्धांत पर आधारित है कि निर्यात पर कर न हो और यह उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए शून्य रेटिंग निर्यात सुनिश्चित करती है[387]	1.1 योजना के लिए आबंटित कुल निधि से छूट के लिए प्रयुक्त निधि का प्रतिशत	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[388]
	2. स्क्रोल्ड आउट शिपिंग बिल की संख्या	2.1 शिपिंग बिलों की संख्या जिसके लिए ई-स्क्रिप जारी किया गया	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते		1.2 इस योजना में कवर किए गए निर्यात के कुल एफओबी मूल्य का प्रतिशत	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[389]

[386] दिनांक 30.04.2026 तक ई-स्क्रिप्स जारी नही हुए शिपिंग बिलों का प्रतिशत किसी विशिष्ट अवधि में आरओएससीटीएल दावों के साथ दायर सभी शिपिंग बिल का 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

[387] (नोट: इसलिए, स्कीम को लागू करने के लिए कोई भी आउटकम टारगेट तय नहीं किए जा सकते। निर्यात कई बातों पर निर्भर करते हैं और आरओएससीटीएल के तहत दिए गए किसी भी सपोर्ट का एक्सपोर्ट ग्रोथ के साथ सीधा सह-संबंध बताना तकनीकी रूप से सही नहीं हो सकता)।

[388] किसी वित्तीय वर्ष में बजट उपयोग का प्रतिशत 95 प्रतिशत तक पहुंचना चाहिए ताकि अग्रेनीत बजट न्यूनतम रहे और निर्यातकों को नकदी अधिक रहे।

[389] अध्याय 61, 62 और 63 के लिए योजना के अंतर्गत शामिल निर्यात के कुल एफओबी मूल्य का प्रतिशत (एचएसकोड 6309 और 6310 को छोड़कर) पिछले वर्ष के दौरान शामिल एफओबी मूल्य के प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

1. विशिष्ट विषयों पर आधारित पर्यटन सर्किट का समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
1,905.00	1. स्वदेश दर्शन (एसडी) और इसकी सीबीडीडी उप योजना के तहत गंतव्यों का विकास [390]	1.1. स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या (कुल)	0	1. यात्रियों की संख्या में वृद्धि	1.1. जिन जिलों में 15 वें वित्त आयोग में मंज़ूर प्रोजेक्ट असल में पूरे हो गए हैं, वहां टूरिस्ट आने वालों की संख्या में पिछले साल से बढ़ोतरी हुई है। (%)	15
		1.2. 15 वें वित्त आयोग में मंज़ूर किए गए प्रोजेक्ट्स की संख्या जिन्होंने 50% से ज़्यादा फिजिकल प्रोग्रेस हासिल की (कुल मिलाकर)	60	2. रोजगार सृजन	2.1 15 वें वित्त आयोग के मंजूर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए ओएण्डएम फेज़ के दौरान बनाई गई सीधी नौकरियों की संख्या	80
		1.3. 15 वें वित्त आयोग में मंज़ूर किए गए प्रोजेक्ट्स की संख्या जो असल में पूरे हुए (कुल मिलाकर)	13	3. पर्यटक संतुष्टि	3.1 चालू प्रोजेक्ट्स का प्रतिशत जिन्हें एवरेज टूरिस्ट फीडबैक रेटिंग 10 में से कम से कम 7 मिली है।[391] (%)	70
		1.4. 15 वें वित्त आयोग में मंज़ूर फिजिकली पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशन्स और मेंटेनेंस (ओ&एम) की शुरुआत	8	4. पीएम-जुगा उप-योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे के विकास के अंतर्गत रोजगार सृजन	4.1 डेवलप किए गए होमस्टे में कुल कितने रोज़गार मिले	1,000

[390] *चुनौती-आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)*

[391] *टूरिस्ट फ़ीडबैक रेटिंग, टूरिस्ट की सुविधा, एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी, सफ़ाई, अनुभव वगैरह के हिसाब से सर्विस स्टैंडर्ड को जांचने के लिए।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	2. पीएम-जुगा उप-योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे का विकास	2.1 स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	6			
		2.2 विकसित होमस्टे की संख्या	500			

1. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	**निर्गम 2026-27**			**परिणाम 2026-27**		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
7,200	1. जनजातीय बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना	1.1. कार्यात्मक ईएमआरएस की कुल संख्या (संचयी)	574	1. पाठ्येतर गतिविधियों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच	1.1. कक्षा 10वीं में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों में से उत्तीर्ण छात्रों का %	90
		1.2. पिछले वर्ष की तुलना में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नामांकन में प्रतिशत वृद्धि	10		1.2. कक्षा 12वीं में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों में से उत्तीर्ण छात्रों का %	86
		1.3. वित्तीय वर्ष के दौरान ईएमआरएस में नामांकित लड़कियों का प्रतिशत	50		1.3. वित्तीय वर्ष के दौरान 10वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का %	1.5
		1.4. सीबीएसई से संबद्ध ईएमआरएस की संख्या (2019-20 से संचयी)	525		1.4. वित्तीय वर्ष के दौरान 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का %	1.5
		1.5. खेलों के लिए कार्यात्मक उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की संख्या	0			

2. अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
5,650.02	**क. अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम- जनजातीय शिक्षा (मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति)**					
	1. पात्र जनजातीय छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्ति	1.1. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के तहत सहायता प्राप्त छात्रों की संख्या (लाख में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते।[392]	1. अजजा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (दसवीं, बारहवीं, स्नातक और स्नातकोत्तर)	1.1. 10वीं कक्षा में पदोन्नत छात्रों का % जिन्हें 9वीं कक्षा में छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी	80
		1.2. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के तहत सहायता प्राप्त बालिकाओं की संख्या (लाख में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते।[393]			
		1.3. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत सहायता प्राप्त छात्रों की संख्या (लाख में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते।[394]		1.2. कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्रों का % (छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले)	80
		1.4. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत सहायता प्राप्त बालिकाओं की संख्या (लाख में)	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते।[395]		1.3. स्नातक उत्तीर्ण छात्रों का % (छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले)	75
					1.4. स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्रों का % (छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले)	75
	ख. धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)					

[392] *मैट्रिकोत्तर योजना ग्यारहवीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के छात्रों को कवर करती है। योजना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाती है और मंत्रालय के पास लाभार्थियों का पाठ्यक्रम-वार विवरण नहीं है।*

[393] *योजना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाती है और मंत्रालय के पास लाभार्थियों का पाठ्यक्रम-वार विवरण नहीं है।*

[394] *योजना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाती है और मंत्रालय के पास लाभार्थियों का पाठ्यक्रम-वार विवरण नहीं है।*

[395] *योजना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाती है और मंत्रालय के पास लाभार्थियों का पाठ्यक्रम-वार विवरण नहीं है।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
	1. जनजातीय बहु मॉडल केंद्र (टीएमएमसी) की स्थापना	1.1. अनुमोदित टीएमएमसी की संख्या	10	1. जनजातीय क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास	1.1. टीएमएमसी के माध्यम से बाजार तक पहुँच प्राप्त करने वाले जनजातीय उद्यमियों की संख्या	1,000
		1.2. कार्यात्मक टीएमएमसी की संख्या	10			
		1.3. मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले जनजातीय उत्पादक समूहों की संख्या	10		1.2. निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यात्मक टीएमएमसी का %	100
		1.4. बाजार तक पहुँच प्राप्त करने वाले जनजातीय व्यापारियों की संख्या.[396]	100		1.3. टीएमएमसी प्रतिष्ठान में % वृद्धि	100
				2. शासन और सेवा वितरण में सुधार	2.1. हाट बाजार में भाग लेने वाले जनजातीय समुदाय की आय में % वृद्धि	20
	ग. जनजातीय अनुसंधान और आजीविका संस्थानों (टीआरएलआई) को सहायता					
	1. जनजातीय अनुसंधान अध्ययन को सुदृढ़ करना	1.1. सहायता प्राप्त शोध अध्ययनों की संख्या	25	1. जनजातीय अनुसन्धान संस्थान (टीआरआई) की क्षमता को सुदृढ़ करना	1.1. प्रकाशित शोध अध्ययनों की संख्या	30
		1.2. सहायता प्राप्त कार्यक्रमों/सेमिनार/ कार्यशालाओं की संख्या	40		1.2. सेक्टोरल क्षेत्रों की संख्या जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण/कार्यक्रम आयोजित किए गए	5

[396] *क. बिक्री आदेश/ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग के माध्यम से प्रमाणित बाजार पहुंच ख. चालान/प्लेटफॉर्म पुष्टिकरण के माध्यम से साक्ष्य*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	घ. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)					
	1. विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बस्तियों/गांवों में बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण और संचालन तथा समुदाय को सेवाएं प्रदान की गईं	1.1. बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) की संख्या जिनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है	633[397]	1. कौशल प्रशिक्षण, पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रौढ़ शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न गतिविधियों और सेवाओं के लिए एमपीसी के माध्यम से पीवीटीजी समुदाय के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देना	1.1. कार्यात्मक और लाभ प्रदान करने वाली एमपीसी की संख्या (आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य सेवाएं और विभिन्न उद्देश्यों जैसे वीडीवीके आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले सामुदायिक हॉल जैसी सुविधाएं)	300[398]

[397] *संचयी:1,000*

[398] *संचयी: 352*

3. राष्ट्रीय जनजातीय कल्याणकारी कार्यक्रम (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
939	**क. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता**					
	1. कार्यक्रम के अंतर्गत समर्थित संगठन/व्यक्ति	1.1. वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या (वर्ष के दौरान)	300	1. कार्यक्रमों के तहत लोगों को मिलने वाले लाभ	1.1. गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित परियोजनाओं में लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या (वर्ष के दौरान)	6,00,000
		1.2. वित्त पोषित परियोजना के साथ साझेदारी करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	180		1.2. शिक्षा क्षेत्र (शैक्षिक परियोजनाओं) में कुल लाभार्थियों में से लाभान्वित होने वाली छात्राओं का % (वर्ष के दौरान)	45
	ख. प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन					
	1. विभिन्न जनजातियों से संबंधित लोगों के लिए व्यापक सहायता	1.1 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) द्वारा आयोजित महोत्सव/प्रदर्शनियों की संख्या	280	1. जनजातीय समूहों के लिए आर्थिक गतिविधियों और आजीविका सृजन गतिविधियों में वृद्धि	1.1. ट्राइफेड द्वारा आयोजित महोत्सव/प्रदर्शनी में भाग लेने वाले कारीगरों की संख्या	6,000
	2. जनजातीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का विपणन	2.1 जनजातीय उत्पादों की कुल खरीद धनराशि (करोड़ रुपये में)	50		1.2. महोत्सव/प्रदर्शनी में भाग लेने वाले वीडीवीके सदस्यों की संख्या	2,000
	3. एमएफपी और गैर-एमएफपी से संबंधित वस्तुओं के मूल्यवर्धन के	3.1 संचालनात्मक वीडीवीके की संख्या	100	2. जनजातीय उत्पादकों के लिए बाजार संपर्क	2.1. खरीद/बाजार संपर्क के माध्यम से लाभान्वित जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं की संख्या	8,500

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	लिए वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) का संचालन			3. जनजातीय आबादी का उद्यमिता विकास	3.1. उद्यमशीलता के लिए वीडीवीके की स्वीकृति से लाभान्वित जनजातीय लाभार्थियों की संख्या	30,000
					3.2. वीडीवीके के कानूनी संस्थाओं में पंजीकरण से लाभान्वित होने वाले जनजातीय सदस्यों की संख्या (200 वीडीवीके)	60,000
	ग. निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण और सामाजिक लेखापरीक्षा					
	1. कल्याण योजना के लाभ के प्रति जागरूकता पैदा करना	1.1. आयोजित जागरूकता सृजन गतिविधियों की संख्या।[399]	10	1. जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं की वास्तविक निरीक्षण द्वारा प्रभावी निगरानी	1.1. पीएमयू द्वारा निगरानी की गई योजनाओं की संख्या	10
	2. आयोजित जागरूकता सृजन गतिविधियों की संख्या	2.1 आयोजित जागरूकता सृजन गतिविधियों की संख्या।	10			
	घ. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति					
	1. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता	1.1. वित्तीय वर्ष में पीएचडी करने के लिए अध्येतावृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या	2,500	1. उच्चतर शिक्षा (स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम) पूर्ण करने वाले अनुसूचित जनजाति के	1.1. वित्तीय वर्ष में पीएचडी पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों का %	20

[399] *इस संबंध में यह सूचित किया जाना है कि एमईएसएसए योजना के तहत जनता, विशेष रूप से देश भर के जनजातीय समुदायों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जानी अभीष्ट है।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
		1.2. वित्तीय वर्ष में उच्चतर शिक्षा (पीएचडी) के लिए छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या[400]	750	छात्रों का प्रतिशत	1.2. वित्तीय वर्ष में उच्चतर शिक्षा (पीएचडी) पूरी करने वाली छात्राओं का प्रतिशत	20
		1.3. वित्तीय वर्ष में उच्चतर शिक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर आदि) के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते		1.3. वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा उच्चतर शिक्षा (स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) पूरा करने का %	25
		1.4. वित्तीय वर्ष में उच्चतर शिक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर) के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते		1.4. वित्तीय वर्ष में उच्चतर शिक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर) पूरा करने वाली छात्राओं का %	25
	ड. विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति					
	1. विदेश में उच्चतर शिक्षा के लिए अजजा छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है	1.1. विदेश में उच्चतर शिक्षा (मास्टर, डॉक्टरल और पोस्ट-डॉक्टरल) के लिए सहायता प्राप्त अजजा छात्रों की संख्या (वित्त वर्ष में)	50	1. छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों का % जिन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा पूरी की	1.1. वित्तीय वर्ष में विदेशों में उच्चतर शिक्षा (मास्टर, डॉक्टरल और पोस्ट-डॉक्टरल) पूरी करने वाले अजजा छात्रों का %	25
		1.2. वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति दी गई छात्राओं की संख्या	15		1.2. विदेश में उच्चतर शिक्षा (मास्टर, डॉक्टरल और पोस्ट-डॉक्टरल)	25

[400] *अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) कोर्स केवल पीएचडी के लिए हैं, इसलिए पीजी/यूजी कोर्स लागू नहीं हैं*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
					(पीएचडी/यूजी/पीजी) पूरी करने वाली छात्राओं का %	
	च. अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष[401]					
	1. रियायती दर पर वित्तीय सहायता	1.1. अजजा उद्यमियों को दी गई वित्तीय सहायता की राशि (करोड़ रुपये में)	15	1. अजजा उद्यमियों को सहायता	1.1. सहायता प्राप्त अजजा उद्यमियों की संख्या (अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाली कंपनियां)	10
	छ. जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)					
	1. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रतिष्ठित संगठन/संस्थानों/विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता दी	1.1. वित्तीय वर्ष में सीओई को दी गई परियोजनाओं की संख्या	8	1. जनजातियों से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान करने में सहायता करना।	1.1. नीति और कार्यक्रम सुधार में शामिल अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या	4

[401] हाल ही में जारी ईएफसी नोट के अनुसार, इस योजना को नई योजना 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास कोष' के अंतर्गत उप-योजना के रूप में विलय कर दिया गया है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो योजना को ढांचे के अनुसार नए संकेतक के साथ नई योजना के अंतर्गत स्थानांतरित किया जा सकता है।

1. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (अम्ब्रेला आईसीडीएस- आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान , किशोरियों के लिए योजना) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
23,100.00	1. आंगनवाड़ी प्रणाली के माध्यम से कुपोषण का समाधान करना	1.1 प्रतिवर्ष सक्षम में उन्नत किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल संख्या	40,000	1. 6 माह से 72 माह तक की आयु के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार	1.1 दुबले बच्चों(अपने आयु वर्ग में) की संख्या में % कमी (आधार- पोषण ट्रैकर जनवरी 2026 और एनएफएचएस-5)	0.5[402]
		1.2 पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत कुल बच्चों में से प्रतिमाह लंबाई एवं वजन मापन हेतु पात्र बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक की आयु) का %	100		1.2 अल्प-वजनी बच्चों(अपने आयु वर्ग में) की संख्या में % कमी (आधार - पोषण ट्रैकर जनवरी 2026 और एनएफएचएस-5)	2
		1.3 पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत (3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग) के कुल बच्चों में से पका गर्म भोजन प्राप्त करने वाले पात्र बच्चों (3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग) का %	100			
		1.4 टेक होम राशन के पात्र लाभार्थियों में से ईकेवाईसी और चेहरे की पहचान(फेस मैचिंग) पूरी करने वाले	100		1.3 बौने बच्चों(अपने आयु वर्ग में) की संख्या में % कमी (आधार- पोषण ट्रैकर जनवरी 2026 और	1

[402] पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार कुपोषण की वर्तमान कम दर (लगभग 5 प्रतिशत) को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने 1 प्रतिशत के बजाय 0.5 प्रतिशत की वार्षिक कमी का लक्ष्य निर्धारित किया है। कुपोषण एक तीव्र और परिवर्तनशील स्थिति है, और बच्चे संक्रमण या अन्य कारणों से थोड़े समय में इस श्रेणी में आ-जा सकते हैं। इस संदर्भ में, उच्च वार्षिक कमी का लक्ष्य व्यावहारिक या टिकाऊ नहीं हो सकता है। इसलिए, 0.5 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य व्यावहारिक और प्राप्त करने योग्य माना गया है।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
		लाभार्थियों का %			एनएफएचएस-5)	
		1.5 फेस रिक्गनीशन सिस्टम (एफआरएस) के माध्यम से टीएचआर प्राप्त करने वाले टीएचआर पात्र लाभार्थियों का %	60			
	2. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का क्षमता निर्माण करना ताकि वे ईसीडीसीई[403] पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकें।	2.1 ईसीडीसीई पाठ्यक्रम विषय पर प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या	7,00,000	2. उन बच्चों के अनुपात में वृद्धि जिनका स्वास्थ्य, अधिगम और मनो-सामाजिक कल्याण के मामले में सही विकास हो रहा है।	2.1 प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास संकेतकों में सुधार	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[404]

[403] *प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास एवं देखभाल शिक्षा*

[404] *कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि वर्ष 2026-27 को आधार वर्ष माना जाएगा।*

2. मिशन वात्सल्य योजना (बाल संरक्षण सेवाएँ एवं बाल कल्याण सेवाएँ) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय **(करोड़ रुपये में)**	**निर्गम 2026-27**			**परिणाम 2026-27**		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**2026-27**
1,550.00	1. जिला स्तर पर बच्चों के लिए देखरेख और संरक्षण सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना	1.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान स्वीकृत बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) में संचलनात्मक बाल देखरेख संस्थानों का %।	100	1. जिलों में बाल देखरेख सेवाओं की उपलब्धता और बच्चों का कवरेज सुदृढ़ करना।	1.1. गैर-संस्थागत देखरेख (प्रायोजन, पालक देखरेख और पश्चात देखरेख) के अंतर्गत शामिल बच्चों की संख्या[405]	1,71,000
					1.2. गैर-संस्थागत देखरेख (प्रायोजन, पालन-पोषण देखरेख और पश्चात देखरेख) के तहत सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (%)	5[406]
		1.2 कार्यशील बाल कल्याण समितियों (सीड्बल्यूसी) की संख्या[407]	797		1.3. गैर-संस्थागत देखरेख (प्रायोजन, पालक देखरेख और पश्चात देखरेख) के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों का प्रतिशत[408]	100
		1.3 कार्यशील किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) की संख्या।[409]	796		1.4. मिशन वात्सल्य पोर्टल पर गैर-संस्थागत देखरेख (पालक देखरेख	531

[405] *गैर-संस्थागत देखरेख (प्रायोजन, पालक देखरेख और पश्चात देखरेख) के अंतर्गत शामिल बच्चों की संख्या वार्षिक आधार पर है, न की त्रैमासिक आधार पर।*

[406] *गैर-संस्थागत देखभाल के संबंध में ईएफसी नोट में किए गए प्रस्ताव की स्वीकृति के अधीन।*

[407] *स्वीकृत सीडब्ल्यूसी के लिए लक्ष्य वार्षिक आधार पर है, त्रैमासिक आधार पर नहीं।*

[408] *गैर-संस्थागत देखरेख(प्रायोजन, पालक देखरेख और पश्चात देखभाल) के लिए लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किया गया है।*

[409] *स्वीकृत जेजेबी के लिए लक्ष्य वार्षिक आधार पर है, त्रैमासिक आधार पर नहीं।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27	परिणाम	संकेतक	2026-27
					और दत्तक ग्रहण) के लिए सीसीआई से जुड़े एसएए की संख्या [410]	
		1.4 कार्यशील जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) की संख्या [411]	779		1.5. क्षेत्रीय केंद्रों/प्रयोगशालाओं में लाभान्वित बच्चों की संख्या	400
		1.5 वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर (सीबीआरसी) वाले कार्यशील राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) की संख्या [412]	300		1.6. बाल देखरेख संस्थानों में लाभान्वित हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या	2,000
		1.6 कार्यशील क्षेत्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एवं सुविधा केंद्रों (एआरएफसी) की संख्या	6			
		1.7 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए कार्यान्वित किए गए बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) की संख्या [413]	10		1.7. बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) में लाभान्वित होने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन(%)	2 [414]

[410] 5मिशन वात्सल्य पोर्टल पर गैर-संस्थागत देखरेख (पालक देखरेख और दत्तक ग्रहण) के लिए सीसीआई से जुड़े एसएए की संख्या के लिए लक्ष्य वार्षिक आधार पर है, त्रैमासिक आधार पर नहीं।

[411] स्वीकृत डीसीपीयू के लिए लक्ष्य वार्षिक आधार पर है, त्रैमासिक आधार पर नहीं।

[412] स्वीकृत एसएए के लिए लक्ष्य वार्षिक आधार पर है, त्रैमासिक आधार पर नहीं।

[413] लक्ष्य वार्षिक आधार पर है, बशर्ते 16वें वित्त आयोग में ईएफसी को स्वीकृति मिल जाए।

[414] विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में ईएफसी नोट में किए गए प्रस्ताव की स्वीकृति के अधीन।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**2026-27**
		1.8 मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहायता (एमएचपीएसएस) के लिए कार्यशील क्षेत्रीय केंद्रों/प्रयोगशालाओं की संख्या[415]	7			
	2. लापता बच्चों का प्रभावी ढंग से पता लगाना और उन्हें वापस लाना	2.1 मिशन वात्सल्य पोर्टल पर डेटा दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशनों की कुल संख्या[416]	15,000	2. लापता बच्चों की मैपिंग और उन्हें वापस लाना	2.1 मिशन वात्सल्य पोर्टल के ज़रिए मैच हुए बच्चों का % [417]	60
		2.2 जिला स्तर पर स्वीकृत चाइल्ड हेल्पलाइन में से कार्यशील की संख्या।[418]	762		2.2 चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं से लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या।[419]	3,00,000
	3. जन जागरूकता बढ़ाएं, बच्चों के अधिकारों, उनकी असुरक्षा और सुरक्षा उपायों के बारे में जनता को शिक्षित करें, और सभी स्तरों	3.1 वर्ष 2026-27 के दौरान, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत, बाल अधिकारों और बाल संरक्षण पर आयोजित सामुदायिक जागरूकता अभियानों की संख्या	100	3. जन जागरूकता बढ़ाएं, जनता को बाल अधिकारों, उनकी असुरक्षा और बाल संरक्षण उपायों के बारे में शिक्षित करें।	3.1 वर्ष 2026-27 के दौरान बाल अधिकारों, उनकी असुरक्षा और बाल संरक्षण उपायों के बारे में जागरूक किए गए व्यक्तियों की संख्या	10,000

[415] लक्ष्य वार्षिक आधार पर है, बशर्ते 16वें वित्त आयोग में ईएफसी को स्वीकृति मिल जाए।

[416] यह लक्ष्य ट्रैक चाइल्ड पोर्टल के अनुसार त्रैमासिक आधार पर निर्धारित है।

[417] ट्रैक चाइल्ड पोर्टल के माध्यम से मिलान किए गए बच्चों के प्रतिशत का लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित है, न कि त्रैमासिक आधार पर। क्योंकि ट्रैक चाइल्ड पोर्टल से मिशन वात्सल्य पोर्टल पर डेटा का स्थानांतरण प्रक्रियाधीन है।

[418] अनुमोदित बाल हेल्पलाइन का लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित है, न कि त्रैमासिक आधार पर।

[419] अनुमोदित बाल हेल्पलाइन का लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित है, न कि त्रैमासिक आधार पर।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27	परिणाम	संकेतक	2026-27
	पर समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।					
	4. सभी स्तरों पर कर्तव्य धारकों और सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण करना।	4.1 वर्ष 2026-27 के दौरान कर्तव्य धारकों और सेवा प्रदाताओं के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की संख्या	100	4. सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए बाल संरक्षण अधिकारियों की क्षमता में सुधार।	4.1. वर्ष 2026-27 के दौरान प्रशिक्षित कर्तव्य धारकों और सेवा प्रदाताओं की संख्या	4,500

3. मिशन शक्ति-स्कीम (महिलाओं के संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए मिशन) (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27	परिणाम	संकेतक	2026-27
3,605	**क. मिशन शक्ति-संबल - वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)**					
	1. संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए देश के प्रत्येक जिले में वन स्टॉप	1.1. कार्यशील वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) की संख्या	1,133	1. ओएससी योजना के तहत दी जाने वाली आपातकालीन और गैर-आपातकालीन	1.1 ओएससी में विभिन्न सेवाओं के माध्यम से सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते[420]

[420] योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त मांग के आधार पर स्थापित किए जाते हैं।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27	परिणाम	संकेतक	2026-27
	सेंटर	1.2. पिछले वर्ष की तुलना में ओएससी की संख्या में परिवर्तन	100[421]	सेवाओं तक पहुंच, जिसमें आश्रय और समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक साधन शामिल हैं	की संख्या	
	ख. मिशन शक्ति-संबल - महिला हेल्पलाइन (सीएसएस)					
	1. सहायता चाहने वाली महिलाओं के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला हेल्पलाइन का कार्यान्वयन	1.1 उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या जिनमें महिला हेल्पलाइन कार्यशील हैं	35.[422]	1. संकटग्रस्त या जरूरतमंद महिलाओं की आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता तंत्र तक पहुंच।	1.1 महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) सेवाओं के माध्यम से सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या (आपातकालीन + गैर-आपातकालीन) [423]	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
	ग. मिशन शक्ति-संबल-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ					
	1. बाल-अनुपात में सुधार के लिए जिलों में बहुक्षेत्रीय कार्रवाई	1.1 जिलों द्वारा आयोजित जागरूकता सृजन गतिविधियों की संख्या	15,080.[424]	1. जन्म के समय लैंगिक अनुपात में सुधार	1.1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जन्म के समय लैंगिक अनुपात (एसआरबी) में सुधार	2.[425]
	घ. मिशन शक्ति-सामर्थ्य - पीएमएमवीवाई [426]					

[421] *16वें वित्त आयोग के लिए ईएफसी की मंजूरी के अधीन*

[422] *पश्चिम बंगाल महिला हेल्पलाइन योजना (181) को कार्यान्वित नहीं कर रहा है।*

[423] यह लक्ष्य आपातकालीन और गैर-आपातकालीन दोनों स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसी सेवाओं के प्रतिशत में वृद्धि कोई परिणाम नहीं है और ऐसा कोई निश्चित प्रतिशत बिंदु नहीं हो सकता जिसके आधार पर इसका आकलन किया जा सके। इसके *अलावा, विभिन्न राज्यों में महिला हेल्पलाइन के कार्यान्वयन की स्थिति अलग-अलग है, जिससे किसी भी प्रतिशत बिंदु को लक्ष्य बनाना और भी कठिन हो जाता है।*

[424] *पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी जिलों की कुल संख्या पर विचार किया गया है और प्रत्येक जिले के लिए 20 गतिविधियों का प्रस्ताव है।*

[425] *प्रत्येक दो वर्षों में जन्म पर लिंगानुपात (एसआरबी) में सुधार।*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27	परिणाम	संकेतक	2026-27
	1. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रावधान।	1.1 पहले बच्चे के नामांकन की संख्या - पहली किस्त	20,00,000	1. पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में महिला को पर्याप्त आराम मिल सके, इसके लिए वेतन हानि के बदले नकद प्रोत्साहन के रूप में आंशिक मुआवजा प्रदान किया जाए। इस नकद प्रोत्साहन से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।	1.1 प्रथम बच्चे के लिए पहली किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	20,00,000
		1.2 पहले बच्चे के नामांकन की संख्या - दूसरी किस्त	20,00,000		1.2 प्रथम बच्चे के लिए दूसरी किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	20,00,000
		1.3 दूसरे बच्चे के नामांकन की संख्या – पहली किस्त [427]	10,00,000		1.3 दूसरे बच्चे के लिए पहली किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	10,00,000
		1.4 दूसरे बच्चे के नामांकन की संख्या – दूसरी किस्त [428]	10,00,000		1.4 दूसरे बच्चे के लिए दूसरी किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	10,00,000
	ङ. मिशन शक्ति-सामर्थ्य - पालना					
	1. छोटे बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष तक) के लिए प्रभावी डे केयर का प्रावधान	1.1 कार्यशील आंगनवाड़ी-सह-क्रेचों की संख्या	1,000	1. आंगनवाड़ी-सह-क्रेच के माध्यम से बाल देखरेख सुविधा का प्रावधान	1.1 एडब्ल्यूसीसी में नामांकित बच्चों की संख्या	20,000

[426] प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को भुगतान किया गया है, उनमें वे लाभार्थी भी शामिल हो सकते हैं जो पिछले वर्ष नामांकित थे, लेकिन जिन्होंने वर्तमान वर्ष में भुगतान की शर्तों को पूरा किया है।

[427] 16वें वित्त आयोग के लिए ईएफसी नोट में सार्वभौमीकरण प्रस्ताव की स्वीकृति के अधीन।

[428] 16वें वित्त आयोग के लिए ईएफसी नोट में सार्वभौमीकरण प्रस्ताव की स्वीकृति के अधीन।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27	परिणाम	संकेतक	2026-27
	च. मिशन शक्ति-सामर्थ्य-सखी निवास[429]					
	1. सखी निवासों की स्थापना के माध्यम से सेवाओं का प्रावधान	1.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान स्थापित किए गए अतिरिक्त सखी निवासों की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते	1. सखी निवास के अंतर्गत सहायता प्राप्त महिलाएं	1.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान विभिन्न सेवाओं के माध्यम से सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की अतिरिक्त संख्या।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
	छ. मिशन शक्ति-सामर्थ्य-शक्ति सदन[430]					
	1. शक्ति सदन की स्थापना के माध्यम से सेवाओं का प्रावधान	1.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान स्थापित अतिरिक्त शक्ति सदन की संख्या।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते	1. संकटग्रस्त महिलाओं, जिनमें तस्करी की शिकार महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।	1.1 वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस योजना के माध्यम से सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की कुल संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते
					1.2 वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान उन महिलाओं की संख्या जिन्हें पुनर्वास प्रदान किया गया है तथा समाज में पहचान दी गई है।	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते

[429] सखी निवास एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय जरूरतों के आकलन के अनुसार अपनी आवश्यकताओं के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और इन प्रस्तावों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा के बाद अनुमोदित किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

[430] शक्ति सदन एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय जरूरतों के आकलन के अनुसार अपनी आवश्यकताओं के आधार पर प्रस्ताव भेजते हैं और इन प्रस्तावों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा के बाद अनुमोदित किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

खेल विभाग

1. खेलो इंडिया (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
924.35	1. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/ प्रतिभागिता	1.1 आयोजित राष्ट्रीय स्तर के खेलो इंडिया गेम्स की कुल संख्या	6	1. देश भर में प्रतिभाशाली एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करना	1.1 राष्ट्रीय स्पर्धा के दौरान तोड़े गए रिकार्डों (राष्ट्रीय रिकार्ड और/या खेल रिकार्ड) की संख्या में वृद्धि %	8
		1.2 राष्ट्रीय स्पर्धा के दौरान तोड़े गए रिकार्डों की संख्या (वर्तमान वि.वर्ष)	10		1.2 खेलो इंडिया स्कीम के तहत वित्तपोषित एनएसएफ द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या में बदलाव का %	10
	2. पर्याप्त खेल अवसंरचना तक पहुंच	2.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों, अन्य पात्र संस्थाओं में अनुमोदित/स्वीकृत नई खेल अवसंरचना परियोजनाओं की कुल संख्या	8	2. नवनिर्मित खेल अवसंरचना में खेल स्पर्धाओं की संख्या में वृद्धि	2.1 आयोजित खेल स्पर्धाओं की संख्या	11
	3. प्रतिभा विकास पहल (मान्यता सहित) को मजबूत करने के लिए अकादमियों/केंद्रों को	3.1 मान्यता प्राप्त अकादमियों की कुल संख्या	32	3. खेल जगत में सफलता को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक	3.1 राष्ट्रीय चैंपियनशिप में संबंधित विधा में खेलो इंडिया एथलीटों द्वारा जीते गए पदकों की संख्या	1,500

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	सहायता	3.2 मान्यता प्राप्त अकादमियों, साई और अन्य द्वारा सहायता प्राप्त खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) की कुल संख्या	3,000	एथलीट विकास (एलटीएडी) पर आधारित पहल	3.2 संबंधित विधा में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेलो इंडिया एथलीटों द्वारा जीते गए पदकों की संख्या	600
		3.3 अधिसूचित खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) की कुल संख्या	120		3.3 राज्य स्तर पर खेलो इंडिया केंद्रों में प्रशिक्षित एथलीटों द्वारा जीते गए पदकों की संख्या	1,000
		3.4 नियुक्त पूर्व चैंपियन एथलीटों (पीसीए) की कुल संख्या	120		3.4 राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले केआईसी के एथलीटों की संख्या	5,000
		3.5 केआईसी में प्रशिक्षण ले रहे एथलीटों की कुल संख्या	300		3.5 राष्ट्रीय स्तर पर केआईएससीई के एथलीटों द्वारा जीते गए पदकों की संख्या	500
		3.6 केआईससीई में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों की संख्या	1,000		3.6 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केआईएससीई से भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या	100
	4. नागरिकों की शारीरिक फिटनेस	4.1. फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संचालित स्पर्धाओं की कुल संख्या	20,000	4. फिटनेस और शारीरिक कार्यकलाप के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना	4.1. फिट इंडिया मोबाइल ऐप के उपयोगकर्ता में बदलाव का %	10
		4.2. विभिन्न फिट इंडिया स्पर्धाओं में सहभागी प्रतिभागियों की	10,00,000			

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
		कुल संख्या				
		4.3. शारीरिक फिटनेस के लिए चयनित बच्चों की संख्या	2,07,625		4.2. शारीरिक फिटनेस के लिए चयनित बच्चों की संख्या में बदलाव का %	10
		4.4. प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की संख्या (ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड सहित)	5189		4.3. शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के नए नामांकन में बदलाव का %	10
	5. खेल के माध्यम से समावेशन का संवर्धन	5.1 सहायता प्राप्त महिला प्रतियोगिताओं की कुल संख्या	4,000	5. सभी नागरिकों के लिए खेल के अवसरों तक बेहतर और समान पहुंच	5.1 ग्रामीण/देशज स्पर्धाओं मे प्रतिभागिता में बदलाव का %	15
		5.2 महिला प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों की कुल संख्या	4,00,000		5.2 प्रतियोगिताओं में महिलाओं की प्रतिभागिता में बदलाव का %	20
		5.3 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त पैरा-एथलीटों की कुल संख्या	90		5.3 पैरा खेल विधाओं में पैरा-एथलीटों की संख्या में बदलाव का %	2
		5.4 ग्रामीण/देशज विधाओं में सहायता प्राप्त एथलीटों की कुल संख्या	4,000		5.4 उग्रवाद प्रभावित और अन्य अशांत क्षेत्रों से स्पर्धाओं में प्रतिभागी एथलीटों की संख्या में बदलाव का %	25
		5.5 उग्रवाद प्रभावित और अन्य अशांत क्षेत्रों में आयोजित स्पर्धाओं की कुल संख्या	395			